राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 174

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, सोमवार, 2 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

गांगुली का कार्यकाल 2024 तक बढ़ाने की तैयारी

>> 14

सरोकार

पहाड़ों को प्रदूषण से आजादी दे रहे कौशल

मनाली : हिमाचल प्रदेश के मनाली के ब्राण गांव निवासी पर्वतारोही कौशल भारद्वाज ने पर्यटकों को सैर कराने के साथ ही पहाड़ों को प्रदूषण से आजादी दिलाने का जिम्मा उठाया है। कौशल ने चोटियों से कई गाड़ियों में कचरा भरकर कूड़ा संयंत्र पहुंचाया। उनके इस प्रयास में कई संस्थाएं भी जुड़ गई हैं। (पेज-11)

जागरण विशेष

कश्मीर में फुटबॉल ने गिराई मजहब की दीवार

जम्मू : फुटबॉल के खेल ने कश्मीर में हिंदू-मुस्लिम एकता की नई इबारत लिखी है। कश्मीरी मुस्लिम शमीम मेराज व पंडित संदीप चट्टू ने विपरीत हालात में मिलकर रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब का गठन किया, जिसने कश्मीर को नई पहचान दी है। (पेज-10)

जांच आयोग का निष्कर्ष–नक्सल ऑपरेशन में मारे गए थे 17 ग्रामीण

नईदुनिया, जगदलपुर

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सारकेगुड़ा कांड की जांच कर रहे न्यायिक आयोग की रिपोर्ट कथित रूप से लीक हो गई है। दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट में केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल (सीआरपीएफ) और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने नक्सल ऑपरेशन के नाम पर 17 ग्रामीणों को एकतरफा फायरिंग में मार डाला था। ग्रामीण निहत्थे थे। मृतकों में सात नाबालिग भी शामिल थे। रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखे जाने से पहले लीक होने की सूचना से छत्तीसगढ़ सरकार सकते में है।

यह घटना बीजापुर जिले के बासागुड़ा स्थित सारकेगुड़ा गांव में 28 और 29 जून 2012 को हुई थी। पहले दिन 16 ग्रामीणों और दूसरे दिन एक ग्रामीण पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। घटना में एक जवान भी मारा गया था और छह जवान घायल हुए थे। पुलिस मारे गए ग्रामीणों को नक्सली बता रही थी, लेकिन ग्रामीण विरोध में उतर आए थे। जुलाई 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सरकार ने इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच कराने के लिए आयोग के गठन का फैसला लिया था। 11 जुलाई 2012 को जबलपुर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीके अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोग ने जांच शुरू की। रिपोर्ट 17 अक्टूबर 2019 को शासन को सौंप दी गई है।

2012 में छत्तीसगढ़ में हुई मुठभेड़ पर उठे सवाल

- बीजापुर में हुई थी घटना, आज सदन में पेश की जानी है आयोग की रिपोर्ट
- सीआरपीएफ ने कहा था कि नक्सलियों की मौजूदगी में हो रही थी बैठक

यह तस्वीर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में वर्ष 2012 के सारकेगुड़ा में ऑपरेशन के दौरान मारे गए ग्रामीणों की है। मृतकों को नक्सली बताया गया था, किंतु जांच में निष्कर्ष निकला है कि सभी मृतक ग्रामीण थे (फाइल फोटो)। नई दुनिया

सुरक्षाबलों की गोलीबारी आत्मरक्षा के लिए नहीं थी: आयोग ने रिपोर्ट के निष्कर्ष में बताया है कि सुरक्षाबलों ने आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाई थी। छह मृतकों के सिर पर गोली लगी थी। 10 मृतकों की पीठ पर रायफल की बट से चोट पाई गई थी। वहीं, जवान की मौत भी सुरक्षा बलों की फायरिंग में हुई थी।

घने जंगल नहीं, खुले मैदान में जुटे थे ग्रामीण : दावा है कि जांच आयोग के अनुसार सारकेगुड़ा, कोत्तागुड़ा और राजपेंटा के ग्रामीण 28 जून 2012 की देर शाम घने जंगल नहीं खुले मैदान में बैठक कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस के जवानों ने आयोग के समक्ष दावा किया था कि बैठक नक्सलियों की मौजूदगी में घने जंगल में हो रही थी। जिसे आयोग ने नहीं माना है। हालांकि आयोग ने ग्रामीणों की भी इस बात से सहमति नहीं जताई है कि बैठक घटना के अगले दिन होने वाले बीज पंडुम त्योहार के लिए बुलाई गई थी।

जस्टिस अग्रवाल आयोग की रिपोर्ट के अहम बिंदु

- ग्रामीणों ने फोर्स पर हमला नहीं किया था। सुरक्षाबलों ने शुरू में कहा था कि बैठक में शामिल लोगों ने हमला किया, डीआइजी ने कहा, उन्होंने बैठक स्थल की दिशा से गोली आते नहीं देखी
- फोर्स को गाइड ने कुछ संदिग्ध आवाज सुनने की बात बताई तो जवानों को हमले की आशंका हुई। इसी कारण उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी
- सीआरपीएफ और राज्य पुलिस ने कहा था कि कार्रवाई के दौरान सुरक्षाबलों के छह जवान भी घायल हुए
- हालांकि जख्म के निशान इस बात को साबित करते हैं कि गोली दूरी से नहीं चलाई गई थी
- अंधेरे की वजह से सुरक्षाबलों के जवानों की गोली ही साथियों को लगने की आशंका है

30 लोगों की हुई थी गवाही : आयोग ने पीड़ित पक्ष के 17, फोर्स और अन्य 13 लोगों को मिलाकर कुल 30 गवाहों का बयान दर्ज किया है। आयोग के गठन के बाद कई महीनों तक पीड़ित परिवारों से कोई भी बयान दर्ज कराने नहीं आया थे। बाद में पीड़ितों की ओर से गवाहों ने शपथ पत्र देकर बयान दर्ज कराया था।

विधानसभा की अवमानना : रिपोर्ट लीक होने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि यह विधानसभा की अवमानना है। विधानसभा चलने के दौरान इस तरह रिपोर्ट को लीक करके सरकार ने बड़ा अपराध किया है। उन्होंने इसकी जांच कराए जाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस विषय में वह सोमवार को विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे।

जो कहना है सदन में कहेंगे : आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट सोमवार को सदन में रखी जाएगी। ऐसे में जो भी कहना है, वह सदन में ही कहेंगे।

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

बालिग दुल्हन के नाबालिग दूल्हे को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह से संबंधित एक मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर दूल्हे पर दर्ज हुए केस को रद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने आदेश देकर गंभीर गलती की है, क्योंकि शादी के वक्त लड़के की उम्र 17 वर्ष थी, इसलिए उस पर बाल विवाह कानून की धारा नौ के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 5

दरिंदों को सजा दिलाने को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

हैदराबाद : महिला पशु चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से मार देने की घटना पर देश भर में उबाल कम नहीं हुआ है। घटना के तीन दिन बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया है, ताकि जल्द से जल्द दरिंदों को सजा दिलाई जा सके।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 12

नवंबर में जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ के पार

नई दिल्ली : देश में नवंबर में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) संग्रह की राशि 1,03,492 करोड़ रुपये पहुंच गई। नवंबर में जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर छह फीसद है। इसे अर्थव्यवस्था के लिए पूरी राहत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर अक्टूबर में मिले तेजी के संकेत नवंबर में हवा हो गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक फिर सड़कों पर उतरे

हांगकांग : हांगकांग में लोकतंत्र की मांग कर रहे आंदोलनकारी रविवार को फिर सड़क पर उतरे। निकाय चुनावों में मिली भारी सफलता और अमेरिका द्वारा समर्थन में बनाए गए कानून से आंदोलनकारी जोश से भरे हुए थे। एक हजार से ज्यादा लोगों अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पहुंचकर आभार जताया। पुलिस ने इन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।

प्रदूषण पर नहीं चेते राज्य

ढुलमुल रवैया ▸ 23 राज्यों को दिया गया पैसा व प्लान, नहीं किया काम

120 दिन में करना था अमल, संसद में उठे सवाल तो सामने आई हकीकत

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर भले ही जानलेवा बना हुआ है, लेकिन राज्यों का रवैया इसे लेकर ढुलमुल है। यह स्थिति तब है, जब केंद्र इससे निपटने को 23 राज्यों को पैसा और कार्ययोजना दोनों मुहैया करा चुकी है। बावजूद इसके अब तक किसी राज्य ने कोई काम शुरू नहीं किया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक साल के अंदर केंद्र से भी कोई पूछताछ नहीं हुई।

राज्यों को जो प्लान दिया गया था, वह करीब 132 बिंदुओं का था। इसमें वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोकथाम से लेकर धूल और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण, बायोमास जलाने से होने वाले प्रदूषण आदि से निपटने की पूरी योजना है। जो प्लान दिया गया है, उनमें अधिकतम 120 दिन में सभी कामों पर अमल करना था, लेकिन इस बीच पत्ता तक नहीं हिला।

मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक राज्यों के रवैये का पता तब चला, जब संसद में उठ रहे सवालों के बीच राज्यों से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी ली गई। इस दौरान ज्यादातर राज्यों ने अब तक योजना के तहत कोई भी काम नहीं किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टों के आधार पर शहरों का चयन : वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना (एनसीएपी) बनाई है। 23 राज्यों के 122 शहरों को इसमें शामिल किया है। इन शहरों का चयन विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2014 और 2018 की उन रिपोर्टों के आधार पर किया गया है, जिनमें वायु प्रदूषण के चलते लोगों की हो रही मौत और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चेताया गया था। इन शहरों में वायु की गुणवत्ता भी मानकों के अनुरूप नहीं है। बता दें कि स्वच्छ वायु की गुणवत्ता का निर्धारण पीएम-10 और पीएम 2.5 के स्तर पर होता है। जिसमें पीएम-10 का स्तर 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर से नीचे और पीएम-2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए।

ये प्रमुख शहर हैं योजना में शामिल : राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना में दिल्ली, मुंबई, कानपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, वाराणसी, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, पटना, रायपुर, विजयवाड़ा, सूरत, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, आगरा, प्रयागराज, आदि शहर शामिल हैं। इस योजना में उत्तर प्रदेश के कुल 15 शहरों को, पंजाब के नौ, मध्य प्रदेश के छह, बिहार के तीन और झारखंड के एक (धनबाद) शहर को शामिल किया गया है।

किस शहर को मिला कितना पैसा

- योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 28 शहरों को 10-10 करोड़ रुपये दिए गए
- पांच से 10 लाख की आबादी वाले प्रत्येक शहर को केंद्र सरकार ने 20 लाख रुपये दिए
- पांच लाख से कम आबादी वाले प्रत्येक शहर को 10 लाख रुपये दिए गए।
- 2024 तक पीएम-10 और पीएम-2.5 के स्तर को 20 से 30 फीसद तक कम करने का दिया गया है लक्ष्य

दिल्ली-एनसीआर की स्थिति प्रदूषण के लिहाज से खराब

नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर की स्थिति प्रदूषण के लिहाज से बेहद खराब है। यहां प्रदूषण के कारकों में कुदरती धूल, कोहरा और मंद हवा ही नहीं बल्कि मानव निर्मित गतिविधियां भी शामिल हैं। सर्दियों में तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इस स्थिति के लिए 93 फीसद तक मानव गतिविधियां ही जिम्मेदार होती हैं। आइआइटी कानपुर, दिल्ली और पुणे (दिल्ली शाखा) के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार संयुक्त रिसर्च पेपर में यह बात कही गई है। (पेज-2)

टेलीकॉम कंपनियों ने डेढ़ गुना किया टैरिफ

नई दिल्ली, प्रेट्र : टेलीकॉम सेक्टर की प्रतिस्पर्धा और कंपनियों की देनदारी का बोझ अब ग्राहकों के कंधे पर आने वाला है। विभिन्न मदों में करीब 80 हजार करोड़ रुपये की देनदारी चुकाने की कोशिश में जुटी टेलीकॉम कंपनियों वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल ने अपने कॉल और डाटा टैरिफ में 50 फीसद तक की वृद्धि का एलान कर दिया है। बढ़ी हुई दरें दो-तीन दिसंबर की दरम्यानी रात से लागू होंगी। रिलायंस जियो ने भी दरों में 40 फीसद तक की वृद्धि की बात कही है।

रविवार को वोडाफोन-आइडिया ने टैरिफ में बढ़ोतरी का एलान किया। इसके बाद एयरटेल और रिलायंस जियो ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया। वोडा-आइडिया और एयरटेल ने कॉल-डाटा टैरिफ में 50 फीसद तक की बढ़ोतरी की है। सबसे ज्यादा 50 फीसद की वृद्धि सालभर के अनलिमिटेड पैक पर की गई है। वोडा-आइडिया में पहले 999 रुपये में 12 जीबी डाटा के साथ सालभर की वैधता मिलती थी। अब इस पैक की कीमत 24 जीबी डाटा के साथ 1499 रुपये हो गई है। एयरटेल में पहले यह पैक 998 रुपये का था। अब एयरटेल भी इस पैक के लिए 1499 रुपये वसूलेगी। इसी तरह वोडा-आइडिया ने सालभर तक प्रतिदिन डेढ़ जीबी डाटा वाला अनलिमिटेड पैक 1699 से बढ़ाकर 2399 रुपये कर दिया है। एयरटेल इसके लिए 2398 रुपये वसूलेगी। अन्य छोटी-बड़ी अवधि वाले पैक में भी बढ़ोतरी की गई है। जियो ने टैरिफ में 40 फीसद तक वृद्धि करने का एलान किया है। जियो की बढ़ी हुई दर छह दिसंबर से प्रभावी होगी।

- तीन दिसंबर से बढ़ जाएगा कॉल और डाटा का खर्च
- वोडा-आइडिया, एयरटेल और जियो ने किया एलान
- ग्राहकों पर पड़ेगा कंपनियों की देनदारियों का बोझ

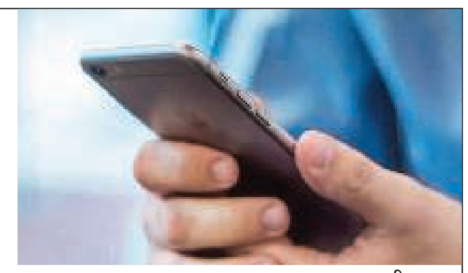

प्रतीकात्मक

कम से कम 49 रुपये का खर्च

टैरिफ वृद्धि के बाद वोडा-आइडिया और एयरटेल दोनों ही कंपनियों ने 28 दिन की वैलिडिटी के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क 49 रुपये कर दिया है। पहले यह पैक 23 रुपये का था। इसका अर्थ है कि एयरटेल या वोडा आइडिया के किसी नंबर को इस्तेमाल करते रहने के लिए आपको न्यूनतम 49 रुपये मासिक का रिचार्ज कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उस नंबर की इनकमिंग भी बंद हो जाएगी।

अनलिमिटेड के दावे से बचना जरूरी

पैक में बदलाव के बाद ग्राहकों को कंपनियों के अनलिमिटेड कॉल के दावे से भी सतर्क रहना होगा। वोडा-आइडिया और एयरटेल ने सभी पैक में अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर की जाने वाली कॉल को सीमित कर दिया है। 28 दिन के पैक पर 1000 मिनट, 84 दिन के पैक पर 3000 मिनट और 365 दिन के पैक पर 12000 मिनट की कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। इसके ऊपर छह पैसे प्रति मिनट का भुगतान करना होगा। समान नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी।

दबाव से जूझ रही हैं टेलीकॉम कंपनियां

2016 में टेलीकॉम सेक्टर में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जियो के उतरने के बाद कॉल और डाटा की कीमतों में तेज गिरावट आई थी। एक जीबी 4जी डाटा के बदले 250 से 400 रुपये तक वसूल रही टेलीकॉम कंपनियों को जियो के सामने प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपने टैरिफ में बड़ी कटौती करनी पड़ी थी। तब से कंपनियां घाटे में चल रही हैं। एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद वोडा-आइडिया की देनदारी करीब 44150 करोड़ रुपये हो गई है। एयरटेल की देनदारी करीब 35586 करोड़ रुपये है। दोनों कंपनियों को पिछली तिमाही में जबर्दस्त गिरावट का सामना करना पड़ा है।

गोरखपुर में स्कूल परिसर में जनाजे की नमाज, बाधित हो रही पढ़ाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के प्राथमिक विद्यालय बड़गो खोराबार में मुस्लिम समुदाय के लोग जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। इस दौरान छात्रों को कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, ताकि विवाद उत्पन्न न हो। रविवार को सूचना पर जिलाधिकारी ने इसके विकल्प की तलाश के लिए तहसीलदार को मौके पर भेजा।

बड़गो खोराबार विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश धर दूबे ने बताया कि यह अंग्रेजी माध्यम विद्यालय 1965 में बना था। इसके पहले यहां खाली मैदान हुआ करता था। यहां एक पीपल का पेड़ है, जहां हिंदू परिवार के सदस्य की मौत होने पर घंट बांधने आते हैं और कर्मकांड करते हैं, जबकि मुस्लिम शव रखकर जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। अब विद्यालय में चहारदीवारी बन गई है। बावजूद इसके यह क्रम जारी है। उन्होंने कहा कि समस्या तब आती है जब जनाजे की नमाज के दौरान लोग परिसर में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक उनकी नमाज चलती है बच्चों को कमरे के अंदर रखना पड़ता है, ताकि हल्ला-गुल्ला न करें। राजेश धर दूबे ने कहा, ऐसी स्थिति में कक्षाओं में पढ़ाई भी बाधित होती है। यदि इसका विकल्प मिल जाता तो बेहतर होता।

- सूचना पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार को भेजा, बीएसए स्वयं तलाशेंगे विकल्प

जानकारी मिली है। मैं स्वयं मौके पर जाकर देखूंगा। सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों पक्षों से बात कर विकल्प की तलाश की जाएगी, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। –भूपेंद्र नारायण सिंह, बीएसए

हिंदुत्व की विचारधारा को कभी नहीं छोड़ूंगा : उद्धव

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को विधानसभा में एलान किया कि वह हिंदुत्व की विचारधारा को कभी नहीं छोड़ेंगे। उद्धव का यह बयान महाविकास अघाड़ी के घटक कांग्रेस और राकांपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, जिन्होंने शिवसेना के साथ राज्य में गठबंधन सरकार बनाई है। यही नहीं, सरकार चलाने के लिए तीनों दलों के बीच बने न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) की भूमिका में ही खासकर 'सेक्यूलर' शब्द का उल्लेख किया गया है। विधानसभा सत्र को 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, 'मैं अभी भी हिंदुत्व की विचारधारा के साथ हूं, इसे मुझसे अलग नहीं किया जा सकता है।' पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस पर कटाक्ष करते हुए ठाकरे ने कहा, 'दिए गए वचन का पालन करना ही मेरे हिंदुत्व का हिस्सा है। जय श्री राम बोलना एवं वचन का पालन न करना हिंदुत्व नहीं है। मैं कल भी अपने हिंदुत्व का पालन करता था, आज भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा।' ठाकरे का इशारा फड़नवीस के उस बयान की तरफ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने कभी सीएम पद को साझा करने का वादा नहीं किया था।

बाद में पत्रकारों से बातचीत में ठाकरे ने कहा कि आरे कालोनी में मेट्रो रेल कारशेड के निर्माण कार्य के विरोध के दौरान लोगों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। उन्होंने आदेश दे दिया है।

उद्धव का फड़नवीस पर कटाक्ष पेज>>4

- राकांपा और कांग्रेस को असमंजस में डाल सकता है ठाकरे का बयान
- आरे कालोनी मामले में लोगों पर दर्ज हुए केस वापस लेगी सरकार

मुंबई में रविवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। एएनआइ

कांग्रेस के विधायक नाना पटोले निर्विरोध स्पीकर निर्वाचित

भाजपा द्वारा अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले लेने के बाद कांग्रेस के नाना पटोले विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष (स्पीकर) चुन लिए गए। भाजपा की ओर से किशन कथोरे उम्मीदवार थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने आज यह कहते हुए अपने दल का उम्मीदवार वापस ले लिया कि महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की परंपरा नहीं रही है।

फड़नवीस नेता प्रतिपक्ष बने

विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद नाना पटोले ने भाजपा नेता फड़नवीस को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया। उन्होंने फड़नवीस पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि जो लोग विपक्ष चाहते ही नहीं थे, उनके साथ उचित न्याय हुआ है कि अब वह स्वयं एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे।

हैदराबाद कांड का साया

गीता महोत्सव के मंच से नारी सम्मान की चिंता

लालकिला मैदान पर आयोजित गीता प्रेरणा महोत्सव पर दिखा हैदराबाद की घटना का साया, भागवत ने कहा, घर से शुरू हो मातृशक्ति के सम्मान की शिक्षा, राजनीतिज्ञों से लेकर साधु-संत तक दिखे मर्माहत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

हैदराबाद में पशु चिकित्सक से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की हृदयविदारक घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। यहां लालकिला मैदान पर आयोजित गीता प्रेरणा महोत्सव में जुटे लोग इससे मर्माहत दिखे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि मातृशक्ति के प्रति सम्मान की शिक्षा हमें घर से ही शुरू करनी होगी। ऐसा अपराध करने वालों की भी बहन और माता हैं। ऐसे लोगों को शायद घर में किसी ने सिखाया नहीं कि मातृशक्ति से कैसे व्यवहार करना चाहिए।

जीयो गीता संस्थान की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में भागवत ने महाभारत के एक प्रसंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब अर्जुन के सामने उर्वशी खड़ी थीं, तो वह उन्हें एकटक देख रहे थे। बाद में उर्वशी ने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए देख रहे हो, तब अर्जुन कहते हैं कि आप हमारी पूर्वज हैं, माता के समान हैं। इसलिए मातृभाव से देख रहा था। समाज में भी जब यही भाव होगा तो देश में मातृशक्ति का सम्मान और सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की है और रहेगी। लेकिन, सबकुछ उन्हीं पर छोड़ देने से नहीं चलेगा। इसके लिए परिवार को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने गीता को जीवन का सार बताते हुए कहा कि इसे संपूर्ण विश्व का बनाने के लिए शुरुआत खुद से करनी होगी। 130 करोड़ की जनता को इसे हर घर और गांव तक पहुंचाना होगा।

साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि पुरुष जब काम वासना का पुतला बनेगा तो घर की बहू-बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। भारत जैसे देश में दुष्कर्म और भ्रष्टाचार अशोभनीय व चिंताजनक है। अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम डॉ. उमर अहमद इलयासी ने कहा कि हैदराबाद की घटना के आरोपितों को सरेआम फांसी होनी चाहिए। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने कहा कि गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे इस तरह के कुसंस्कारी पैदा न हों। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गीता को वैश्विक धरोहर बताते हुए कहा, इसमें हर चुनौती और समस्या का समाधान समाहित है। महोत्सव में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश पढ़ा। इसके साथ ही मध्यम एवं लघु उद्योग राज्य मंत्री प्रताप चंद सारंगी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी, अवधेशानंद महाराज, परमानंद महाराज, राघवानंद महाराज, स्वामी ज्ञानानंद, विवेक मुनि समेत अन्य ने महोत्सव को संबोधित किया।

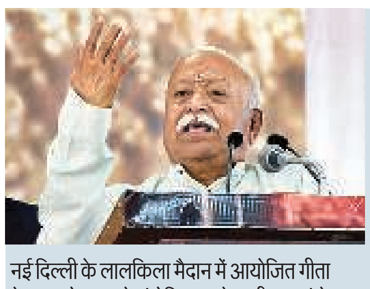

नई दिल्ली के लालकिला मैदान में आयोजित गीता प्रेरणा महोत्सव को संबोधित करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत। जागरण

मातृशक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की है और रहेगी, लेकिन, सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देने से नहीं चलेगा। इसके लिए परिवार को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। –मोहन भागवत, सरसंघ चालक

साधु-संत भी करें समाज को जागरूक : स्मृति ईरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला सुरक्षा को लेकर समाज को जागरूक करने के लिए साधु-संतों को आगे आने का आह्वान किया। महिलाओं का सम्मान और उनका संरक्षण न सिर्फ हमारा कर्तव्य है, बल्कि इसे धर्म स्वयं परिभाषित करता है। ऐसे में आग्रह है कि संत चरण जहां-जहां पड़ें, इसका उच्चारण विशेष रूप से करें। उन्होंने नवजात और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण के प्रति भी सबको जागरूक करने का आग्रह किया।

स्मृति ईरानी फाइल फोटो

करतारपुर पर पाक की साजिश बेपर्दा, इमरान से सतर्क रहें सिद्धू : कैप्टन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद द्वारा करतारपुर कॉरिडोर पर दिए हालिया बयान से पाक सेना की साजिश बेपर्दा हो गई है। उन्होंने अपने पूर्व कैबिनेट सहयोगी नवजोत सिद्धू को सलाह दी है कि वह इमरान खान से दोस्ती और पाक सरकार से मिलने वाले मौकों को लेकर सतर्क रहें। दोस्ती का किसी फैसले पर प्रभाव न पड़ने दें। यह भारत के लिए घातक होगा।

कैप्टन ने कहा, उनकी इस आशंका की पुष्टि हो गई है कि करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के दिमाग की उपज है। बाजवा ने जब सिद्धू से कॉरिडोर के निर्माण संबंधी फैसले की बात कही थी तब इमरान ने पद भी नहीं संभाला था। यह कैसे संभव है कि कॉरिडोर के फैसले के पीछे बाजवा नहीं था। इसलिए सिद्धू को ज्यादा सचेत रहना चाहिए।

कैप्टन ने राशिद के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई कि कॉरिडोर भारत को नुकसान पहुंचाएगा और इसके माध्यम से बाजवा द्वारा दिए घाव को भारत हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत को उम्मीद थी कि यह कॉरिडोर दोनों देशों के बीच शांति के लिए पुल का काम करेगा, लेकिन राशिद का बयान भारत की सुरक्षा व अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। पाकिस्तान गलतफहमी पैदा करने का प्रयास न करे, अन्यथा उसे गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

करतारपुर कॉरिडोर को पहले भी आइएसआइ का एजेंडा बता चुके कैप्टन ने कहा कि वह हमेशा यही कहते आए हैं कि एक सिख होने के नाते कॉरिडोर खुलने की उनको बहुत खुशी हुई है, लेकिन इससे हमारे देश को संभावित खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगाह किया कि कॉरिडोर के द्वारा पाकिस्तान सिखों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। जिससे आइएसआइ के इशारे पर काम करने वाले सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) द्वारा रेफरेंडम-2020 के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। उल्लेखनीय है कि एसएफजे खालिस्तान समर्थक संगठन है।

32 पुरावशेष विदेश से वापस लाने में पिछले पांच वर्षों में सफलता मिली है। इन्हें करोड़ों में विदेश में बेच दिया गया था। इनमें सबसे अधिक पुरावशेष अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से वापस आए हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 2 दिसंबर 2019

आम आदमी हूं, इसीलिए आम जन की व्यथा समझता हूं : केजरीवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं आम आदमी हूं इसीलिए आम जन की व्यथा समझता हूं। दिल्ली के लोग धन्यवाद के काबिल हैं। उन्होंने मेरे जैसे छोटे से आम आदमी को इतनी बड़ी कुर्सी पर बिठाया। वह रविवार को ओखला विधानसभा क्षेत्र स्थित तैमूर नगर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए संघर्ष कर रहे रूपेश गुर्जर की सितंबर 2018 में ड्रग्स माफियाओं ने हत्या कर दी थी। रूपेश गुर्जर के सम्मान में रविवार को तैमूर नगर में समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें रूपेश गुर्जर की पत्नी को मुख्यमंत्री ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में स्थायी नियुक्ति का पत्र सौंपा।

उन्होंने कहा, अधिकतर लोग सोचते हैं, मुझे क्या पड़ी है। वहीं समाज में कुछ लोग होते हैं जो बहादुरी के साथ लड़ते है, वह जान की परवाह नहीं करते, रूपेश गुर्जर उनमें से एक थे। उनकी हत्या के बाद परिवार पर समस्याओं का पहाड़ टूट गया। फिर समाज के लोग मुझसे मिले। उन्होंने सहायता राशि, चौक का नाम रूपेश गुर्जर के नाम पर रखने, पत्नी को नौकरी देने और बच्चों के स्कूल में दाखिले की मांग की। उनकी सभी मांगें पूरी की। इसके लिए कुछ नियम बदलने पड़े, वह भी किया, लेकिन परिवार की मदद की। मेरी कामना है कि बच्चे बड़े होकर पिता की तरह देश की सेवा करें।

इस दौरान मुख्यमंत्री कहा, मैं आम आदमी हूं। इसीलिए समझता हूं कि आम आदमी को बिजली, पानी का बिल व बच्चों की स्कूल फीस भरने, बस व मेट्रो के किराये देने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। आम आदमी के परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो जमीन जायदाद बेचने की नौबत आ जाती है। मैं दिल्ली को परिवार और खुद को परिवार का बड़ा बेटा मानता हूं। इसीलिए परिवार के बड़े बेटे के तौर पर दिल्लीवालों के लिए काम कर रहा हूं। आगे भी इस फर्ज को निभाता रहूंगा।

हर समय दिल्ली के विकास की सोचता रहता हूं: मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली में अगर कहीं किसी की दुर्घटना हो जाए, उसको पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराएं, दिल्ली सरकार इलाज का खर्च उठाएगी। उन्होंने कहा कि छह सात साल पहले केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। आपने जब से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी है, रात दिन-सेवा में लगा हूं। पूरी दिल्ली को आगे कैसे बढ़ाना है, इसी में लगा रहता हूं। मैं 24 घंटे लगकर आपकी सेवा करता रहूंगा।

तैमूर नगर में शहीद रूपेश की पत्नी मोनू को स्थायी नौकरी का नियुक्ति पत्र देते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस दौरान रूपेश की बेटी-बेटा और (दाएं से) विधायक सहीराम व अमानतुल्लाह खान भी मौजूद रहे। जागरण

शाहबेरी की बड़ी मछली को खाकी की क्लीन चिट पुन: जांच के आदेश

- दो अवैध इमारतें गिरने से हुई नौ लोगों की मौत के मामले में दर्ज हुई थी पहली एफआइआर
- 17 जुलाई 2018 को हुई थी घटना, 18 जुलाई पुलिस ने दर्ज की थी रिपोर्ट

ग्रेनो वेस्ट के शाहबेरी में गिरी इमारत के पास जुटी लोगों की भीड़। जागरण आर्काइव

प्रवीण विक्रम सिंह, ग्रेटर नोएडा

शाहबेरी प्रकरण में दर्ज हुई पहली एफआइआर की पुनः जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि पहली एफआइआर में बड़ी मछली को खाकी की क्लीन चिट मिल गई और किसी अन्य व्यक्ति को आरोपित का नाम दर्शा कर जेल भेज दिया गया। मामले की पुनः जांच सीओ तृतीय ग्रेटर नोएडा राजीव सिंह को सौंपी गई है। जांच के बाद रिपोर्ट एसएसपी वैभव कृष्ण को भेजी जाएगी। वहीं, शाहबेरी के ही एक अन्य प्रकरण में एफआइआर दर्ज होने के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम चार्जशीट दाखिल होने के दौरान कागजों में बदल दिया गया और गुनहगारों को बचाया गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम कागजों में बदलने के मामले में रजिस्ट्रार कार्यालय से भी रिपोर्ट भी मांगी गई है।

बताया गया है कि शाहबेरी प्रकरण में जो पहली एफआइआर दारोगा राजेंद्र कुमार की तरफ से दर्ज कराई गई। उसमें गंगा शंकर द्विवेदी को शाहबेरी में प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने वाला बताया गया। एफआइआर में 14 नंबर पर अंकित नाम श्याम जी पाठक उर्फ सोनू पाठक को दाखिल चार्जशीट में गंगा शंकर द्विवेदी का साला बताया गया है। जांच में आदेश दिए गए हैं कि श्याम जी पाठक ही सोनू पाठक है या नहीं और श्याम जी पाठक का प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने से कोई सरोकार है या नहीं, इसका पता किया जाए।

वहीं, दूसरे मामले में 16 अक्टूबर 2018 को एक मुकदमा मैसर्स एक्टिव इक्विपमेंट के सोनित्य कुमार के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस जांच के दौरान मैसर्स एक्टिव के सोनित्य कुमार का नाम चार्जशीट से निकाल कर दीपक त्यागी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया। जांच में दर्शाया गया कि मैसर्स एक्टिव के निदेशक द्वारा दीपक त्यागी की कंपनी दिव्यांका से पूर्व में ही निर्माण एग्रीमेंट कर लिया गया था। जांच में पूछा गया है कि दोनों कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच जो करार हुआ है वह पंजीकृत है या नहीं। रजिस्ट्रार कार्यालय के रजिस्टर में कंपनी का दूसरे से करार किस नंबर पर है यह भी पुनः जांच में पूछा गया है।

यह है शाहबेरी प्रकरण

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर स्थित शाहबेरी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण किया गया। बीते साल 17 जुलाई 2018 को शाहबेरी में दो अवैध इमारतें गिर गई थी। मलबे में दबने से नौ लोगों की मौत हो गई थी। मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचने के बाद शाहबेरी प्रकरण की जांच के लिए एसआइटी का गठन कर दिया गया था।

दो पर रासुका के तहत हो चुकी है कार्रवाई

शाहबेरी में अवैध निर्माण करने वाले आरोपित बिल्डरों में से दो शाहबुद्दीन व जसवीर मान पर जिला प्रशासन रासुका की कार्रवाई कर चुका है। वहीं 42 बिल्डरों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। मामले में कुल 86 मुकदमे दर्ज है।

पानी-प्याज व कॉलोनी पर होगी चर्चा

हंगामे के आसार ▶ दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू

सदन में पेश होंगे चार बिल, जरूरत पड़ने पर सत्र की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। दो दिवसीय इस सत्र में अनधिकृत कॉलोनियों का मुद्दा गरमाएगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा प्याज की आपूर्ति रोक दिए जाने का भी मुद्दा उठेगा। दिल्ली के पेयजल की गुणवत्ता पर केंद्र द्वारा सवाल उठाए जाने पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है।

शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में चार बिलों को रखा जाएगा। इसमें से दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बिल 2019, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2019 के अलावा श्रम विभाग और जीएसटी से संबंधित दो बिल शामिल हैं। पहले दो विधेयकों के प्रालेखों को दिल्ली कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है। विधेयकों को दिल्ली के उपराज्यपाल ने विधानसभा में पेश किए जाने की अनुमति भी दे दी है। सत्र में विधायी कार्यों के बारे में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल के कार्यालय को दिल्ली सरकार ने सूचित भी कर दिया है। हालांकि यह सत्र आगे भी बढ़ाया जा सकता है। खास बात यह है कि यह दिल्ली विधानसभा का संभवतः अंतिम सत्र भी हो सकता है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल कहते हैं कि जब तक फरवरी में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है। तब तक जरूरत पड़ने पर विधानसभा में कभी भी सत्र बुलाया जा सकता है। ऐसे में इसे अभी संभावित अंतिम सत्र ही कहा जाएगा।

दिल्ली विधानसभा। फाइल

ऐसी पढ़ाई जिसमें नौकरी की गारंटी होगी : स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बिल 2019 पास होने के बाद इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से दिल्ली सरकार नौकरी की गारंटी वाली पढ़ाई कराएगी। दिल्ली के युवाओं को उद्योगों की जरूरत व नौकरी के हिसाब से तैयार करने के लिए दिल्ली में यह यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। इसमें 85 फीसद सीटें दिल्ली के बच्चों के लिए होंगी। वहीं दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2019 बिल पास हुआ तो अकादमिक स्तर पर खिलाड़ियों को पढ़ाई करने से राहत मिल जाएगी। उनको नौकरी के लिए किसी और डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। खेलों में उनके प्रदर्शन के आधार पर ही डिग्री मिल जाएगी। यहां तक कि वे सिविल सेवा जैसी परीक्षाएं भी दे सकेंगे।

केंद्र ने दाम बढ़ाने के लिए बंद की प्याज की आपूर्ति : सिसोदिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने प्याज की आपूर्ति रोकने का केंद्र पर आरोप लगाया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जानबूझकर कर दाम बढ़ाने के लिए प्याज की आपूर्ति बंद की गई, जिससे दिल्ली सरकार सस्ते दामों पर प्याज न बांट सके। सिसोदिया ने प्रेसवार्ता में कहा कि केंद्र ने पत्र लिखकर 56 हजार मीट्रिक टन प्याज स्टॉक में होने की बात कही थी। यह पत्र 5 सितंबर को लिखा गया था, फिर अचानक दिल्ली को आपूर्ति क्यों रोक दी गई? उपमुख्यमंत्री ने फिर मांग की है कि हर दिन दस गाड़ी प्याज दिया जाए, जिससे हम आम जनता को 23.90 रुपये किलो में प्याज दे सके। सिसोदिया ने कहा दिल्ली में प्याज को लेकर लोग दुखी हैं। केंद्र को पत्र लिखकर बताया गया था कि हम रोजाना 10 गाड़ी प्याज लेकर सस्ते दाम पर लोगों को देंगे। जिससे प्याज की कालाबाजारी करने वालों पर लगाम लग सके। हमने केंद्र सरकार से 9 दिसंबर तक प्याज के लिए अनुमति मांगी थी। 2.5 लाख किलो प्याज हमने रोजाना 9 दिसंबर तक मांगा था। कभी भी 10 गाड़ी हमें प्याज की आपूर्ति नहीं हुई। वहीं, खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि केंद्र चाहता है कि दिल्ली में प्याज के दाम बढ़ जाएं और जनता परेशान हो। हमने प्याज की मांग की, लेकिन उसपर कोई जवाब नहीं आया। 24 नवंबर को प्याज की आखिरी गाड़ी दिल्ली आई थी, जिसमें 13-14 हजार किलो ही प्याज था। उसके बाद प्याज नहीं आ रहा। मैंने केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से मिलने का समय मांगा, अभी तक उन्होंने समय नहीं दिया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा ने दिखाई बहादुरी लुटेरे को दबोचा

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की एक छात्रा ने बहादुरी दिखाते हुए शुक्रवार रात लुटेरे को दबोचकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। घटना संगम विहार थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से छात्रा से लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 18 वर्षीय अंजलि परिवार सहित संगम विहार डी-ब्लॉक में रहती हैं।। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। वह शुक्रवार शाम को बुटिक गई थीं, जहां से पैदल घर लौट रही थीं। जैसे ही वह संगम विहार डी-ब्लॉक में गली नंबर-5 के पास पहुंचीं, तभी बदमाश उनसे मोबाइल लूटकर भागने लगा। वारदात के बाद घबराने की बजाय पीड़िता ने बहादुरी दिखाई और लुटेरे के पीछे दौड़ लगा दी। थोड़ा आगे जाकर पीड़िता ने लुटेरे को दबोच लिया और शोर मचाते हुए उससे भिड़ गई। लुटेरे ने भागने की कोशिश की लेकिन इस दौरान आसपास के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए।

पीड़िता ने लोगों ने साथ मिलकर पहले आरोपित की पिटाई की और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर लुटेरे को उसके हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित की शिनाख्त बंटी गुप्ता के रूप में हुई है। उससे पूछताछ जारी है।

हर कर्मचारी को मिले एक समान वर्दी एवं धुलाई भत्ता : हाई कोर्ट

जासं, नई दिल्ली : वर्दी और धुलाई भत्ता दिए जाने में भेदभाव को लेकर हाई कोर्ट के ही कई कर्मचारियों की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कर्मचारियों को राहत दी है। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने कहा कि अदालत परिसर के अंदर और बाहर अनुशासन व शिष्टाचार बनाए रखना प्रत्येक कर्मचारी का कर्तव्य है। पीठ ने सभी कर्मचारियों को वर्दी व भत्ते के लिए समान राशि दिए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि भेदभाव के लिए कोई तर्क नहीं है।

वर्दी भत्ते में विसंगतियों से नाराज कर्मचारियों की याचिका पर दो सदस्यीय पीठ ने हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि अदालतों के भीतर सीधे न्यायाधीशों की सहायता करने वाले अधिकारियों को निर्धारित वर्दी पहनकर अदालत में शिष्टाचार और अनुशासन बनाए रखने की जरूरत होती है। इस पर पीठ ने कहा कि वह यह समझने में नाकाम हैं कि आखिर कैसे सिर्फ अदालत परिसर के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को ही इसकी गरिमा को बनाए रखने की जरूरत है और जो रजिस्ट्री विभाग में काम करते हैं, उन्हें जरूरत नहीं है। यहां तक कि अदालत परिसर के अंदर और बाहर प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी इसकी गरिमा और अनुशासन बनाए रखने की है। अदालत परिसर में हर कर्मचारी इसकी छवि को प्रदर्शित करता है और उसे अपने व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए। पीठ ने इन टिप्पणियों के साथ ही याचिकाकर्ताओं और विभिन्न पदों पर काम करने वाले अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को मई 2019 से एक समान वर्दी एवं धुलाई भत्ता देने का निर्देश दिया।

निर्भया के गुनहगार विनय की फांसी की फाइल आगे बढ़ी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषियों को जल्द फांसी दिए जाने की तेज होती मांग के बीच दिल्ली सरकार ने शनिवार को विनय शर्मा की दया याचिका खारिज करने की संस्तुति कर दी है। उपराज्यपाल को फाइल भेज दी गई है। अब वह अपनी संस्तुति के साथ इसे गृह मंत्रालय को भेजेंगे। पूरे मामले में सिर्फ विनय ने ही दया याचिका दाखिल की थी।

दिल्ली सरकार में गृहमंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दोषी विनय ने युवती के साथ जिस तरह का जघन्य व क्रूर अपराध किया, उसे माफ नहीं किया जा सकता। दिल्ली सरकार ने संस्तुति पत्र में लिखा है कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी की याचिका खारिज कर दी क्योंकि वह दया का हकदार नहीं है।

सत्येंद्र जैन। फाइल

अदालत ने जारी किया है नोटिस : दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर पीड़िता की मां की तरफ से दायर याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी दोषियों को नोटिस जारी करके पूछा है कि उन्होंने दया याचिका दायर की है या नहीं?

'सड़क हादसों को रोकने के लिए जनआंदोलन जरूरी'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए कांस्टीट्यूशन क्लब व जेके टायर के संयुक्त तत्वावधान में कार रैली का आयोजन कांस्टीट्यूशन क्लब में हुआ। रैली में सांसदों व पूर्व सांसदों के साथ नौकरशाहों ने हिस्सा लेकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व क्लब के सचिव राजीव प्रताप रूडी और जेके टायर के उप प्रबंध निदेशक आयुष्मान सिंघानिया ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। राजनेताओं ने अपने वाहनों के साथ रैली में हिस्सा लिया। वहीं, इससे पूर्व सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे, राजेश पायलट व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह समेत अन्य राजनेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। रैली कांस्टीट्यूशन क्लब से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर जाकर समाप्त हुई। इस अवसर पर विंटेज कारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी।

कांस्टीट्यूशन क्लब में जेके टायर एवं कांस्टीट्यूशन क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विंटेज कार रैली के शुभारंभ समारोह के दौरान एक विंटेज कार में बैठे मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व उनकी पत्नी अमिता बिरला। इस दौरान कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला (बाएं) भी मौजूद रहे। जागरण

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि सड़क दुर्घटना न तो उम्र देखती है और न ही जाति देखती है। भारत में हर मिनट सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ज्यादातर देखने में आता है कि 25-30 वर्ष के युवा सड़क दुर्घटनाओं की चपेट में आते हैं। इन दुर्घटनाओं में किसी युवा की जान जाती है तो कई वर्षों तक उसके परिवार को पीड़ा होती है। कई परिवारों में व्यक्ति के ऊपर घर के पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है तो उसका परिवार बिखर जाता है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का एकमात्र उपाय सड़क सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना और यातायात नियमों का पालन करना है। इस आंदोलन में देश की 130 करोड़ जनता को शामिल होना जरूरी है। रैली में सांसदों के भाग लेने से जनता में यह संदेश जाएगा कि जन प्रतिनिधि भी जागरूक हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि संसद में भी सड़क सुरक्षा को लेकर चर्चा हो। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि जन प्रतिनिधियों का 80 फीसद समय यात्रा में गुजरता है। इसलिए सांसद सड़क सुरक्षा के लिए सबसे बड़े ब्रांड एंबेसडर हो सकते हैं।

घोषणापत्र में दिल्ली के विकास का होगा रोडमैप : तिवारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को उनके आशियाने का मालिकाना हक देने का बिल लोकसभा में पास किए जाने के बाद भाजपा नेता अब जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। रविवार को मटियाला, किराड़ी और नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा आयोजित की गई, जिसे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी व अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से ही भाजपा के सभी सांसदों ने इन कॉलोनियों को नियमित करने का प्रयास शुरू कर दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार इसमें बाधा डालती रही। आखिरकार केंद्र सरकार ने अपने हाथ में यह काम लेकर पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में दिल्ली के विकास का रोडमैप होगा।

मनोज तिवारी। फाइल

उन्होंने कहा कि मुफ्त पानी देने का वादा करके सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को साफ पानी देने में फेल हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व दिल्ली के प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि कांग्रेस और बाद में आम आदमी पार्टी (आप) अनधिकृत कॉलोनियों के नाम पर लोगों को धोखा देती रही है। आप सरकार यह झूठ बोलती रही कि वह तो इन कॉलोनियों को नियमित करना चाहती है लेकिन करने नहीं दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के निर्णय से आप सरकार की पोल खुल गई है। 16 दिसबंर से अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपने घर की रजिस्ट्री करा सकेंगे। वहीं, सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों के सीमांकन का काम करने के बजाय सिर्फ समय मांगती रही। इस वजह से लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक देने में देर हुई। दूसरी बार मोदी के प्रधानमंत्री बनने के सौ दिन में दिल्ली के 40 लाख लोगों के हक में फैसला कर लिया गया।

सांसद हंसराज हंस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दिल में देश के हर नागरिक की चिंता है। कार्यक्रम संयोजक व दिल्ली प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि लाखों लोगों को घर खोने का डर सताता रहता था। अब इन कॉलोनियों में रहने वालों को बैंक से ऋण भी मिल सकेगा।

राजपूतों के विरोध पर दलितों ने बदला बरात का रास्ता

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

हरियाणा के फरीदाबाद जिले के भूपानी थाना क्षेत्र के गांव महावतपुर में राजपूत समुदाय के युवकों पर दलितों की बरात का रास्ता रोकने का आरोप लगा है। आरोप है कि रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा कर उनका रास्ता रोका गया। मजबूरी में उन्हें रास्ता बदलकर बरात ले जानी पड़ी। रविवार को दलितों ने भूपानी थाने में शिकायत दी। पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं राजपूतों ने कहा कि रास्ते से उन्हें बरात ले जाने से कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि संगीत की आवाज को सिर्फ कम करने का आग्रह कर रहे थे।

शनिवार रात गांव में कल्लूराम की बेटी पूजा की शादी थी। रात करीब 9.30 बजे पल्ला सेहतपुर से बरात आई थी। कल्लूराम का आरोप है कि जब बरात चलनी शुरू हुई तो राजपूत समुदाय के युवकों ने ट्रैक्टर खड़ा कर बरात का रास्ता रोक दिया। इस दौरान काफी कहासुनी हुई। झगड़े से बचने के लिए वह बरात दूसरे रास्ते से निकालकर ले गए। शादी की रस्में पूरी कर लड़की को विदा करने के बाद रविवार सुबह दलित बड़ी संख्या में एकत्रित होकर भूपानी थाने पहुंचे और घटना की शिकायत दी। पुलिस ने संदीप, सोनू, अंकित, महिपाल चौहान के दोनों लड़कों सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दलितों ने एक वीडियो भी पुलिस को सौंपा है, जिसमें बरात के दौरान उनकी राजपूत युवकों से कहासुनी हो रही है और रास्ते में ट्रैक्टर भी खड़ा दिख रहा है। मुकदमे में एससी एसटी एक्ट लगने से एसीपी सेंट्रल मोहिंदर वर्मा जांच कर रहे हैं।

> हमारे घर और पड़ोस में दो-तीन बुजुर्गों की हृदय की बाइपास सर्जरी हुई है। उन्हें डीजे की तेज आवाज से समस्या होती है। रात में जब बरात में तेज आवाज में डीजे बज रहा था, तो हमारे बच्चों ने आवाज कुछ कम करने का आग्रह किया था। इसको लेकर कहासुनी हुई थी। पहले भी गांव में सभी की बरात उसी रास्ते से निकलती रही है, कभी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई।
>
> **-महिपाल, आरोपित युवकों का पिता**

> मुझे रात में इस बाबत सूचना मिली थी। मैं तुरंत मौके पर पहुंचा और मामला शांत कराया। हमारे गांव में दलित और राजपूत सालों से भाईचारे के साथ रहते हैं। सभी समाज की बरात गांव के मुख्य रास्ते से ही निकलती हैं, कभी किसी को नहीं टोका गया।
>
> **- भान सिंह, सरपंच, गांव महावतपुर**

एक अंक में पहुंचा न्यूनतम तापमान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में रविवार इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हवा में नमी का अधिकतम स्तर 100 फीसद तो न्यूनतम स्तर 52 फीसद दर्ज हुआ।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर की दिशा से ठंडी हवा दिल्ली और आसपास के इलाकों में दस्तक दे सकती है। इसके प्रभाव के कारण न्यूनतम तापमान इसी तरह से कम रह सकता है। पिछले वर्ष एक दिसंबर को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। वहीं वर्ष 2017 में इस दिन न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था।

सोमवार के दिन सुबह के वक्त कोहरा छा सकता है। तेज गति से 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इससे ठिठुरन का अहसास होगा। रविवार के दिन पूसा में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं पालम में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

बढ़ गया प्रदूषण का स्तर : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रदूषण मॉनीटरिंग स्टेशन में दिल्ली का एयर इंडेक्स रविवार के दिन 250 दर्ज हुआ। शनिवार के दिन यह 193 था। रविवार के दिन हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषक तत्व एक ही जगह पर ठहर गए। इसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। सोमवार को हवा की रफ्तार तेज होती है तो प्रदूषण के कम होने की संभावना है।

लेह में पारा माइनस 13.2 पहुंचा : कश्मीर और लद्दाख के अधिकतर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। रविवार को लेह की रात सबसे ठंडी रही। यहां न्यूनतम तापमान माइनस 13.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि अधिकतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में भी न्यूनतम तापमान लगातार गिरने से ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है।

प्रदूषण के लिए खाना बनाने जैसे काम भी जिम्मेदार

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

- आइआइटी कानपुर, आइआइटी दिल्ली और आइआइटी पुणे द्वारा तैयार संयुक्त शोध पत्र में दी गई है यह जानकारी
- भौगोलिक बनावट के कारण दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाते प्रदूषक तत्व

दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण के लिहाज से सुपर हॉट स्पॉट है। यहां प्रदूषण के कारकों में कुदरती धूल, कोहरा और मंद हवा ही नहीं बल्कि मानव निर्मित गतिविधियां भी शामिल हैं। सर्दियों में तो दिल्ली-एनसीआर को सुपर हॉट स्पॉट बनाने में 93 फीसद तक मानव गतिविधियां ही जिम्मेदार होती हैं। विडंबना यह कि यहां की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि प्रदूषक तत्व स्वयं से छंट भी नहीं पाते।

आइआइटी कानपुर, आइआइटी दिल्ली और आइआइटी पुणे (दिल्ली शाखा) के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार संयुक्त शोध पत्र में यह जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण के लिहाज से सुपर हॉट स्पॉट बनाने में मानवीय गतिविधियां सर्दियों में 93 फीसद, गर्मियों में 54 फीसद और मॉनसून में 88 फीसद रहती हैं। सर्दियों के दौरान कुल पीएम 2.5 का 50 से 60 फीसद हिस्सा द्वितीयक (स्रोत से छूटने के बजाय रासायनिक रूपांतरण के जरिये वातावरण में बनता है) किस्म का होता है। ऐसा सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड (वीओसी) और पोली साइकल एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) आदि के पार्टिकुलेट मैटर में तब्दील होने से होता है। इन गैसों का आंशिक रिश्ता कोयले से होता है।

इस पेपर के मुताबिक बायोमास और अपशिष्ट जलने से ब्लैक कार्बन एवं कार्बनिक कण धुंए के रूप में निकलते हैं जो धीरे धीरे वाहनों, कारखानों, ईंट के भट्टों आदि के प्रदूषण से मिलकर वातावरण में प्रदूषण की मोटी परत बनाते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक पराली का धुंआ, आंधी और पटाखे वायु प्रदूषण के अल्पकालिक कारक हैं, स्थायी नहीं। वायु प्रदूषण के स्थायी कारक वे होते हैं जो वर्ष भर प्रदूषण फैलाते हैं और वायु प्रदूषण भी बनाए रखते हैं। इनमें घर पर खाना बनाना, निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल, कूड़ा जलाना, ईंट के भट्टे, रेस्तरां, औद्योगिक गतिविधियां, डीजल जेनरेटर, परिवहन व्यवस्था एवं थर्मल पावर प्लांट हैं।

संयुक्त रिसर्च पेपर के अनुसार प्रदूषण के स्थायी कारकों को दूर करने में भी राज्यों की हीलाहवाली हमेशा ही सामने आती रही है। फिर वह चाहे परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना हो, जेनरेटर पर निर्भरता को खत्म करना हो या फिर औद्योगिक गतिविधियों को प्रदूषण मुक्त बनाना। यहां तक कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 3000, 2800, 19000 और 246 से ज्यादा ईंट के भट्टे हैं। इनमें से ईपीसीए, एनजीटी और सीपीसीबी की सख्ती के बावजूद अभी भी इन राज्यों में क्रमशः 1600, 1000, 10000 और 160 भट्टे पर्यावरण अनुकूल जिग-जैग तकनीक नहीं अपना सके हैं।

राष्ट्रीय संस्करण www.jagran.com
दैनिक जागरण
सोमवार 2 दिसंबर 2019

12 करोड़ पौधे लगाए गए हैं पिछले पांच वर्षों में देश में। देश को हरा-भरा करने के लिए सरकार 47,000 करोड़ के कैंपा फंड का भी इस्तेमाल करेगी।

बालिग दुल्हन के नाबालिग दूल्हे को सुप्रीम कोर्ट से राहत

माला दीक्षित, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

- हाई कोर्ट के आदेश पर बाल विवाह का केस दर्ज हुआ, उच्चतम न्यायालय ने किया रद
- बाल विवाह कानून में बालिग दुल्हन के नाबालिग दूल्हे से शादी करने पर नहीं है सजा का प्रावधान

कानून की विसंगति और व्याख्या कभी-कभी अजीब स्थिति पैदा कर देती है। इसका एक उदाहरण यह केस है, जिसमें शादी के वक्त दूल्हा 17 वर्ष का नाबालिग और दुल्हन 18 वर्ष से ऊपर की बालिग थी। हाई कोर्ट के आदेश पर बाल विवाह का केस दर्ज हुआ दूल्हे पर जो खुद कानून की निगाह में बच्चा था। सुप्रीम कोर्ट ने दूल्हे पर दर्ज केस रद करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने आदेश देकर गंभीर गलती की है, क्योंकि शादी के वक्त लड़के की उम्र 17 वर्ष थी जो कि 18 वर्ष से कम है। इसलिए उस पर बाल विवाह कानून की धारा नौ के प्रावधान लागू नहीं होंगे। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि दूल्हे के पास विकल्प है कि अगर वह चाहे तो बाल विवाह कानून की धारा तीन के तहत अपनी शादी रद करा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही बाल विवाह कानून की धारा नौ की कानूनी विसंगति को उजागर करते हुए उसकी नई व्याख्या भी की है। यह फैसला न्यायमूर्ति एमएम शांतनगौडर और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दूल्हे की अपील स्वीकार करते हुए सुनाया है। दूल्हे की तरफ से वकील ऋषि मल्होत्रा ने हाई कोर्ट के फैसले की विसंगतियां सुप्रीम कोर्ट के सामने उजागर की।

बाल विवाह कानून की धारा नौ बालिग पुरुष के नाबालिग से शादी करने पर सजा का प्रावधान करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने लड़के के स्कूल प्रमाणपत्र में दी गई आयु पर भरोसा करके धारा नौ में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। लेकिन, स्कूल प्रमाणपत्र के मुताबिक शादी के वक्त लड़का 17 वर्ष का था। यानी वह 18 से कम का था। इसलिए इस मामले में धारा नौ (बालिग पुरुष के बाल विवाह करने पर सजा) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

कोर्ट ने कहा कि धारा नौ का अपराध समझने के लिए कानून की अवधारणा और उद्देश्य समझना होगा। इसकी धारा 2 (ए) कहती है कि 21 वर्ष से कम का लड़का और 18 वर्ष से कम की लड़की बच्चे समझे जाएंगे। धारा दो (बी) कहती है कि बाल विवाह का मतलब है कि शादी करने वाले दोनों में से किसी का भी बच्चा होना। इसका मतलब है कि अगर पति 18 से 21 के बीच का भी होता है, तो भी बाल विवाह माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यहां शादी के वक्त लड़की बालिग थी। कानून बालिग लड़की के नाबालिग से शादी करने पर सजा का प्रावधान नहीं करता। ऐसे में तो अर्थ निकलता है कि अगर लड़का 18 से 21 के बीच का है और वह बालिग लड़की से शादी करता है, तो लड़की को सजा नहीं होगी, लेकिन लड़के को सजा होगी, जबकि वह खुद बच्चा है। कोर्ट ने कहा कि यह व्याख्या कानून के उद्देश्य के खिलाफ है। निसंदेह यह कानून समाज में व्याप्त बाल विवाह रोकने के लिए है। इसका उद्देश्य बाल वधुओं पर बुरे असर को रोकना है। कोर्ट ने धारा नौ की व्याख्या करते हुए कहा है कि इस धारा में 18 वर्ष से अधिक के पुरुष के बाल विवाह करने की जगह 18 वर्ष से अधिक के पुरुष के बच्चे (नाबालिग) से विवाह करना पढ़ा जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कहा कि वह 18 से 21 वर्ष के पुरुष और बालिग महिला के बीच हुई शादी की वैधानिकता पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा।

क्या है मामला

- परिवार की सहमति के बगैर प्रेम विवाह करने वाले दंपती ने 2010 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दी। कोर्ट ने सुरक्षा का आदेश दे दिया।
- लड़की के पिता ने हाई कोर्ट से कहा कि लड़के ने पुलिस सुरक्षा के लिए कोर्ट को शादी के वक्त अपनी आयु 23 वर्ष बताई है। स्कूल प्रमाणपत्र के मुताबिक वह 17 साल का था।
- हाई कोर्ट ने दंपती को सुरक्षा देने का आदेश वापस ले लिया और लड़के के खिलाफ बाल विवाह कानून में केस दर्ज करने का आदेश दिया।
- लड़के ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश में पहले ही हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। नवंबर के पहले सप्ताह में हाई कोर्ट का आदेश रद कर दिया।

इस साल अंत तक हो सकता है उल्फा से समझौता

- विद्रोही नेताओं को लगता है कि उसकी मांगों पर अधिक चर्चा की जाती है
- हर दौर की वार्ता में अपनी मांगों को मौलिक बताता है संगठन

नई दिल्ली, प्रेट्र : उल्फा के वार्ता-समर्थक गुट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि शांति वार्ताओं में उसकी मांगों पर 'अनावश्यक रूप से अधिक चर्चा' की जा रही है, जिससे ऐसा लगता है कि वार्ता को लंबा खींचा जा रहा है। सूत्रों ने रविवार को कहा, 'लगभग हर दौर की वार्ता में उल्फा नेता दोहराते रहे हैं कि उनकी सभी मांगें मौलिक हैं। उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मांगें संवैधानिक दायरे के भीतर हैं और सरकार को उनसे किसी पर ध्यान न देने के लिए नहीं कहना चाहिए।'

उल्फा के वार्ता समर्थक गुट का नेतृत्व अनूप चेतिया, ससधर चौधरी और जितेन दत्ता कर रहे हैं। ये तीनों नेता इस समय जमानत पर बाहर हैं। परेश बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा (इंडिपेंडेंट) सरकार से कोई बातचीत नहीं कर रहा है। वह हमेशा असम की स्वायत्तता पर जोर देता रहा है। उल्फा (वार्ता समर्थक) और केंद्र सरकार के वार्ताकार एबी माथुर के बीच अंतिम दौर की वार्ता अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में यहां हुई थी। हालांकि, गुट ने कहा कि पिछले एक साल में बातचीत में कुछ प्रगति हुई है और साल खत्म होने तक अंतिम समझौता हो सकता है। 1979 में संगठन की स्थापना करने वाले लगभग सभी शीर्ष विद्रोही नेता वार्ता समर्थक गुट में शामिल हैं, जिसने 2010 में केंद्र सरकार के साथ बातचीत शुरू की थी। हालांकि, कुछ मांगों पर गतिरोध के कारण वार्ता की प्रक्रिया धीमी रही है। इन मांगों में विशेष भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर असमी मूल के लोगों का अधिकार शामिल है।

पिछले वर्षों में कई बार गतिरोध के बाद सरकार और उल्फा के वार्ता समर्थक गुट अब एक समझौते के नजदीक पहुंच गए हैं। सरकार ने दूसरे पक्ष को बताया है कि दिसंबर के अंत तक शांति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

सौ दिन परिवार के साथ बिताएंगे जवान

ऐलान ▶ सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कही यह बात

बीएसएफ महानिदेशक ने कहा, सीमा पर ड्रोन की घुसपैठ रोकने में जुटे

नई दिल्ली, एजेंसियां : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीएसएफ के 55वें स्थापना दिवस पर कहा है कि केंद्र सरकार जवानों को हर साल सौ दिन अपने परिवार के साथ बिताने की अनुमति दे रही है।

रविवार को केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार एक साल में सौ दिन जवानों को अपने परिवार के साथ बिताने देने के लिए सभी इंतजाम कर रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों को यह सुविधा देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने जवानों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर साठ साल कर दी है और उन्हें आधुनिक तकनीकों से लैस किया जा रहा है। कश्मीर में तैनात जवानों को जम्मू से दिल्ली तक की मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा दी जाएगी। शहीदों और वीरता पुरस्कारों से नवाजे गए जवानों की पत्नियों को डीडीए एक बीएचके फ्लैट भी उपलब्ध कराएगा। अर्धसैनिक बल वेतन पैकेज योजना के तहत उनका दुर्घटना बीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है।

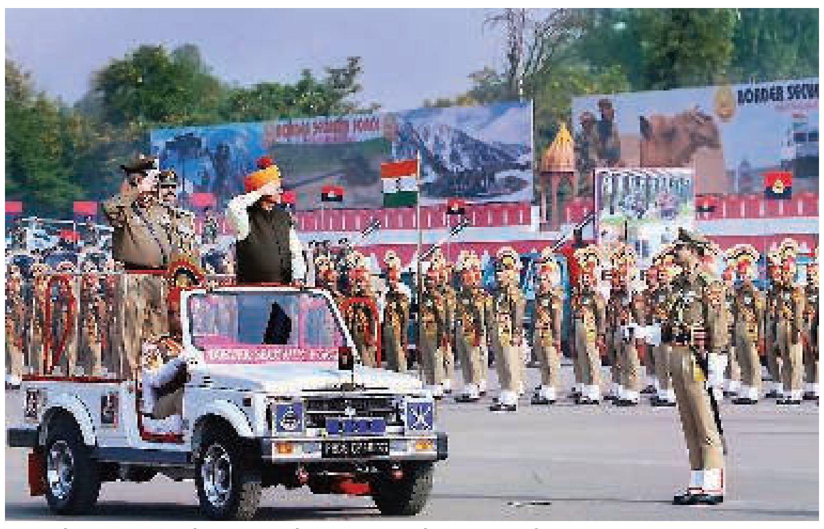
नई दिल्ली में शनिवार को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 55 वें स्थापना दिवस परेड का निरीक्षण किया। जीप में उनके साथ में हैं बीएसएफ के महानिदेशक विवेक जौहरी (बाएं)। प्रेट्र

अर्धसैनिक बल बीएसएफ के महानिदेशक विवेक कुमार जोहरी ने इस अवसर पर कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी हुई 6,386 किलोमीटर से लंबी भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल ने अपनी रणनीतिक क्षमताओं में विस्तार किया है। इसके लिए तकनीक और खुफिया जानकारियों की मदद ली जा रही है। बीएसएफ के शिविर में उन्होंने कहा कि कश्मीर में नियंत्रण रेखा और पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा हाल में सक्रियता के स्तर पर अधिक संवेदनशील हो गई है।

डीजी जोहरी ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान से लगे पश्चिमी सीमा के मोर्चों पर जासूसी के लिए उपयोग होने वाले मानवरहित ड्रोन विमानों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इस मुद्दे से निपटने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं और तकनीकी समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। सीमा पर भारत विरोधी ताकतें लगातार घुसपैठ की कोशिशें कर रही हैं और इसे नाकाम करने के लिए बीएसएफ हर वक्त मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से भारत-पाक सीमा बहुत संवेदनशील हो गई है। तब से आतंकियों को घुसपैठ कराने की कई नाकाम कोशिशें हुई हैं।

एक दिसंबर, 1965 में देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए 2.5 लाख जवानों के साथ बीएसएफ का गठन किया गया था। शांतिकाल में यह अर्धसैनिक बल मूलतः पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाला बीएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी सीमा की रक्षा करने वाला सुरक्षा बल है। प्राकृतिक आपदा और संकट के समय में भी यह बल देशवासियों की सेवा करता है। यह सीमा पर तैनाती के दौरान घुसपैठ रोकने से लेकर तस्करी और सैन्य हमले को भी नाकाम करता है।

पीएम और रक्षा मंत्री ने दी शुभकामनाएं

बीएसएफ के 55वें स्थापना दिवस पर अग्रिम मोर्चे पर तैनात होने वाले इस सुरक्षा बल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर प्रशंसा की है। मोदी ने ट्वीट करके सभी जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा बल तत्परता से हमारी सीमाओं की रक्षा करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीएसएफ की साहस, वीरता, मुस्तैदी और देश की सेवा के लिए बधाई।

देश में सौ प्रतिशत डिजिटल हुई 'हज यात्रा'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- हज यात्रा प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश
- मोबाइल एप के जरिए अब हर सुविधा की मिलेगी अग्रिम जानकारी

हज यात्रा की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल हो गई है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। अब हज यात्रियों के आवेदन से लेकर उसकी मंजूरी, सऊदी अरब में उनके ठहरने, आवागमन और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की सारी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। वहीं सऊदी अरब के साथ हुए समझौते के बाद अब हज यात्रियों को 'ई मसीहा' स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी, जिसमें संबंधित यात्री के स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां ऑनलाइन होंगी ताकि जरूरत पड़ने पर उसका तत्काल उपचार हो सके। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को सऊदी अरब के हज मंत्री मोहम्मद सालेह बिन ताहेर बेंतेन के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया।

पिछले कुछ वर्षों में हज यात्रा को लेकर बड़े सुधार किए गए हैं। भारत से हज यात्रियों का कोटा बढ़ाया गया है और अब भारत से सबसे ज्यादा यात्री जाएंगे। वहीं इसे पूरी तरह पारदर्शी कर दिया गया है। हज यात्रा 2020 में इसका पूरा प्रदर्शन होगा। ऑनलाइन आवेदन, ई-वीजा, हज मोबाइल एप, लगेज, प्री टैगिंग जैसी व्यवस्था की गई है जो यात्रा को सुगम बनाएगी। यात्रियों को मक्का मदीना में कहां ठहरना है, हवाईअड्डे पर उतरने के बाद कितनी नंबर बस से जाना है, इस तरह की तमाम जानकारी भारत में रहते हुए ही मिल जाएगी। इसके अलावा यात्रियों के मोबाइल को एप से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें सभी संबंधित जानकारियां मिलती रहें।

प्रतीकात्मक

भारत से जाने वाले सभी हज यात्रियों के पास हेल्थ कार्ड होगा और सऊदी अरब के ई-मसीहा एप के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जरूरत पड़ने पर तत्काल उपचार हो सके।

ध्यान रहे कि कुछ वर्ष पूर्व भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हज यात्रा को सब्सिडी से मुक्त कर दिया था। लेकिन सुविधाएं बढ़ा दी थी। मसलन यह सुविधा भी दी गई कि कोई भी यात्री किसी भी चुने गए 21 स्थानों में से किसी भी जगह से हज यात्रा के लिए विमान पकड़ सकता है। दरअसल, अलग-अलग स्थानों पर किराए का अंतर है। एक बड़ा सुधार करते हुए इसका भी फैसला लिया गया था कि मुस्लिम महिलाएं चाहें तो बिना किसी पुरुष के भी एक छोटे समूह में जा सकती हैं। 2020 में कुल दो लाख हज यात्री जाने हैं। इसके लिए 5 दिसंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि है और जानकारी के अनुसार केवल जम्मू-कश्मीर से ही अब तक 15 हजार आवेदन आ चुके हैं।

छह केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को किया जाएगा अपग्रेड

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की छह केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को जल्द ही अपग्रेड (उच्चीकृत) किया जाएगा। इसका उद्देश्य गंभीर व जघन्य अपराधों की वैज्ञानिक और प्रभावी जांच सुनिश्चित करना है। उच्चाधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, पुणे और गुवाहाटी स्थित इन केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) को अपग्रेड करने के साथ-साथ इनकी क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। एक अधिकारी ने बताया, 'गृह मंत्रालय ने फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले छह सीएफएसएल की क्षमता में वृद्धि का निर्णय लिया है। इससे फोरेंसिक साइकोलॉजी के क्षेत्र में वाह्य विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ेगी।' उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गंभीर व जघन्य प्रकृति वाले अपराधों की जांच को प्रभावी और वैज्ञानिक बनाना है। फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय नई दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर साइंस व गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद ने शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञात हो, देश में अपराधों की जांच में पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की कमी है। साथ ही जो प्रयोगशालाएं हैं उनका उन्नयन न होने से जुटाए गए साक्ष्यों का सटीक परीक्षण नहीं हो पाता है।

मप्र में आदिवासी 'पत्थलगड़ी' से तय कर रहे गांव की सीमा

विवेक पाराशर, बड़वानी

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में 'हमारे गांव में हमारा राज' और 'न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊपर ग्रामसभा' इन वाक्यों को ध्येय बनाकर जिले में आदिवासी संगठनों ने आंदोलन की शुरुआत की है। इसके तहत 'पत्थलगड़ी' परंपरा की तर्ज पर गांव की सीमा तय कर बोर्ड लगाया जा रहा है। इस पर विभिन्न कानूनों का उल्लेख कर 'पेसा (पंचायत एक्सटेंशन ओवर शिड्यूल एरियाज एक्ट-1996) और वन अधिकार कानून लागू करने की मांग की जा रही है। साथ ही सामुदायिक पट्टों की मांग भी है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल को बचाने, गांव की प्राथमिकता गांव में तय करने, विकास कार्य स्वयं तय करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। ज्ञात हो, छत्तीसगढ, झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पत्थलगड़ी परंपरा का अलगाववाद व नक्सलवाद से जुड़ाव होने के चलते, इसे विवादित माना गया है।

प्रदेश के गृहमंत्री के गृह जिले में लग रहे इन बोर्ड की जानकारी शासन-प्रशासन को न होना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। डीएम अमित तोमर ने कहा, मामले को दिखवाया जाएगा। पूरे मामले को समझने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे।

बोर्ड लगाए जाने की बात पहली बार सुनी है, लेकिन सरकार को यदि कहीं काम करना है तो वो विधिवत तरीकों से करेगी। पेसा कानून हमारे वचन पत्र में है। 2006 में जो वन अधिकार कानून तत्कालीन पीएम मनमोहनसिंह ने बनाया, उसे वैसा ही लागू करने से मप्र की कांग्रेस सरकार और सीएम कमलनाथ को कोई परहेज नहीं है। वनों में रहने वाली जनता के विकास के लिए सरकार इस कानून को लागू कर पालन करवाएगी। मप्र में कोई नक्सली गतिविधि पनप नहीं सकती। जरूरत होने पर संगठन के लोगों से बात की जाएगी।
-बाला बच्चन, गृहमंत्री मप्र शासन

पत्थलगड़ी के साथ क्या है विवाद : देश के विभिन्न राज्यों में गत वर्ष जून माह में नक्सलवाद के बाद नया आंदोलन जोर पकड़ता नजर आया, इसे पत्थलगड़ी कहा गया। इस आंदोलन की आहट मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना व बंगाल के विभिन्न इलाकों में सुनी गई। इस दौरान विभिन्न जगहों पर गांवों के बाहर एक पत्थर लगाया गया, इस पर लिखा गया कि 'यहां ग्रामसभा का शासन है, सरकारी आदेशों और सरकारी संस्थानों की यहां कोई मान्यता नहीं है'। इस प्रक्रिया को नक्सलवाद व अलगाववाद से जोड़कर देखा गया। इसी के चलते यह मुद्दा खासा विवादास्पद भी रहा है।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले, नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं बाहरी

- कहा, दोनों नेताओं का घर गुजरात में आ गए दिल्ली, मुसलमान को भगाने की हिम्मत नहीं
- लोस में कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने कहा, एनआरसी के माहौल से डरे हैं हिंदुस्तान के असली नागरिक

नई दिल्ली, एएनआइ : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने विवादित बयान दिया है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को घुसपैठिया बता दिया है। एनआरसी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'हिंदुस्तान सबके लिए है। ये किसी की जागीर है क्या? सबका समान अधिकार है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी आप खुद बाहरी हैं। घर आपका गुजरात है, आ गए दिल्ली। वैध-अवैध बाद में पता चलेगा।' कांग्रेस नेता के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए भाजपा नेता नलिन कोहली ने उन्हें माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ज्ञात हो, केंद्र सरकार पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने की बात कह रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने असम के बाद पूरे देश में एनआरसी लागू करने का वादा किया है।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम को भगाएंगे। उनको भगाने की उनकी हिम्मत नहीं है। मुसलमान हमारे देश का नागरिक है, भागेगा क्यों? हिंदुस्तान सबके लिए है, हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए है। गंगा-जमुनी तहजीब का हिंदुस्तान है। सबके सहयोग से हिंदुस्तान बना है, लेकिन वे दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदू को रहने देंगे, मुस्लिमों को भगा देंगे।'

अधीर रंजन चौधरी फाइल फोटो

चौधरी ने कहा, 'एनआरसी नाम लेते-लेते ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि हिंदुस्तान के असली नागरिक सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा। लोग सारे कागजात लेकर नहीं बैठे रहते, क्योंकि यह हमारा देश है, हम वोट डालते हैं, अब इतने सारे कागजात जुटाने की क्या जरूरत है। जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनके पास कागजात होते हैं कभी? सुबह जब वह उठते हैं तो दिनभर यही सोचते हैं कि रात और कल के खाने का जुगाड़ कैसे होगा। उनके पास इतने कागजात के बारे में सोचने का समय नहीं है। आज वे लोग डरे हुए हैं।' ध्यान रहे कि अधीर कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बताकर भी विवादों में घिर चुके हैं।

कांग्रेस नेता चौधरी का यह विवादास्पद बयान ऐसे समय में आया है जब शाह नागरिकता (संशोधन) बिल के सिलसिले में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोगों की सहमति के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हैं। विगत शुक्रवार और शनिवार को उन्होंने बैठकें की थीं और अगली बैठक तीन दिसंबर को है।

कश्मीर के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद करता है जापान

- आरसीईपी में भारत की चिंताओं को दूर करने का दिया भरोसा
- बुलेट ट्रेन पर संकट पर कहा-दोनों देशों के अफसर बातचीत कर रहे हैं

नई दिल्ली, प्रेट्र : जापान ने कहा है कि वह कश्मीर के हालात पर बहुत सावधानी से गौर कर रहा है और उम्मीद करता है कि बातचीत के जरिए इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सकता है। इतना ही नहीं, रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) में भारत के नहीं शामिल होने के फैसले पर जापान के प्रवक्ता ने कहा कि इस संगठन के सदस्य देश पिछले महीने बैंकाक की बैठक में जताई भारत की चिंताओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।

रविवार को जापान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और उप प्रेस सचिव अत्सुशी कैफू ने कश्मीर पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि मंत्रियों ने ऐसे मुद्दे पर विस्तृत बात नहीं की है। लेकिन इसी के साथ हम यह भी कह सकते हैं कि हम कश्मीर के हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। हमें कश्मीर के संबंध में लंबे मतभेदों का अंदाजा है। हम उम्मीद करते हैं कि द्विपक्षीय बातचीत के जरिए इसका शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा।

महाराष्ट्र में सत्ता बदलने से मुंबई से अहमदाबाद के लिए जापान की ओर से तैयार की जाने वाली बुलेट ट्रेन के भविष्य पर संकट मंडराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी बड़ी परियोजनाओं में इस तरह की चुनौतियां आती हैं। दोनों देशों के अधिकारी इस विषय पर काम कर रहे हैं।

रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) के मुद्दे पर कैफू ने कहा कि इस संगठन में भारत के नहीं शामिल होने के फैसले पर संगठन भारत की चिंताओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है। ताकि भारत इस संगठन में शामिल हो जाए। अरुणाचल प्रदेश में परियोजनाएं शुरू करने के विषय में उन्होंने कहा कि जापान विकास परियोजनाएं भारत में जारी रखने को लेकर उत्सुक है।

चीन अरुणाचल में ऐसी परियोजनाओं का विरोध कर रहा है। 5जी स्पेक्ट्रम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि विगत शनिवार को इस मुद्दे पर बहुत संक्षिप्त वार्ता हुई। चीन 5जी नेटवर्क के लिए अपनी दूरसंचार कंपनी हुआवेई को भारत लाना चाहता है। जबकि अमेरिका ने इस कंपनी पर प्रतिबंध लगा रखा है और वह अपने सहयोगी देशों से भी यही चाहता है।

जुबानी हमला

कांग्रेस ने राहुल बजाज के भय के माहौल संबंधी बयान पर केंद्र सरकार की खिंचाई की, दूरसंचार क्षेत्र में निजी कंपनियों पर मेहरबानी का लगाया आरोप

बजाज के बयान से पूरा देश सहमत : कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस ने उद्योगपति राहुल बजाज के 'भय के माहौल' के बयान पर मोदी सरकार पर करारा हमला किया है। पार्टी का कहना है कि बजाज की भावना ही पूरे देश की भावना है। विपक्षी दल का कहना है कि बिना सद्भावना के भला देश में निवेशकों के आने की उम्मीद कैसे की जा सकता है। कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर दूरसंचार क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों का खास ख्याल रखने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रधानमंत्री से पूछा है कि इस बात का ताल्लुक कहीं चुनावी बांड के फायदे से तो नहीं है।

उल्लेखनीय है कि विगत शनिवार को मुंबई में एक पुरस्कार समारोह के दौरान उद्योगपति राहुल बजाज ने कहा था कि देश में भय का माहौल है। लोग सरकार की आलोचना करने से डरते हैं। उन्हें इस बात का भरोसा ही नहीं है कि सरकार किसी आलोचना को स्वीकार करेगी।

बजाज के विवादित बयान के समय श्रोताओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं। बजाज के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रविवार को कहा कि राहुल बजाज का बयान हर क्षेत्र में पूरे देश की भावनाओं को बताता है। देश के माहौल में बदलाव जरूर हुआ है लेकिन इसमें सुधार हो सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर समाज, देश या शहर में कोई सद्भावना नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कोई यहां निवेश करने आएगा। धन वहीं जाता है जहां वह ठहर सकता है।

लोकपाल या जोकपाल

कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने देश की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल को जोकपाल बताया है। उन्होंने लोकपाल के अशोका होटल में हर महीने 50 लाख रुपये का किराया देने की रिपोर्ट का मखौल उड़ाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 31 अक्टूबर, 2019 तक भ्रष्टाचार की 1,116 शिकायतें हैं। लेकिन इनमें से एक की भी प्रारंभिक जांच तक शुरू नहीं हो सकी है।

रणदीप सुरजेवाला

कांग्रेस पार्टी के ही एक अन्य प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सदियों बाद कारपोरेट जगत के किसी जाने माने उद्योगपति ने सत्ता के खिलाफ सच्चाई बताने का साहस किया है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय विज्ञापन उद्योग जगत में सबसे चर्चित टैग लाइन 'यू जस्ट कांट बीट ए बजाज' ताजा घटनाक्रम पर सटीक है। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करके कहा कि हम हमेशा से जानते हैं कि राहुल बजाज गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। वह राष्ट्रवादी और बेबाक वक्ता हैं। उनका बयान वही था जो बैंकर और उद्योगपतियों का है।

इस बीच, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकारी कंपनियां जैसे- बीएसएनएल और एमटीएनएल यूपीए-1 और यूपीए-2 में मुनाफा कमाने वाली कंपनियां थी। लेकिन नई सरकार में यह सब घाटे में जा रही हैं। उनका बयान ऐसे समय पर आया है जब वोडाफोन-आइडिया और भारती एयरटेल ने रविवार को मोबाइल फोन नेटवर्क की दरों में बढ़ोतरी का एलान किया है।

लद्दाख की गाड़ियों का 'एलए' से शुरू होगा पंजीयन

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में वाहनों का पंजीयन 'एलए' से शुरू होगा। इस बारे में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 'केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 12 जून 1989 को प्रकाशित अधिसूचना एसओ-444(ई) में संशोधन किया है। इसके तहत क्रम संख्या 17 में बदलाव करते हुए इसमें क्रम संख्या 17ए के अंतर्गत लद्दाख एलए को जोड़ा गया है।'

उल्लेखनीय है कि सरकार ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 की ज्यादातर धाराओं को निष्प्रभावी करते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख नाम से दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया है। लद्दाख में कारगिल और लेह दो जिले हैं तथा यह अब दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

2014 में झारखंड विधानसभा चुनाव में सामान्य सीटों पर 601, एसटी पर 266 और एससी सीटों पर 80 यानी कुल 947 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए 10 हजार रुपये और एससी–एसटी प्रत्याशियों के लिए 2500 रुपये जमानत राशि निर्धारित है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 2 दिसंबर 2019

कर्नाटक में जदएस से फिर हाथ मिलाने से कांग्रेस को परहेज नहीं

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए उठाएंगे जरूरी कदम

बेंगलुरु, प्रेट्र : महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रही कांग्रेस की नजरें अब कर्नाटक में पांच दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के नतीजों पर टिकी हैं। पार्टी ने संकेत दिए हैं कि उपचुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा अगर बहुमत से दूर रहती है तो उसे जनता दल सेक्युलर (जदएस) से हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं है। हालांकि, राज्य के मुख्यमंत्री व भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने जदएस से गठबंधन की अटकलों को खारिज करते हुए सभी 15 सीटों पर जीत का दावा किया है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'संविधान व लोकतंत्र की रक्षा और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे। इसके लिए हम गठबंधन के साथी और संप्रग के घटक दलों से बात करेंगे।' यहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, 'देखते हैं भविष्य में क्या होता है... हम सभी 15 सीटों पर जीतना चाहेंगे। हम नौ दिसंबर को आपके समक्ष सही तस्वीर पेश करेंगे... आपको शुभ समाचार सुनाएंगे।' उल्लेखनीय है कि भाजपा से पहले राज्य में 14 महीनों तक जदएस-कांग्रेस की सरकार रही थी। दोनों दलों के 17 विधायकों के बागी हो जाने के कारण जुलाई में राज्य की एचडी कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी। इसके बाद दोनों दल अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बहुमत के जादुई आंकड़े 224 तक पहुंचने के लिए राज्य की भाजपा सरकार को 15 में से छह सीटों पर जीत हासिल करनी होगी।

भाजपा के समर्थन से सांसद बनी एस. अंबरीश रहेंगी तटस्थ : भाजपा के समर्थन से राज्य की मांड्या लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने वाली एस. अंबरीश ने तटस्थ रहने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने खुलकर मेरा समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भरपूर सहयोग किया। ऐसे में वह किसी को नाराज नहीं कर सकतीं।

'महाराष्ट्र में सरकार बनाना नहीं चाहती थीं सोनिया गांधी'

मल्लिकार्जुन खड़गे फाइल

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'महाराष्ट्र को देखिए, जहां शिवसेना, राकांपा व कांग्रेस सरकार गठन में सफल रहीं। हम आपको सच बताते हैं। हमारी अध्यक्ष (सोनिया गांधी) महाराष्ट्र में सरकार में शामिल नहीं होना चाहती थीं। वह चाहती थीं कि कांग्रेस विपक्ष में बैठे, लेकिन प्रगतिशील सोच वाली पार्टियों ने कहा कि हमें भाजपा को सत्ता से दूर रखना चाहिए।' पूर्व प्रदेश कांग्रेस प्रमुख व पूर्व उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने भी कहा कि चुनाव बाद गठबंधन की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए।

'येदियुरप्पा के पास 105 विधायक ...उनकी सरकार क्यों गिरेगी'

उपचुनाव बाद कुछ कांग्रेस–जदएस विधायकों के भाजपा में शामिल होने वाली अटकलों पर जदएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने रविवार को कहा, 'येदियुरप्पा के पास 105 विधायक हैं... उनकी सरकार क्यों गिरेगी...।' हालांकि, पूर्व में वह कांग्रेस से गठबंधन का संकेत देते हुए कह चुके हैं कि उपचुनाव परिणाम आने के बाद सोनिया गांधी की पहल को देखा जाना चाहिए। उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी भी कह चुके हैं कि उपचुनाव बाद राज्य में स्थिर सरकार होगी।

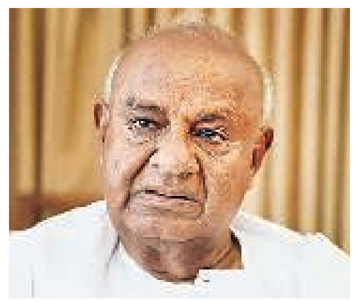
एचडी देवेगौड़ा फाइल

कर्नाटक और झारखंड पर टिका भाजपा का मनोबल

आशुतोष झा, नई दिल्ली

- इसी हफ्ते कर्नाटक में होने हैं 15 सीटों पर उपचुनाव
- झारखंड में चार चरण का मतदान है अभी बाकी

महाराष्ट्र और हाल के बंगाल उपचुनाव के झटके के बाद अगले हफ्ते हो रहे कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव और झारखंड चुनाव पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। झारखंड में बहुकोणीय लड़ाई के बीच कर्नाटक का प्रदर्शन भाजपा के मनोबल पर प्रभाव डालेगा जहां इसी हफ्ते 15 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यही नतीजा तय करेगा कि पिछले डेढ़ दो साल से विवादों में रहे कर्नाटक में भाजपा बहुमत की स्थिर सरकार देगी या फिर से राजनीतिक बवंडर खड़ा होगा।

झारखंड में पहले चरण का मतदान हो चुका है। सात दिसंबर को दूसरे चरण से पहले ही कर्नाटक में उन 15 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां से कांग्रेस और जद (एस) के बागी विधायकों ने उनकी सरकार गिरा दी थी और सत्ता दूसरी बार भाजपा के हाथ आई है। लेकिन अभी भी भाजपा विधानसभा संख्या के अनुसार बहुमत में नहीं है। नौ दिसंबर को आने वाला नतीजा ही भाजपा का शक्ति परीक्षण होगा। फिलहाल भाजपा के पास 105 सीटें है। इन 15 सीटों पर होने वाले चुनाव के बाद भाजपा को कम से कम सात सीटें चाहिए होंगी क्योंकि दो अन्य रिक्त सीट पर फिलहाल चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन भाजपा को कोशिश करनी होगी कुल 224 की संख्या के लिहाज से कम से कम आठ सीटें जीतकर न्यूनतम 113 की संख्या तक पहुंचे।

यूं तो भाजपा ने वहां बागियों को ही टिकट दिए हैं, जो अपने क्षेत्रों में मजबूत हैं। खुद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा लगातार दौरा कर रहे हैं। खास कर ओल्ड मैसूर क्षेत्र की दो सीट-केआर पेटा और हुंसूर क्षेत्र में अपने पुत्र विजयेंद्र को लगाया है जो येदियुरप्पा का राजनीतिक प्रबंधन देख रहे हैं। ये वही विजयेंद्र हैं जो विधानसभा चुनाव के वक्त वरुणा सीट से लड़ना चाहते थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। विजयेंद्र वहीं कैंप किए हुए हैं। पेटा का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि येदियुरप्पा का जन्म यहीं हुआ था। इस जीत का सांकेतिक महत्व होगा क्योंकि पहले यह सीट जदएस के खाते में थी।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस और जदएस इस चुनाव को एक अवसर के रूप में देख रही है। खासकर महाराष्ट्र में शिवसेना-कांग्रेस-राकांपा गठबंधन के बाद जिस तरह जदएस के नेताओं की ओर से बयान आए और यह संकेत दिया गया कि उन्हें भाजपा के साथ आने में परहेज नहीं होगा। जबकि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अब पूरा जोर लगाने का संकेत दिया जा रहा है ताकि भाजपा को असहज किया जा सके। सूत्रों के अनुसार भाजपा के अंदर भी एक धड़ा ऐसा है जो शुरू से जदएस को साथ लेकर चलने की हिमायत करता रहा है। अटकलें ऐसी भी लगाई जाती रही हैं कि पिछले चुनाव में जदएस को सकारात्मक संदेश देने के लिहाज से कुछ सीटों पर कमजोर उम्मीदवार उतारने की बात भी हुई। लेकिन नेतृत्व ने इसे नकार दिया। हालांकि झारखंड में पुराने सहयोगी सुदेश महतो के खिलाफ उम्मीदवार न देकर भाजपा ने यही संदेश देने में संकोच नहीं किया कि चुनाव बाद स्थिति में दोनों दोस्त ही होंगे। येदियुरप्पा के लिए जाहिर तौर पर आठ से ज्यादा सीटें जिताकर खुद को साबित करने की चुनौती है। वहीं भाजपा के लिए यह जीत स्थानीय हार-जीत से बड़ा मनोबल का सवाल है। नौ दिसंबर को आने वाले नतीजे के बाद भी झारखंड में तीन चरणों का चुनाव बाकी होगा और ऐसे में यह चुनावी मनोबल से भी जुड़ा है। ध्यान रहे कि महाराष्ट्र की तरह ही कर्नाटक में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी। भाजपा मुख्यमंत्री ने शपथ भी लिया लेकिन दोनों जगहों पर बहुमत साबित नहीं कर पाए। दोनों जगह शक्ति परीक्षण से पहले मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। दोनों राज्यों में दो विरोधी खेमों ने हाथ मिलाकर भाजपा को झटका दिया। कर्नाटक में दूसरी बार मौका मिला है और बहुमत से आगे बढ़ना भाजपा के मनोबल के लिए आवश्यक शर्त है।

स्टार प्रचारक

सुदेश हमारे मित्र और भाई जैसे : धर्मेंद्र प्रधान

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पहले चरण के मतदान से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और अकेले दम पर 65 से अधिक सीटें जीतकर झारखंड में सरकार बनाएगी। धर्मेंद्र प्रधान रविवार को जमशेपुर के बिष्टुपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव तक आजसू (ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन) हमारे गठबंधन का हिस्सा थी। विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग–अलग लड़ रही हैं। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो रही है। सुदेश हमारे मित्र हैं और भाई जैसे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर झारखंड स्थिर सरकार की ओर बढ़ रहा है।

कांग्रेस, झामुमो दोनों ने आदिवासियों को लूटा : नड्डा

जासं, प. सिंहभूम : वोटरों को साधने झारखंड के प. सिंहभूम पहुंचे भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चाईबासा में कांग्रेस व झामुमो (झारखंड मुक्ति मोर्चा) पर करारा हमला बोला और कहा कि दोनों ने आदिवासियों को लूटा है। झामुमो और कांग्रेस में सिर्फ कुर्सी की दोस्ती है। इसे विकास से कोई लेन देना नहीं है। ये स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जब अलग झारखंड की मांग चल रही थी, उस समय कांग्रेस के लोग यहां की जनता पर गोली चलवा रहे थे।

कांग्रेस का काम उलझाना भाजपा करती है सुलझाने का काम : रविशंकर

रविशंकर प्रसाद फाइल

जागरण संवाददाता, सिमडेगा : केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को झारखंड के सिमडेगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार समस्याओं को उलझाने का प्रयास करती रही है, लेकिन भाजपा सरकार ने समस्याओं को सुलझाने की पहल की। झारखंड भी इसी का उदाहरण है। यहां के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2000 में अलग झारखंड का गठन किया था। जब झारखंड राज्य अलग बना तब भी कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का काम करती रही। सभी जानते हैं कि उसका हश्र क्या हुआ। उन्होंने संवाद को बढ़ाते हुए कहा–बालाकोट याद है न? हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुंसकर आतंक व आतंकियों पर प्रहार किया था। पहले कांग्रेस की सरकार जवानों को एक हाथ बांधकर कार्रवाई करने की बात कहती थी। आज हम दुश्मनों की आंख में आंख डालकर बात करते हैं और घर में घुस कर मारते हैं।

'जो विदेशी हैं, उन्हें भारत का नागरिक कभी नहीं मानेंगे'

दो टूक ▸ रक्षा मंत्री ने झारखंड में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में की चुनावी सभाएं

महासमर
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

असम के बाद पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात दोहराई

जेएनएन, जमशेदपुर

असम के बाद अब पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लागू किया जाएगा। जो सचमुच में विदेशी हैं, उन्हें भारत का नागरिक कभी नहीं मानेंगे। यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को जमशेदपुर के आदित्यपुर और बोकारो के बेरमो में आयोजित चुनावी सभाओं में कही।

रक्षा मंत्री ने इस दौरान भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकारों ने विकास के नए युग की शुरुआत की है। इसलिए झारखंड में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनवाएं।

उन्होंने जहां अनुच्छेद 370 की चर्चा की वहीं राम मंदिर भी उनके भाषण के केंद्र में रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। भाजपा सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया और देश में एक संविधान, एक झंडे के नारे को पूरा किया। इसके अलावा तीन तलाक से महिलाओं को मुक्ति दिलाई। राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस विवाद का समाधान हो गया है। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। झारखंड की चर्चा करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यहां नए झारखंड का सपना पूरा किया। पांच साल में झारखंड भारत के टॉप सात राज्यों में आ गया है, जहां विदेश के लोग भी निवेश करना चाहते हैं।

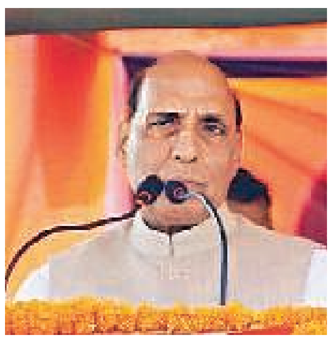
झारखंड के बोकारो जिले के बेरमो में रविवार को चुनावी सभा को संबोधित करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जागरण

दुनिया ने माना हमारे मजबूत फैसलों का लोहा

राजनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की धाक बढ़ी है और हमारे मजबूत फैसलों का दुनिया ने लोहा माना। कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति हमने जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाया। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास, पीएम किसान और उज्ज्वला योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि इन योजनाओं से देशवासियों के जीवन में बदलाव आया है।

महाराष्ट्र में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए होगा 80 फीसद आरक्षण

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80 फीसद आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उद्धव सरकार जल्द ही कानून बनाएगी। महाराष्ट्र विधानभवन में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश की नवगठित सरकार के इस बड़े फैसले की घोषणा की। कोश्यारी ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार प्रदेश में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80 फीसदी आरक्षण देने के लिए कानून बनाएगी। प्रदेश सरकार के संकल्प की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि 'माटी के सपूतों' के लिए ऐसे कानून का प्रावधान करेगी। उद्धव सरकार ने 10 रुपये में भोजन देने के लिए कैंटीन और एक रुपये में उपचार करने के लिए क्लीनिक खोलने की भी घोषणा की है। हर जिले में सभी तरह की सुविधाओं वाले अस्पताल खोलने की बात भी कही गई है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही राज्य की आर्थिक स्थिति की असली तस्वीर पेश करेगी। सरकार ने किसानों के लिए भी जल्द ही पैकेज घोषित करने की बात कही है। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत मिले।

उद्धव ठाकरे का फड़नवीस पर कटाक्ष

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

देवेंद्र फड़नवीस के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर मुख्यमंत्री ठाकरे ने भी उन पर कटाक्ष किया। ठाकरे ने कहा, 'मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं पुनः आऊंगा। लेकिन मैं इस सदन में आ गया। मैं इस सदन और महाराष्ट्र के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं कोई निर्णय अर्धरात्रि में नहीं करूंगा।' बता दें कि ठाकरे का कटाक्ष फड़नवीस के उस चुनावी नारे को लेकर था जिसमें उन्होंने कहा था कि 'मैं पुनः आऊंगा'। फड़नवीस ने भी उद्धव के कटाक्ष का जवाब हास्य के अंदाज में दिया। कहा, 'मैं पुनः आऊंगा' यह कहते हुए मैं अपना टाइम टेबल बताना भूल गया था। उन्होंने एक शेर पढ़ा, 'मेरा पानी उतरते देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा'। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दिनों ठाकरे किसानों की समस्याओं को जानने गए थे, तब उन्होंने किसानों को 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की मांग की थी। अब जब वो सीएम बन गए हैं तो किसानों को यह मुआवजा दें। सीएम ने कहा कि वह फड़नवीस को नेता प्रतिपक्ष कहकर नहीं, एक जिम्मेदार नेता कह कर बुलाएंगे। ठाकरे ने कहा, 'अगर आप हमारे लिए अच्छे होते तो ये सब होता ही नहीं। मैं अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा होता और आप यहां होते।' ठाकरे ने यह भी कहा कि उन्होंने फड़नवीस से बहुत कुछ सीखा है और वो हमेशा उनके मित्र बने रहेंगे।

भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी तरह से संभाली कमान

राज्य ब्यूरो, रांची

- अमित शाह व नड्डा एक–एक सीट की कोर टीम के साथ कर रहे समीक्षा

झारखंड विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए महज एक राज्य का चुनाव भर ही नहीं रह गया है। महाराष्ट्र के नाटकीय घटनाक्रम के बाद अब झारखंड की जीत भाजपा की साख व प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। आगे अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी झारखंड की जीत या हार का असर होगा, भाजपा इससे अनजान नहीं है। यही वजह है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी तरह से चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है। अब तक चुनाव में भाजपा की शीर्ष टोली की भूमिका जनसभा के माध्यम से पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने तक ही सीमित रहती थी लेकिन इस बार टॉप लीडरशिप अपने को विधानसभावार तैयारियों की तह तक ले जा रही है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी सभा के तत्काल बाद विधानसभावार कोर टीम की समीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, स्मृति इरानी भी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। पहले चरण में अमित शाह ने लोहरदगा में इसकी शुरुआत की थी।

नड्डा ने भी पलामू में कोर टीम के साथ बैठक कर एकजुटता की नसीहत और जीत के मंत्र दिए थे। रविवार को भी चाईबासा की जनसभा के बाद नड्डा ने चाईबासा और जमशेदपुर में विधानसभावार बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। इन बैठकों का बड़ा उद्देश्य पार्टी की अंदरूनी खेमेबंदी को समाप्त करना है। स्पष्ट है भाजपा ने चुनाव प्रभारी ओम माथुर को जो जवाबदेही सौंपी थी वे उसमें खरे नहीं उतरे। केंद्रीय टीम का कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद का फर्क भी काफी हद तक पड़ा है। लोहरदगा में शाह की नसीहत के बाद आसपास के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं में एकजुटता देखी गई थी।

अमित शाह फाइल

विपक्ष की किला बचाने की जद्दोजहद

राज्य ब्यूरो, रांची : मतदान के रूझान से संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) खेमा उत्साहित है और अब उसने अन्य चरणों के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। अब तक संप्रग के लिए वन मैन आर्मी बने हुए हेमंत सोरेन को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का साथ भी मिला है। राहुल सिमडेगा से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। आगे इस कड़ी में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा का नाम जुड़ने की बात भी कही जा रही है। झारखंड में दूसरे चरण की जिन 20 सीटों के लिए चुनाव होना है उनमें कोल्हान (सरायकेला खरसावां, प. सिंहभूम और पू. सिंहभूम) की सभी 14 सीटें शामिल है। संताल (जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज) के बाद कोल्हान को झामुमो का गढ़ बताया जाता रहा है। लोकसभा चुनाव में भी चाईबासा सीट मोदी लहर के बावजूद यूपीए ने जीत ली थी। इस बार भी झामुमो ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सीमित संसाधनों के माध्यम से अधिक से अधिक मतदाताओं को अपनी बात पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। कोल्हान वह क्षेत्र है जहां से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा व मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर है कि भाजपा यहां पूरी तैयारी से उतरी है।

फड़नवीस की जल्दबाजी महाराष्ट्र में भाजपा को ले डूबी : संजय राउत

- शिवसेना नेता ने कहा, महाराष्ट्र में जो हुआ, वह देश को भी स्वीकार है
- चुनाव से पहले फड़नवीस पर 'बचकानी टिप्पणियां' करने का आरोप

मुंबई, प्रेट्र : शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की सत्ता हासिल करने में जल्दबाजी और 'बचकानी टिप्पणियां' महाराष्ट्र में भाजपा को ले डूबी और उनको विपक्ष में बैठना पड़ गया। राउत ने शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में अपने 'रोखठोक' स्तंभ में दावा किया कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, राकांपा सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ आने से महाराष्ट्र में जो हुआ वह देश को भी स्वीकार है।

बिना किसी का नाम लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र दिल्ली की तरह 'भीड़ तंत्र' के आगे नहीं झुका। 'सामना' के कार्यकारी संपादक राउत ने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि उद्धव ठाकरे शक्तिशाली 'मोदी-शाह के दबदबे' को खत्म कर सत्ता में आए। उन्होंने भरोसा जताया कि यह सरकार (शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन) पांच साल तक चलेगी।

राउत ने कहा, 'मुझे यह देखकर मजा आ रहा है कि जो लोग अजीत पवार के फड़नवीस से गठजोड़ को शरद पवार की पहले से तय योजना बता रहे थे, वह अब महा विकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद राकांपा प्रमुख के आगे नतमस्तक हो रहे हैं।'

राउत ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले फड़नवीस ने इस तरह की 'बचकानी टिप्पणियां' की कि राज्य में कोई विपक्षी दल नहीं बचेगा। शरद पवार का काल खत्म हो रहा है और प्रकाश आंबेडकर का वंचित बहुजन अघाडी मुख्य विपक्षी दल होगा। लेकिन वह खुद विपक्षी नेता बन गए। फड़नवीस ने कहा था कि वह वापस लौटेंगे लेकिन सत्ता में आने की उनकी जल्दबाजी 80 घंटे में भाजपा को ले डूबी।

शिवसेना से हाथ मिलाने को लेकर संशय में थी कांग्रेस : राउत ने कहा कि कांग्रेस में हर किसी को शिवसेना से हाथ मिलाने को लेकर संशय था। शरद पवार ने ही सोनिया गांधी से कहा कि शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ मित्रवत संबंध थे। राउत ने कहा कि शिवसेना ने देश में आपातकाल के बाद हुए राज्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। शिवसेना ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी की उम्मीदवारी का भी समर्थन किया था। मुंबई में हिंदी भाषी समुदाय भी शिवसेना को वोट देता है। इसलिए पार्टी शहर के नगर निकाय चुनाव जीतती आ रही है। शरद पवार ने यह भी सोनिया गांधी को बताया।

संजय राउत फाइल

तृकां का दावा

लोस चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उपचुनाव में सभी तीन सीटों पर मिली है तृणमूल को जीत, पीके की टीम ने की मेहनत,

हक में रहा एनआरसी विरोध व बंगाली गौरव का मुद्दा

जागरण संवाददाता, कोलकाता

लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद तीन विधानसभा सीटों का फैसला बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में रहा है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जो बड़ा झटका लगा था, उससे उबरने में एनआरसी विरोधी अभियान और लगातार 'बंगाली गौरव' की बात करना पार्टी के हक में रहा है और उपचुनाव में जनादेश तृणमूल के समर्थन में मिला है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हमें लोकसभा चुनाव में अस्थाई तौर पर झटका लगा था। इसके बाद हमने एनआरसी अभियान छेड़ा और लगातार बंगाली गौरव की बात करते रहे जबकि उपहास उड़ाने वालों पर हमलावर रहे।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को तीन महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों करीमपुर, कालियागंज और खड़गपुर सदर में तृणमूल को जीत मिली है। इस जीत को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पार्टी ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी, भाजपा से लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया।

बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की थी जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी को अपने ही गढ़ में महज 22 सीटों पर जीत मिली थी। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा है कि हमने इस फैसले के लिए जून से कड़ी मेहनत शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने संसदीय चुनावों के बाद भाजपा से हारने वाली सभी सात नगरपालिकाओं पर दोबारा कब्जा जमा लिया है।

हिंदी थोपने का विरोध किया

ज्योतिप्रिय मल्लिक ने दावा किया कि जन जागरूकता अभियान को पुनर्जीवित करने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को भी पार्टी के पक्ष में काम में लगाया गया था। वहीं, तृणमूल के एक सांसद ने कहा कि एनआरसी अभियान और बंगाली गौरव के मुद्दे ने हमें अपना खोया हुआ मैदान वापस पाने में मदद की। किशोर के दीदी के बोलो अभियान ने भी काफी मदद की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र द्वारा हिंदी थोपने का विरोध किया और बंगाली गौरव को बढ़ावा देने की बात की। सांसद ने कहा कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार यह कहा कि हमें अन्य भाषा तो सीखना चाहिए लेकिन बंगाली को बढ़ावा देना होगा। इतना ही नहीं उन्होंने जेईई मेन्स परीक्षा में बांग्ला भाषा को शामिल करने की भी मांग रखी।

ज्योतिप्रिय मल्लिक फाइल

ट्विटर यादव और ट्विटर वाड्रा रख लें अपना नाम : केशव

जागरण संवाददाता, वाराणसी : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज किया कि उन्हें अपना नाम ट्विटर यादव और ट्विटर वाड्रा रख लेना चाहिए। उन्होंने रविवार को काशी में मीडिया से कहा कि हमारी सरकार ईमानदार है, हमें किसी के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।

कांग्रेस जब प्रदेश में रही तो प्रदेश नहीं संभाल पाई। जब देश में रही तो देश को नहीं संभाल पाई। यूपी में बड़े-बड़े दावे करने वाली प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी को हारने से नहीं बचा पाईं। महंगाई के सवाल पर कहा कि नियंत्रण में है। यदि कहीं कोई समस्या है तो सरकार उस पर कदम उठा रही है। हैदराबाद में महिला चिकित्सक के साथ घटना पर कहा कि देश में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। घटना में शामिल लोगों के खिलाफ जल्द कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड में भाजपा की पुनः सरकार बनने का उन्होंने भरोसा जताया।

पंकजा मुंडे की 'भावी यात्रा' वाली फेसबुक पोस्ट ने मचाई खलबली

- भाजपा नेता ने कहा, 8–10 दिनों तक रणनीति पर करूंगी मंथन

औरंगाबाद, प्रेट्र : महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री व दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे की 'भावी यात्रा' वाली फेसबुक पोस्ट ने रविवार को राज्य की राजनीति में खलबली मचा दी। पंकजा ने पिता के जन्मदिन पर 12 दिसंबर को अपने समर्थकों से गोपीनाथगढ़ पहुंचने का आह्वान किया है, ताकि राज्य के मौजूदा राजनीतिक माहौल में वह आगे के रास्ते पर निर्णय ले सकें। बीड जिले में स्थित गोपीनाथगढ़ पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का स्मारक है।

भाजपा नेता पंकजा ने फेसबुक पर मराठी में लिखा, 'राज्य के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए सोचने और आगे का रास्ता तय करने का वक्त आ गया है। मैं खुद से संवाद के लिए 8-10 दिनों का समय चाहती हूं। हमें भावी यात्रा के बारे में निर्णय लेना चाहिए।' उन्होंने लिखा, 'आगे क्या करना है? क्या रास्ता अपनाना है? हम लोगों को क्या दे सकते हैं? हमारी शक्ति क्या है? लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं? मैं इन सभी पहलुओं पर चिंतन करूंगी और 12 दिसंबर को आपके समक्ष आऊंगी।'

महाराष्ट्र भाजपा प्रवक्ता शिरीष बोरालकर ने कहा, 'भाजपा को मजबूत करने के लिए पंकजा मुंडे अपना काम जारी रखेंगी। मैंने उनकी फेसबुक पोस्ट पढ़ी है। इसमें कहीं नहीं जाहिर होता कि वह भाजपा से नाखुश हैं। वह गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, जिन्होंने राज्य में भाजपा को मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया है।'

पंकजा मुंडे फाइल

26 जिलों के पुलिस अधीक्षकों से तीन दिसंबर तक अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने पराली जलाने की घटनाओं के न रुकने पर जवाब मांगा है उत्तर प्रदेश में। उन्हें एक अक्टूबर से 25 नवंबर तक पिछले वर्ष और इस वर्ष पराली जलाए जाने की घटनाओं की सूची भेजी गई है।

हैदराबाद दुष्कर्म मामला ▸ तेलंगाना सीएम राव ने तोड़ी चुप्पी

शीघ्र सजा दिलाने को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का भी दिलाया भरोसा

हैदराबाद, प्रेट्र : महिला पशु चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से मार देने की घटना पर देश भर में उबाल कम नहीं हुआ है। घटना के तीन दिन बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया है, ताकि जल्द से जल्द दरिंदों को सजा दिलाई जा सके। घटना को भयानक करार देते हुए मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है।

रविवार को मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सीएम राव ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि हत्यारों को कठोर से कठोर सजा मिल सके। बयान के मुताबिक सरकार बर्बरता पूर्वक मारी गई महिला चिकित्सक के परिजनों को सभी जरूरी मदद भी मुहैया कराएगी। बयान में दुष्कर्म की उस घटना का जिक्र भी किया गया है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर छह महीने में सजा सुनाई गई थी।

इतनी बर्बर घटना पर अब तक चुप्पी साधने पर भाजपा, कांग्रेस, वाम दलों और अन्य पार्टियों ने मुख्यमंत्री की आलोचना की थी। भाजपा ने कहा था कि बर्बर घटना से लोगों में उबाल है और मुख्यमंत्री विवाह समारोह में फोटो शूट करा रहे हैं।

कठोर सजा के लिए कानून में बदलाव की मांग : तेलंगाना के आइटी मंत्री केटी रामा राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आइपीसी और सीआरपीसी की धाराओं में बदलाव करने का अनुरोध किया है, ताकि महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध करने वालों को फांसी की सजा दी जा सके। मुख्यमंत्री राव के पुत्र रामा राव ने सिलिसिलेवार ट्वीट कर मामले में त्वरित सुनवाई की जरूरत पर भी बल दिया है।

हाई सिक्योरिटी सेल में आरोपित : चारों आरोपितों को चेरलपल्ली सेंट्रल जेल में अन्य कैदियों से अलग हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। जेल के अधिकारियों ने कहा कि इन पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचा सकें और दूसरे कैदी भी उन पर हमला न करने पाएं। वहीं, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के सिलसिले में आरोपितों को रिमांड पर लेने पर विचार किया जा रहा है। पुलिस पेट्रोल पंप के उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानूनी राय ले रही है, जहां से आरोपितों ने महिला चिकित्सक के शव को जलाने के लिए बोतल में पेट्रोल और डीजल खरीदे थे।

उन्हें जो सजा देना है दो : इस घटना ने आरोपितों के परिजनों को भी स्तब्ध कर दिया है। उनका घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। तीन आरोपितों मोहम्मद आरिफ, चेन्नकेसवुलु और शिवा के घरवालों का कहना है कि उन्हें जो भी सजा देनी है दे दो। फांसी पर लटका दो या गोली मारकर मौत के घाट उतार दो, हममें से कोई भी उनका बचाव करने नहीं जाएगा। चेन्नकेसवुलु की मां ने कहा कि उसकी भी एक बेटी है इसलिए वह उस मां का दर्द समझ सकती है, जिसने अपनी बेटी खो दी है। उसने बताया कि उसका बेटा लंबे समय से बीमार था, इसलिए पिछले छह महीने से वो उसे काम पर भी नहीं भेजती थी।

नेताओं-अधिकारियों के प्रति गहरी नाराजगी

पशु चिकित्सक की कॉलोनी में रहने वाले लोगों में नेताओं, पुलिस अधिकारियों, मीडिया और बाहरी लोगों के प्रति भारी नाराजगी है। लोगों ने अपनी कॉलोनी के गेट बंद कर दिए हैं और बाहरी लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें सहानुभूति नहीं न्याय चाहिए।

अनु दुबे के साथ बदसलूकी की जांच को कमेटी गठित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हैदराबाद में डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद जलाकर हत्या किए जाने के विरोध में संसद पर धरना देने वाली अनु दुबे के आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। अनु ने पुलिस कर्मियों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। पुलिस की इस कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी।

हैदराबाद की घटना के विरोध में शनिवार को धरने पर बैठी अनु दुबे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। थाने से बाहर आते ही उन्होंने तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दी थी। उनका आरोप था कि वह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही थीं। इसी बीच पुलिसकर्मी जबरन उन्हें थाने में ले गए। वहां उनके साथ मारपीट किए जाने के साथ ही बदसलूकी की गई। अनु से मुलाकात के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नई दिल्ली के डीसीपी को नोटिस जारी कर युवती को हिरासत में लेने का कारण पूछा है। पीड़िता ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गठित की गई टीम में पुरुष सहित महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया है। वहीं, आरोपों की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि हकीकत सामने आ सके। दरअसल शनिवार सुबह संसद भवन के गेट संख्या 2-3 के समीप अनु दुबे प्रदर्शन के लिए पहुंची थीं। उनके हाथ में एक तख्ती थी, जिस पर लिखा था कि मैं अपने भारत में सुरक्षित महसूस क्यों नहीं कर सकती।

कैबिनेट बैठक के बाद होगी कैप्टन की लंच डिप्लोमेसी

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर घिरी पंजाब सरकार की सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक खासी अहम रहेगी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस सरकार के करीब पौने तीन साल में पहली ऐसी कैबिनेट बैठक होगी जिसके बाद दोपहर के भोजन का भी इंतजाम किया गया है। माना जा रहा है कि कैप्टन की लंच डिप्लोमेसी में सरकारी एजेंडों में आर्थिक मुद्दे भी होंगे। करीब एक माह बाद पहली ऐसी बैठक होगी जिसमें धर्म के बाद सरकारी कामकाज पर चर्चा की जाएगी।

कैबिनेट की इस बैठक में एक दर्जन से ज्यादा एजेंडे हैं। सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं कि आर्थिक संकट पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्या रुख रहेगा। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है कि भले ही केंद्र सरकार को जीएसटी का 4100 करोड़ रुपये राज्य सरकार को देना है, लेकिन सरकार के अपने राजस्व में भी भारी गिरावट आई है। महत्वपूर्ण यह है कि शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। जिसके लिए विपक्ष सीधे राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अवकाश मनाकर विदेश से लौटे मुख्यमंत्री के समक्ष 20 दिनों में राजनीतिक से लेकर आर्थिक मोर्चों पर बदलाव का संकट खड़ा हो चुका है। आशंका जताई जा रही है कि आर्थिक संकट के कारण सरकारी मुलाजिमों को इस माह वेतन देने में भी मशक्कत करनी पड़ सकती है। वित्तमंत्री मनप्रीत बादल बेशक कह चुके हैं कि वेतन समय पर मिलेगा, लेकिन यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री आर्थिक मोर्चे को संभालने के लिए क्या कदम उठाते हैं। राजनीतिक रूप से भी कांग्रेस को खासा झटका लगा है। कांग्रेस के ही विधायक सरकार के खिलाफ हो गए हैं। मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्रियों के साथ इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसीलिए कैबिनेट बैठक के बाद लंच का प्रबंध किया गया है। किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति को संभालने के लिए मुख्यमंत्री अक्सर इस तरह की नीति का सहारा लेते रहे हैं। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कैप्टन संदीप संधू ने जरूर विधायकों को बुलाकर उनकी नाराजगी दूर करने के प्रयास किए हैं, लेकिन नाराज विधायकों ने उनके साथ बैठक करने से इंकार कर दिया। इससे लगता है कि मामला बिना मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के निपटने वाला नहीं है।

बागी विधायकों को अभी तक कैप्टन ने गंभीरता से नहीं लिया

मुख्यमंत्री के गृह जिले पटियाला में चार कांग्रेस विधायक लगातार सरकारी कामकाज पर उंगली उठा रहे हैं। इस सबके बावजूद अभी तक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस 'बगावत' को कोई खास तवज्जो नहीं दी है। सरकार ने विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जरूर कील-कांटे कसे हैं लेकिन कैप्टन ने मोर्चा खोलने वाले विधायकों को शांत करने के लिए सीधे रूप से कमान अपने हाथ में नहीं ली है।

होटल प्रबंधन और रियल एस्टेट में दूरस्थ शिक्षा नहीं : यूजीसी

नई दिल्ली, प्रेट्र : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दूरस्थ शिक्षा से होटल प्रबंधन और रियल एस्टेट जैसे पाठ्यक्रमों पर रोक लगा दी है। एक हालिया आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि विभिन्न नियामक इकाइयों से मिली जानकारी के आधार पर होटल प्रबंधन, पाक कला और रियल एस्टेट मूल्यांकन पाठ्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा में 2019-20 और उसके बाद से मान्यता नहीं दी जाएगी।

हालांकि, आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अब तक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत इस अवधि में जो दाखिला हो चुके हैं, उन्हें वह पाठ्यक्रम खत्म होने तक मान्यता मिलेगी। यूजीसी ने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा नियम को 2017 में अधिसूचित किया था। इसमें कहा गया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की पढ़ाई दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संभव नहीं है। बाद में इसमें कृषि को भी शामिल कर दिया गया। इसके अलावा यूजीसी ने अपनी हालिया बैठक में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में नामांकन के समय में भी बदलाव का फैसला किया है। इसने एक आदेश जारी कर कहा कि चूंकि देश में अगस्त-सितंबर तक बरसात का मौसम रहता है, इसलिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में नामांकन का कार्यक्रम बदला जा रहा है। आगे से जनवरी से शुरू होने वाले सत्र में फरवरी के अंत तक और जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के लिए सितंबर के अंत तक नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के दो पुत्रों पर बैंक का 42 लाख बकाया

नईदुनिया, नरसिंहपुर : विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के दो बेटों द्वारा इलाहाबाद बैंक की नरसिंहपुर शाखा से लिए गए करीब 42 लाख रुपये से ज्यादा का ऋण समय पर अदा नहीं किए करने और एनपीए (गैर उत्पादक संपत्ति) हो जाने पर बैंक ने नोटिस प्रकाशित कराए हैं। उनसे 60 दिन में बकाया राशि ब्याज व अन्य खर्च सहित जमा करने को कहा है।

प्रीतिराज प्रजापति के नाम जारी नोटिस में 20 लाख 68 हजार 530 रुपये व नीर प्रजापति के नाम जारी नोटिस में बैंक ने 21 लाख 54 हजार 578 रुपये व ब्याज तथा अन्य खर्च की राशि मांगी है। दोनों बेटों के लिए इस ऋण में विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति जमानतदार हैं, जबकि नीर के प्रकरण में प्रजापति के अलावा दिनेश कुमार कठल भी जमानतदार हैं।

इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति, उनके दोनों बेटों से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

'महिला अपराध से मिलकर लड़ना होगा'

जागरण संवाददाता, कानपुर

▸ स्वजन-रिश्तेदार और मित्रों से मिल कई भावों में दिखे राष्ट्रपति

▸ मुलाकात का दौर, अपनों को दिया जल्द गांव आने का भरोसा

देश भर में हो रहे महिला अपराधों पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चिंतित दिखे। तेलंगाना में महिला पशु चिकित्सक के साथ हुई घटना का सीधे जिक्र तो नहीं किया लेकिन उन्होंने कहा कि यह बहुत चिंता का विषय हो गया है। महिला अपराधों से सभी को मिलकर लड़ना होगा। समाज के हर तबके को आगे आना होगा। रविवार को गुरुनानक गर्ल्स पीजी कॉलेज की शिक्षिका डॉ. आरती वाजपेयी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की।

इससे पहले राष्ट्रपति ने रामनाथ कोविंद ने स्वजन, रिश्तेदार, मित्र और परिचितों से मुलाकात की, जीभर बात की। सर्किट हाउस में चले इस मुलाकात के दौर में जहां बातें हुईं, यादें ताजा हुईं, अपनों की अपेक्षाएं भी थीं। इस दौरान राष्ट्रपति कई भावों में दिखे। किसी बात पर मुस्कराते तो कभी तकलीफ सुन भावुक होते। अपनों का सबसे जोर परौंख गांव बुलाने पर था।

राष्ट्रपति ने उनको जल्द गांव आने का भरोसा दिया। राष्ट्रपति सुबह करीब पांच बजे ही उठ गए। छह बजे सर्किट हाउस परिसर के पार्क में वॉक पर निकले। साढ़े आठ बजे से मिलने वालों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। गेस्ट रूम में राष्ट्रपति ने 46 लोगों से मुलाकात की।

चकेरी एयरपोर्ट में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व उनकी पत्नी सविता कोविंद (बगल में) को विदा करतीं राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री एन कटियार, महापौर प्रमिला पांडेय (बाएं से)। जागरण

बड़े भाई रामस्वरूप कोविंद और स्वामी जी से गुफ्तगू की। झींझक से आए बड़े भाई प्यारेलाल के बेटे दीपक, बेटी रंजना, उनके पति विनोद, बेटी कविता, उनके बेटे हर्षित को आशीर्वाद दिया। बीमार चल रहीं भांजी मीना कोविंद को उनकी पत्नी सविता कोविंद ने प्यार दिया। नातिन मोनिका और मनी से बात की। इस दौरान दिल्ली के डॉ. मनोज सैनी ने मीना का चेकअप भी किया।

विजिटर बुक में लिखा : राष्ट्रपति ने विजिटर बुक में लिखा कि, कानपुर आना हमेशा सुखद अहसास होता है। मेरा दिन काफी सुकून भरा और आरामदायक रहा। सर्किट हाउस के प्रशासन और स्टॉफ को मेरी शुभकामनाएं।

मुजफ्फरपुर कांड के सरगना ने सरकारी धन का किया दुरुपयोग

नई दिल्ली, प्रेट्र : बिहार के सनसनीखेज मुजफ्फरपुर महिला आश्रय कांड के सरगना ब्रजेश ठाकुर ने लड़कियों के कल्याण के लिए सरकार की तरफ से मिले धन का निजी इस्तेमाल किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में यह भी सामने आया है कि सरकारी धन का हस्तांतरण गैरकानूनी गतिविधियों के लिए भी किया गया था। आश्रय गृह में कई लड़कियों से यौन उत्पीड़न के मामले में ब्रजेश ठाकुर मुख्य आरोपित है।

▸ ईडी ने अपनी जांच में बताया कि ब्रजेश ठाकुर ने बच्चों के लिए मिले फंड को अपने हित में खर्च किया

ईडी ने ब्रजेश ठाकुर, उसके परिवार के सदस्यों व अन्य के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर को मनी लांड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया था। ब्रजेश ठाकुर के गैर सरकारी संगठन सेवा संकल्प विकास समिति की ओर से चलाए जा रहे आश्रय गृह में नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न की खबर सामने आने के बाद यह मामला दर्ज किया गया था। ईडी ने कहा है, 'गैर सरकारी संगठन के बैंक खातों के जरिए सीधे ठाकुर और उसके परिवार के सदस्यों के खाते में उनके निजी इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरित किया गया था।' जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि यह 'मनी लांड्रिंग का एक अनोखा मामला' है जहां बच्चों के कल्याण में इस्तेमाल होने वाले धन को हस्तांरित किया गया, विभिन्न खातों के माध्यम से बांटा गया और व्यक्तिगत हित के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। ईडी ने रिपोर्ट में आरोप गया है, 'ठाकुर ने संगठन के बैंक खातों से अन्य लोगों के खातों में धन का अवैध रूप से हस्तांतरण किया जिन्होंने बाद में बिना कोई निशान छोड़े नकद राशि अपने बैंक खाते से निकाल कर ठाकुर को सुपुर्द कर दिया। गैर सरकारी संगठन के खातों से धन निकाल कर उसका इस्तेमाल 'सीधे' उसके बेटे के मेडिकल कॉलेज की फीस चुकाने में किया गया।' आयकर विभाग ने पिछले साल ठाकुर के गैर सरकारी संगठन के पंजीयन एवं कर छूट को रद्द कर दिया था। मनी लांड्रिंग के तहत मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी पाया कि ठाकुर और उसके परिवार ने आयकर रिटर्न में अपनी संपत्ति एक करोड़ 97 लाख से कम बताई थी जबकि उनके पास लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये की संपत्ति है।

गुवाहाटी विवि ने 21 गैर स्वीकृत पाठ्यक्रम शुरू किए

गुवाहाटी, प्रेट्र : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि गुवाहाटी विवि ने करीब 74,000 छात्रों के कॅरियर को खतरे में डाल दिया है। इसने दूरस्थ शिक्षा केंद्र के माध्यम से 21 गैर स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए सात साल तक छात्रों से 39 करोड़ रुपये एकत्र किए। कैग की रिपोर्ट को असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया गया। इसमें कहा गया है कि पूर्वोत्तर के सबसे पुराने विश्वविद्यालय ने यूजीसी को कई गलत हलफनामे दिए थे, जिसमें उसने आश्वासन दिया था कि वह बगैर स्वीकृति के कोई नया पाठ्यक्रम नहीं शुरू करेगा। कैग ने कहा कि इग्नू ने दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी) की स्वीकृति के साथ अगस्त 2010 में 2010-11 से तीन साल के आठ पाठ्यक्रमों के लिए गुवाहाटी विवि को मान्यता दी थी।

मध्य प्रदेश में मीडिया समूह तक पहुंची हनी ट्रैप की आंच, ताबड़तोड़ छापेमारी

नईदुनिया, इंदौर

▸ पांच एफआइआर की गई दर्ज, एक गिरफ्तार भी हुआ

▸ मीडिया समूह के ठिकानों पर सुबह तक चलती रही जांच-पड़ताल

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले को लेकर उजागर हो रहे ऑडियो व वीडियो फुटेज के मामले में इंदौर में एक मीडिया समूह के कई प्रतिष्ठानों, ऑफिस और घर पर छापे मारे गए। शनिवार रात रविवार सुबह आठ बजे तक चली कार्रवाई के बाद चार थानों में पांच एफआइआर दर्ज की गईं। इनमें मानव तस्करी, अवैध कारतूस, नौकर व कर्मचारियों की जानकारी छुपाने और आइटी एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने समूह के कर्ताधर्ता के बेटे अमित सोनी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने दावा किया कि होटल में अवैध गतिविधियां और घर से कारतूस मिले हैं। हनी ट्रैप कांड के फरियादी हरभजन सिंह (निलंबित इंजीनियर) की शिकायत पर अमित सोनी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। हरभजन ने आरोप लगाया कि मीडिया हाउस ने उनकी निजता का उल्लंघन किया है। अश्लील सामग्री यूट्यूब पर प्रसारित कर अप्रत्यक्ष रूप से ब्लैकमेल किया जा रहा है। दूसरा केस कनाडिया थाने के थाना प्रभारी अनिलसिंह चौहान की शिकायत पर मीडिया संस्थान के मालिक के बेटे विक्की व भतीजे लक्की के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का दर्ज किया। अनिल सिंह की शिकायत पर ही तीसरा केस अवैध रूप से कारतूस रखने का बनाया गया। थाना प्रभारी के मुताबिक सर्चिंग के दौरान पुलिस को 36 कारतूस और 6 चले हुए कारतूस मिले। अमित और जीतू के पास रिवॉल्वर का लाइसेंस है, लेकिन जब्त कारतूस का उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। एक अन्य केस तुकोगंज थाने में दर्ज किया गया है। इस थाना क्षेत्र में जीतू की होटल है जिसमें पब, बार भी है। मैनेजर व संचालक द्वारा कर्मचारियों की जानकारी थाने में नहीं देने पर प्रकरण कायम किया गया। पांचवां केस पलासिया थाने में दर्ज किया गया। हरभजन ने आरोप लगाया कि होटल के डांसबार में कई युवतियां बंधक होकर काम करती हैं। अवैध गतिविधियां संचालित होती हैं। सूचना पर अधिकारी होटल पहुंचे। होटल की तीसरी मंजिल पर 67 लड़कियां व महिलाएं, 7 बच्चे और 25 पुरुष मिले। महिलाओं ने बयानों में दुर्व्यापार करवाना बताया। उन्हें वेतन और पीएफ नहीं मिलता है। होटल में डांस करती हैं। टिप से ही जीवन यापन करती हैं।

जिला कोर्ट से लेकर थाने आए: रविवार सुबह अमित को एमआइजी थाने में हिरासत में रखा गया। दोपहर करीब 4 बजे पुलिस अमित को जिला कोर्ट लेकर रवाना हो गई। अचानक किसी अफसर का फोन आया और पुलिसकर्मी अमित को लेकर पलासिया थाने पहुंच गए। एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अमित की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं हुई है। फिलहाल मानव तस्करी के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। अमित ने कहा कि पुलिस ने छापे और गिरफ्तारी हनी ट्रैप मामले में फंसे अफसरों और नेताओं के इशारे पर की है। शनिवार को ही उनकी तरफ से हाई कोर्ट में एक हार्ड डिस्क जमा की गई थी। एसएसपी के मुताबिक कार्रवाई का हनीट्रैप से कोई लेना-देना नहीं है। वहां तीन सेफ मिले हैं। इसकी जांच के लिए दफ्तर सील करना पड़ा।

बिहार में नाइट गार्ड के बेटे ने न्यायिक सेवा परीक्षा में लहराया परचम

जागरण संवाददाता, जमुई : नाइट गार्ड की नौकरी कर मामूली तनख्वाह में परिवार की गाड़ी खींचने वाले मनोहर सिंह के बेटे अनीश कुमार सिंह ने बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में अपना परचम लहराया है। दृढ़ निश्चय और लगन के बलबूते अनीश ने न्यायिक सेवा परीक्षा में सातवां स्थान हासिल किया है। आर्थिक विपन्नता के कारण उसने मैट्रिक तक की शिक्षा एक रिश्तेदार के घर पर रह कर पूरी की। विपन्नता से संघर्ष कर सफलता हासिल करने के बाद वह इलाके के युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गए हैं।

बिहार के जमुई निवासी अनीश मनोहर सिंह के सबसे बड़े पुत्र हैं। मनोहर दिल्ली में नाइट गार्ड की नौकरी करते हैं। अनीश की सफलता पर माता गुड्डी देवी सहित चाचा सुशील कुमार सिंह फूले नहीं समा रहे हैं। चाचा के घर पर रहकर ही अनीश ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की थी। उन्होंने बताया कि वह बचपन से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर था। मैट्रिक के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। कहा, उसके दादा त्रिपुरारी सिंह हमेशा उसे प्रोत्साहित करते थे। अब गांव के छात्र अनीस को आदर्श मानकर पढ़ाई में जुट गए हैं।

नगालैंड ने मनाया स्थापना दिवस

पूर्वोत्तर राज्य नगालैंड के 57 वें स्थापना दिवस पर राजधानी कोहिमा में आयोजित समारोह के दौरान स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने आतंकियों और विघटनकारी ताकतों से निपटने के लिए अपने जौहर का प्रदर्शन किया। एक दिसंबर वर्ष 1963 में नागालैंड 16 वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं। प्रेट्र

उल्लास

फूलों की बारिश के बीच प्रभु श्रीराम व सीता का निकला डोला, बारहबीघा में दोनों डोलों का हुआ मिलन, सात फेरों की रस्म कराई गई पूरी

जनकपुरधाम में जानकी विवाह पर उत्सव का माहौल

जागरण संवाददाता, जनकपुरधाम (नेपाल)

जनकपुरधाम में जानकी विवाह पंचमी को लेकर हर घर में उत्सव का माहौल रहा। जगह-जगह राम-जानकी विवाह के गीत बजते रहे। शहर में बिहार व उत्तर प्रदेश के लाखों श्रद्धालु रात में ही पहुंच गए थे।

रविवार सुबह शहर के विभिन्न पोखरों में सामूहिक स्नान के बाद जानकी और राम मंदिर में पूजा-अर्चना हुई। फिर फूलों की बारिश के बीच माता सीता व प्रभु राम का डोला निकला। शहर में घूमने के बाद बारहबीघा में उनके सात फेरे कराए गए।

दोपहर में जानकी और राम मंदिर से अलग-अलग डोला निकला। प्रभु राम व माता जानकी का डोला जिस रास्ते से गुजरा, वहां सड़कों के किनारे हजारों की भीड़ रही। अपने-अपने घरों की छतों से लोग पुष्प वर्षा करते रहे। हर गली की बेहतर सफाई की गई थी। शंख, झाल, मृदंग की आवाज से इलाका गुंजायमान होता रहा। साथ चल रहे नेपाली सेना के बैंड की आवाज आ रही थी। श्रीराम नाम की गूंज भीड़ में जोश भर रही थी।

जनकपुरधाम के बारहबीघा में फूलों की बारिश के बीच श्रीराम व सीता के डोले का मिलन। जागरण

जहां ठहरे थे दशरथ, वहां उतारी गई आरती

श्रीराम का डोला विभिन्न मार्गों से होते हुए दशरथ मंदिर पहुंचा। कहा जाता है कि त्रेता में राम की बरात लेकर अयोध्या से आए राज दशरथ यहीं ठहरे थे। यहां डोला की विधिवत आरती उतारी गई, भोग लगाया गया। महिलाएं गीत गा रही थीं, सांवर दूल्हा, श्रीराम दूल्हा....।

बारहबीघा में हुई सात फेरों की रस्म

दशरथ मंदिर से निकल कर प्रभु श्री राम का डोला बारहबीघा पहुंचा। यहां पहले से माता जानकी का डोला पहुंचा हुआ था। यहीं दोनों का मिलन हुआ। परंपरागत तरीके से हजारों की भीड़ के बीच दोनों डोले के सात फेरों की रस्म को पूरा कराया गया। फिर लोग वापस मंदिर पहुंचे।

बिहार समेत 18 राज्यों में राजद की नई प्रदेश कार्यकारिणी

राज्य ब्यूरो, पटना

राजद ने बिहार समेत 18 राज्यों में नई प्रदेश कार्यकारिणी समिति का गठन कर लिया है। इन सभी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी करा लिया गया है। हालांकि उप्र और महाराष्ट्र समेत तीन राज्यों में अभी भी मामला लटका हुआ है। उक्त राज्यों में जिले के चुनाव ही अभी लंबित हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक किसी भी राज्य के 50 फीसद जिलों में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रदेश ईकाई का चुनाव कराने का प्रावधान है। संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते हुए राजद की ओर से 24 राज्यों में सदस्यता फॉर्म भेजे गए थे। इनमें से 18 राज्यों में निर्धारित समय के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई। बाकी छह राज्यों से अभी तक सूची नहीं आई है। राजद के सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन ने दावा किया है कि जिन राज्यों में अभी अड़चन है, वहां भी संगठन विस्तार की प्रक्रिया जारी है। इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव अभी लंबित है, उनमें यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम भी शामिल हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश, असम और बंगाल में राष्ट्रीय परिषद के चुनाव करा लिए गए हैं। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो सका है।

इनके हाथ राजद की कमान

बिहार में जगदानंद सिंह, झारखंड में अभय कुमार सिंह, दिल्ली में मनोज चौधरी, हिमाचल प्रदेश में बलवंत सिंह, आंध्र प्रदेश में टी वेणुगोपाल, पंजाब में मुकीद आलम, तमिलनाडु में एस गौरीशंकर, अंडमान निकोबार में एम धनाशेखरण, केरल में अन्नू चाको, उड़ीसा में हरिश महापात्रा, मुंबई में सैयद मो. इकबाल, गुजरात में असलम मलिक, नगालैंड में खेतोमी किन्नी, कर्नाटक में जी याकूब और जम्मू-कश्मीर में विजय महाजन को राजद का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है।

77641 युवाओं ने एसपीओ के 5199 पदों के लिए आवेदन किया है जम्मू-कश्मीर में। उनके चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसमें केवल घाटी से 26594 युवक-युवतियों ने एसपीओ के लिए आवेदन किया है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 2 दिसंबर 2019

मप्र में लोकायुक्त के पूर्व डीजी व पांच आइएएस अफसरों पर केस

आरोप ▸ उज्जैन हवाई पट्टी का लीज रेंट जमा नहीं करने का मामला

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में करीब 26 साल पहले लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना में डीजी (पुलिस महानिदेशक) रहे अरण गुर्टू और कलेक्टर रहे पांच आइएएस अधिकारियों के खिलाफ उज्जैन हवाई पट्टी की लीज राशि वसूल न कर पाने को लेकर लोकायुक्त पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है। आरोपित शिवशेखर शुक्ला, अजातशत्रु श्रीवास्तव, एम. गीता, बीएम शर्मा व कवींद्र कियावत आइएएस अधिकारी हैं। इनके अलावा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री रहे एसएस सलूजा, एके टूटेजा और जीपी पटेल सहित 14 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम और आइपीसी की धारा 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

मालूम हो, राज्य शासन ने 2006 में यश एयरवेज को पायलटों के प्रशिक्षण के लिए उज्जैन (मध्य प्रदेश) की हवाई पट्टी लीज पर दी थी। इसके एवज में यश एयरवेज को हर साल करीब डेढ़ लाख रुपये लीज रेंट के तौर पर जमा करना थे। साथ ही हवाई पट्टी का रखरखाव भी इसी कंपनी के जिम्मे था। कंपनी द्वारा रखरखाव खुद नहीं कर पाने पर पीडब्ल्यूडी को राशि देकर उसकी मरम्मत कराने की शर्त थी। यश एयरवेज ने उस वर्ष का लीज रेंट तो जमा किया, जिस वर्ष लीज मिली, लेकिन अगले साल से लीजरेंट जमा करना बंद कर दिया। कुछ समय बाद यश एयरवेज का नाम सेंटार एविएशन लिमिटेड कर दिया गया। इसके बाद यश एयरवेज या सेंटार एविएशन ने न तो लीज रेंट जमा किया और न ही हवाई पट्टी का रखरखाव किया। इससे हवाई पट्टी हवाई सेवाओं के उड़ान के मापदंडों के अनुकूल नहीं बची। बताया जाता है कि हवाई पट्टी को उड़ानों के अनुकूल बनाने के लिए 2013 में तत्कालीन कलेक्टर बीएम शर्मा ने कार्रवाई की। शर्मा ने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हवाई पट्टी की मरम्मत पर दो करोड़ 66 लाख रुपये सरकारी खजाने से खर्च कराए, लेकिन इस राशि की यश एयरवेज या सेंटार एयर लिमिटेड से वसूली नहीं की। वहीं, 2007 से लेकर 2016 के बीच लीज रेंट की राशि नहीं मिलने तथा हवाई पट्टी का रखरखाव नहीं होने पर तत्कालीन कलेक्टरों ने यश एयरवेज या सेंटार एविएशन लिमिटेड के खिलाफ लीज निरस्तीकरण और हवाई पट्टी की मरम्मत करने के नोटिस देने तक की कार्रवाई नहीं की।

कंपनी में यह रहे शामिल : यश एयरवेज और सेंटार एविएशन लिमिटेड के प्रमुख कर्ताधर्ता यश टोंग्या और भरत टोंग्या ने अध्यक्ष के रूप में लोकायुक्त के पूर्व डीजी अरण गुर्टू को शामिल कर लिया। लोकायुक्त पुलिस में दर्ज एफआइआर में कंपनी के दो अन्य संचालकों के नाम भी हैं। आरोपितों में उज्जैन के कलेक्टर रहे शिवशेखर शुक्ला अभी प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य हैं तो कवींद्र कियावत भोपाल में सचिव स्तर के अधिकारी हैं। आइएएस अधिकारी एम. गीता की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य कैडर आवंटित होने से वहां सौंपी जा चुकी हैं। अजातशत्रु श्रीवास्तव और बीएम शर्मा सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस प्रकरण की जांच के दौरान तब विमानन विभाग की कमान संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विभाग के प्रशासनिक प्रमुख रहे इकबाल सिंह बैंस की भूमिका भी तय की जाएगी।

यश एयरवेज घोटाला

गुर्टू ने दी थी लोकायुक्त की नियुक्ति को चुनौती

उल्लेखनीय है कि उज्जैन हवाई पट्टी के मामले में आरोपित बनाए गए अरण गुर्टू ने मौजूदा लोकायुक्त जस्टिस एनके गुप्ता की नियुक्ति को 2017 में चुनौती दी थी। गुर्टू ने मौजूदा उप लोकायुक्त जस्टिस यूसी माहेश्वरी से छह साल जूनियर होने को आधार बनाकर यह चुनौती दी थी।

सीबीआइ के शिकंजे में फंसे उप डाकपाल व कैशियर निलंबित

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़ : उप डाकघर कुंडा में एजेंट से रिश्वत लेने के मामले में सीबीआइ के शिकंजे में फंसे उप डाकपाल व कैशियर को प्रवर डाक अधीक्षक ने निलंबित कर दिया गया है। दोनों का प्रभार अन्य कर्मियों को सौंप दिया गया। उधर, शनिवार रात तक जांच के बाद सीबीआइ टीम दोनों को अपने साथ लखनऊ ले गई।

संग्रामगढ़ क्षेत्र के धनगढ़ गांव के कुंवर प्रभात सिंह की पत्नी एजेंट शुभा सिंह ने कर्मचारियों के रिश्वत लेने की शिकायत सीबीआइ से की थी। इस पर सीबीआइ की लखनऊ ब्रांच की टीम ने शनिवार दोपहर उप डाकघर कुंडा पहुंची। यहां प्लानिंग के तहत कैशियर सूरज मिश्र और उप डाकपाल संतोष कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। जांच के दौरान कैश में 970 रुपये अधिक मिला, जिसका हिसाब कैशियर व उप डाकपाल नहीं दे सके। जांच के बाद सीबीआइ संतोष को उसके पैतृक आवास पट्टी और शहर में देवकली स्थित आवास पर ले गई। वहां से आने के बाद लखनऊ लेकर चली गई। जांच के दौरान दोनों डाक कर्मियों के मोबाइल फोन के सिम को कब्जे में लेते हुए मोबाइल उनके घर वालों को दे दिया। सीबीआइ अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।

प्रवर डाक अधीक्षक केएस वाजपेयी ने बताया कि सीबीआइ द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद कैशियर सूरज मिश्रा और उप डाकपाल संतोष कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी की जाएगी।

पटना में चलती कार में जवान ने पत्नी व साली को गोली से उड़ाकर खुदकशी की

जागरण संवाददाता, पटना

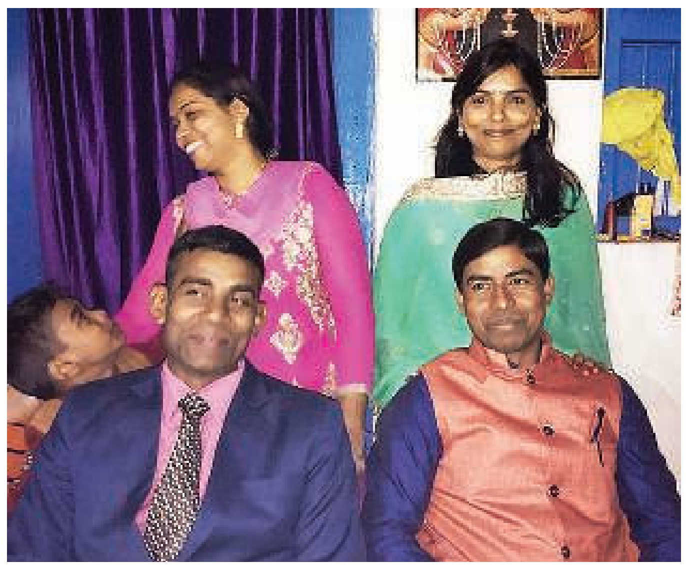

बाएं से आर्मी का जवान विष्णु शर्मा, पत्नी दामिनी (पीछे), पवन (साली का पति), साली खुशबू (पीछे)। फाइल फोटो।

पटना के बिक्रम शहर में रविवार सुबह सेना के एक जवान ने गाड़ी में पत्नी और साली को गोलियों से छलनी कर दिया और खुद को भी गोली मार ली। बच्चों के रोने व ड्राइवर के शोर मचाने पर आसपास के लोग कार की ओर दौड़े। लोगों ने कार के अंदर झांका तो होश उड़ गए। पिछली सीट पर खून से लथपथ तीन लाशें पड़ी थीं। कार के शीशे भी गोलियों से चकनाचूर हो चुके थे। पूछने पर कार चला रहे मिथिलेश ठाकुर ने लोगों को बताया कि गोली मारने वाला सेना का जवान है। उसने पत्नी व साली पर गोलीबारी के बाद खुद को भी गोली मार ली। लोगों ने दोनों बच्चों को कार से बाहर निकाला।

जानकारी के अनुसार आर्मी मैन विष्णु शर्मा (35) गुजरात के भुज में पदस्थापित थे। 12 दिन पहले अपने गृह जनपद आरा आए थे। 22 नवंबर को ससुराल में साली की शादी में शिरकत करने गए थे। ससुराल में उनकी तबीयत खराब हो गई। रविवार को विष्णु शर्मा अपनी ससुराल से कार से पटना एम्स में इलाज के लिए जा रहे थे। साथ में पत्नी दामिनी (32), साली खुशबू (22), दो बेटे विराट (8) व वैभव (6) भी थे। गाड़ी रिश्तेदार मिथिलेश ठाकुर चला रहे थे। मिथिलेश ने बताया कि घर से सभी लोग सामान्य रूप से निकले थे। पटना आने के दौरान सैदाबाद गांव के समीप अचानक विष्णु ने पिस्टल निकाली और साली पर गोली चला दी। वह कुछ सोच पाता, तब तक उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं और बगल में बैठी पत्नी दामिनी को भी गोली मार दी। कार रोककर वह जैसे ही विष्णु की ओर लपका तो उसने पिस्टल तान दी और गोली मारने की धमकी दी। पत्नी व साली को गोली मारने के उसने खुद को उड़ा लिया। आनन-फानन तीनों को बिक्रम स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया। मौके पर फोरेंसिक टीम पहुंची और कार के अंदर और बाहर जांच की। पिस्टल, खोखे और पिलेट को जांच के लिए टीम अपने साथ ले गई।

डीएसपी मनोज पांडेय ने जवान के ससुर सुरेश शर्मा से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि बड़ी बेटी दामिनी की शादी 2012 में विष्णु से हुई थी। कुछ दिनों से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।

कश्मीर में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार बरामद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : कश्मीर में सुरक्षाबलों ने शनिवार रात को रफियाबाद, बारामुला में एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान जवानों ने तलाशी के दौरान तीन आरपीजी राउंड समेत भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया है।

सेना की 22 आरआर और राज्य पुलिस विशेष अभियान दल के जवानों ने मिलकर सुबह रफियाबाद के डोलरी जंगल में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर तलाशी अभियान चलाया। जवानों ने जंगल में एक जगह बने आतंकी ठिकाने का पता लगाया। इस ठिकाने में पांच आतंकियों के रहने की सुविधा थी। जवानों ने इस ठिकाने को ध्वस्त कर यहां की की तलाशी ली।

इस दौरन जवानों को तीन एके-47, दो हजार एके कारतूस, तीन आरपीजी राउंड, तीन अत्याधुनिक रेडियो सेट और अन्य युद्धक सामग्री के अलावा कंबल, राशन और दवाएं मिली हैं। सुरक्षाबलों की ओर से बताया गया कि आतंकियों के और ठिकाने तलाशने के लिए फिलहाल, तलाशी अभियान जारी रखा हुआ है। सूत्रों के अनुसार आसपास आतंकी गतिविधियों की सूचना है।

बरेली कैंट से पकड़े गए संदिग्ध नेपाली युवक के दोनों आधार कार्ड फर्जी पाए गए

जासं, बरेली

- असली मुहम्मद मंजर कौन, पता लगाने में जुटी एटीएस
- लगातार मिल रहे फर्जी कागजातों से युवक पर गहराता जा रहा शक

मंगलवार को कैंट क्षेत्र से पकड़े गए संदिग्ध नेपाली युवक पर जांच एजेंसियों का शक और गहराता जा रहा है। उसके पास से एक के बाद एक फर्जी कागजात मिलते जा रहे हैं। उसके पास से दो आधार कार्ड बरामद हुए थे, जिन्हें वह अपने बता रहा था। जो कार्ड मुहम्मद मंजर के नाम से बना है, उसमें कार्ड नंबर तो ठीक है मगर फोटो नेपाली युवक के बजाए उससे मिलते-जुलते किसी शख्स की है। पुष्टि होने के बाद अब एटीएस असली मुहम्मद मंजर की तलाश में जुट गई है। वहीं दूसरा आधार कार्ड पूरी तरह से फर्जी है, उसका नंबर सिस्टम में डालने पर कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी।

आर्मी इंटेलीजेंस के हाथों पकड़ा गया नेपाल युवक गूंगा-बहरा है। उसके पास से अलग नाम के दो आधार कार्डों के साथ ही एक अलग नाम से संस्था का परिचय पत्र, पेनड्राइव, पासबुक, मोबाइल व कई सिम कार्ड बरामद हुए थे। शनिवार को एटीएस की टीम युवक को अपने साथ ले गई और आधार कार्ड की जांच कराई। जांच में फिंगर प्रिंट, आई टेस्ट आदि की जांच के बाद भी आधार कार्ड की जानकारी नहीं मिली। इस पर आधार कार्डों का नंबर जांचा गया तो मो. मंजर नाम के आधार कार्ड की डिटेल सामने आई, जिसमें उसके पिता का नाम मंसूर, ग्राम निखरैल, पोस्ट-बभनी, पूर्णिया बिहार दर्ज है। एटीएस इंस्पेक्टर मंजीत सिंह ने बताया कि नेपाली युवक से मिले पहले आधार कार्ड से उसका फोटो मैच नहीं कर रहा। दूसरा आधार कार्ड भी फर्जी तरह से बनाया गया है। मो. मंजर है कौन इसकी तलाश कराई जा रही है।

निष्कर्ष निकालने में जुटी जांच एजेंसियां : पकड़े गए संदिग्ध युवक से पुलिस, आर्मी इंटेलीजेंस, एटीएस, एलआइयू आदि एजेंसियां पूछताछ कर चुकी हैं। अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए उसे लेकर सभी एजेंसियों ने रविवार को एक साथ बैठक की। इसमें युवक को लेकर निष्कर्ष निकालने की कवायद चलती रही। अब उसका मेडिकल करा मालूम किया जाएगा कि वह वास्तव में दिव्यांग है या नाटक कर रहा।

कैंट क्षेत्र में एक और संदिग्ध नेपाली पकड़ा गया था। शनिवार रात को उसे जाट रेजीमेंट की भरतौल फायरिंग रेंज से आर्मी ने पकड़कर कैंट पुलिस को सौंप दिया। वह भारत कैसे आया, क्यों आया, किसके साथ आया या किसने भेजा जैसे पुलिस के सवालों का एक ही जवाब दे रहा है कि उसे कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना बताया कि वह नेपाल के मकराना जिले का रहने वाला है। उसका नाम सरोज है। परिवार में पत्नी सीमा व दो बच्चे हैं।

दोनों संदिग्धों का कराया सामना

रविवार को दोनों को आमने सामने बैठाया गया। दोनों ने कहा कि वे एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं। हालांकि बातचीत करते समय काफी सहज लग रहे थे। कैंट इंस्पेक्टर अवनीश सिंह ने बताया कि दूसरे संदिग्ध से काफी पूछताछ की जा चुकी है। संदिग्ध मानकर जांच की जा रही है।

मप्र में 20 लाख का प्याज चुराने वाले तीन आरोपित गिरफ्तार

नईदुनिया, शिवपुरी: प्याज की बढ़ती कीमतों के चलते नासिक की 20 लाख पए कीमत की 40 टन प्याज चुराने के मामले में पुलिस ने रविवार को ट्रक मालिक और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों के पास से 434 बोरी प्याज भी बरामद की गई है।

तेंदुआ थाना प्रभारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि नासिक के ट्रांसपोर्टर ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मामले की शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपित जावेद (25) पुत्र सलीम अहमद निवासी पुरानी शिवपुरी, शौकत (25) उर्फ गोपाल पुत्र लियाकत खान, शकील (23) पुत्र मोहम्मद अहमद कुरैशी निवासी पुरानी शिवपुरी को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने बताया कि उन्होंने प्याज को मुरैना के जौरा में बेच दिया है। इसके बाद जौरा से 280 बोरी और ग्राम लखेरी से 154 बोरी प्याज को जब्त किया। मालूम हो, नासिक के ट्रांसपोर्टर प्रेमचंद्र ने बताया था कि हाल ही में उन्होंने नासिक से गोरखपुर के लिए प्याज को लोड करवाया था और वह जावेद से संपर्क में थे। प्याज गोरखपुर नहीं पहुंचा और जावेद का मोबाइल भी बंद था। जब वे शिवपुरी में जावेद के घर पहुंचे तो उन्हें जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया गया।

11 वर्ष की बेटी बोली-अभी पढ़ना है, मेरी शादी रुकवा दें

जागरण संवाददाता, फतेहपुर

- उप्र के फतेहपुर में बालिका वधू बनाने की तैयारी पर पुलिस की निगरानी
- 11 वर्ष की बेटी की 28 साल के युवक के साथ शादी करवा रहा था पिता

माता-पिता ने तो खेलने-पढ़ने की उम्र में 11 वर्ष की बेटी को बालिका वधू बनाने की तैयारी कर ली थी। विरोध पर बेटी को डपट देते थे। स्कूल भी भेजना बंद कर दिया था लेकिन बेटी भी हिम्मत वाली थी। उसने बाल विवाह के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। फोन करके पुलिस को बुलाया और थाने पहुंच गई। रोते हुए पूरी दास्तान बताई। बोली, साहब! मुझे अभी पढ़ना है, मेरी शादी रुकवा दें। पुलिस ने पिता को बुलाकर बाल विवाह के अपराध पर जेल भेजने की चेतावनी दी। बाल विवाह नहीं करने की बात लिखित लेने के बाद छोड़ा। थानाध्यक्ष जेपी उपाध्याय ने बताया कि किशोरी को अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया है। बालिग होने के बाद ही शादी के लिए पिता राजी हो गया है और गलती के लिए क्षमा मांगी है।

उप्र के फतेहपुर जिले की लक्ष्मी देवी कक्षा छह की छात्रा है। पिता सूरजभान निषाद ने उसका विवाह 28 साल के युवक से तय कर दिया। यह बात छात्रा को पता चली तो उसने विरोध शुरू कर दिया। किसी ने उसकी नहीं सुनी। तब उसको पुलिस से मदद लेने की बात सूझी। रविवार को घर से सभी सदस्य खेत चले गए तो मोबाइल से पुलिस को पूरी बात बताई। फोन करने के आधे घंटे के अंदर पुलिस टीम उसके घर पहुंची। छात्रा ने पुलिस को बताया कि जिससे शादी तय हुई, वह युवक अक्सर घर आता है। पिता के साथ बैठकर शराब पीता है। जब पिता से कहा- अभी पढ़ने दो, शादी बाद में कर देना तो उन्होंने स्कूल जाने से रोक दिया। डांटते हुए कहा कि तुम्हारी मेरे सामने यह सब कहने की हिम्मत कैसे हुई। मां ने भी शांत कर दिया कि बेटी विवाह तो एक दिन होना ही है। लड़का जान-पहचान का है, शादी कर लो।

325 करोड़ रुपये से जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में बनेगा मेडिकल कॉलेज

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- 90 फीसद केंद्र तो 10 फीसद राज्य प्रशासन खर्च करेगा

प्रतीकात्मक

केंद्र सरकार ने कुपवाड़ा जिले के लिए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी है। यह कॉलेज 325 करोड़ की लागत से बनेगा। इस कॉलेज पर 90 फीसद केंद्र सरकार और 10 फीसद जम्मू कश्मीर प्रशासन खर्च करेगा।

इसके साथ ही वर्तमान जिला अस्पताल कुपवाड़ा को ही रेफरल अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें आधारभूत ढांचा और मजबूत किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जम्मू कश्मीर के नए मेडिकल कॉलेजों के प्रशासन को कुपवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी मिलने का पत्र मिल गया। इस कॉलेज की घोषणा मेडिकल कॉलेज ऊधमपुर के साथ ही हुई थी, लेकिन कॉलेज के लिए पर्याप्त जगह न मिलने से इसे मंजूरी मिलने में देरी हुई।

यह केंद्र प्रायोजित योजना के तहत बनेगा। 325 करोड़ रुपयों में से 115 करोड़ रुपये प्रशासनिक और अकादमिक ब्लॉक के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। 80 करोड़ रुपये हॉस्टल और आवासीय सुविधाओं पर खर्च होंगे, जबकि 60 करोड़ रुपये वर्तमान जिला अस्पताल कुपवाड़ा में टीचिंग फैकल्टी को अपग्रेड करने पर खर्च होंगे। 70 करोड़ रुपयों से मशीनरी और उपकरणों की खरीदारी होगी।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव मांगे थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने ऊधमपुर, लेह और कुपवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल ढुल्लू ने कहा कि एक और मेडिकल कॉलेज मंजूर होने से जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। इससे यहां एमबीबीएस डॉक्टर अधिक बनेंगे, जिससे डॉक्टरों की कमी दूर होगी।

उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग की कम समय में भूमि की समस्या हल करने के लिए सराहना की। यह कॉलेज मंजूर होने से अब जम्मू कश्मीर में 10 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। यही नहीं दो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) खोलने के लिए भी काम चल रहा है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू, राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस श्रीनगर, जम्मू संभाग के कठुआ, राजौरी व डोडा और कश्मीर संभाग के बारामुला व अनंतनाग में मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी थी। डोडा को छोड़ कर अन्य सभी मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से कक्षाएं शुरू हो गई हैं। डोडा में अगले सत्र से कक्षाएं शुरू होने की उम्मीद है।

जान बचाने के लिए बस से उतरा शिक्षक, हाथी ने पटककर ली जान

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : उत्तराखंड स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) के मंदाल रेंज में टस्कर हाथी ने रामनगर-भौनखाल रोड पर यात्रियों से भरी बस पर ही हमला कर एक शिक्षक को पटककर मार डाला। शिक्षक बस से उतरकर जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की तरफ जाने का प्रयास कर रहा था। इस इलाके में टस्कर हाथी करीब डेढ़ साल से आए दिन उत्पात मचा रहा है। इसकी तलाश के लिए वन विभाग अब ड्रोन का सहारा लेने की योजना बना रहा है।

टस्कर हाथी एक साल के दरम्यान रामनगर क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा हमले कर चुका है। शनिवार सुबह करीब सवा छह बजे हाथी ने रामनगर से भराड़ी कपकोट (बागेश्वर) जा रही बस को निशाना बनाया। यह देख चालक ने बस रोक दी। ऐसे में पुरुष यात्री जान बचाने के लिए बस से उतरकर भागने लगे, जबकि महिला यात्री बस में ही बैठी रहीं। इसी बीच शिक्षक गिरीश चंद्र को टस्कर हाथी ने बस से उतरते ही सूंड से लपेट सड़क पर पटक दिया। इसके बाद हाथी ने बस के अगले शीशे तोड़ डाले। हाथी का उत्पात देख बस में बैठी महिलाएं रोने बिलखने लगीं। कुछ देर बाद हाथ जंगल की ओर चला गया।

जवाबी गोलाबारी में पाकिस्तान की छह चौकियां तबाह, दो सैनिक ढेर

जागरण संवाददाता, जम्मू

- पुंछ में भारतीय सेना की कार्रवाई में दर्जनों पाक सैनिकों के घायल होने की सूचना
- किरनी, कसबा, शाहपुर व गुनतरिया में तड़के से जारी थी पाक गोलाबारी
- पाक गोलाबारी में स्थानीय नागरिक घायल, दर्जन भर मकानों को नुकसान

जम्मू के पुंछ जिले में पिछले तीन दिन से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर लगातार जारी पाक गोलाबारी का भारतीय सेना ने रविवार देर रात करारा जवाब दिया है। शाहपुर सेक्टर के पार (पाकिस्तान में) भारतीय सेना ने पाक की छह चौकियों को तबाह कर दिया और दो पाक सैनिकों को भी मार गिराया। इसके अलावा दर्जनों पाक सैनिक घायल भी हुए हैं। देर रात तक गोलाबारी के चलते हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इससे पहले पाक गोलाबारी में एक भारतीय नागरिक घायल हुआ है। जबकि कई मकानों को नुकसान पहुंचा है।

जानकारी के अनुसार, शाहपुर सेक्टर में पाक सैनिक भारतीय चौकियों पर तड़के साढ़े तीन बजे गोलाबारी करने लगे। इसके बाद तीन और सेक्टरों कीरनी, कसबा, और गुनतरिया सेक्टर में भी तोपों से गोले दागने शुरू कर दिए। एलओसी से सटे गांवों में दर्जन भर मकानों को नुकसान पहुंचा। वहीं, 50 वर्षीय नागरिक जमाल दीन निवासी मोहला सकी वाला कसबा घायल हो गया। गोलाबारी के बीच घायल जमाल का जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद भी दिनभर चारों सेक्टरों में रुक-रुक गोलाबारी जारी रही। सूत्रों के अनुसार, भारत ने रविवार रात को जवाबी कार्रवाई करते हुए शाहपुर के सामने पाक के सैन्य ठिकानों पर भारी गोलाबारी की। इसमें छह चौकियां तबाह हो गई और पाक दो सैनिक मारे गए। जबकि दर्जन से अधिक घायल हो गए।

बताया जाता है कि भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पाक की एंबुलेंस घायल जवानों को ले जाती दिखीं। भारतीय सेना के बड़े अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पुंछ में कई दिन से गोलाबारी कर रहा है जिसे भारतीय सेना विफल रही है। सीमांत लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने रविवार को तोपों का इस्तेमाल किया, जिसकी रेंज कई दूर-दराज के इलाकों तक है। गोलाबारी की वजह से कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं।

कम बर्फबारी वाले क्षेत्रों से हो रही गोलाबारी

मौजूदा समय में जम्मू-कश्मीर में एलओसी पर भारी बर्फबारी हुई है। इसके चलते सभी रास्ते बंद हैं। इसलिए पाक सेना पुंछ से आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए उन जगहों को निशाना बना रही है जहां पर कम बर्फबारी हुई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद हताश पाक सेना लगातार तीन माह से लगातार गोलाबारी कर रहा है।

भोपाल गैस कांड

पूछा था भोपाल को बचाने का उपाय, यूका ने दिखाया मौत का रास्ता

भोपाल गैस हादसे को लेकर यूका में तैनात तत्कालीन एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट योगेंद्र शर्मा ने किया राजफाश, यूका प्रबंधन ने लोगों को घर से बाहर निकलने को कहा था, नहीं बताया था कि गीले कपड़े से आंख-मुंह ढंके

राजीव सोनी, भोपाल

भोपाल गैस कांड के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने यूनियन कार्बाइड (यूका) प्रबंधन से जब जहरीली मिथाइल आइसो सायनेट (एमआईसी) गैस से बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने लोगों को घरों से बाहर निकालने का सुझाव दे डाला। सरकार ने इस बारे में लाउड स्पीकर से उद्घोषणा करा दी। यह उपाय नागरिकों को मौत के रास्ते पर ले जाने वाला साबित हुआ और सैकड़ों लोग जहरीली गैस के सीधे संपर्क में आ गए। इसके विपरीत जो घरों में थे, उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।

पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली इस औद्योगिक त्रासदी के इस स्याह पक्ष का राजफाश यूनियन कार्बाइड प्लांट में पदस्थ तत्कालीन एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट योगेंद्र शर्मा (अब सेवानिवृत्त आईएएस) ने किया। गैस कांड की 35वीं बरसी पर 'नईदुनिया' से हुई विशेष चर्चा में उन्होंने इस सच्चाई से पर्दा हटाया। यह जानकारी अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं करने पर वे बोले कि हादसे के बाद फैक्टरी परिसर में रहकर मैंने अपनी सुरक्षा की खातिर सेफ्टी मेजर्स का अध्ययन किया तब यह जानकारी मिली, और तब तक देर हो चुकी थी। बाद में उनसे कोई पूछताछ भी नहीं हुई, जिससे यह तथ्य बाहर नहीं आ पाया।

योगेंद्र शर्मा नईदुनिया

बड़े हादसे के लिए नहीं था वह उपाय : उन्होंने बताया कि हादसे वाली रात में प्रशासन ने 'यूका' से बचाव का रास्ता पूछा तो प्रबंधन ने महज फैक्टरी मेन्युअल पढ़ दिया जबकि वह उपाय छोटी-मोटी गैस लीकेज के संदर्भ में परिसर खाली करने के लिए था। एमआईसी गैस का भूमिगत टैंक फटने और करीब 40 टन गैस रिसाव से वह इलाका गैस चेंबर में तब्दील हो गया था। पांच लाख लोग गैस के प्रभाव में आए, ऐसी दुर्घटना के लिए वह उपाय कारगर नहीं था। इससे तो सैक्ड़ों लोग उस रात को जहरीली गैस की चपेट में आ गए। प्रशासन की उद्घोषणा (एनाउंसमेंट) के बाद पुराने शहर के बाशिंदे घरों को छोड़कर भाग गए। उस वक्त यूका की ओर से दूसरा उपाय नहीं बताया गया कि गैस से बचने के लिए 'गीले कपड़े से आंख-मुंह ढंक लें।' जिन लोगों ने अपनी समझ से ऐसा किया वे बच गए।

हेलीकॉटर से कराई थी बारिश : शर्मा ने बताया कि उनके स्वास्थ्य को लेकर परिजन चिंतित थे, लेकिन तब डॉ. लोया, एचएस त्रिवेदी, योगीराज शर्मा, वायके चुघ व अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों के चलते वे आश्वस्त रहे। ये सभी 7-8 दिन तक लगातार हमीदिया अस्पताल में ही मरीजों के इलाज में व्यस्त रहे। 'ऑपरेशन फैथ' के दौरान हेलीकॉप्टर से फैक्टरी परिसर के आसपास बारिश कराई गई। यूका में बची जहरीली 'एमआईसी' गैस को खत्म करने 'सेविन और टेमिक' नामक कीटनाशक का निर्माण कराया गया तब भी शहर में हड़कंप मचा और लोग बसों में बैठकर पलायन कर गए।

सीएम-मुख्य सचिव भी यूका पहुंचे

जीवन के सबसे कटु अनुभव के बारे डॉ. योगीराज शर्मा और योगेंद्र शर्मा ने बताया कि हादसे के बाद तत्कालीन मुख्य सचिव ब्रह्मस्वरूप और मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भी यूका परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भोपाल आए, उसके पहले अस्पताल की सफाई और मृतकों का सामूहिक दाह संस्कार हुआ। ये दृश्य आज आंखों में हैं। डॉ. योगीराज शर्मा बताते हैं कि एनाउंसमेंट से मची भगदड़ से लोगों के फेफड़ों में ज्यादा गैस भर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के चार-पांच माह बाद उनकी बेटी का जन्म हुआ, जो 34 साल के बाद भी बोल नहीं पाती है। वह सेरीब्रल पाल्सी से पीड़ित है।

बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या, 1745 ने किए करतारपुर साहिब के दर्शन

पाकिस्तान में स्थित टिकट काउंटर पर जांच के लिए खड़े गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालु। रविवार को 1745 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। जागरण

संस, डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर) : डेरा बाबा नानक में बनाए कॉरिडोर के रास्ते गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। 1745 श्रद्धालुओं ने रविवार को सीमा पार जाकर गुरुद्वारा साहिब के दर्शन किए। हालांकि पाकिस्तान की ओर से 2024 श्रद्धालुओं को मंजूरी दी गई थी। रविवार को एक दिन में सबसे अधिक श्रद्धालु पैसेंजर टर्मिनल पर पहुंचे। उद्घाटन के 23 दिन बाद 12774 श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर चुके हैं। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन कर लौटे पूर्व सरपंच गुरदेव सिंह, ने बताया कि रविवार को करतारपुर टर्मिनल में कई श्रद्धालुओं की पीटीए फार्म में फोटो धुंधली थी, जिस कारण उन्हें जाने से रोक दिया गया।

33 आवेदन पहुंच चुके हैं शिमला में आवारा कुत्तों को गोद लेने के। नगर निगम द्वारा लावारिस कुत्तों से निपटने के लिए बनाई गई नीति में कुत्ता गोद लेने वालों की पार्किंग स्लॉट और कूड़े की फीस माफ होगी।

जमीयत भी दाखिल कर सकता है पुनर्विचार याचिका

तैयारियां पूरी ▶ अयोध्या मामले में सोमवार को या एक-दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकती है याचिका

नौ दिसंबर को समाप्त हो रही है 30 दिनों की अवधि

माला दीक्षित, नई दिल्ली

राम जन्मभूमि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद सोमवार को या एक-दो दिनों में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है। इसकी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। पुनर्विचार याचिका 30 दिनों के अंदर दाखिल करनी होती है, जिसकी अवधि नौ दिसंबर को खत्म हो रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और हाशिम अंसारी ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इन्कार कर दिया था। हालांकि, जमीयत उलेमा ए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ अन्य मुस्लिम पक्षकारों ने फैसले पर सवाल उठाते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की घोषणा की है।

सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गत नौ नवंबर को सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी थी। पीठ ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह अयोध्या अधिग्रहण कानून-1993 के प्रावधानों के मुताबिक एक ट्रस्ट गठित करे और उसे पूरी विवादित जमीन, अंदर का अहाता और बाहर का अहाता सौंपे। ट्रस्ट को उस जमीन पर मंदिर निर्माण का अधिकार होगा। हालांकि, कोर्ट ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने को गैरकानूनी माना था। कोर्ट ने मुसलमानों को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में ही किसी अन्य प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया था।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव वकील जफरयाब जिलानी ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की घोषणा की थी। उधर, जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करने और पुनर्विचार याचिका की संभावनाएं तलाशने के लिए 14 नवंबर को पांच सदस्यीय समिति बनाई थी। समिति को जिम्मेदारी दी गई थी कि वह कानूनविदों से बातचीत कर जमीयत को रिपोर्ट सौंपे। समिति ने 17 नवंबर को अपनी रिपोर्ट जमीयत को सौंपी, जिसमें पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की सलाह दी गई है। इसके बाद जमीयत ने पुनर्विचार याचिका की तैयारी शुरू कर दी। अब याचिका का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। पूरी संभावना है कि याचिका सोमवार को या एक-दो दिन में दाखिल कर दी जाएगी। जमीयत का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में माना है कि वहां मस्जिद थी और वहां नमाज होती थी तो फिर मुसलमानों को हक क्यों नहीं दिया गया?

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा-पुनर्विचार याचिका के पक्ष में हैं ज्यादातर मुस्लिम

लखनऊ, प्रेट्र : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि देश के ज्यादातर मुस्लिम अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने के पक्ष में हैं। बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी ने कहा है-हमें आशंका है कि हमारी याचिका ठुकरा दी जाएगी, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे दायर भी न करें। हालांकि मामले के प्रमुख पक्षकार रहे उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका नहीं दाखिल करने का निर्णय लिया है। बता दें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 9 दिसंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। इस सवाल पर कि कई लोग कह रहे हैं कि मसले को यहीं खत्म कर दिया जाए, मौलाना ने कहा कि ये वे लोग हैं, जिन्होंने मुकदमे में कोई योगदान नहीं दिया।

नकवी बोले-अयोध्या मुद्दे को उलझाए रखना चाहते हैं कुछ लोग

नई दिल्ली, प्रेट्र : अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा कि कुछ लोग अयोध्या मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। इस मसले पर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के पुनर्विचार याचिका दायर करने के फैसले की आलोचना करते हुए नकवी ने कहा कि दोनों संगठन समाज को बांटने और टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

नकवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी वर्गों ने स्वागत किया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा ने भी फैसले को स्वीकार किया था। नकवी ने तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं बाद में इन दोनों को कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ कि अब वो पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रहे हैं।

पीटीआइ के साथ बातचीत में भाजपा नेता ने एक सवाल पर कहा कि अगर कोई इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है तो वो अपने घरों में ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लिए यह मुद्दा अब खत्म हो गया है। मुस्लिम समाज इस फैसले को स्वीकार कर आगे बढ़ गया है। उसके लिए बाबरी (मस्जिद) से ज्यादा अहम शिक्षा और आर्थिक व सामाजिक विकास के क्षेत्र में बराबरी का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि दशकों पुराने विवाद का सर्वसम्मति से निपटारा हो गया है और अब उसे फिर से उलझाने का प्रयास नहीं होना चाहिए।

बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा ने कहा है कि पुनर्विचार याचिका का मसौदा तैयार है और नौ दिसंबर से पहले उसे दाखिल कर दिया जाएगा।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का पहुंचे और उमरा अदा किया। उन्होंने अपना वीडियो ट्विटर अकाउंट पर डाला है। अपने ट्वीट में नकवी ने लिखा है कि मक्का मुकर्रमा में उमरा अदा किया। उमरा, सऊदी अरब के लिए इस्लामी तीर्थयात्रा है। प्रेट्र

पुनर्विचार याचिका मुस्लिम संगठनों का दोहरा रवैया : श्री श्री

जागरण संवाददाता, कोलकाता

अयोध्या फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआइएमपीएलबी) और जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के फैसले को अध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने दोहरा रवैया करारा दिया है। उन्होंने कहा कि अब हिंदू और मुसलमानों को देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए।

महानगर के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आर्ट ऑफ लीविंग के कार्यक्रम 'व्यक्ति विकास से राष्ट्र विकास' का उद्घाटन करने पहुंचे श्री श्री रविशंकर ने समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि स्वाभाविक रूप से हर किसी को एक फैसले से खुश नहीं किया जा सकता है, लोगों की अलग राय हो सकती है, लेकिन जो लोग पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रहे हैं मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि ये वही लोग हैं जो पहले कहा करते थे कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करेंगे। यह लोग दोहरा रवैया अपना रहे हैं। बता दें कि एआइएमपीएलबी ने छह दिसंबर से पहले श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है।

यह जिद की मस्जिद वहीं बनाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता : द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री अयोध्या विवाद में मध्यस्थता कमेटी के सदस्य रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हां, मैं अयोध्या के फैसले से खुश हूं। मैं 2003 से यह बता रहा हूं कि दोनों समुदायों को इस पर मिलकर हल निकालना चाहिए। एक तरफ मंदिर का निर्माण और दूसरी तरफ मस्जिद का निर्माण हो सकता था लेकिन यह जिद की मस्जिद वहीं बनाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता।

जन्मभूमि के साथ ही बहुरेंगे नाभि-नाल स्थल के दिन

आनंदमोहन, अयोध्या

▶ भगवान राम की नाभि-नाल से जुड़ी विरासत पर बने यह स्थल

▶ आइजीआरएस में नार कुंड संबंधी शिलालेख का उल्लेख

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रामजन्मभूमि पर भव्यतम राममंदिर निर्माण के साथ ही गुप्तारघाट से तिहुरा माझा क्षेत्र तक टूरिस्ट सिटी के लिए मास्टर प्लान बनाने की कवायद लखनऊ से दिल्ली तक तेज है। इसी के साथ रामनगरी को संवारे जाने के प्रयासों के बीच भगवान राम की नाभि-नाल से जुड़े एक पौराणिक कुंड के सुंदरीकरण की उम्मीद जगी है। एकीकृत समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आइजीआरएस) पर भी इस मुद्दे का उल्लेख किया गया है। यह बताते हुए कि भगवान राम की नाभि-नाल इसी जिला के पूराबाजार ब्लॉक के ग्राम नरियावां में गड़े होने की मान्यता है। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी आरपी यादव के अनुसार, अगले वित्तीय वर्ष में संबंधित पौराणिक कुंड के सुंदरीकरण का प्रस्ताव जिला योजना में शामिल किया जाएगा। आइजीआरएस में पौराणिक कुंड का नाम नरकुंड एवं उसी कुंड के नाम पर गांव का नाम नरियावां होने का उल्लेख है। शिकायत में पौराणिक कुंड का शिलालेख एवं उस कुंड कर पक्की सीढ़ियों की मौजूदगी का हवाला है।

भव्यतम राम मंदिर की कामना के लिए हनुमानगढ़ी में यज्ञ

जागरण संवाददाता, अयोध्या : हनुमानगढ़ी में भगवान राम के भव्यतम मंदिर निर्माण के लिए यज्ञ जारी है। इसका संचालन संत राजू दास कर रहे हैं। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्त्रोत की तीन आवृत्तियों का पारायण होता है और राम जन्मभूमि पर दुनिया के भव्यतम मंदिर निर्माण की कामना के साथ आहुतियां समर्पित की जाती हैं। साधु-संतों के अलावा आरएसएस और भाजपा के दिग्गज यज्ञ में समिधा डाल चुके हैं। भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल का नाम भी कतार में शामिल है। युवा संत राजूदास ने मंदिर निर्माण से जुड़ी साध पूरा करने के लिए नियमित यज्ञ का सिलसिला 2012 में शुरू किया। आचार्य सतीश वैदिक के साथ मिलकर राजूदास ने इसे आगे बढ़ाया। सतीश वैदिक ने बताया कि लंका में रावण का वध करने के पहले भगवान राम ने सूर्यदेव की उपासना की थी। इसी वजह से भव्यतम राम मंदिर निर्माण के स्वप्न को साकार करने के लिए इसी स्त्रोत के मंत्रों से आहुति डाली जा रही है।

रामकी पैड़ी बनेगी नित्य रामलीला की गवाह

जागरण संवाददाता, अयोध्या : रामनगरी का आकर्षण बढ़ाने की योजना के तहत रामकी पैड़ी पर प्रतिदिन लेजर-शो होगा। पूरा शो लाइट एवं साउंड सिस्टम पर आधारित होगा। अयोध्या आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु इसका आनंद ले सकेंगे। दीपोत्सव पर होने वाले लेजर-शो की तरह ही होने वाले इस कार्यक्रम में पैड़ी के मंदिरों पर रामलीला का दृश्यांकन होगा। नगर निगम ने इसके लिए कार्ययोजना फाइनल कर ली है। शो के जरिए भगवान राम से जुड़े प्रसंगों को प्रस्तुत करने के साथ ही अयोध्या का परिचय भी कराया जाएगा। नगर आयुक्त डॉ. नीरज शुक्ला ने बताया कि यह शो एक से दो घंटे का होगा। नगर निगम प्रयास कर रहा है कि अगले साल रामनगरी में लाइट एवं साउंड शो पर्यटकों को सुलभ हो सके। शो देखने में पर्यटकों को कोई असुविधा न हो इसके लिए पैड़ी पर 250 लोगों के बैठने का भी इंतजाम होगा।

न्यूज गैलरी

आइआइटी रुड़की में तीन को मिला 1.54 करोड़ का पैकेज

रुड़की : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) रुड़की में रविवार को कैंपस प्लेसमेंट के पहले दिन कुल 322 छात्रों को जॉब के ऑफर मिले। तीन छात्रों को 1.54 करोड़ का सालाना पैकेज मिला है। इनमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और फिजिक्स के छात्र शामिल हैं। बता दें कि यह आइआइटी रुड़की में अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। इससे पहले पिछले साल तीन छात्रों को 1.39 करोड़ का पैकेज मिल चुका है। आइआइटी रुड़की में रविवार से कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो गया। पहले दिन कैंपस प्लेसमेंट में शामिल होने के लिए कुल 30 कंपनियां पहुंची। इन कंपनियों की ओर से कुल 322 ऑफर दिए गए। इनमें 10 अंतरराष्ट्रीय ऑफर शामिल हैं। वहीं, इस साल कैंपस प्लेसमेंट में संस्थान के तीन छात्रों को पहले दिन 1.54 करोड़ का सालाना पैकेज मिला। जो अभी तक का उच्चतम पैकेज है। (जासं)

चित्रकूट : भगवा रंग में दिखेगा कामदगिरि परिक्रमा पथ

चित्रकूट : पर्यटन विभाग कामदगिरि परिक्रमा पथ (चित्रकूट) के मठ मंदिरों व भवनों को भगवा रंग में रंगने की तैयारी कर है। इसके लिए दो करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेजा है जिसमें सिर्फ रंगाई ही नहीं और भी तमाम कार्य कराएं जाएंगे। तपोभूमि में प्रति माह लाखों श्रद्धालु मंदाकिनी स्नान के बाद कामदगिरि की परिक्रमा लगाते हैं। सबसे अधिक भीड़ परिक्रमा पथ पर रहती है। अमावस्या के विशेष पर्व दीपावली, भदई और श्रावणी मेले में यह संख्या 30 से 35 लाख तक पहुंच जाती है। (जासं)

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक महिला नक्सली गिरफ्तार

दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में रविवार को पुलिस ने एक महिला नक्सली को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान गंगी (20) पुत्री सन्नू मुचाकी के रूप में की गई। वह नक्सलियों की अपील पर मनाए जा रहे विरोध सप्ताह के लिए ग्रामीणों को एकत्र करने निकली थी। एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि वह चेतना नाट्य मंडली (सीएनएम) की सक्रिय सदस्य है। (नईदुनिया)

प्रयागराज में उठा काशी-मथुरा की मुक्ति का मुद्दा

ज्ञानेंद्र सिंह, प्रयागराज

विहिप (विश्व हिंदू परिषद) के अध्यक्ष रहे अशोक सिंहल की पुण्यतिथि पर रविवार शाम आयोजित व्याख्यान में काशी और मथुरा के मंदिरों का मुद्दा उठा। प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में जय श्रीराम के साथ हर-हर महादेव का उद्घोष भी हुआ। राज्यसभा सदस्य डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने यहां तक कहा कि केंद्र सरकार श्रीकृष्ण जन्मस्थान और विश्वनाथ मंदिर के लिए जमीन अधिगृहीत करे। संविधान में इसके लिए प्राविधान भी है। मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने भी डॉ. स्वामी का समर्थन किया।

अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ की ओर से आयोजित 'धर्म : समग्र विकास का सनातन मार्ग' विषयक व्याख्यानमाला में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.जोशी ने 'धर्म के मूल को कैसे समझें' के बारे में बताया। कहा कि अंग्रेजी इतिहासकारों ने धर्म को संकुचित रूप देकर उसे रिलीजन का पर्याय बता दिया, जबकि धर्म व्यापक विचारधारा है। धर्म सनातन है। अन्य सभी रिलीजन जैसे यहूदी, ईसाई, इस्लाम आदि यह मानते हैं कि कोई सत्ता इस सृष्टि के बाहर की है जो धरती को चलाती है और वह अपना मसीहा भेजकर यहां शासन चलाता है। लेकिन धर्म यह नहीं मानता। धर्म को इस सृष्टि के बाहर से कोई नहीं चलाता, बल्कि यह सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुआ है। यह सभी को समाविष्ट करता है। पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता और न ही किसी से विरोध होता है। आज मनुष्य के धर्म से नहीं चलने के कारण विसंगतियां, हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ गई हैं, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध बढ़े हैं। समाज को फिर से धर्मानुशासित करने की आवश्यकता है। अध्यक्षता करते हुए पूर्व केंद्रीय विधि व वाणिज्य मंत्री डॉ.सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि धर्म आस्था से जुड़ा हुआ है और बिना आस्था के धर्म नहीं हो सकता। धर्म के क्रियान्वयन के समय यह ध्यान रखना चाहिए।

अशोक सिंहल की पुण्यतिथि पर रविवार को प्रयागराज में व्याख्यानमाला को संबोधित करते पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी (बाएं)। साथ में राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी (दाएं)। शरद मालवीय

प्रयागराज के परेड मैदान से बड़ा संदेश

प्रयागराज में रविवार को परेड मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रयाग महानगर की ओर से आयोजित शाखा कुंभ में लगा यह कटआउट आकर्षण का केंद्र रहा। प्रभु श्रीराम, स्वामी विवेकानंद के साथ संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर का चित्र गहरे निहितार्थ का संकेत दे रहा है। मुकेश कनौजिया

ले. जनरल ओपी कौशिक का निधन

जागरण संवाददाता, देहरादून : कई मोर्चों पर दुश्मन के हौसले पस्त करने वाले देहरादून निवासी ले. जनरल (सेनि.) ओपी कौशिक का शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के आरआर अस्पताल में अंतिम सांस ली। सोमवार को नई दिल्ली स्थित सेना के बराड़ स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार होगा। मूल रूप से हरियाणा के झज्जर निवासी ले. जनरल (सेनि.) ओपी कौशिक करीब चार दशक से देहरादून की विजय कॉलोनी में रहते थे। वह राजपूताना राइफल्स की बैठक के लिए 23 नवंबर को दिल्ली गए थे। इस दौरान रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई। जिस पर उन्हें मेरठ के मेट्रो अस्पताल और फिर दिल्ली स्थित सेना के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां शनिवार रात करीब सवा दस बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। ले. जनरल (सेनि.) ओपी कौशिक ने 1962, 1965, 1971 व 1999 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के कुलपति भी रहे।

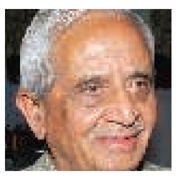

ले. जनरल (सेनि) ओपी कौशिक। फाइल

शुभ्रा कुंडू पर ईडी के शिकंजे से बढ़ सकती है राजनीतिज्ञों की बेचैनी

रोजवैली घोटाला

▶ गौतम कुंडू की पत्नी शुभ्रा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद विदेशी संपत्तियों की जांच की तैयारी

▶ नौकरशाही और राजनीतिक हलकों में ऊंची पहुंच रखती हैं शुभ्रा

जागरण संवाददाता, कोलकाता

रोजवैली चिटफंड घोटाले के सरगना गौतम कुंडू की पत्नी एवं बांग्ला अभिनेत्री शुभ्रा कुंडू पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का कसता शिकंजा उनके करीबी बंगाल के राजनीतिज्ञों की बेचैनी बढ़ा सकता है। यही वजह है कि ईडी ने शुभ्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवा कर उनकी विदेशी संपत्तियों की जांच करने पर विचार करना शुरू कर दिया है। आशंका है कि शुभ्रा ने पति द्वारा चिटफंड के जरिए कमाई गई रकम को मनी लांड्रिंग के जरिए विदेश भेजकर संपत्ति खरीदने में उसका प्रयोग किया है।

गौरतलब है कि 15 हजार करोड़ से अधिक के रोजवैली चिटफंड घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद ग्रुप के चेयरमैन एवं घोटाले के सरगना गौतम कुंडू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके अलावा सीबीआइ और ईडी ने हाई प्रोफाइल जांच के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं से भी मैराथन पूछताछ की थी। इस दौरान तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और विधायक तापस पाल को भी जेल भेज दिया गया था। लेकिन बाद में उक्त दोनों को अदालत ने जमानत दे दी। जांच एजेंसियों ने गौतम कुंडू द्वारा फाइनेंस की गई बांग्ला फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी और रितुपर्णा सेनगुप्ता से भी पूछताछ की थी। ईडी ने रोजवैली के साथ लेनदेन में तृणमूल सांसद एवं अभिनेत्री शताब्दी राय को भी तलब किया था। हालांकि शताब्दी ने रोजवैली से मिले रुपये को ईडी को लौटा दिए थे। चिटफंड घोटाले में कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार, आइपीएस दमयंती सेन को भी नोटिस भेजकर तलब किया गया था। रोजवैली से स्पांसरशिप मांगने के लिए आइपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के सीइओ वेंकी मैसूर से भी पूछताछ की जा चुकी है। गौतम कुंडू द्वारा चिटफंड के जरिए कमाई रकम को हवाला के माध्यम विदेश भेजने का सुराग मिलते ही ईडी ने गौतम की पत्नी एवं बांग्ला अभिनेत्री शुभ्रा कुंडू को भी जांच के दायरे में ले लिया था।

सूत्रों के अनुसार, ईडी का आशंका थी कि जांच से बचने के लिए नीरव मोदी, विजय माल्या की तरह शुभ्रा कुंडू भी विदेश भाग सकती है, इसके चलते बीते शुक्रवार को ईडी ने शुभ्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवा दिया था। इसके बाद ही ईडी ने कोलकाता के साउथ सिटी स्थित उनके आवास पर छापेमारी की थी। ईडी सूत्रों के अनुसार रोजवैली के आभूषण व्यवसाय को शुभ्रा देखती थीं। उम्मीद है कि पति गौतम के मनी लांड्रिंग रैकेट के बाबत वह कुछ बता सकती हैं। क्योंकि नौकरशाही और राजनीतिक हलकों में ऊंची पहुंच के लिए जानी जाने वाली शुभ्रा अपने पति को पर्दे के पीछे से मदद पहुंचा रही थी।

सूत्रों की माने तो वर्ष 2017 में ईडी के तत्कालीन जांच अधिकारी मनोज कुमार के साथ शुभ्रा को दिल्ली के होटल और एयरपोर्ट में भी देखा गया था। जांच प्रभावित करने के मकसद से शुभ्रा ने कई मर्तबा मनोज के साथ मुलाकात की थी। शुभ्रा को दिल्ली में एक पूर्व सीबीआइ निदेशक से भी मिलवाया गया था। वह पति गौतम के करीबी सहयोगियों के साथ भी नियमित संपर्क में थी, जो धन की निकासी में शामिल थे। सूत्रों के अनुसार ईडी ने रोजवैली का शीघ्र खुलासा करने के लिए गौतम कुंडू के साथ ही शुभ्रा कुंडू पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

शुभ्रा कुंडू। फाइल

सीएम रीप : पौराणिकता के साथ आधुनिकता का संगम

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तरप्रदेश सरकार की प्राथमिकता अयोध्या को 'इक्ष्वाकुपुरी' के रूप में विकसित करना है। सरकार की कोशिश है कि अयोध्या को विश्व मानचित्र पर एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित किया जाए। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कंबोडिया के शहर सीएम रीप की तर्ज पर अयोध्या को विकसित करने की कार्ययोजना पेश की है। सीएम रीप आधुनिकता और प्राचीनता का मिश्रण है। जहां प्राचीन मंदिरों के साथ आधुनिक सुख सुविधाएं भी मौजूद हैं।

कंबोडिया के सीएम रीप में मंदिर का शानदार दृश्य (फाइल फोटो)।

अंकोर क्षेत्र का प्रवेश द्वार

सीएम रीप उत्तरी पश्चिमी कंबोडिया के सीएम रीप प्रांत की राजधानी है। इसे अंकोर क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहां से साढे पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अंकोर क्षेत्र। खामेर भाषा में अंकोर का अर्थ होता है राजधानी। यह खामेर साम्राज्य की राजधानी थी। अंकोर क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहां आते हैं। बारहवीं सदी में बने अंकोर के मंदिर आध्यात्मिक केंद्र हैं। ये विशाल मंदिर खामेर साम्राज्य के समय बनवाए गए थे और अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं।

इतिहास के झरोखे से सीएम रीप

नवीं से 13वीं सदी का दौर सीएम रीप का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस दौर में खामेर साम्राज्य ने कंबोडिया के साथ ही थाइलैंड, लाओस और म्यांमार तक अपना विस्तार कर लिया था। सीएम रीप में उस वक्त लाखों लोग रहते थे। इसके सबसे यशस्वी शासक जयवर्मन सप्तम थे जिन्होंने 1181 से 1215 तक शासन किया। कहा जाता है कि अंकोर का वास्तविक नाम यशोधरपुर है। खामेर साम्राज्य 1431 तक रहा। अंकोर की संस्कृति बहुत हद तक भारत से मिलती जुलती है। जानकारों के मुताबिक यह लंबे व्यापारिक संबंधों के चलते है।

कंबोडिया के सीएम रीप का एक बाजार (फाइल फोटो)।

आधुनिकता में भी नहीं है पीछे

आज सीएम रीप आधुनिकता में किसी से पीछे नहीं है। अंकोर जहां एक प्राचीन नगर है तो वहीं पर सीएम रीप आधुनिक सुख सुविधाओं को स्वयं में समेटे हर पर्यटक के लिए बाहें बिछाए खड़ा है। यह कंबोडिया का सबसे तेजी से विकसित होता शहर है। एयरपोर्ट से लेकर बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स की यहां कोई कमी नहीं है।

हिंदू पौराणिक कथाओं का चित्रण

अंकोर क्षेत्र में मंदिर करीब 200 हेक्टेयर में फैले हैं। अंकोर दुनिया का सबसे विशाल धार्मिक स्मारक है। मान्यता है कि इन्हें पूर्व में हिंदू मंदिरों के रूप में निर्माण किया गया था और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित थे। 14वीं शताब्दी में भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। इन मंदिरों में समुद्र मंथन सहित कई हिंदू पौराणिक कथाओं का चित्रण किया गया है। यहां पर करीब सौ मंदिर हैं।

फ्रांसीसियों ने लौटाया खोया वैभव

बीसवीं शताब्दी तक सीएम रीप अपना वैभव खो चुका था। इसके बाद फ्रांसीसियों ने इसके पुनरुत्थान का बीड़ा उठाया। इसके बाद मंदिरों को फिर से खोजा गया और पर्यटकों की आवक शुरु हुई। 1929 में यहां पहला होटल खुला और धीरे-धीरे दुनिया के नक्शे पर छा गया। 1953 में फ्रांस के शासन से आजादी के बाद भी सीएम रीप का तेजी से विकास हुआ।

दैनिक जागरण

प्रार्थना हृदय की पुकार है

राज्यों का रवैया

यह बात सामने आने पर हैरानी नहीं कि प्रदूषण की रोकथाम के मामले में राज्यों का रवैया बेहद लापरवाही भरा है। यदि उत्तर भारत को वायु प्रदूषण से निजात नहीं मिल पा रही है तो इसी कारण कि संबंधित राज्य सरकारें प्रदूषण रोधी उपायों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। चूंकि राज्य सरकारों के साथ उनकी एजेंसियां भी अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं इसलिए स्थानीय निकाय भी कुछ करने के लिए सक्रिय नहीं होते। वैसे भी यह किसी से छिपा नहीं कि वे अपना तय काम मुश्किल से ही करते हैं। यदि वे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के अड्डों के तौर पर जाने जाते हैं तो अपने नाकारापन के कारण ही। वे घटिया राजनीति के गढ़ भी बन गए हैं और इसी कारण कई बार यह सामने आता है कि अगर स्थानीय निकाय पर राज्य में सत्तारूढ़ दल से इतर दल का वर्चस्व हो तो शासन की अपेक्षाओं की भी अनदेखी होती है। इस सबका ही यह नतीजा है कि छोटे-बड़े शहरों में वे सारी गतिविधियां बिना रोक-टोक जारी रहती हैं जो हर तरह के प्रदूषण को जन्म देती हैं।

वास्तव में सभी को यह समझने की जरूरत है कि प्रदूषण और खासकर वायु प्रदूषण पर तब तक प्रभावी लगाम नहीं लग सकती जब तक स्थानीय निकाय प्रदूषण फैलाने वाले कारणों का निवारण करने के मामले में सजगता का परिचय नहीं देते। वे सजग हों, इसके लिए राज्य सरकारों को अपना रवैया बदलना होगा। यह अपेक्षा इसलिए, क्योंकि बीते दो-तीन वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि केंद्र सरकार अक्टूबर-नवंबर में राज्यों को इसके लिए आगाह करती है कि पराली जलने न पाए, लेकिन होता वही है जो दशकों से होता चला आ रहा है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को पराली दहन को लेकर आगाह करने का काम राष्ट्रीय हरित अधिकरण की ओर से भी किया जाता है, लेकिन वह भी काम नहीं आता। आखिर यह लापरवाही की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है कि इस बार भी पंजाब, हरियाणा समेत कुछ और राज्यों में पराली जली? इस साल हरियाणा में तो तब भी गनीमत रही, लेकिन पंजाब में पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा पराली दहन हुआ। इससे यही पता चलता है कि राज्य सरकारें वायु प्रदूषण से निपटने के मामले में राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय नहीं दे रही हैं। उनकी अनिच्छा का नकारात्मक असर स्थानीय निकायों पर दिखता है। यदि यह समझा जा रहा है कि सब कुछ केंद्र सरकार कर सकती है तो यह सही नहीं। वायु प्रदूषण से छुटकारा तो तभी मिल सकता है जब सभी अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। निःसंदेह इसमें आम आदमी भी शामिल हैं।

पंचायतों की मजबूती

उत्तराखंड में शहरी निकायों और पंचायतों की व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय निकायों और पंचायतों को धन आवंटन की व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन इसके बाद भी उनकी हालत में अपेक्षित बदलाव नहीं हो पाया है। अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में शहरीकरण की दर काफी तेज है। अर्द्धशहरी क्षेत्रों में तेजी से इजाफा होने की वजह से सरकार को शहरी निकायों की संख्या बढ़ानी पड़ी है। इन क्षेत्रों में जन सुविधाओं को बढ़ाने का दबाव ज्यादा है, लेकिन निकाय इस बदलाव के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। कमोबेश यही हाल त्रिस्तरीय पंचायतों का है। इनका सांगठनिक ढांचा बेहद लचर है। एक ओर निकायों और पंचायतों के माध्यम से सरकार नीति नियोजन को निचले स्तर पर मजबूत करने का दावा तो करती है, लेकिन हकीकत जुदा है। हालांकि केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के चलते निकायों और पंचायतों को वित्तीय संकट से काफी हद तक निजात मिली है। केंद्र सरकार से दी जाने वाली धनराशि सीधे निकायों और पंचायतों को ट्रांसफर होने लगी है। इसमें देरी होने पर राज्य सरकार के साथ ही संबंधित महकमों की जवाबदेही बढ़ गई है। बावजूद इसके विकास कार्यों के लिए मिलने वाली धनराशि का समयबद्ध सदुपयोग करने में तमाम निकाय और पंचायतें अक्षम साबित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण जनता से सीधे जुड़ी इन छोटी सरकारों को मजबूत करने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई है। सड़कों, पेयजलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, आवास निर्माण, स्वच्छकों की नियुक्ति, ढांचे को दुरुस्त करने समेत जनसंख्या नियोजन को लेकर निकायों और पंचायतें सरकार का मुंह तकने को विवश हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव होने पर दोनों संस्थाएं अपनी अहम और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को सशक्त तरीके से अंजाम देंगी। पांचवें राज्य वित्त आयोग ने निकायों और पंचायतों के ढांचे के सरलीकरण और उसे दुरुस्त करने के साथ ही मौजूदा वित्तीय व्यवस्था में सुधार के संबंध में आम नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों के आधार पर आयोग निकायों और पंचायतों के संबंध में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा। हालांकि सुझावों और विचारों की भागीदारी की इस प्रक्रिया में अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ भी विस्तार से चर्चा की जानी है। आयोग की रिपोर्ट निकायों और पंचायतों को दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगी, ऐसी स्वाभाविक अपेक्षाएं हैं।

वास्तव में राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों और पंचायतों को मजबूत करने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई है

महिलाओं के लिए कब सुधरेंगे हालात

अद्वैता काला

हैदराबाद की पीड़िता न केवल उन दरिंदों की शिकार हुई जिन्होंने उसकी देह की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि वह उस तंत्र से भी प्रताड़ित हुई जिसने उसके जीवन की परवाह नहीं की

हैदराबाद की एक हृदयविदारक घटना से मन बेहद व्यथित है। वहां एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या से पूरा देश आक्रोशित है। उस 26 वर्षीय युवती ने अभी अपनी जिंदगी ढंग से शुरू ही की थी। आम हिंदुस्तानी मध्यमवर्गीय परिवार की उस लड़की से मेरा कोई निजी परिचय नहीं था, लेकिन उसने पशु चिकित्सक का जो पेशा चुना उससे यही आभास होता है कि वह करुणा भाव से भरी थी। ऐसा इसलिए, क्योंकि इस काम में बेजुबानों के दुखदर्द को समझकर उनका इलाज करना पड़ता है और यह कोई खास किस्म का शख्स ही कर सकता है।

बीते गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात उसके साथ जो हैवानियत हुई, वह मानवता को शर्मसार करने वाली है। उससे भी ज्यादा हमारा रवैया निराश करने वाला रहा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हम खामोश रहे। समूचा तंत्र, पूरा समाज और जिन्हें उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, वे मौन रहे। जिस दिन उसका जला हुआ शव मिला, तब क्या हुआ? जनता की प्रतिनिधि लोकसभा ने एक पल के लिए उस पर चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। न उसके साथ हुई बर्बरता की भर्त्सना में एक शब्द फूटा और न ही उसके शोकसंतप्त परिवार को कोई दिलासा दिया गया। जब ऐसी बर्बरता के बावजूद लोकसभा में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कोई चर्चा तक न की जाए, तब आखिर महिलाओं को क्या करना चाहिए कि उनके मुद्दों पर सुनवाई हो?

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाना तो दूर हमारे नेता उल्टे पीड़ितों पर सवाल दागने लगते हैं। जब भी महिलाओं के खिलाफ ऐसा कोई अपराध होता है तो किसी न किसी नेता की जुबान जरूर फिसलती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ जब तेलंगाना के गृहमंत्री ने कहा कि उनके जैसी पढ़ी-लिखी महिला डॉक्टर ने भी पुलिस को फोन करने के बजाय अपनी बहन को क्यों फोन किया। यह एक तरह से अपने पाले में किया गया गोल था। मानों इतना ही काफी नहीं था। बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी परिवार को तमाम परेशानियां झेलनी पड़ीं। यह दर्शाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायत को लेकर प्रशासन कितना नाकारा और निर्दयी होने के साथ-साथ असंवेदनशील भी है। पीड़िता का परिवार रात ग्यारह बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन उनकी गुमशुदा बेटी की तलाश के लिए निकलने में पुलिस को सुबह तीन बज गए। इस दौरान आपराधिक कृत्य का ब्योरा सामने आता गया। उससे पता चला कि चार लोगों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। उसे इतना प्रताड़ित किया कि वह मौत के मुंह में चली गई। फिर उन दरिंदों ने उसकी देह को कंबल में लपेटकर आग के हवाले कर दिया। यह सब उस जगह हुआ जहां से वह टोल प्लाजा बमुश्किल कुछ ही दूरी पर है जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। अगर पुलिस वक्त रहते कार्रवाई करती तो संभव था कि कम से कम उसकी जान बचाई जा सकती थी। इसके उलट तत्परता से कार्रवाई के बजाय पुलिस इसी टालमटोल में वक्त जाया करती रही कि यह अपराध किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। क्या इससे भी ज्यादा कुछ भयावह हो सकता है? पूरी तरह टूट चुके उसके पिता ने कई साक्षात्कारों में अपनी आपबीती सुनाई है।

फाइल फोटो

वह युवा डॉक्टर न केवल उन दरिंदों की शिकार हुई जिन्होंने उसकी देह की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि वह उस तंत्र से भी प्रताड़ित हुई जिसने उसके जीवन की परवाह नहीं की। पुलिस ने पीड़िता की खोज-खबर के लिए शीघ्रता दिखाने के बजाय उसके परिवार को कायदे-कानूनों की घुट्टी पिलाई। इससे यही सवाल उठता है कि क्या महिलाओं की जिंदगी मायने नहीं रखती?

जाहिर है कि इस मामले में नेताओं ने हमें एक बार फिर निराश किया। मीडिया ने ही इस मामले को उठाया। उन्होंने निर्भया की मां से संपर्क साधा। वह एक और मामले की सुनवाई के लिए पटियाला हाउस अदालत के बाहर मिलीं। अपनी बेटी के साथ हुए वीभत्स सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बाद से उनकी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटने में ही गुजर रही है। पहले तो बेटी के साथ हुई बर्बरता के मामले में इंसाफ को लेकर और अब उस न्याय को हासिल करने के लिए जिसका वादा किया गया था। वह अपनी बेटी के क्रूर अपराधियों के लिए मौत की सजा से कम कुछ भी नहीं चाहतीं। फिर भी हमारा न्यायिक तंत्र उन्हें निराश कर रहा है। देश में दुष्कर्म के सबसे अधिक चर्चित मामले में अगर यह स्थिति है तो फिर अन्य मामले में क्या उम्मीद की जा सकती है?

वर्ष 2016 के एक आंकड़े के अनुसार भारत में दुष्कर्म के रोजाना 106 मामले सामने आते हैं। इससे पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि यहां दुष्कर्म के सभी मामलों की रपट नहीं दर्ज कराई जाती। कुछ सामाजिक पहलुओं और इंसाफ पाने के लिए जटिल न्यायिक प्रक्रिया के कारण इससे जुड़े सभी अपराध दर्ज नहीं हो पाते। तिस पर प्रत्येक चार में से एक मामले में ही अपराध सिद्ध हो पाता है। यह बहुत निराशाजनक दर है। डीएनए विश्लेषण जैसी तकनीक से दोषसिद्धि दर बढ़ाई जा सकती है। इसमें 2018 की एक रिपोर्ट बताती है कि दुष्कर्म से जुड़े 12,000 मामले सिर्फ इसलिए लंबित हैं, क्योंकि नमूनों की जांच के लिए पर्याप्त प्रयोगशालाएं नहीं हैं। क्या यह शर्मनाक नहीं है? एक तो अपराध सिद्ध होने की दर इतनी कमजोर है और जिन साक्ष्यों से इन अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकता है, उन्हें जुटाने में इतनी देरी हो रही है। अगर यह महिलाओं को इंसाफ दिलाने में हीलाहवाली की मिसाल नहीं है तो और क्या है?

यह बहुत निराश-हताश करने वाली स्थिति है। इसमें नेताओं से सिर्फ नाकामी मिली है। उन्हें महिलाओं की याद केवल चुनावों के दौरान आती है। वे यही उम्मीद करते हैं कि हम कुछ प्रतीकों के उन्माद में ही संतुष्ट रहें। जैसे-मौजूदा संसद में महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी कि कुल सांसदों में महिलाओं की संख्या 14.36 प्रतिशत हो गई है। यहां इस तथ्य को भी याद रखें कि पिछली जनगणना के अनुसार देश की आबादी में 48 प्रतिशत महिलाएं हैं। क्या उस हिसाब से यह बराबरी की हिस्सेदारी है? वहीं हमारी संसद महिलाओं के हितों से जुड़े कानून तो बनाती है, लेकिन हैदराबाद जैसे वीभत्स मामलों पर चर्चा के लिए समय नहीं निकाल पाती। यह रवैया महिलाओं को आक्रोशित और नाउम्मीद ही करता है।

हैदराबाद की उस पीड़िता की जिंदगी के आखिरी घंटों की कल्पना कर आप सिहर उठेंगे। रात का घुप अंधेरा। सुनसान सड़क। फोन पर बहन से आखिरी बातचीत में सिर्फ खौफ की अनुभूति। एक बेहद व्यस्त टोल प्लाजा से चंद किलोमीटर की दूरी पर दुष्कर्म। इसके बाद वे वहशी उसका वजूद ही मिटा देते हैं। अगर इससे भी आप व्यथित होकर यह नहीं सोचते कि हम महिलाओं को क्यों लगातार निराश कर रहे हैं तो फिर यही समझना होगा कि यह देश आधी आबादी के लिए है ही नहीं।

(स्तंभकार जानी-मानी पटकथा लेखिका हैं)

response@jagran.com

हिंदुत्व का अहित करते फर्जी पैरोकार

अवधेश कुमार

आजकल हिंदुत्व के नाम पर तमाम फर्जी संगठन खड़े हो गए हैं जिनके विकृत विचारों से हिंदुत्व को नुकसान पहुंच रहा है

भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर विवादों में हैं। उन पर संसद में नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने का आरोप है। निःसंदेह देश का एक सांसद यदि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहता है तो इससे शर्मनाक और निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए भाजपा ने कार्रवाई करते हुए साध्वी प्रज्ञा के भाजपा संसदीय दल की बैठक में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही रक्षा मामलों की संसदीय समिति से उन्हें हटाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा उन्हें लोकसभा में दो बार क्षमा याचना भी करनी पड़ी है। हालांकि साध्वी का कहना है कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। दरअसल द्रमुक सांसद ए राजा द्वारा शहीद उधम सिंह का नाम लेने पर उन्होंने कहा था कि किसी देशभक्त को मत घसीटिए। हम उनके स्पष्टीकरण पर नहीं जाना चाहते। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने गोडसे को देशभक्त बताया था। उस बयान ने देश भर में खलबली मचा दी थी। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी आलोचना करते हुए कहा था कि 'सभ्य समाज में इस तरह की भाषा नहीं चलती। दूसरा कोई उन्हें माफ कर दे, मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा।' अगर साध्वी ने वाकई संसद में गोडसे के बारे में दोबारा यही बात कही तो फिर यह बिल्कुल अक्षम्य है। पार्टी ने इसकी छानबीन करके ही उनके विरुद्ध फैसला किया होगा, लेकिन यहां सवाल केवल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नहीं है।

देश में एक वर्ग है जो गांधी जी के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है। वह उनके बारे में निहायत ही झूठी बातें फैलाने का काम रहा है। यह सच है कि गांधी जी के जीवनकाल में ही जम्मू-कश्मीर में सेना भेजने तथा पाकिस्तानी सेना से लड़ने का फैसला हुआ था, जिसे उन्होंने रोका नहीं था। इसका मतलब हुआ कि उस पर उनकी सहमति थी। हैदराबाद में भी उनके समय में ही सेना भेजी गई थी। वास्तव में गांधी जी अखंड भारत की भावना से अंतिम समय तक काम करते रहे। उन्होंने विभाजन को रोकने के लिए भी जितना संभव था किया, लेकिन कुछ लोगों ने उनके खिलाफ कई नकारात्मक बातों को फैला दिया है। इस दौरान भाजपा पर हमला करने वाली कांग्रेस यह भूल रही है कि जिस शिवसेना के साथ वह महाराष्ट्र सरकार में भागीदार हो गई है उसका विचार हमेशा से गोडसे के पक्ष में रहा है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे तो डंके की चोट पर नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताते थे। बाल ठाकरे के बेटे और हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे भी सामना के संपादक रहे हैं। गोडसे के महिमामंडन में उनकी कई टिप्पणियां सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। अगर कांग्रेस को गांधी जी के सम्मान की वाकई चिंता है और गोडसे की प्रशंसा करने वालों से उनका विरोध है तो फिर शिवसेना के साथ गठबंधन बनाने का मतलब क्या है?

इस समय विपक्षी पार्टियां यह भी कह रही हैं कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा वही संघ और भाजपा की आत्मा है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। वास्तव में नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के नाम का जितनी बार उल्लेख किया है उतना किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने शायद ही किया हो। जिस संघ परिवार को राजनीतिक पार्टियां और कथित बुद्धिजीवी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि संघ के प्रशिक्षण शिविरों में प्रातः गांधी जी का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। वहां गांधी जी के जीवन से जुड़े कई प्रसंग बताए जाते हैं। यह सच है कि नाथूराम गोडसे कभी संघ से जुड़ा था, किंतु उससे निराश होकर उसने जल्द ही संघ छोड़ दिया, क्योंकि हिंदू, मुसलमान, हिंदुत्व के बारे में उसकी जो अतिवादी सोच थी, वह संघ से मेल नहीं खाती थी। उसका देशप्रेम विकृत था। उसमें संतुलन का अभाव था। लिहाजा वह संघ की आलोचना करने लगा था। उसके अखबार पहले दैनिक अग्रणि तथा बाद में हिंदू राष्ट्र के अंकों में उसके विचारों के बारे में काफी कुछ पता चलता है। यह भी सच है कि वह लंबे समय तक गांधी जी और वीर सावरकर, दोनों का प्रशंसक रहा था, जिसका उसके भाई गोपाल गोडसे ने अपनी पुस्तक 'गांधी वध क्यों' में जिक्र किया है। बाद में उसने सावरकर की भी तीखी आलोचना शुरू कर दी थी। साथ ही गांधी जी को भी वह अधिनायकवादी मानने लगा था।

दरअसल गोडसे के पास भारत, हिंदू, हिंदुत्व को लेकर सही धारणा नहीं थी, जिसके कारण उसके इर्द-गिर्द विकृत सोच वाले लोग एकत्रित होते गए थे। वे भारत को उस समय की स्थिति से उबारने के लिए गलत रास्ते अपनाने लगे थे। वे मानने लगे थे कि गांधी जी की हत्या से ही हिंदू समाज की रक्षा होगी और भारत सही रास्ते पर आएगा। यह उनकी बड़ी घटिया सोच थी। दुख की बात है कि इसी तरह की निकृष्ट सोच का विस्तार देश में पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। हिंदू, हिंदुत्व, भारतीय राष्ट्र-राज्य की इनकी कल्पनाएं अतिवाद से भरी हैं। ऐसे तत्वों को संयमित करना जरूरी है। ऐसे लोग किसी संगठन की विचार सीमा और अनुशासन में नहीं रह सकते। अजमेर शरीफ विस्फोट में जिन लोगों को सजा हुई है वे ऐसी ही सोच की उपज हैं। इनसे आज यह पूछने की जरूरत है कि अगर नाथूराम इतना ही वीर था तो उसने मोहम्मद अली जिन्ना को गोली क्यों नहीं मारी, जो कि भारत विभाजन के लिए सीधे जिम्मेवार थे? एक निहत्थे, निरपराध महात्मा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और मानवता को समर्पित कर दिया उसका हत्यारा कभी देशभक्त नहीं माना जा सकता।

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कहना कठिन है कि इस घटनाक्रम के बाद उनकी सोच बदली है या नहीं? वस्तुतः इस तरह की मानसिकता वालों को शायद यह भी पता नहीं होगा कि हिंदू महासभा के किसी कार्यालय में गोडसे की तस्वीर नहीं है। जिस हिंदू महासभा से वह जुड़ा था, वही संगठन उसे महापुरुष या देशभक्त नहीं मानता। हिंदू महासभा के साहित्य में गोडसे की कोई पुस्तक भी नहीं मिलेगी। यहां मूल हिंदू महासभा की बात हो रही है। यह अलग बात है कि आजकल जगह-जगह हिंदू महासभा के नाम से संगठन खड़े हो गए हैं, जो गोडसेवादी हैं। वास्तव में थोड़ी गहराई से विचार करें तो देश में इन दिनों एक खतरनाक प्रवृत्ति का प्रसार हो रहा है, जो किसी के भी हित में नहीं। इससे हिंदुत्व का विचार ही बदनाम होता है। इस प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए, आज इस पर चिंतन-मनन करने की आवश्यकता है?

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

खुशियों का पता

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसे तनाव एवं उदासी से जूझना नहीं पड़ता। किसी के सिर पर काम का बोझ है तो कोई अपने निजी एवं पारिवारिक कारणों की वजह से दुखी है। किसी को परीक्षा में कम नंबर आने का मलाल है तो किसी को नौकरी नहीं मिलने का गम। इन हालातों में अब खुशी और हंसी इंसानी चेहरों से ओझल हो चुकी है।

प्रतिस्पर्धा की जंग में अव्वल आने की चाह में व्यक्ति ने अपना सुख-चैन सब कुछ दांव पर लगा दिया है। हमारे पास जो है उसकी हमें कद्र नहीं है। मृगतृष्णा के पीछे भागते मन को संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि के अभाव में जीवन में बढ़ता कोलाहल हमें निरंतर नकारात्मक बनाने पर आमादा है। इसका मूल कारण यही है कि हमने अपने जीवन को समझा नहीं, बल्कि हम जीवन को दुखों का घर समझने वाली विचारधारा के पीछे चलते गए और कभी जीवन में खुशियों को आने का निमंत्रण ही नहीं दिया। हमें जो मिलता है और हमारे साथ जो होता है ये हमारे कर्म तय करते हैं। अतः इंसान के कर्मों में सादगी एवं सत्यता बनी रहनी चाहिए।

यकीन मानिए कि हम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे पास तंदुरुस्त शरीर है। आंख, कान, नाक एवं हमारे हाथ-पैर सही सलामत हैं। एक बड़ी जनसंख्या इनसे वंचित जीवन जी रही है। वास्तव में खुशियां हमारे आस-पास ही हैं। बस उन्हें तलाशने वाली नजर की जरूरत है। समस्याएं तो सबके साथ हैं। बात बस नजरिये की है। जब तक हम अपना नजरिया नहीं बदलेंगे तब तक दुनिया हमारे लिए दुखों का घर बनकर हमारी परेशानी बढ़ाती ही रहेगी। इससे स्पष्ट होता है कि जिस दिन हमने सकारात्मक दृष्टिकोण से जिंदगी को देखना शुरू कर दिया उसी दिन से खुशियां हमारा पता ढूंढते हुए दौड़ी चली आएंगी। अतः अपनी हंसी और खुशी को आगे बढ़ने की व्यर्थ होड़ में खोने न दें। ऐसी दौलत का क्या फायदा जो हमारी नींद ही उड़ाकर रख दे। कहा भी गया है-कमाओ हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती।

देवेंद्रराज सुथार

कब छंटेगा असुरक्षा का अंधेरा

फिर से

घर आने के बाद मां को फोन कर बताती हूं कि चिंता मत कीजिए मैं आज भी सुरक्षित वापस लौट आई हूं

आदरणीय प्रधानमंत्री जी,

एक और घटना घट गई। देश की एक और बेटी दरिंदों की हवस का शिकार हो गई। एक बार फिर आपके देश की बेटियां भीतर तक सहम गई हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नारे लगने शुरू हो गए हैं। मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं। चीजें घूम-फिर कर फिर से वहीं आ गई हैं जहां सात साल पहले निर्भया कांड के समय थीं। मेरे सामने कई आंखें हैं जिनमें हैदराबाद की घटना को लेकर रोष है। कुछ मन हैं जो कष्ट और वेदना से भरे हुए हैं। कुछ आंखों में मुझे वही डर नजर आ रहा है जो मेरे भीतर भी जगह बनाने लगा है।

प्रधानमंत्री जी, घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में रोज स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के लिए निकलना और रात को सुरक्षित वापस लौट आना कितना असामान्य हो गया है। मैं सुबह जिस बस से ऑफिस जाती हूं, उनके पीछे लिखा होता है-'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ', 'बेटियां बेटों से कम हैं क्या?'। ये नारे और स्लोगन आज मुझे मुंह चिढ़ा रहे हैं! सड़क पर चलते वक्त या रात को वापस घर लौटते समय मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कदम तेज हो जाते हैं और दिमाग एक ही बात सोच रहा होता है कि कहीं मेरे साथ भी...! हर रात घर आने के बाद मां को फोन कर बताती हूं कि आप चिंता मत कीजिए मैं आज भी सुरक्षित वापस लौट आई हूं। हम अपनी सफलता की उड़ान किस ओर ले जाएं प्रधानमंत्री जी? आखिर सरकार इन पापियों के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? निर्भया कांड के गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन देश की न्याय व्यवस्था की लाचारी देखिए अभी तक वे नरदानव सिर उठाए खड़े हैं। क्या उन्हें फांसी की सजा देना, हमारे साथ इतनी घिनौनी और विभत्स हिंसा को अंजाम देने से ज्यादा कठिन है?

हैदराबाद तो वह है जो नजरों में आ गया, लेकिन ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें आरोपी जमानत लेकर अपने अगले शिकार की तलाश में बाहर घूम रहे हैं। सरकार बनाने के लिए तो रविवार के दिन भी न्यायालय खोला जाता है, सुनवाई होती है और सरकार बनाई जाती है। आखिर बेटियों के लिए यह सामूहिक लाचारी क्यों? कई देशों में यौन उत्पीड़न के बाद आरोप सिद्ध होने पर आरोपियों को 'नपुंसक' बनाने का प्रावधान है। यह व्यवस्था हमारे देश में क्यों नहीं लागू की जा सकती है? इसमें क्या मजबूरी है? कोई सांसद इस विषय पर 'प्राइवेट मेंबर बिल' क्यों नहीं लाता? उन्हें बेटियों की चिंता है तो कदम क्यों नहीं उठाते? सरकार और संवैधानिक प्रतिष्ठानों की यह बेबसी देखकर तरस आता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां बेटियां हताश हैं, निराश हैं, बेचैन हैं, निःशब्द हैं, असहाय हैं, डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं कि किस क्षण उनके साथ...! प्रधानमंत्री जी, हम जानवरों से तो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं, पर राक्षसों से नहीं। आपसे बहुत उम्मीदें हैं। यदि इस पर कोई ठोस कदम उठा सकते हैं तो देर मत कीजिए। और यदि नहीं तो हमें इन राक्षसों की हवस का शिकार होने से पहले वैसे ही जिंदा जला दीजिए, जैसे हैदराबाद में उन दरिंदों ने...।

एक बेटी।

(प्राची प्रियम के फेसबुक वॉल से साभार)

मेलबाक्स

जनादेश पर हावी अवसरवादी राजनीति

'भितरघात की शिकार तो नहीं भाजपा' शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भाजपा में भितरघात की जो आशंका जताई है, वह इस राज्य में भाजपा के पूर्ण बहुमत प्राप्त न कर पाने की एकमात्र वजह नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय फलक पर दोबारा अपना परचम फहराने वाली भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद भी राज्यों में सरकार बना पाने में नाकाम हो रही है, यह विचारणीय अवश्य है। वस्तुतः जब से भारतीय राजनीति में जनादेश को नजरंदाज कर जोड़-तोड़ की अवसरवादी राजनीति का बोलबाला हुआ है, तब से बहुमत के जादुई आंकड़े से पीछे रहने वाले सबसे बड़े दल को सरकार बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद भी भाजपा द्वारा सरकार न बना पाने के पीछे यही अवसरवादी राजनीति है। महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव पूर्व भाजपा-शिवसेना गठबंधन को बहुमत के साथ जनादेश मिला था, उसका सम्मान हर हाल में होना ही चाहिए था, लेकिन शिवसेना ने ऐसा नहीं होने दिया। अपनी विचारधारा को तिलांजलि देकर विरोधियों के साथ मिलने वाली शिवसेना महाराष्ट्र पर शासन करने के बाद भी यहां के जनमानस पर राज कर पाएगी, इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि जिस अपेक्षा के साथ महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा-शिवसेना गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया था, उसका निरादर करके लोकतंत्र को लज्जित किया गया है। भाजपा ने भी जिस उतावलेपन से राकांपा के अजीत पवार पर विश्वास करके देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व में सरकार बनाने की कुचेष्टा की, उसे भी उचित नहीं माना जा सकता। भाजपा के इस अविवेकपूर्ण कृत्य ने शिवसेना को कांग्रेस और राकांपा जैसे धुर विरोधी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने का अवसर उपलब्ध करा दिया। निःसंदेह अवसरवाद की यह विकृत राजनीति जिस तरह से जनादेश पर हावी होकर लोकतंत्र की खिल्ली उड़ा रही है, वह विचारणीय है।

डॉ. वीपी पांडेय, अलीगढ़

यह कैसा मनोरंजन?

टीवी के एक चैनल पर प्रसारित हो रहे कार्यक्रम बिगबॉस के प्रतिभागी अच्छे परिवारों से हैं। ये सभी एक ही घर में रहते हैं जहां सब जगह कैमरे लगे हैं। ये खाने पर, घर के कामों पर या अन्य कारणों से दिन रात लड़ते ही रहते हैं। इनको नए-नए टास्क दिए जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। अंग्रेजी, हिंदी या अन्य आम बोली का इस्तेमाल करने वाले ये प्रतिभागी कैसे हमारा मनोरंजन करते हैं समझ से परे है? एक साथ रहने वाले ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने, गाली गलौच करने, षडयंत्र रचते हुए समाज को क्या शिक्षा दे रहे हैं? यह मूलतः एक विदेशी धारावाहिक बिग ब्रदर की नकल है जो वहां की सभ्यता से शायद मेल खाता हो, पर यहां ये केवल और केवल नुकसान ही पहुंचा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

प्रवीण कुमार सक्सेना, आर्य विहार, नोएडा

अवैध कॉलोनियों पर जुबानी जंग

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर दोनों सरकारों के बीच जुबानी जंग जारी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार चुनाव को देखते हुए अनाधिकृत कॉलोनियों को पंजीकृत कर रही है और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केवल 100 कॉलोनियों को नहीं, बल्कि सभी कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री होनी चाहिए। हालांकि यह साफ है कि अगर कालोनियां पंजीकृत हो गईं तो उनको कोई यह नहीं कहेगा कि उन्होंने प्रयास नहीं किया था। राज्य सरकार भी पूरे प्रयास में है कि पूरा श्रेय कहीं भाजपा अकेले ना ले ले। अब देखना यही है की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के ऊपर अस्थाई छत कब होगी।

satyamraiw|6304@gmail.com

सत्ता पाने की होड़

आजादी के कुछ वर्षों बाद ही अवसरवादी राजनीति ने अपना क्रूर पंजा फैलाना शुरू कर दिया था। इसके लिए किसी दल विशेष को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। आज के इस राजनीतिक वातावरण में कोई दल पूरी तरह से बेदाग नहीं है। सत्ता पाने की होड़ लगी है। इसी का नतीजा अभी महाराष्ट्र की राजनीति में भी देखने को मिला। पार्टियों के प्रयास से ही इस तरह की राजनीति से मुक्ति मिल सकती है।

hemahariupadhyay@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

5.8 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई अक्टूबर माह में देश के आठ कोर सेक्टर में, जबकि सितंबर माह में कोर सेक्टर में 5.2 फीसद की गिरावट आई थी।

आजकल

राहुल लाल
आर्थिक मामलों के जानकार

अर्थव्यवस्था की रफ्तार हो रही धीमी

भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो गई है। अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र मांग की कमी से प्रभावित है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 4 .5 फीसद पर पहुंच चुकी है जो पिछले छह वर्षों का सबसे निचला स्तर है। वर्ष 2016-17 के प्रथम तिमाही में जीडीपी विकास दर 9 .2 प्रतिशत थी, जो 2016-17 के संपूर्ण वार्षिकी में गिरकर 8 .2 प्रतिशत हो गई। जीडीपी विकास दर वर्ष 2017-18 में घटकर 7 .2 प्रतिशत और वर्ष 2018-19 में 6 .8 प्रतिशत रह गई। इसके साथ ही इस वर्ष जनवरी से मार्च तिमाही में जीडीपी विकास दर केवल 5 .8 प्रतिशत रह गई थी

प्रतीकात्मक

बीते सप्ताह जारी किए गए जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 4.5 फीसद पर पहुंच चुकी है। जीडीपी की विकास दर घटने से लोगों की आमदनी, खपत और निवेश पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इससे नौकरियों पर भी अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दरअसल सरकारी राजस्व एवं मध्य वर्ग के वेतन में वृद्धि काफी हद तक नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर पर ही निर्भर करता है। नॉमिनल वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत से कम रहने पर अब उस स्तर से भी नीचे आ गई है, जिस पर सरकार उधारी लेती है। अपने घाटे की भरपाई के लिए सरकार फिलहाल 6.5 फीसद के नॉमिनल जीडीपी दर पर उधारी ले रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अर्थव्यवस्था के लिए यह तगड़ा आघात है। इसका मतलब होगा कि सरकार पर कर्ज बोझ आगे और बढ़ेगा। इससे भी अहम है कि अर्थव्यवस्था के उधारी दर में सुस्त रफ्तार से बढ़ने पर उन प्रोत्साहनों में भी कमी आएगी, जिनके आधार पर निवेशक फैसले लेते हैं।

लगातार दूसरे माह कोर सेक्टर में आई गिरावट : देश के आठ कोर सेक्टर में अक्टूबर माह में 5.8 फीसद गिरावट देखने को मिली। सितंबर माह में भी कोर सेक्टर में 5.2 प्रतिशत गिरावट आई थी। जीडीपी के इसी तिमाही में वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत तक लुढ़काने में कोर सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोर सेक्टर इंडेक्स के अनुसार औद्योगिक उत्पादन घटने से बिजली की मांग में 12.4 प्रतिशत तक की कमी आई है। पिछले माह यह खपत सितंबर के माइनस तीन फीसद यानी ऋणात्मक तीन प्रतिशत के मुकाबले इस बार माइनस बारह फीसद हो गई है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार सबसे तगड़ा झटका कोयला क्षेत्र को लगा है, जिसमें उत्पादन में 17.6 फीसद की कमी दर्ज की गई है। वहीं कच्चे तेल के उत्पादन में 5.1 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 5.7 फीसद की कमी आई है। इसके अतिरिक्त सीमेंट के उत्पादन में 7.7 फीसद और इस्पात के उत्पादन में 1.6 प्रतिशत की कमी आई है। कोर सेक्टर में मुख्यतः आठ उद्योग शामिल होते हैं- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, स्टील, सीमेंट, बिजली, फर्टिलाइजर और रिफाइनरी उत्पाद। आइआइपी की गणना में इनका योगदान करीब 40.27 प्रतिशत रहता है।

निर्यात में भी गिरावट : देश के निर्यात में लगातार तीसरे माह गिरावट आई है। सितंबर माह के निर्यात में 6.57 फीसद की गिरावट आई है, तो वहीं अक्टूबर में 1.1 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय घरेलू मांग की कमी की समस्या से जूझ रही है, ऐसे में उद्योगपति अपना सामान निर्यात करते हैं और विदेशों में बाजार तलाशतें हैं। लेकिन भारतीय निर्यात की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है।

दरअसल निर्यात जीडीपी के चार प्रमुख घटकों में से एक है। इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में गिरावट काफी परेशान करने वाला है। नरेंद्र मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल में 2014 से 2019 के दौरान कुल औसत निर्यात वृद्धि दर चार फीसद रहा। इस मामले में यदि वर्ष 2014-15 से पहले की बात करें, तो निर्यात बेहतर था। वर्ष 2013-14 में निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर 17 प्रतिशत थी, जो 2014-15 और 2015-16 में घटकर क्रमशः माइनस एक प्रतिशत और माइनस नौ प्रतिशत हो गई। अभी भी निर्यात दर लगातार ऋणात्मक बना हुआ है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा है कि भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के लिए निर्यात दर 19 से 20 प्रतिशत तक होना आवश्यक है। ऐसे में निर्यात वृद्धि के लिए विशिष्ट रणनीति बनाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए चीन में अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ने से एक रिक्तता भी पैदा हुई है, ऐसे में भारत लगभग 57 प्रकार के उत्पादों का निर्यात चीन को आसानी से कर सकती है। इस सदंर्भ में यह उल्लेखनीय है कि ट्रेड वॉर के संकट को वियतनाम और बांग्लादेश ने अपने लिए अवसर में बदला है। हमें इन दोनों देशों से भी सीखना होगा।

विनिर्माण में गिरावट : पिछले दो वर्षों में पहली बार विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में एक प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि इसकी पहली तिमाही में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके पहले वित्त वर्ष की समान तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष की पहली छमाही में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 0.2 प्रतिशत की गिरावट आई है।

घरेलू कारणों से धीमी हुई अर्थव्यवस्था की रफ्तार

सरकार बार-बार कह रही है कि विकास की धीमी रफ्तार का कारण वैश्विक मंदी है। सरकार इसके लिए चीन-अमेरिका ट्रेड वॉर को भी जिम्मेदार मानती है। हालांकि, यह दलील काफी सतही है। मसलन, ट्रेड वॉर में उलझे चीन की इसी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में वृद्धि दर छह प्रतिशत है। यह कहना मुश्किल है कि चीन की तुलना में भारत पर ट्रेड वॉर का असर ज्यादा पड़ रहा है। इसी तरह पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी जीडीपी विकास दर सात प्रतिशत बना हुआ है। इससे समझा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार के कारण बाहरी न होकर, बल्कि आंतरिक ही हैं।

पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण के कुछ दिन बाद कहा था कि हम देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर कर देंगे। लेकिन जिस तरह से देश में आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट जारी है, उससे देश के लिए इस संकल्प को पूरा करने का लक्ष्य भी हाथ से फिसलता जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 2024-25 तक पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए 12 प्रतिशत का विकास दर अपेक्षित है। स्वयं सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने के लिऐ आठ प्रतिशत विकास दर तो न्यूनतम आवश्यक है। अगर जीडीपी विकास दर 4 .5 फीसद रही, तो भारतीय अर्थव्यवस्था और भी धीमी गति से विकसित होगी। इस विकास दर से इस लक्ष्य को पाने में कम से कम 14 वर्ष लगेंगे। दूसरे शब्दों में इस विकास दर से पांच ट्रियिलन डॉलर का लक्ष्य 2033-34 तक ही हासिल किया जा सकता है।

खपत में गिरावट का असर

खपत दर घटने से लोगों की आमदनी पर बुरा असर पड़ रहा है। देश में बाजार की एक बड़ी शोधकर्ता कंपनी की रिपोर्ट कहती है कि तेजी से खपत वाले सामान एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंजम्प्शन गुड्स की बिक्री की विकास दर भी गिरती जा रही है। गिरती अर्थव्यवस्था के लिए खपत दर में कमी को 'गोल्डमैन सैक्स' ने भी रेखांकित करते हुए कहा है कि खपत में गिरावट का कारण एनबीएफसी संकट को नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि आइएलएंडएफएस के भुगतान संकट से पहले खपत में गिरावट को देखा जा सकता है। एनबीएफसी में संकट सितंबर 2018 में शुरू हुआ, लेकिन खपत में गिरावट जनवरी 2018 से ही जारी है।

विनिर्माण क्षेत्र में अत्यंत कमजोर प्रदर्शन का कारण मांग में कमी है। उपभोक्ता उत्पादों के कमजोर मांग के कारण विनिर्माण क्षेत्र सिकुड़ गया है, क्योंकि क्षमता ज्यादा है और उसकी तुलना में मांग काफी कम है। विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए भयावह है।

राजकोषीय घाटा बजट लक्ष्य के पार : केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा अप्रैल- अक्टूबर के दौरान 7.2 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो 7.01 लाख करोड़ रुपये के 2019-20 के बजट लक्ष्य से अधिक है। जुलाई- सितंबर के दौरान जीडीपी के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में सामान्य जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर राजकोषीय घाटा 6.6 फीसद रही, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच जुलाई के अपने पहले बजट भाषण में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.3 प्रतिशत निर्धारित किया था।

अब तक सरकार अर्थव्यवस्था का सबसे तेज बढ़ता हिस्सा रही है, लेकिन राजकोषीय घाटे का पूरे वर्ष का लक्ष्य सात माह में ही पार हो जाने के बाद यह जारी नहीं रहने वाला। इस तिमाही में जीडीपी विकास दर 4.5 प्रतिशत इसलिए रही, क्योंकि सरकारी खर्च 15.6 प्रतिशत बढ़ा है। ऐसे में यदि सरकारी खर्च को अलग कर दें और तब संपूर्ण अर्थव्यवस्था को देखेंगे, तो पाएंगे कि यह स्थिति और भी बुरी है। इस खर्च से अलग जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसका विकास दर गिरकर तीन फीसद हो गया है।

कृषि विकास दर की चुनौती : वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में भारत की कृषि विकास दर 2.1 प्रतिशत रही। यह पहली तिमाही के दो प्रतिशत की तुलना में कुछ ही अधिक है। उल्लेखनीय है कि पिछले पांच वर्षों में देश में औसत कृषि विकास दर 2.7 प्रतिशत रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाए। इसके लिए नीति आयोग के तत्वावधान में अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया, जिसने कृषि आय को दोगुना करने के लिए कृषि विकास दर को 12 प्रतिशत तक पहुंचाने की सिफारिश की। परंतु कृषि विकास दर अब भी दो प्रतिशत के आसपास ही है। ऐसे में अब इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य से भी हम लोगों की दूरी लगातार बढ़ रही है।

... तो क्या है समाधान? सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की थी। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने कई बार रेपो रेट में कटौती कर ब्याज दरों को घटाया। लेकिन इन प्रयासों का कोई विशेष परिणाम नहीं दिख रहा है। अर्थव्यवस्था का वर्तमान संकट मूलतः मांग पक्ष से संबद्ध है। कॉरपोरेट टैक्स में कमी का लाभ मांग पक्ष से संबद्ध न होकर आपूर्ति पक्ष से संबद्ध है। आपूर्ति पक्ष में पहले ही समस्या नहीं है। उपभोक्ता की क्रय क्षमता में कमी के कारण मांग में कमी आ रही है। इस कारण कंपनियों को उत्पादन में कटौती करनी पड़ रही है। कंपनियों को अगर लंबे समय तक यह कटौती करनी होगी, तो उन्हें अपने कर्मचारियों की छंटनी भी करनी होगी। सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान क्या है? इसके लिए सबसे आवश्यक है कि सरकार सबसे निम्न वर्ग की क्रय क्षमता में वृद्धि करे। उदाहरण के लिए सरकार इस समय किसानों को 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के तहत सीधे बैंक खातों में रकम भेज रही है। इस तरह की योजनाओं और लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसी तरह सरकार को आधारभूत संरचना पर भी खर्च में वृद्धि करनी होगी। इससे एक ओर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण भी होगा, वहीं लोगों को भारी मात्रा में रोजगार भी मिलेगा।

अगर निवेश में विकास दर को देखें, तो वह गिरकर एक प्रतिशत पर आ गई है। इसका मतलब है कि निवेश लगभग नहीं के बराबर हो रहा है। जब अर्थव्यवस्था में मांग बनी रहती है, तभी निवेश भी सुगमता से उपलब्ध हो पाता है। अभी निवेश वृद्धि दर पिछली 19 तिमाही के निचले स्तर पर है। जब तक अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं बढ़ेगा, तब तक नौकरियां नहीं पैदा होंगी। जब तक नौकरियां पैदा नहीं होंगी, तब तक लोगों की आय में वृद्धि नहीं होगी, और तब तक लोग खर्च नहीं करेंगे। जब लोग खर्च नहीं करेंगे, तो निजी खपत कैसे बढ़ेगी। यह सब एक -दूसरे से जुड़ा हुआ है।

सरकार को इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। आर्थिक मंदी की किसी परिभाषा में उलझने के बजाय निचले स्तर के उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता को बढ़ाने में अपनी ऊर्जा लगा देनी चाहिए।

खरी-खरी

आखिरकार... त्रिकोणीय सरकार

निर्मल गुप्त

महीना भर से ज्यादा अरसा हो गया चुनाव संपन्न हुऐ। अब किसी तरह सरकार बनी तो जनता सदमे से बाहर आई है। सबने यही कहा कि हुजूर, बड़ी देर कर दी सरकार बनते-बनाते। चुनाव तो हमेशा होते ही हैं, पर ऐसा कभी-कभी ही देखने में आता है कि न वे जीते, न ये हारे।

राजनीति में अमूमन ऐसा होता नहीं, पर अब हुआ है तो हो गया। कोई कह रहा है कि जो हुआ, अच्छा हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि लोकतंत्र तो बाल-बाल बच निकला। सवाल यह उठना चाहिए कि कौन-सा वाला लोकतंत्र? वह जो लंबे समय से खतरे में घिरा है, या फिर वो वाला जो तय मियाद से पहले जन्मे किसी नवजात-सा रुई के फाहे में इन्क्युबेटर के भीतर धरा हुआ है? किसी ने कहा कि सेक्युलरिज्म की पुनर्स्थापना हुई। कौन-सा वाला सेक्युलरिज्म? वही जिसका जादू वक्त-जरूरत सिर चढ़कर बोलता है, या वो वाला जिसके मायने समय-असमय खुद-ब-खुद बदल जाते हैं?

बहरहाल, देखने वाली बात यह कि निपट राजनीतिक उदासी काफूर हुई। सिरों की गिनती की चकल्लस शुरू हुई। बाग-बगीचे में लुकाछिपी के प्रहसन का पटाक्षेप हुआ। शुद्ध आबोहवा वाले रिजॉर्ट में जल-किलोल के मनभावन दिन लौट आए। नैतिकता से भरे स्वीमिंग पूल में आकंठ डूबकर ही पॉलिटिकल सैद्धांतिकी की थाह पाई जा सकती है। सिंगल माल्ट गरल जब शिराओं में उतरती है, तब जीवन मूल्यों में लगी जटिल गिरह खुलती हैं। अब जनादेश के बीजगणितीय समीकरण इसी तरह से हल होने लगे हैं। काम करने लायक सरकारें इसी तरीके से आकार ग्रहण करती हैं। तीन तिलंगे इसी तरह सक्रिय होते हैं। सत्ता की सुगंध मिलते ही वे मदमाते हुए खिल जाते हैं।

आजकल राजनीतिक हलकों में बड़ी हलचल है। लंबे अरसे से अस्तबल में बंधे निठल्ले घोड़े दाना-भूसा चरना भूल, दबी जबान में हिनहिना रहे हैं। उनकी सिक्स्थ सेंस बता रही है कि अबकी बार बनी है विशुद्ध सरोकारों वाली अद्भुत त्रिकोणीय सरकार। जब तक यह नियमानुसार न हुआ था, तब तक गजब कौतूहल और उहापोह था। बेचारी लोकशाही की जान सांसत में फंसी थी। न्यायप्रियता को जगजाहिर करने के लिए इस बार अदालती रतजगे तो न हुए, पर छुट्टी वाले दिन कानूनी कामकाज हुआ।

अब तो यह कहने को मन हो रहा है कि अबकी बार ऐसी न वैसी, तीन टांग वाली जबर्दस्त कामकाजी (?) सरकार।

ट्वीट-ट्वीट

हैदराबाद में महिला चिकित्सक के साथ बर्बरता की कल्पना भी मुश्किल है। प्रत्येक स्थान पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सरकार एवं समाज की साझा जिम्मेदारी है। हम बार-बार इसमें बुरी तरह नाकाम होकर खुद को शर्मसार कर रहे हैं।
सुधींद्र कुलकर्णी@SudheenKulkarni

अगर भारत के साथ-साथ जापान भी आरसेप से बाहर रहता है तो इसके बड़े निहितार्थ होंगे। एशिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बिना आरसेप वैसा नहीं रह जाएगा जैसा उसे लेकर अनुमान लगाया जा रहा था।
सदानंद धूमे@dhume

भारत के खिलाफ पाक फौज की लड़ाई मुख्य रूप से कश्मीर और खालिस्तान पर केंद्रित है। अब पाकिस्तानी मंत्री ने खुद कुबूल किया है कि करतारपुर कॉरिडोर खोलना असल में बाजवा की साजिश है। उनके कुबूलनामे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का कद भी बढ़ाया जिन्होंने दलगत भावना से ऊपर उठकर ऐसी आशंका जताई थी।
ब्रह्मा चेलानी@Chellaney

उत्तर प्रदेश डायरी

यह लल्लू की कांग्रेस है... जुबान चली तो नपे

सद्गुरु शरण
स्थानीय संपादक, लखनऊ

प्रियंका गांधी वाड्रा को नई यानी युवा पीढ़ी का नेता तो नहीं कहा जा सकता यद्यपि वह पुरानी पीढ़ी (राजीव-सोनिया वाली) के बाद की प्रतिनिधि हैं। वर्ष 1977 में मंत्री रहे सत्यदेव त्रिपाठी तो राजीव-सोनिया से भी पहले की पीढ़ी के कांग्रेसी हैं, जबकि उनके साथ पार्टी से बेइज्जत करके निकाले गए नौ अन्य वरिष्ठों को राजीव-सोनिया की पीढ़ी का माना जा सकता है। प्रियंका ने इन सबको धक्के मारकर पार्टी से रुखसत कर दिया, क्योंकि इन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की एक विचित्र आत्म-स्वीकारोक्ति पर आपत्ति जताई थी।

दरअसल अध्यक्ष बनने के बाद लल्लू ने यह जानकारी देकर सबको हैरत में डाल दिया था कि जीवन के शुरुआती दौर में वह धनोपार्जन के लिए सिनेमा के टिकट ब्लैक करते थे। लल्लू पहले नेता नहीं हैं जिन्हें परिस्थितियों के सामने इस तरह संघर्ष करना पड़ा। इसके बावजूद वजह और परिस्थिति जो भी रही हो, टिकट ब्लैक करना अच्छा नहीं माना जाएगा। लल्लू ने अपनी गुजरी जिंदगी का यह पन्ना किस प्रेरणा से खोला, वही बेहतर जानते होंगे, पर प्रदेश अध्यक्ष की जुबान से उद्घाटित इस सच ने अधिकतर कार्यकर्ताओं के मुंह का स्वाद कसैला कर दिया। चाय बेचने और सिनेमा के टिकट ब्लैक करने में बड़ा फर्क है। बहरहाल टिकट ब्लैक करने से शुरू हुई जीवन-यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी हासिल कर लेना साधारण उपलब्धि नहीं, पर इन सठियाए कांग्रेसियों ने इसे उपलब्धि के बजाय अनैतिक कृत्य ठहराने की कोशिश की और अंततः इसका खमियाजा भोगकर पार्टी से बाहर हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में लल्लू की उपलब्धियां ज्यादा चर्चित नहीं हैं। अध्यक्ष बनने के बाद एक वीडियो जरूर वायरल हुआ था जिसमें वह प्रियंका वाड्रा की कार के आगे कई अन्य कार्यकर्ताओं के साथ झूमकर नाचते दिख रहे हैं। कई कांग्रेसियों का यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अपनी बेहतरीन नृत्य-

अजय कुमार लल्लू फाइल फोटो

निपुणता की वजह से वह प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। बेशक यूपी में कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं चल रहे, पर इतने बुरे भी नहीं। प्रियंका जी ने उनमें कोई खूबी जरूर देखी होगी, यह बात सत्यदेव त्रिपाठी एंड कंपनी को भी समझनी चाहिए थी। बुजुर्गों ने समझाया था कि हमेशा सोच-समझकर बोलना चाहिए। वैसे माफी मंगवाकर मामला रफा-दफा किया जा सकता था, पर प्रियंका कुछ ज्यादा ही खफा हो गईं। शायद लल्लू फैक्टर की वजह से उनके दिल को ठेस लगी और उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस के लिए न्योछावर करने वाले दस वरिष्ठों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सिर्फ मक्खन-पॉलिश करके सियासी सफर में चांद-सितारे तलाशने वाले कांग्रेसी बेशक इस फैसले के लिए प्रियंका को बधाई दे रहे हैं, पर निष्ठावान कार्यकर्ताओं को नेतृत्व की यह अति-आक्रामकता अच्छी नहीं लगी। घर में ऐसी बातें होती रहती हैं। इसके लिए इतना अतिवादी कदम। ये सब वे कांग्रेसी हैं जिन्हें हमेशा पता था कि कमजोर नेतृत्व और दिशाहीन नीतियों के कारण कांग्रेस यूपी की सत्ता में वापस नहीं आने वाली। इसके बावजूद पिछले 30 वर्षों में इनमें किसी ने कांग्रेस छोड़ने की बात नहीं सोची। कई अन्य की तरह इन्हें भाजपा, सपा या बसपा में बेहतर स्थान मिल सकता था, पर इनके दिल में कांग्रेस बसती थी। इन्हें आभास नहीं था कि उनकी जुबान से लल्लू के बारे में निकले कुछ लफ्ज उनके जीवन भर की वफादारी पर भारी पड़ जाएंगे।

जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक बुजुर्ग महिला हैं, उस पार्टी में बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कितना उचित है, इस पर बहस करने को कांग्रेस नेतृत्व शायद ही तैयार हो। अब इसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि लीवर खींचा जा चुका है। भाजपा, सपा और बसपा बेशक खुश हैं, क्योंकि कांग्रेस की कमजोरियों से ही ये पार्टियां पिछले तीन दशक में मजबूत हुईं। हां, यह सोचकर कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता जरूर चिंतित हो रहे हैं कि पार्टी की दशा देख नए लोग आ नहीं रहे और पुराने धकियाए जा रहे तो फिर बचेगा कौन? प्रियंका के भरोसे की अपनी वजहें होंगी, पर क्या लल्लू में यह माद्दा है कि अकेले अपने दम पर कांग्रेस को वापस ले आएं?

योगी का अयोध्या एजेंडा जारी : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ दुकानदार टाइप हिंदू-मुस्लिम मठाधीशों को छोड़ दें तो दोनों खेमों में शांति और सुकून है। सबको भरोसा है कि विवाद सुप्रीम कोर्ट के जरिये हमेशा के लिए खत्म हो जाने के बाद अब देर-सबेर मंदिर और मस्जिद बन ही जाएंगे। इसके विपरीत मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम जन्मभूमि विवाद को पीछे छोड़कर अयोध्या की प्रतिष्ठा एवं विकास के लिए जो एजेंडा निर्धारित किया था, उस पर निर्बाध अमल जारी है। अयोध्या में सरयू तट पर साढ़े छह लाख दीपों का रिकॉर्डतोड़ दीपोत्सव, सरयू के किनारे विश्व में सर्वाधिक 251 मीटर ऊंची भगवान राम की प्रतिमा और सरयू पर ही गुप्तारघाट से नयाघाट तक सबसे लंबे नदी तट की स्थापना जैसी परियोजनाओं के बाद रामनगरी को त्रेतायुगीन इक्ष्वाकुपुरी के तर्ज पर विकसित करने की तैयारी मुख्यमंत्री के अयोध्या एजेंडे की ताजा कड़ी है। हिंदू श्रद्धालुओं को हमेशा यह शिकायत रहती थी कि राम और उनकी नगरी को राजनीतिक अस्त्र बनाने के बावजूद भाजपा सरकारों ने अयोध्या के विकास एवं समृद्धि के लिए कुछ नहीं किया। योगी के अयोध्या एजेंडे से यह शिकायत दूर हो गई है। इसी बीच राम मंदिर निर्माण संबंधी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाने से अयोध्या के साथ पूरे प्रदेश का माहौल बम-बम है।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

मुख्य आर्थिक सलाहकार के दावे पर भरोसा किया जाए कि तीसरी तिमाही में विकास दर बढ़ेगी?

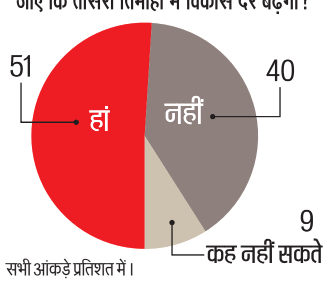

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तानी मंत्री का बयान भारत के लिए खतरे का संकेत है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

दानव के वंशज यहां घूम रहे हर ओर,
जाने कब इस रात की हो पाएगी भोर।
हो पाएगी भोर कि होंगे खत्म दरिंदे,
हो करके स्वच्छंद भरें परवाज परिंदे।
शैतानों के बीच तंग दिखता है मानव,
सुखी देश तब होय चढ़ें जब फांसी दानव।
– ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

पोर्न फिल्मों पर लगे पाबंदी

देश में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, लेकिन स्मार्टफोन और सस्ते डाटा के जरिये पोर्न फिल्मों को देखने की बढ़ती प्रवृत्ति एक बड़ा कारण माना जा रहा है

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

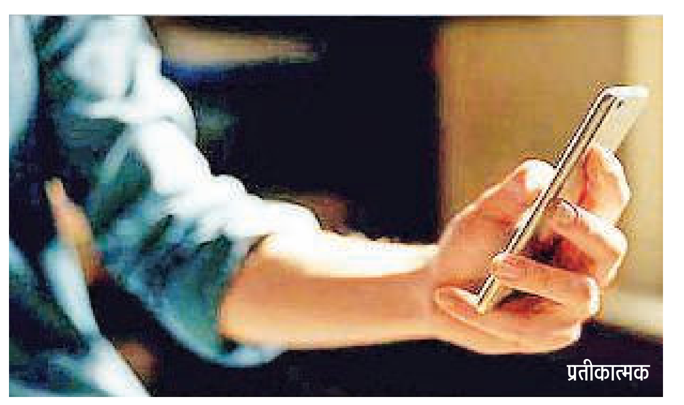

प्रतीकात्मक

उप-राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने देश में लगातार सामने आ रहीं दुष्कर्म की घटनाओं के संदर्भ में पोर्न फिल्मों द्वारा परोसी जा रही अश्लीलता पर चिंता जताई है। अतएव सांसदों की एक समिति से सार्थक उपाय सुझाने का निर्देश दिया है। दरअसल आसान संचार तकनीक ने स्मार्टफोन के जरिये अश्लीलता परोसकर समाज की चिंता बढ़ा दी है।

टेलीकॉम कंपनियों द्वारा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे डाटा का 80 प्रतिशत उपयोग मनोरंजन व अश्लील सामग्री देखने में हो रहा है। जबकि इसे सूचनात्मक ज्ञान बढ़ाने का आधार बताया गया था। दुनिया भर के समाजशास्त्री, राजनेता, कानून विद और प्रशासनिक अधिकारी स्वीकार रहे हैं कि बढ़ते यौन अपराधों का यह एक बड़ा कारण है। चूंकि इंटरनेट पर नियंत्रण विदेशी कंपनियों के हाथों में है, इसलिए वह हर तरह की पोर्न सामग्री परोसकर भारतीय जनमानस के दिमाग को विकृत कर रही हैं।

हालांकि पोर्न फिल्मों पर जताई गई चिंता कोई नई बात नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर केंद्र व राज्य सरकारें भी इस पर चिंता जताती रही हैं, लेकिन इन्हें प्रतिबंधित करने के अब तक कोई सार्थक उपाय सामने नहीं आए। सात वर्ष पहले 'निर्भया' और अब हैदराबाद की महिला पशु चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म के कारणों में एक कारण स्मार्टफोन पर उपलब्ध पोर्न फिल्में भी मानी जा रही हैं।

पोर्न फिल्में देखने के बाद दुष्कर्मियों ने दुष्कर्म करना स्वीकारा है, लिहाजा यह तथ्य सत्य के निकट है। पिछले वर्ष जयपुर में एक शिक्षक द्वारा 25 बच्चों से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। यौन विकृती से पीड़ित मुंबई की एक शिक्षिका को पुलिस ने हिरासत में लिया था। वह बच्चों को अपने घर बुलाकर मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर अपनी यौन कुंठाओं की पूर्ति करती थी। इस तरह की घटनाएं समाज में बढ़ रही उस विकृत मानसिकता को शर्मसार करने वाले हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में पोर्न फिल्में रही हैं।

इंटरनेट की आभासी व मायावी दुनिया से अश्लील सामग्री पर रोक की मांग सबसे पहले इंदौर के जिम्मेदार नागरिक कमलेश वासवानी ने सर्वोच्च न्यायालय से की थी। याचिका में दलील दी गई थी कि इंटरनेट पर अवतरित होने वाली अश्लील वेबसाइटों पर इसलिए प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ये साइटें स्त्रियों एवं बालकों के साथ यौन दुराचार का कारण तो बन ही रही हैं, सामाजिक कुरूपता बढ़ाने और निकटतम रिश्तों को तार-तार करने की वजह भी बन रही हैं। इंटरनेट पर अश्लील सामग्री को नियंत्रित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं होने के कारण जहां इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं दर्शक संख्या भी बेतहाशा बढ़ रही है। ऐसे में समाज के प्रति उत्तरदायी सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह अश्लील प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण की ठोस पहल करे। लेकिन सरकारों ने असहायता जताते हुए शीर्ष न्यायालय को कहा था, 'यदि हम एक साइट अवरुद्ध करते हैं तो दूसरी खुल जाती हैं।'

दरअसल ये साइटें नियंत्रित या बंद इसलिए नहीं होती, क्योंकि सर्वरों के नियंत्रण कक्ष विदेशों में हैं। इस मायावी दुनिया में करोड़ों अश्लील वीडियो एवं क्लीपिंग चलायमान हैं, जो एक क्लिक पर कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि की स्क्रीन पर उभर आती हैं।

यहां सवाल उठता है कि इंटरनेट पर अश्लीलता की उपलब्धता के यही हालात चीन में भी थे। जब चीन ने इस यौन हमले से समाज में कुरूपता बढ़ती देखी तो उसके वेब तकनीक से जुड़े अभियंताओं ने एक झटके में सभी वेबसाइटों को प्रतिबंधित कर दिया। गौरतलब है, जो सर्वर चीन में अश्लीलता परोसते हैं, उनके ठिकाने भी चीन से जुदा धरती और आकाश में हैं। तब फिर यह बहाना समझ से परे है कि हमारे इंजीनियर इन साइटों को बंद करने में क्यों अक्षम साबित हो रहे हैं? चीन ने गूगल की तरह अपने सर्च-इंजन बना लिए हैं जिन पर अश्लील सामग्री अपलोड करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

इस तथ्य से दो आशंकाएं पकट होती हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में एक तो हम भारतीय बाजार से इस आभासी दुनिया के कारोबार को हटाना नहीं चाहते, दूसरे इसे इसलिए भी नहीं हटाना चाहते, क्योंकि यह कामवर्धक दवाओं व उपकरणों और गर्भ निरोधकों की बिक्री बढ़ाने में भी सहायक हो रहा है जो विदेशी मुद्रा कमाने का जरिया बना हुआ है। कई वर्षों से हम विदेशी मुद्रा के लिए इतने भूखे नजर आ रहे हैं कि अपने देश के युवाओं के नैतिक पतन और बच्चियों व स्त्रियों के साथ किए जा रहे दुष्कर्म और हत्या की भी परवाह नहीं कर रहे?

अमेरिका, जापान और चीन से विदेशी पूंजी निवेश का आग्रह करते समय क्या हम यह शर्त नहीं रख सकते कि हमें अश्लील वेबसाइटें बंद करने की तकनीक और गूगल की तरह अपना सर्च-इंजन बनाने की तकनीक दें? लेकिन दिक्कत व विरोधाभास यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कोरिया और जापान इस अश्लील सामग्री के सबसे बड़े निर्माता और निर्यातक देश हैं। लिहाजा वे आसानी से यह तकनीक हमें देने वाले नहीं है।

ब्रिटेन में सोहो एक ऐसा स्थान है, जिसका विकास ही पोर्न वीडियो फिल्मों एवं पोर्न क्लीपिंग के निर्माण के लिए हुआ है। यहां बनने वाली अश्लील फिल्मों के निर्माण में ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करती हैं, जो कामोत्तेजक सामग्री, दवाओं व उपकरणों का निर्माण करती हैं। ये कंपनियां इन फिल्मों के निर्माण में पूंजी निवेश कर मानसिकता को विकृत करने वाले कारोबार को बढ़ावा दे रही हैं। यह शहर 'सेक्स उद्योग' के नाम से ही विकसित हुआ है। बाजार को बढ़ावा देने के ऐसे ही उपायों के चलते ग्रीस और स्वीडन जैसे देशों में क्रमशः 89 और 53 फीसद किशोर कंडोम का उपयोग कर रहे हैं।

सरकार द्वारा साइटों पर पाबंदी लगाने की लाचारी में कंपनियों का नाजायज दबाव और विदेशी पूंजी के आकर्षण की शंकाएं बेवजह नहीं हैं? बावजूद देश के भाग्य विधाताओं को सोचने की जरूरत है कि युवा पीढ़ियों की बर्बादी के लिए खेला जा रहा यह खेल कालांतर में राष्ट्रघाती सिद्ध हो सकता है।

1.40 करोड़ एयर कंडीशनर हैं देश में वर्तमान में, जबकि दुनिया में इनकी संख्या करीब 120 करोड़ है। इस मामले में अमेरिका सबसे आगे है, जहां 90 फीसद घरों में एसी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 2 दिसंबर 2019

डाटागीरी

देश में मातृ मृत्यु अनुपात में दर्ज की गई गिरावट

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के विशेष बुलेटिन 'भारत में 2015-17 में मातृ मृत्यु' में सामने आया है कि देश में मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट आई है। यानी स्थिति में सुधार आया है। इस मामले में केरल सबसे अच्छा, जबकि असम सबसे खराब राज्य रहा।

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर), जिसे प्रति एक लाख बच्चों के जन्म में हुई माताओं की मौत की संख्या के रूप में मापा जाता है, भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। असम में यह अनुपात सबसे ज्यादा 229 है, जबकि केरल में सबसे कम 42 है। यह आंकड़े सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के विशेष बुलेटिन 'भारत में 2015-17 में मातृ मृत्यु' में सामने आए हैं।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में मातृ मृत्यु अनुपात 2014-16 के दौरान 130 से घटकर 2015-17 में 122 तक आ गया। 2004 के बाद से देखें तो इसमें लगभग आधे की गिरावट आइ है। 2004-05 में जहां मातृ मृत्यु दर 254 थी, वहीं 2015-17 में 122 तक पहुंच गई। वर्ष 2013 के बाद से देखें तो मातृ मृत्यु दर में 26.9 प्रतिशत की कमी देखी गई है।

रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में बच्चों को जन्म देने वालीं प्रत्येक पांच मां में एक को खतरा रहता है। राज्यों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा एमएमआर असम में दर्ज किया गया है। यहां 2015-17 में एमएमआर 229 प्रति एक लाख दर्ज किया गया। हालांकि, इसमें कुछ सुधार आया है 2014-16 में यहां एमएमआर 237 प्रति एक लाख था। इसके बाद उत्तर प्रदेश (216), मध्य प्रदेश (188), राजस्थान (186), ओडिशा (168), बिहार (165) और फिर छत्तीसगढ़ (144) आते हैं।

अगर मातृ मृत्यु दर की बात करें तो यह सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में (20.1) है। इसके बाद मध्य प्रदेश (17.5), बिहार (16.9), राजस्थान (16.8) और असम (15.2) है। मातृ मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अनुपात दोनों अलग-अलग हैं। मातृ मृत्यु दर एक निश्चित आबादी में बच्चों को जन्म देने वाली कुल महिलाओं में जान गंवाने वाली महिलाओं की संख्या भाग देकर उसे एक लाख से गुणा कर दिया जाता है।

2030 तक एमएमआर को 70 से कम लाना है लक्ष्य : सबसे कम एमएमआर केरल में (42) और इसके बाद महाराष्ट्र (55), तमिलनाडु (63), आंध्रप्रदेश (74), झारखंड (76) और तेलंगाना (76) है। इस तरह कह सकते हैं कि इन राज्यों की स्थिति सबसे अच्छी रही। मातृ मृत्यु दर के मामले भी केरल (1.9) में सबसे कम हैं। महाराष्ट्र (3.3) के साथ दूसरे नंबर पर है। संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स (एसडीजी) के अनुसार, वैश्विक लक्ष्य 2030 तक एमएमआर को 70 से कम लाना है। इसके लिए सभी देश अपने-अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं। इसके बाद ही स्थिति में और सुधार आना संभव हो सकेगा।

प्रतीकात्मक

मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) भारत में (प्रति एक लाख की आबादी में)

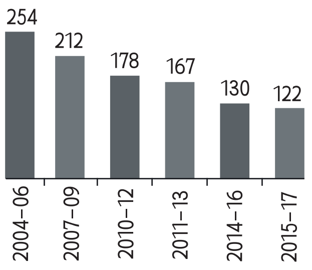

उच्च एमएमआर वाले राज्य

राज्य	मातृ मृत्यु अनुपात	मातृ मृत्यु दर
असम	229	15.2
उत्तर प्रदेश	216	20.1
मध्य प्रदेश	188	17.5
राजस्थान	186	16.8
ओडिशा	168	11.1
बिहार	165	16.9
छत्तीसगढ़	141	11.0

निम्न एमएमआर वाले राज्य

राज्य	मातृ मृत्यु अनुपात	मातृ मृत्यु दर
केरल	42	1.9
महाराष्ट्र	55	3.3
तमिलनाडु	63	4.8
आंध्र प्रदेश	74	3.6
झारखंड	76	6.1
तेलंगाना	76	3.8

फुटबॉल ने गिराई मजहब की दीवार

जागरण विशेष ▶ शमीम और संदीप ने विपरित हालात में बनाया रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब

युवाओं को मिली सकारात्मक दिशा, विदेशी खिलाड़ी भी बने टीम का हिस्सा

रोहित जंडियाल, जम्मू

एक खेल ने कश्मीर की तस्वीर बदल दी है। अलगाववादियों और आतंकवादियों की दहशत को दरकिनार कर कश्मीरी मुस्लिम शमीम मेराज और कश्मीरी पंडित संदीप चट्टू ने मिलकर हिंदू-मुस्लिम एकता का ऐसा बीज बोया, जिसने कश्मीर को नई पहचान दी है। दोनों ने विपरीत हालात में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब का गठन किया। आज यह पूरे देश में चर्चित क्लब है। संदीप और मेराज कहते हैं कि हमने युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर मजहब की दीवार फुटबॉल से गिरा दी है। हमारा मकसद नए कश्मीर को फुटबॉल का स्वर्ग बनाना है।

संदीप चट्टू और शमीम दोस्त हैं। वर्ष 2014 में कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली थी। उस समय कई बच्चे गलियों में बैठे रहते थे। उनमें कई बच्चे नशा करने लगे थे। यह देख दोनों दोस्तों ने उनके लिए कुछ करने की ठानी। उन्होंने बच्चों को खेलने के लिए फुटबॉल दिया। यहीं से नया रास्ता खुल गया। दोनों ने देखा कि कुछ दिनों में सैकड़ों बच्चे फुटबॉल लेकर छोटे-छोटे मैदानों में खेल रहे हैं। चट्टू का कहना है कि उन्हें लगा कि बच्चों में फुटबॉल खेलने को लेकर जबरदस्त उत्साह है। 2016 में रियल फुटबॉल क्लब की नींव रखी। इसके बाद पूरे कश्मीर से जुझारू खिलाड़ियों को परखकर एक टीम तैयार की, जिसने अपने खेल से खलबली मचा दी।

लोग कहते थे पंडित-मुस्लिम कैसे साथ : लोगों को यह दुर्लभ घटना लगती थी कि मुस्लिम बहुल कश्मीर में एक पंडित और मुसलमान ने मिलकर फुटबॉल क्लब बनाया। कई लोगों ने इसमें सहयोग किया, तो कुछ ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन स्थानीय लोगों ने प्यार और आशीर्वाद ने इस काम को आसान बना दिया।

हर जगह हैं फैन : तीन साल में ही इस फुटबॉल क्लब ने देश-विदेश में समर्थक बना लिए। पहले ही साल में राष्ट्रीय फुटबॉल लीग में रियल कश्मीर तीसरे स्थान पर रहा। टीम के सदस्य दानिश राणा को कश्मीर का रोनाल्डो कहा जाता है। चट्टू का कहना है कि डुरंड कप में खेल के दौरान बच्चे बैनर लेकर टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे। कोलकाता में ईस्ट बंगाल और मोहन बागान में हुए मैच में उन्हें समर्थन मिला था। स्कॉटलैंड और यूरोप तक में उनके क्लब के समर्थक हैं।

इस साल भी बेहतर की उम्मीद : संदीप और शमीम का कहना है कि इस साल के सीजन में उन्हें बेहतर करने की उम्मीद है। इस क्लब ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। कश्मीर में भी शांति स्थापित हो रही है। उम्मीद है कि फुटबॉल के जरिये कश्मीर में शांति बहाली में और मदद मिलेगी।

कई कंपनियों ने किए करार : इस क्लब ने बहुत जल्दी ख्याति प्राप्त कर ली। कई बड़ी कंपनियों ने इसके साथ करार किया है। राज्य प्रशासन भी कश्मीरी खिलाड़ियों के जच्बे को देख टीम की मदद भी कर रही है। रियल कश्मीर क्लब पर बनी डाक्यूमेंट्री फिल्म को भी अवार्ड मिला था।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/jagran-special

फुटबालर बाएं से दानिश राणा, संदीप चट्टू और शमीम मेराज। जागरण आर्काइव

कई देशों से हैं खिलाड़ी

रियल क्लब में इस समय स्कॉटलैंड, जिंबाब्वे, नाइजीरिया, कीनिया, ब्रिटेन से खिलाड़ी हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, पंजाब, उत्तर-पूर्वी राज्यों और कोलकाता से भी खिलाड़ी हैं। संदीप का कहना है कि क्लब में सांस्कृतिक विविधता है। खिलाड़ियों में सिर्फ फुटबॉल को लेकर उत्साह है। अलग-अलग जगहों से होने के बावजूद एक टीम की तरह खेलना अच्छा लगता है।

काई बताएगी 'पानी की कहानी'

हिमांशु मिश्र, बरेली : पानी वाली जगहों पर हरे रंग की दिखाई देने वाली काई जिसे देखकर अक्सर लोग मुंह फेर लेते हैं असल में वो बड़े काम की चीज है। इसकी मदद से आप पानी की पूरी कहानी जान सकते हैं। यानी पानी में किस तरह के कीटाणु पनप रहे, आर्सेनिक, लैड आदि भारी तत्वों की सटीक पहचान कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर रुहेलखंड विश्वविद्यालय (रुविवि) के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. ललित कुमार पांडेय ने इसको लेकर शोध किया है।

▶ **साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों संग रुविवि के असिस्टेंट प्रोफेसर ने किया शोध, तैयार की स्पेशल अल्वा किट**

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनरल ऑफ हजारडस मैटेरियल्स ने डॉ. ललित के इस शोध को मान्यता भी दे दी है। डॉ. ललित ने बताया कि साउथ कोरिया के इनशियॉन नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काई का अल्वा किट तैयार किया गया है। यह किट पानी में मौजूद सभी तत्वों की मात्रा और उसके प्रकार की जानकारी दे देगी। वैज्ञानिक जांच के लिए यह किट अन्य के मुकाबले काफी सस्ता है। डॉ. ललित के मुताबिक, 10 लाख रुपये से सामान्य किट मिलनी शुरू होती है और 50 लाख रुपये तक की मिलती हैं, लेकिन जो परिणाम इन महंगे किट से मिलेंगे वही परिणाम अल्वा किट देगा। अल्वा किट का दाम पांच हजार रुपये रखा गया है। दक्षिण कोरिया में इसे लांच भी कर दिया गया है। अब भारत में इसे लांच करने के लिए निजी कंपनियों से बातचीत चल रही है।

उत्तराखंड के आठवीं कक्षा के छात्र ने तैयार किया पॉलीथिन का विकल्प

रोहित लखेड़ा, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

▶ **राजकीय इंटर कॉलेज अनस्यारी में पढ़ता है 13 साल का प्रमोद परिहार**

▶ **इनका बनाया मॉडल बना प्रांतीय विज्ञान महोत्सव में आकर्षण का केंद्र**

▶ **प्रमोद के पिता प्रकाश परिहार गांव में ही इलेक्ट्रीशियन का कार्य करते हैं**

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में राजकीय इंटर कॉलेज अनस्यारी का 13 साल का छात्र प्रमोद परिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को परवान चढ़ाने में जुटा है। कक्षा आठ के इस विद्यार्थी ने पॉलीथिन का ऐसा विकल्प तैयार किया है, जो न केवल सस्ता है, बल्कि पूरी तरह से एंवायरमेंट फ्रेंडली भी है।

कोटद्वार के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रांतीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण महोत्सव में पॉलीथिन का यह विकल्प सभी के आकर्षण का केंद्र बना रहा। बागेश्वर जिले के बूंगा गांव का रहने वाले प्रमोद परिहार ने यह कारनामा किया है। प्रमोद के पिता प्रकाश परिहार गांव में ही इलेक्ट्रीशियन का कार्य करते हैं, जबकि माता ललिता देवी गृहणी हैं। प्रमोद के बड़े भाई रोहित भी उन्हीं के साथ कक्षा आठ के छात्र हैं।

प्रमोद के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पर्यावरण संरक्षण की अपील कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। वह बताते हैं कि उन्होंने लीसा (चीड़ के पेड़ से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ), गोंद और नमक के मिश्रण से इसे तैयार किया है। इससे पॉलीथिन जैसे कैरी बैग बनाए जा सकते हैं। इसकी खूबी यह है कि फेंकने के बाद यह खुद ही गल जाता है। वह बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में लीसा आसानी से मिल जाता है। ऐसे में यह विकल्प सस्ता भी है। प्रांतीय विज्ञान महोत्सव के संयोजक जगमोहन सिंह रावत कहते हैं कि प्रमोद के बनाया पॉलीथिन का विकल्प भविष्य की राह प्रशस्त करने वाला है। वह कहते हैं कि प्रमोद अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। प्रमोद के इस प्रयोग को महोत्सव में प्रथम पुरस्कार मिला है।

खेल-खेल में हुआ आविष्कार : प्रमोद ने बताया कि अवकाश के दिन अक्सर वह मवेशी लेकर जंगल जाते हैं। साथ में वह तख्ती (एक प्रकार की लकड़ी से बनी स्लेट) भी ले जाते हैं, जिससे समय मिलने पर सुलेख का अभ्यास किया जा सके। एक दिन उन्होंने तख्ती पर लीसा, गोंद और नमक का मिश्रण का लेप कर दिया। करीब एक घंटे बाद जब उनका ध्यान तख्ती पर गया तो देखा कि एक परत जमी हुई है। परत दिखने में पॉलीथिन की भांति थी। उत्साहित प्रमोद ने घर लौटकर यह प्रयोग बार-बार दोहराया। इसके बाद उन्होंने अपने शिक्षकों को इससे अवगत कराया तो उन्होंने भी प्रमोद का उत्साह बढ़ाया।

पौड़ी के कोटद्वार में आयोजित प्रांतीय विज्ञान महोत्सव में लीसा, गोंद व नमक से तैयार पॉलीथिन के विकल्प को दिखाते प्रमोद परिहार। जागरण

'एक्सीलेंट 40' के जरिये तराश रहे देश का भविष्य

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर

▶ **राजस्थान में आइएएस अफसर रवि जैन ने गरीब बच्चों को सिविल सर्विसेज में भेजने का लिया संकल्प**

विद्या ऐसा धन है, जिसे जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है और इसी धन की बदौलत न केवल व्यक्ति बल्कि देश के स्वर्णिम भविष्य की इबारत लिखी जा सकती है। ऐसा ही विचार है राजस्थान के झुंझुनूं जिले में जिला कलेक्टर के पद पर कार्यरत आइएएस अधिकारी रवि जैन का, जिन्होंने बीड़ा उठाया है वंचित वर्ग की प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने का। दरअसल, रवि जैन ने बिहार के 'सुपर 30' की तर्ज पर राजस्थान के झुंझुनूं में 'एक्सीलेंट 40' शुरू किया है। इसके माध्यम से उन्होंने गरीब परिवारों के युवाओं का भविष्य संवारने का बीड़ा उठाया है। जिस तरह बिहार के सुपर 30 में हर साल 30 बच्चों को आइआइटी में प्रवेश की तैयारी कराई जाती है, उसी तरह एक्सीलेंट 40 में प्रतिवर्ष 40 बच्चों को सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई जाती है।

राजस्थान में ही जोधपुर शहर के मूल निवासी रवि जैन ने सिविल इंजिनियर एवं एमबीए की शिक्षा हासिल करने के बाद सिविल सेवा में भाग्य अजमाया और सफलता हासिल की। 2004 में उनका आइएएस में चयन हुआ। आइएएस अधिकारी के रूप में अपने 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने हमेशा सफाई और शिक्षा पर जोर दिया। बाड़मेर, चित्तोडगढ़ और बीकानेर जिलों में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया। ऐसे परिवार जिनके बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, उनका सरकारी स्कूलों में प्रवेश कराया। झुंझुनूं के कलेक्टर बनने के बाद उन्होंने यहां के युवाओं को सिविल सेवा में भेजने का बीड़ा उठाया। इसी के लिए उन्होंने एक्सीलेंट-40 क्लास शुरू की है। वह अपनी ड्यूटी के बाद नियमित रूप से युवाओं को परीक्षा की तैयारी कराते हैं। रवि जैन के पिता धनपत राय जैन सहकारिता विभाग में कर्मचारी थे। एक मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने शुरू से ही गरीबों का शैक्षिक स्तर ऊंचा उठाने पर जोर दिया। बचपन से लेकर एमबीए तक की शिक्षा पूरी करने तक वे अपनी पाठ्यपुस्तकें गरीब परिवारों के बच्चों के वितरित करते थे।

इस तरह हुई शुरुआत : झुंझुनूं में पहले 'कलेक्टर की क्लास' नाम से युवाओं को सरकारी सेवा की तैयारी कराई जाती थी, लेकिन रवि जैन ने कुछ समय पूर्व इसे एक नया नाम 'एक्सीलेंट 40' दिया। इसके जरिये राज्य प्रशासनिक एवं सिविल सेवा की तैयारी कराने का काम हाथ में लिया है। कलेक्टर की क्लास से कई युवाओं को सरकारी नौकरी हासिल हुई है। रवि ने बताया कि अब तक कलेक्टर की क्लास के चार बैच में 70 युवा आरएएस मैंस तक पहुंच गए हैं, जबकि चार दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर चुके हैं। नौ युवाओं ने फिजीकल क्लियर कर लिया है। इसके अलावा चार अध्यापक सेकंड ग्रेड, एक लेक्चरर, एक कॉलेज प्रोफेसर, एक अतिरिक्त स्टेशन तथा छह युवा थर्ड ग्रेड टीचर, छह युवा एलडीसी तथा एक रेलवे आरपीएफ में ज्वाइन कर चुके हैं। इनमें लड़कियों की संख्या अधिक है। अब इसे एक्सीलेंट 40 के नाम से आगे बढ़ाया जा रहा है।

रवि जैन जागरण

प्रवेश के लिए परीक्षा, कोई शुल्क नहीं

'एक्सीलेंट 40' में युवाओं का चयन करने के लिए एक प्रवेश परीक्षा ली जाती है। इस साल की प्रवेश परीक्षा हाल ही में संपन्न हुई। इसके लिए 346 युवाओं ने आवेदन किया था। इन युवाओं में 40 युवाओं को चयनित किया गया। वहीं, करीब 10 युवाओं को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। खास बात यह रही कि इस बैच में करीब 70 फीसद बेटियों को मौका मिला है। इसमें चयनित होने वाले युवाओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, साथ ही शैक्षिक सामग्री को रवि जैन अपने वेतन और दानदाताओं के सहयोग से नि:शुल्क मुहैया कराते हैं।

100 रुपये का एक अमरूद, बिक रहा हाथों-हाथ

▶ **हरियाणा के जींद जिले के किसान ने जैविक तरीके से दो साल पहले लगाया बाग**

▶ **एक अमरूद का वजन 800 ग्राम से भी ज्यादा, दूर दराज के लोगों को भी भा रहा**

▶ **एक एकड़ में पैदा कर रहे थाइलैंड में मिलने वाली खास प्रजाति के अमरूद**

बिजेंद्र मलिक, जींद

हरियाणा के जींद जिले के कंडेला गांव में अमरूद किलो के भाव से नहीं, बल्कि प्रति नग के हिसाब से बिक रहा है। एक नग की कीमत 100 रुपये है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि इतना महंगा तो सेब भी नहीं होता है। दरअसल, यह कोई बाजार में मिलने वाला सामान्य अमरूद नहीं है, बल्कि इसे जैविक तरीके से उगाया गया है। एक अमरूद का वजन 800 ग्राम से एक किलो तक है। कंडेला के किसान सुनील कंडेला ने अपने खेत में दो साल पहले तीन एकड़ में अमरूद का बाग लगाया था। इसमें से एक एकड़ में थाइलैंड की किस्म के अमरूद लगाए हैं। इसमें पैदा हो रहे अमरूद केवल गांव ही नहीं, दूर दराज के लोगों को भी भा रहे हैं।

सुनील के मुताबिक, इस साल बड़ी मात्रा में अमरूद का उत्पादन हुआ। न मार्केटिंग करनी पड़ी और न ही बेचने के लिए मंडी जाना पड़ा। खेत से ही अमरूद खरीदकर ले जाने वालों की होड़ लग गई। आसपास के गांवों के अलावा दूसरे जिलों व राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। गत सप्ताह चौपाल ऑर्गेनिक कल्याण मंच के संस्थापक विनोद मेहता के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सुनील के खेत में पहुंचा, जिसमें विनोद शर्मा, राजेंद्र सिंह व नरवीर चौहान शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए अमरूद के फलों की प्रक्रिया समझी। वे अपने साथ 10 किलो अमरूद लेकर गए हैं, ताकि वहां लोगों को इसके आकार व स्वाद के बारे में बता सकें।

ऐसे किया तैयार : सुनील ने बताया कि उन्होंने पौधे पर लगे फलों को ट्रिपल प्रोटेक्शन फॉम से कवर किया, जिससे फल पर गर्मी, सर्दी, धूल व बीमारियों का सीधा असर ना हो। इससे अमरूद का आकार भी काफी बढ़ गया। इसमें ना तो किसी तरह के स्प्रे का प्रयोग किया गया है और न ही रासायनिक खाद का। खेत में घास-फूस व पौधों के पत्तों को गला कर तैयार की गई खाद का प्रयोग करते हैं।

डालते हैं गाय का गोबर : सुनील ने तीन गाय पाल रखी हैं। इनके गोबर व मूत्र को खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। खाद व मूत्र में डी-कंपोजर डाल कर जैविक खाद बनाते हैं। सुनील बताते हैं कि इससे लागत भी काफी कम आती है और फसल में किसी तरह के कीटनाशकों का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता।

पानीपत से पहुंची कृषि विभाग की टीम : सुनील के बाग को देखने के लिए पानीपत से कृषि विभाग की टीम पहुंची, जिसने अमरूद की क्वालिटी देखी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में पहली बार इस किस्म का अमरूद देखा है और स्वाद भी अच्छा है।

पौधे पर लगे अमरूद को दिखाते किसान सुनील कंडेला। जागरण

राजाजी टाइगर रिजर्व में शिकारियों के मंसूबे नाकाम करेगी 'स्ट्राइक फोर्स'

केदार दत्त, देहरादून

▶ **राजाजी टाइगर रिजर्व में पहली बार कर्मियों को दी गई कमांडो ट्रेनिंग**

▶ **स्ट्राइक फोर्स के लिए कमांडो ट्रेनिंग लेने वाले 18 वन रक्षक चयनित**

▶ **शिकारियों और तस्करों पर नकेल कसने को स्ट्राइक करेगी यह फोर्स**

एशियाई हाथियों के लिए मशहूर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में अब शिकारियों के मंसूबे नेस्तनाबूद करने को 'सर्जिकल स्ट्राइक' होगी। इसके लिए पहली बार 50 वन रक्षकों को कमांडो ट्रेनिंग दी गई, जिनमें से 18 का चयन 'स्ट्राइक फोर्स' के लिए किया गया है। यह फोर्स शिकारियों-तस्करों के खिलाफ स्ट्राइक करेगी। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इस रिजर्व में सुरक्षा व्यवस्था अधिक पुख्ता होगी।

विषम भूगोल और 71 फीसद वन भूभाग वाले उत्तराखंड में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में जंगल के रखवालों का शारीरिक रूप से सशक्त होना ही पर्याप्त नहीं, मानसिक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है। इसी के दृष्टिगत राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक पीके पात्रो ने रिजर्व की सुरक्षा में तैनात वन रक्षकों को कमांडो ट्रेनिंग दिलाने का निर्णय लिया। इसके लिए ऐसे व्यक्ति के चयन पर जोर दिया गया, जो अर्से तक जंगल से जुड़े अभियानों से जुड़ा रहा हो। ट्रेनिंग को बतौर ट्रेनर एसटीएफ तमिलनाडु के इंस्पेक्टर जे. सुरेश का नाम फाइनल हुआ। सुरेश ने चंदन तस्कर वीरप्पन के खिलाफ चले अभियान में अहम भूमिका निभाई थी। इंस्पेक्टर सुरेश की अगुआई में राजाजी के मिट्ठावाली, धौलखंड के जंगलों में 20 से 27 नवंबर तक ट्रेनिंग हुई, जिसमें रिजर्व के 50 वन रक्षकों ने भाग लिया।

निदेशक पात्रो के अनुसार, अब स्ट्राइक फोर्स गठित हो रही है, जिसके लिए कमांडो ट्रेनिंग लेने वाले वन रक्षकों में से 18 का चयन किया गया है। यह फोर्स जरूरत पड़ने पर कहीं भी शिकारियों-तस्करों के खिलाफ स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक फोर्स के सदस्य अन्य कर्मियों को समय-समय पर कमांडो ट्रेनिंग देंगे।

ये सीखे गुर : फायर ड्रिल, घात लगाना, सर्च ऑपरेशन, पेड़ों की टहनियां व पत्तियां लगाकर जंगल से चिपककर रहना, रेसक्यू ऑपरेशन, हथियारों का रखरखाव, रॉक व ट्री क्लाइंबिंग, ऑपरेशन के दौरान हथियार की पोजिशन, ट्रैप लगाना, स्टाफ को बचाना आदि।

इसलिए माना जाता है संवेदनशील : देहरादून, हरिद्वार व लैंसडौन प्रभागों के मध्य स्थिति राजाजी टाइगर रिजर्व 1075.17 वर्ग किमी में फैला है। इसमें 840 वर्ग किमी कोर और शेष बफर जोन है। चारों तरफ आबादी और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण इसे संवेदनशील माना जाता है।

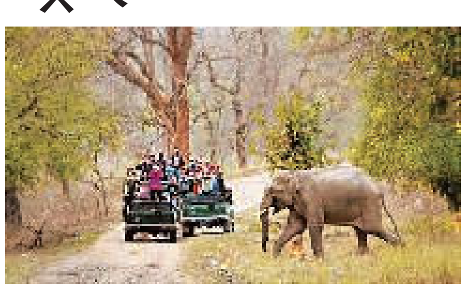

राजाजी टाइगर रिजर्व का लुत्फ उठाते सैलानी। फाइल

संक्रमण से बचाएगी आइआइटी रुड़की की नई तकनीक

रीना डंडरियाल, रुड़की

▶ **लंबी अवधि के लिए शरीर के किसी खास हिस्से में दवा पहुंचाने में मदद करेगी यह तकनीक**

▶ **ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में अमूमन बना रहता है सर्जरी के बाद संक्रमण का खतरा**

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी विशेष तकनीक ईजाद की है, जो शरीर के किसी खास हिस्से में लंबी अवधि के लिए दवा पहुंचाने में मददगार होगी। यह तकनीक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी फायदेमंद होगी क्योंकि इसी समस्या में सर्जरी के बाद अक्सर संक्रमण का खतरा बना रहता है।

आइआइटी रुड़की की शोधकर्ता प्रमुख प्रोफेसर देवरूपा लाहिरी ने बताया कि हड्डियों के क्षतिग्रस्त अथवा रोगग्रस्त होने पर आर्थोपेडिक सर्जरी में बायोमेडिकल ग्रेड इंप्लांट लगाने का काफी चलन है। हालांकि, इस तरह की सर्जरी में इंप्लांट वाले हिस्से में बैक्टीरिया का संक्रमण एक आम समस्या है। दरअसल, हड्डी इंप्लांट के दस फीसद मामले बीमारियों की वजह से व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसे में इस समस्या को दूर करने के लिए दवाइयों की उच्च खुराक दी जाती है। इसी को देखते हुए संस्थान के शोधकर्ताओं ने बायोमेडिकल इंप्लांट लगाने के बाद की इस समस्या को दूर करने के लिए एक नई पद्धति विकसित की है। इससे इंप्लांट वाले हिस्से में बैक्टीरिया संक्रमण का खतरा न्यूनतम होगा। इसके तहत मेटलिक इंप्लांट की सतह में परिवर्तन किया जाएगा और उस पर बैक्टीरिया रोकने की दवा लगा दी जाएगी। दवा इंप्लांट वाले हिस्से में एक सप्ताह या इससे अधिक समय तक धीरे-धीरे पहुंचती रहेगी। इससे किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा।

प्रो. देवरूपा ने बताया कि यह दवा बायोमेडिकल ग्रेड टाइटेनियम एलॉय मेटल की सतह पर हाइड्रॉक्सी एपेटाइट (एचए) के माइक्रो-लेयर में रखी जाएगी। एचए में दवा भरने के लिए छिद्र बने हैं। इसके साथ ही इस पद्धति में हड्डी और इंप्लांट का जुड़ना भी आसान होगा। बताया कि परीक्षण अगले चरण में है और पॉलीमर में दवाइयों का मिश्रण देने व दवा निकलने की अवधि बढ़ाकर एक महीना करने के लिए टीम जुटी है। प्रो. देवरूपा के अनुसार, यह भारतीय पेटेंट बनने वाला है। यह इनोवेशन प्रो. पार्थ रॉय, उनके ग्रुप और प्रो. अरविंद अग्रवाल एवं फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अमेरिका में उनके ग्रुप के सहयोग से किया गया है। डॉ. मनोज कुमार और उनकी टीम इसमें शामिल है।

बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है सुरक्षा परत : शोधकर्ताओं ने बताया कि टाइटेनियम मेटल एलॉय शीट पर प्लाज्मा स्प्रे तकनीक से हाइड्रॉक्सी एपेटाइट की 200-माइक्रोन मोटी परत बनाई गई। एचए एक जैव-अनुकूल मटेरियल है। जिसकी हड्डी की तरह संरचना है और यह सिरामिक इंप्लांट में इस्तेमाल होता है। इस पद्धति में एक प्रचलित दवा जेंटामाइसीन को बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर चिटोसन के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद दवायुक्त पॉलीमर लिक्विड को निर्वात में एचए के छिद्रों में भर दिया जाता है। चिटोसन धीरे-धीरे इंप्लांट वाले हिस्से में गल जाता है। शरीर के विभिन्न द्रवों के प्रभाव में सहज ढंग से ऐसा होने के कारण दवा सही जगह पहुंच जाती है। यह दवा सुरक्षा परत बनाकर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है।

आइआइटी रुड़की। फाइल

इंप्लांट की चोट सहने की क्षमता 42 फीसद बढ़ी

शोधकर्ताओं ने पॉलीमर-एचए के तालमेल में एक अन्य लाभ भी देखा है। इससे इंप्लांट की चोट सहने की क्षमता 42 फीसद तक बढ़ गई। परीक्षण से सामने आया कि इंप्लांट मैटेरियल में परिवर्तन से एस औरियस बैक्टीरिया रोकने की उत्कृष्ट क्षमता दिखी। आर्थोपेडिक सर्जरी में इस बैक्टीरिया की वजह से इंप्लांट संबंधी संक्रमण पाए गए। इतना ही नहीं, मानव ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पर हुए परीक्षण में भी यह सामने आया कि एचए ने परिवर्तित सतह के साथ जैव अनुकूलता बढ़ा दी।

100 साल पुराने मंदिर का स्ट्रक्चर उसके आधार से पांच फीट उठाया गया है तमिलनाडु में मदुरई के पालंगनाथम में। अरुलमिगु कलियम्मन मंदिर के 600 टन वजनी इस स्ट्रक्चर को उठाने के लिए हरियाणा की एक कंपनी की मदद ली गई।

पहाड़ों को दे रहे प्रदूषण से आजादी, ताकि न लगे सांसों पर ताला

स्वच्छता की अलख ▸ पहाड़ों को कचरा मुक्त करने के लिए मनाली निवासी कौशल भारद्वाज ने चलाया है अभियान

जसवंत ठाकुर, मनाली

सैलानियों को पहाड़ों की सैर करवाने के साथ इन्हें स्वच्छ रखने का जिम्मा उठाया। लोगों का साथ मिला तो अब इसे जीवन का ध्येय ही बना लिया। यह प्रण कर लिया है कि उन्हीं पर्यटकों को ट्रैकिंग अभियानों पर ले जाएंगे जो स्वच्छता में योगदान देंगे। कुल्लू जिले की चोटियों से कई गाड़ियों में कचरा भरकर मनाली कूड़ा संयंत्र पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के मनाली के ब्राण गांव के पर्वतारोही कौशल भारद्वाज के इस प्रयास में अब कई संस्थाएं भी जुड़ गई हैं।

पर्यावरण संरक्षण

मनाली के अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान से पर्वतारोहण में बेसिक और एडवांस कोर्स करने के बाद कौशल भारद्वाज ने कई साल इसी संस्थान में गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में सेवाएं दीं। पहाड़ों को नापने के जुनून के चलते नौकरी छोड़ दी। डिस्कवर हिमालया संस्था का गठन किया और काफी समय तक लद्दाख में काम किया। लद्दाख की कई पहाड़ियों के लिए नए ट्रैकिंग रूट खोज निकाले और पर्वतारोहण में अपनी धाक जमाई।

कौशल ने इसके बाद कुल्लू और मनाली में काम शुरू किया। वह जब भी ट्रैकिंग अभियान पर जाते तो चोटियों पर कूड़े के ढेर देखकर मन उदास हो जाता। फिर सोचा क्यों न प्रकृति को संवारने में योगदान दिया जाए। इसके बाद कौशल ने इन पहाड़ों की सफाई का बीड़ा उठाया। उन्होंने कुल्लू जिले की चोटियों देओ टिब्बा, हनुमान टिब्बा, पिन पार्वती पास, फ्रेंडशिप पीक, ब्यास कुंड, भृगु झील, कनामो पीक और कई अन्य इलाकों में सफाई अभियान चलाकर 20 से अधिक जीप कूड़ा एकत्र किया। इसे मनाली के रांगड़ी कूड़ा संयंत्र केंद्र में पहुंचाया।

मुहिम को प्रभावी बनाने के लिए शपथ ली : इस मुहिम को और भी प्रभावी बनाने के लिए कौशल ने अब शपथ ली है कि वह सिर्फ उन्हीं सैलानियों को ट्रैकिंग अभियानों पर ले जाएंगे जो सफाई में योगदान देंगे। ट्रैकिंग के दौरान कचरे को एकत्र करेंगे और इसे लाने में भी सहयोग देंगे। अब अन्य ट्रैकर भी कौशल बताए रास्ते पर चलने लगे। देश के कई बड़े पर्वतारोहण क्लब और एजुकेशन संस्थान भी उसके साथ जुड़ गए हैं। देश का अग्रणी शिक्षा संस्थान आइआइटी भी कौशल की डिस्कवर हिमालया संस्था से जुड़कर विद्यार्थियों को पर्वतारोहण और कई अन्य साहसिक गतिविधियों की शिक्षा दे रहे हैं। हर साल विभिन्न ट्रैकिंग रूट पर मिलकर सफाई अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

कौशल आइआइटी मंडी में पर्वतारोहण प्रशिक्षण भी देते हैं। मनाली के पहले टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर रूप चंद नेगी व अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण खेल संस्थान के निदेशक कर्नल नीरज राणा ने कौशल भारद्वाज के कार्य की प्रशंसा की है।

पहाड़ों को कचरामुक्त करने के अभियान में जुटे हैं मनाली के कौशल भारद्वाज। जागरण

▸ देओ टिब्बा, हनुमान टिब्बा, पिन पार्वती पास, फ्रेंडशिप पीक समेत कई चोटियों को कर चुके हैं साफ

▸ पहल के बाद अब कई संस्थाएं उनके साथ जुड़ीं, दे रहीं पहाड़ों को स्वच्छ रखने में योगदान

देश-विदेश से सैलानी प्रकृति को नजदीक से निहारने हिमाचल आते हैं। चोटियों पर बिखरी गंदगी पर्यटकों के सामने शर्मिंदा करती है। प्रदूषण पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को कर्तव्य मानकर कई चोटियों पर सफाई अभियान चलाया। अब उन्हीं सैलानियों को ट्रैकिंग पर ले जाता हूं, जो मेरे साथ वहां सफाई करते हैं और कचरा वापस ले आते हैं।

– कौशल भारद्वाज, संचालक डिस्कवर हिमालया संस्था मनाली

ये संस्थाएं जुड़ी हैं कौशल के साथ

स्वास्तिक माउंटेनियरिंग क्लब बेंगलुरु, आइआइटी मंडी, बाली भागीरथी क्लब कोलकाता, द लद्दाख टूर्स लेह सहित कुल्लू मनाली के 12 से अधिक टूर एंड ट्रैकिंग ग्रुप कौशल भारद्वाज के साथ जुड़े हैं। ये पहाड़ों को स्वच्छ रखने में योगदान दे रहे हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

माघ मेला की सफलता के लिए गंगा पूजन अक्षयवट के द्वार खुले

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : प्रयागराज में माघ मेला सकुशल संपन्न होने की कामना के लिए रविवार को संगम नोज पर गंगा पूजन किया गया। इसमें मेला की तैयारियों में लगे प्रशासन व पुलिस सहित 11 विभागों के अधिकारी शामिल हुए। सभी ने विधि विधान से मां गंगा की पूजा की। इसके बाद डीएम भानुचंद्र गोस्वामी एवं सांसद केशरी देवी पटेल ने किले के गेट पर फीता काटकर अक्षय वट दर्शन का शुभारंभ किया। सोमवार से आम श्रद्धालु भी दर्शन कर सकेंगे। दस जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ माघ मेला की शुरुआत होगी। मेला बसाने का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी बीच रविवार को दो घंटे चली पूजा में डीएम सपत्नीक शामिल हुए।

बाढ़ के चलते चार माह बंद था दर्शन : अक्षयवट का दर्शन-पूजन करने के बाद डीएम ने श्रद्धालुओं के लिए कराई जा रही तैयारियों का जायजा लिया। कहा कि अक्षयवट दर्शन की रविवार से औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। एडीएम सिटी अशोक कनौजिया ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से किला गेट पर स्कैनिंग मशीन और मेटल डिटेक्टर लग जाने पर सोमवार से आम श्रद्धालु भी अक्षयवट के दर्शन कर सकेंगे।

अगले साल से वैष्णो देवी यात्रा में नहीं पड़ेगा पत्थरों से खलल

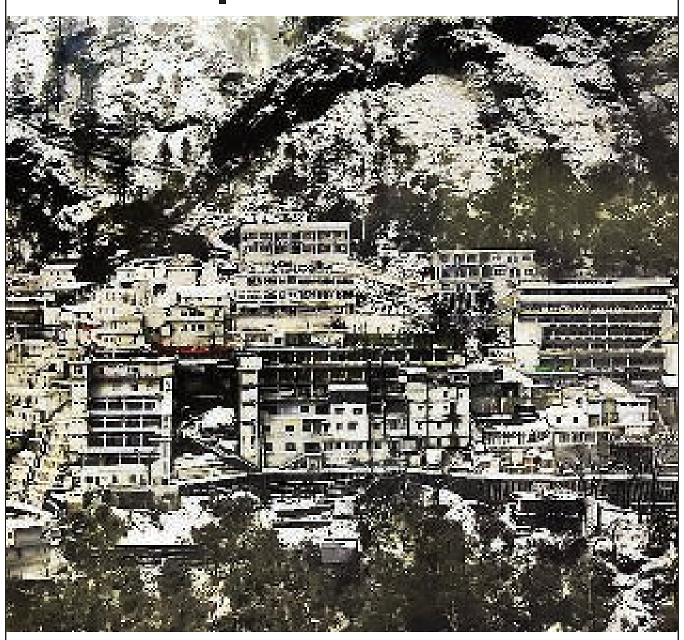
वैष्णो देवी भवन (फाइल फोटो)। प्रेट्र

सतनाम सिंह, जम्मू

▸ दोनों यात्रा मार्ग शेड से होंगे कवर सिर्फ सात किमी में काम बाकी

▸ सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए श्राइन बोर्ड लगातार प्रभावी कदम उठा रहा

श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर तीर्थयात्रियों को पहाड़ से गिरने वाले पत्थरों से बचाने के लिए वर्ष 2021 तक पूरे यात्रा मार्ग को शेड से ढक दिया जाएगा। फिलहाल, सात किलोमीटर यात्रा मार्ग ही शेष बचा है जिसे शेड से ढकना बाकी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ सिमरनदीप सिंह ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए बोर्ड के कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा रहा है। श्राइन बोर्ड के पास अपना आपदा प्रबंधन ढांचा है। इसी के जरिये वह प्रभावी कदम उठाता है।

जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में जल शक्ति और आपदा प्रबंधन पर आयोजित दो दिवसीय रीजनल कांफ्रेंस में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिमरनदीप सिंह ने वैष्णो देवी यात्रा के सफर, सुविधाओं और चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012-13 में आपदा प्रबंधन के लिए बोर्ड ने काम शुरू किए। इसके लिए 170 करोड़ रुपये खर्च किए गए। पहाड़ों से गिरने वाले पत्थरों को रोकने के लिए शेड बनाने का कार्य शुरू किया गया। यात्रा के दो मार्ग हैं। एक 13 किलोमीटर है और दूसरा 11 किलोमीटर का है। बोर्ड ने कुल 24 किलोमीटर के क्षेत्र में 17 किलोमीटर मार्ग को शेड से कवर कर दिया है। मात्र सात किलोमीटर क्षेत्र ही शेष बचा है।

साल 2021 तक पूरे क्षेत्र को शेड से कवर कर लिया जाएगा। जो शेड लगाए हैं उनमें स्प्रिंग एक्शन होता है। पत्थर शेड पर गिरने के बाद नीचे गिर जाते हैं। इससे यात्रियों की सुरक्षा होती है। उन्होंने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को 1980 से पहले पर्याप्त सुविधाएं हासिल नहीं होती थीं। तब विकास कार्य बहुत ही सीमित थे। यात्रा मार्ग नहीं बने थे, सुविधाओं का अभाव था। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन होने के बाद सुविधाओं का सफर शुरू हुआ, जिसमें बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सिमरनदीप ने बताया कि साल 1980 में यात्रियों की संख्या 13 लाख थी जो 2018 में 85 लाख तक पहुंच चुकी है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पहाड़ी है, साथ में जंगल है। पत्थर गिरने वाले क्षेत्र हैं, वन्य जीव क्षेत्र है। रियासी जिले में सबसे अधिक बारिश होती है। इसमें भूकंप, पहाड़ों से पत्थर गिरने, वनों में आग, तूफान जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

चट्टानों की हलचल का पता लगाएंगे

पिछले दो साल में पत्थर गिरने से किसी यात्री की मौत नहीं हुई है। चट्टानें मूव करती रहती हैं, जिससे खतरा बना रहता है। चूंकि वहां पर कुछ क्षेत्र संवेदनशील हैं इसलिए रडार और अन्य उपकरणों की मदद से यह पता लगाया जाएगा कि क्या हलचल हो रही है। इससे हम खुद अलर्ट होकर यात्रियों को भी अलर्ट कर सकते हैं।

चारधाम यात्रा के लिए अब ऑनलाइन बनेगा ग्रीन कार्ड

मिलेगी सुविधा ▸ परिवहन विभाग एनआइसी से तैयार करा रहा सॉफ्टवेयर

10 सीटर टैक्सी तक कागजों को ही माना जाएगा आधार

विकास गुसाईं, देहरादून

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान ग्रीन कार्ड बनवाने में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए परिवहन विभाग इस व्यवस्था को अब ऑनलाइन करने जा रहा है। इससे वाहन स्वामी को ऑनलाइन आवेदन करने और अपनी फोटो और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने पर एक क्लिक में ही ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। हालांकि, यह सुविधा चालक समेत 10 सवारी क्षमता वाले वाहनों के लिए ही रहेगी। इससे अधिक यात्री क्षमता वाले वाहनों को फिटनेस कराने के लिए कार्यालय आना होगा। ग्रीन कार्ड की व्यवस्था को ऑनलाइन करने के लिए परिवहन विभाग ने नेशनल इन्फार्मेटिक सेंटर (एनआइसी) को सॉफ्टवेयर विकसित करने का जिम्मा सौंपा है।

चारधाम यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर संचालित होने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए परिवहन विभाग ग्रीन कार्ड जारी करता है। प्रतिवर्ष 15 से 20 हजार ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं। ग्रीन कार्ड का अर्थ यह होता है कि संबंधित वाहन के सारे दस्तावेज पूरे हैं, वाहन की फिटनेस भी चेक कर ली गई है और यह पर्वतीय मार्गों पर चलने को पूरी तरह फिट है। इसका मकसद वाहन दुर्घटना के साथ ही अवैध संचालन पर रोक लगाना है। यात्रा के दौरान विभिन्न आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में ये कार्ड बनाए जाते हैं। यात्रा सीजन में ग्रीन कार्ड बनाने के लिए वाहनों की लंबी कतारें लगती हैं। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने वर्ष 2020 की चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है।

विभाग ने यह माना है कि चालक समेत 10 सीटर क्षमता वाले वाहन की आयु कम होती है। परमिट जारी करते समय इसकी फिटनेस भी चेक होती है। ऐसे में बार-बार इसकी फिटनेस चेक कराने की जरूरत नहीं है। इन्हें बिना निरीक्षण के ग्रीन कार्ड दिए जा सकते हैं। 10 सीट से अधिक यात्री क्षमता वाले वाहनों की प्रक्रिया भी ऑनलाइन रहेगी लेकिन इनका निरीक्षण अनिवार्य रखा गया है। ऐसे वाहन स्वामी अपने जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने के साथ ही निरीक्षण के लिए अपने पसंद के कार्यालय और समय के लिए बुकिंग कर सकेंगे। निश्चित तिथि पर परीक्षण कराने के बाद उन्हें भी ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह का कहना है कि यात्रा के दौरान आने वाली दिक्कतों को देखते हुए ग्रीन कार्ड को ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए एनआइसी से सॉफ्टवेयर तैयार करने को कहा गया है।

ग्रीन कार्ड बनवाने में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए अब व्यवस्था को ऑनलाइन करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। प्रतीकात्मक

श्राइन बोर्ड गठन का विरोध करने झारखंड जाएंगे 1000 तीर्थ पुरोहित

जागरण संवाददाता, देहरादून

▸ झारखंड विस चुनाव के दौरान लोगों के बीच जाकर करेंगे विरोध

▸ चारों धामों में गठित की जाएंगी कोर कमेटियां

उत्तराखंड सरकार के श्राइन बोर्ड गठन के फैसले के खिलाफ प्रदेशभर में तीर्थ पुराहितों का विरोध जारी है। चारधाम सहित अन्य क्षेत्रों में भी तीर्थ पुराहित और हक हकूकधारियों ने धरना-प्रदर्शन व कैंडल मार्च निकालकर सरकार का विरोध किया। वहीं, देहरादून और हरिद्वार में तीर्थ पुरोहितों की बैठकों का दौर जारी रहा। देवभूमि तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी घेर लिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए प्रदेश के एक हजार तीर्थ पुरोहित झारखंड जाएंगे।

तीर्थ पुरोहितों ने एलान किया है कि झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के आगामी चरणों में वहां जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रचार किया जाएगा। इससे पहले तीर्थ पुराहितों का चार दिसंबर को विधानसभा कूच तय है, जिसे अन्य संस्था और समितियों से सहयोग मिल रहा है। हरिद्वार के गंगा महासभा के तीर्थ पुराहितों ने समर्थन देते हुए विधानसभा कूच में शामिल होने की घोषणा की है। महापंचायत के संयोजक सुरेश सेमवाल ने बताया कि सरकार का रवैया तीर्थ पुराहितों के प्रति उपेक्षा पूर्ण है। 27 नवंबर से अभी तक कैबिनेट के निर्णय का विरोध कर रहे तीर्थ पुराहितों से सरकार ने वार्ता का प्रयास भी नहीं किया। चेतावनी दी कि अगर सरकार श्राइन बोर्ड गठन के निर्णय पर अड़ी रही तो तीर्थ पुरोहित बड़े स्तर पर आंदोलन को बाध्य होंगे।

महापंचायत के महामंत्री हरीश डिमरी ने बताया कि इस माह के दूसरे सप्ताह में तीर्थ पुराहितों की प्रदेश इकाइयां अपने-अपने क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन करेंगी। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि महापंचायत ने निर्णय लिया है कि चारों धामों में कोर कमेटियों का गठन किया जाएगा। जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल कैबिनेट के निर्णय को वापस लेने का दबाव बनाएंगी। यमुनोत्री मंदिर समिति के उपाध्यक्ष जगमोहन उनियाल ने आरोप लगाया कि राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा मंदिरों का व्यवसायीकरण करना चाहती है, जो किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में मोबाइल पाठशाला देगी हरियाली का सबक

जितेंद्र उपाध्याय, लखनऊ

▸ प्रदेश के हर मंडल में बनेगी मोबाइल विशेषज्ञों की टीम

▸ शहरी-ग्रामीण पर्यावरण प्रेमियों व किसानों को होगा फायदा

उत्तर प्रदेश में बंजर हो रही धरती को हरा-भरा करने के प्रयास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग आपके घर आकर न केवल बागवानी के गुर सिखाएगा, बल्कि मौसमी फूलों और फलों के पौधे लगाने की जानकारी भी देगा। इसके लिए हर मंडल में एक उद्यान विशेषज्ञों की मोबाइल टीम का गठन होगा।

पर्यावरण में आ रहे बदलाव का असर आम लोगों के जीवन पर भी पड़ने लगा है। विकास के नाम पर हरियाली को नष्ट करने में कोई संकोच भी नहीं किया जा रहा है। बावजूद इसके पर्यावरण को लेकर कुछ लोग संजीदा हैं, लेकिन पौधों और उनके लगाने के समय की जानकारी के अभाव में वह पौधारोपण नहीं कर पाते। आम, अमरूद, कटहल, नींबू व आंवला की बागों को लगाने से पहले किसानों की सही जानकारी नहीं होती। किसान भी उद्यान अधिकारियों के पास जाने में संकोच करते हैं। उद्यान विभाग ने इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए विशेषज्ञों की मोबाइल पाठशाला शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया था। सभी जिलों में चलने वाली किसान पाठशाला में विशेषज्ञों की टीम जाने लगी हैं। इसका काफी असर पड़ा है। अब इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी की जा रही है। मंडल स्तर पर टीम गठित होगी।

उद्यान विभाग की ओर से बनने वाली मोबाइल पाठशाला के विशेषज्ञों की टीम ऑनकॉल मंडल कार्यालयों में तैयार रहेगी। इसके लिए फोन नंबर जारी किया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों के जागरूक करने और पौधारोपण से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए यह प्रस्ताव बनाया था। उद्यान विशेषज्ञों की टीम गठित कर दी गई है। विशेषज्ञों के पास आधुनिक उपकरणों के साथ ही मृदा परीक्षण का भी इंतजाम होगा। किसान पाठशाला में विशेषज्ञों की टीम जाने लगी है। राजकीय उद्यानों में भी इसकी व्यवस्था की गई है। अगले वर्ष इसका और विस्तार किया जाएगा।

– डॉ. एसबी शर्मा, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

रामपुर के नवाब खानदान के हथियारों के जखीरे में तोप जैसी बंदूकें

▸ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाब खानदान की संपति का अब होगा बटवारा

मुस्लेमीन, रामपुर : आजादी से पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर में नवाबों का राज था। उनकी अपनी फौज थी। उसमें बड़े-बड़े हथियार थे। इनमें तोपें भी शामिल थीं। रामपुर रियासत के भारत सरकार में विलय के समय ये तमाम हथियार सरकार को दे दिए गए थे, लेकिन नवाब खानदान के निजी हथियार नहीं दिए गए। इनकी संख्या भी चार सौ से ज्यादा है। इनमें तोप, राइफल, बंदूक, रिवाल्वर, पिस्टल, तलवार, खंजर आदि शामिल हैं। बंदूकें तो तोप जैसी हैं। ये सभी हथियार कोठी खासबाग में रियासत की आर्मरी (शस्त्रागार) के स्ट्रांग रूम में रखे हैं। इन पर प्रशासन की सील लगी है। इसके चलते ये हथियार अभी आमजन नहीं देख सकते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात रहती है। कोठी खासबाग में ही पुलिस चौकी भी बना दी गई है।

दो माह पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अब नवाब खानदान की संपत्ति का बटवारा होगा। इसमें हथियार भी शामिल रहेंगे। दरअसल, नवाब खानदान में अरबों रुपये की संपत्ति के बंटवारे को लेकर मुकदमेबाजी चल रही थी। 45 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बंटवारे का फैसला किया है। बटवारे के बाद नवाब खानदान के लोग अपने हिस्से में आए शस्त्रों को बेच भी सकेंगे। इन पर लगी सील हटेगी और आम जनता इसे देख भी सकेगी।

छह गुना बड़े होते थे कारतूस : रामपुर रियासत की बंदूकें भी खास हैं। हथियारों के जखीरे में चार और आठ बोर की बंदूक भी शामिल हैं। शस्त्र विक्रेता राशिद खान बताते हैं कि चार बोर की बंदूक के कारतूस आजकल के कारतूस से करीब छह गुना बड़े होते थे। ये बंदूक मिनी तोप जैसी होती थी। अब इसके कारतूस ही नहीं मिल पाएंगे। रामपुर रियासत में हथियार बनाने के अपने कारीगर थे। वे ही कारतूस बनाते थे। शस्त्रागार में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी के हथियार भी शामिल हैं, जो सैकड़ों साल पुराने हैं। इनके अलावा जो हथियार रामपुर में बनाए गए हैं, उन पर रामपुर एस्टेट लिखा है।

प्रशासन की निगरानी : नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां बताते हैं कि ये सभी हथियार उस समय प्रशासन की निगरानी में आ गए थे, जब नवाब खानदान में बटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ। नवाब खानदान में अरबों रुपये की संपत्ति को लेकर 1974 से मुकदमेबाजी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संपत्ति का बंटवारा इस्लामी शरीयत के हिसाब से करने के आदेश दिए और बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी।

दो कमिश्नर नियुक्त : जिला जज ने नवाब खानदान की संपत्ति बंटवारे के लिए दो कमिश्नर नियुक्त किए हैं। इनमें अधिवक्ता कैलाश अग्रवाल और मुजम्मिल हुसैन शामिल हैं। ये दोनों नवाब खानदान की संपत्ति का सत्यापन करने के बाद बटवारे संबंधी रिपोर्ट जिला जज को देंगे। अग्रवाल ने बताया कि चल और अचल संपत्ति का बटवारा होना है। दोनों का अलग-अलग सत्यापान किया जाएगा। हथियार चल संपत्ति है।

एक व्यक्ति के तीन शस्त्र लाइसेंस ही बन सकते हैं। बटवारे के बाद जो भी स्थिति सामने आएगी, उससे शासन को अवगत कराया जाएगा। ज्यादा हथियार रखने के संबंध में शासन ही फैसला कर सकता है।

–सर्वेश कुमार गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट

गीता जयंती महोत्सव

लकड़ी से बने झूले और डाइनिंग टेबल को पसंद कर रहे है पर्यटक, लकड़ी और पीतल से बनी तोप भी बनी आकर्षण का केंद्र

सहारनपुर की तोप और कुल्लू की पशमीना शॉल की दीवानगी

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बने लकड़ी के सामान की पहचान पूरे देश में है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित गीता जयंती महोत्सव में इन सामानों की बिक्री हाथों-हाथ रही है। 16 वर्षों से महोत्सव में आ रहे मुहम्मद इमरान इस बार लकड़ी और पीतल से बनी 30 इंच की तोप भी लाए हैं। इस तोप की कीमत पांच हजार रुपये रखी गई है।

मुहमद इमरान ने कहा कि उनके फर्नीचर को कुरुक्षेत्र महोत्सव में काफी पसंद किया जाता है। इस बार आसाम की पापड़ी, लकड़ी का चार फीट का फ्लावर पॉट भी लेकर आए हैं। इस पॉट को तैयार करने में तीन दिन का समय लगता है। इस महोत्सव में लकड़ी का सामान 300 रुपये से लेकर 60 हजार रुपये तक का है। इसके अलावा पर्यटकों के लिए आकर्षक झूला, लकड़ी का डाइनिंग टेबल, लकड़ी के खिलौने व अन्य सामान भी उपलबध है।

मिट्टी के तवे पर बनी रोटी से बढ़ेगा स्वाद : महोत्सव में मिट्टी के तवे को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस तवे पर बनने वाली रोटी लोगों के स्वाद को दोगुना कर देगी। इतना ही नहीं इस तवे पर बनने वाली रोटी लोगों के स्वास्थ्य का भी पूरा खयाल रखेगी। महोत्सव में हरियाणा के अंबाला से आए शिल्पकार धर्मेंद्र का कहना है कि वह इस महोत्सव में पिछले तीन सालों से मिट्टी के तवे और अन्य समान लेकर आ रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों में दाल, चावल, साग, दलिया, खीर बनाई जा सकती है व दूध गर्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर को प्रतिदिन 18 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये सभी तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं। मिट्टी में कैल्शियम, सल्फर, आयरन, सिलिकॉन, कोबाल्ट, जिप्सम इत्यादि पोषक तत्व मिलते हैं। मिट्टी के इन्ही गुणों और पवित्रता के कारण भारत वर्ष के कई प्रसिद्ध मंदिरों में आज भी मिट्टी के बर्तनों में ही प्रसाद एवं भोजन बनाया जाता है।

कुरुक्षेत्र में आयोजित गीता जयंती महोत्सव में लकड़ी की तोप दिखाते शिल्पकार मुहमद इमरान। जागरण

180 ग्राम की पशमीना शॉल को आधे इंच की अंगूठी से निकाला

कुल्लू के शिल्पकारों की 180 ग्राम वजन वाली शॉल महज आधे इंच की अंगूठी से आर-पार हो जाती है। इसे देखने के लिए स्टाल पर पर्यटकों की भीड़ लग रही है। शिल्पकार हीरा लाल की इस पशमीना शॉल के अतिरिक्त किन्नौरी और अंगूरी शॉल भी खूब लुभा रही है। महोत्सव में कुल्लू के बने हुए शॉलों के 300 से ज्यादा पक्के ग्राहक बन चुके हैं। कुल्लु की इस शिल्पकला को पर्यटकों के समक्ष रखने के लिए शिल्पकार हीरालाल के साथ-साथ अन्य लोग सचिन व संजू भी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। कुल्लु निवासी हीरा लाल ने बताया कि पशमीना शॉल का कम से कम वजन 120 ग्राम का हो सकता है। इसकी कीमत डेढ़ लाख रुपये से भी ज्यादा है। इस क्राफ्ट मेले में इस बार पशमीना की 15 हजार रुपये से 35 हजार रुपये तक की शॉल और लोई खास आर्डर पर लेकर आए हैं। पिछले 18 सालों से गीता महोत्सव में कुल्लु शॉल, जैकेट लेकर आ रहे हैं। इस बार महिलाओं के लिए अंगूरी स्वेटर और लोंग कोट लेकर आए हैं। किनौरी शॉल को बनाने के लिए 45 दिन का समय लगता है और पशमीना शॉल को 10-12 दिनों में तैयार कर लिया जाता है।

कानपुर विश्वविद्यालय में नए साल में गर्भ संस्कार का पाठ

जागरण संवाददाता, कानपुर

▸ 12वीं पास महिलाओं के लिए तीन व छह माह का सर्टिफिकेट कोर्स

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (सीएमजेएमयू) में नए साल से गर्भ संस्कार की पढ़ाई शुरू होगी। गर्भवती को संस्कार का ज्ञान देने के लिए इसका विशेष पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। इसे बोर्ड ऑफ स्टडीज से भी पारित हो गया है। मकसद है कि संस्कारों के ज्ञान का गर्भ में संतान पर अच्छा प्रभाव पड़े। इसी माह अकादमिक परिषद की बैठक में यह पाठ्यक्रम पास कराने के बाद एक जनवरी से इसकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।

सीएसजेएमयू राज्य का पहला विश्वविद्यालय होगा, जहां इस पाठ्यक्रम की पढ़ाई होगी। इसके लिए योग्यता 12वीं पास रखी गई है। हालांकि प्रवेश के लिए गर्भवती के साथ ही सामान्य महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। पाठ्यक्रम की अवधि तीन व छह माह की रहेगी। पढ़ाई पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

नए साल में गर्भ संस्कार की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस पाठ्यक्रम को बोर्ड ऑफ स्टडीज से पारित करा लिया है। अब बस अकादमिक परिषद से इसे पास कराकर शुरुआत करा देंगे।

– प्रो. नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सीएसजेएमयू (कानपुर विवि)

11 सितंबर को जब छत्रपति शाहूजी महाराज विवि का 34वां दीक्षा समारोह हुआ था, उसमें उप्र की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने गर्भ संस्कार का पाठ्यक्रम शुरू करने की बात कही थी। उनका कहना था कि छात्राएं आगे चलकर मां बनती हैं, भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी का संतान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर वे संस्कारों की जानकारी रखेंगी तो उनकी संतान पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

कैट ने ई-कॉमर्स कंपनियों को बताया आर्थिक आतंकी

नई दिल्ली, प्रेट्र : उद्योग संगठन कैट ने अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट को आर्थिक आतंकी की संज्ञा दी है। संगठन ने सरकार से कहा है कि वह एफडीआइ नियमों के उल्लंघन के लिए इन कंपनियों पर कार्रवाई करे। हालांकि फ्लिपकार्ट ने इन आरोपों का खंडन किया है। फ्लिपकार्ट ने कहा है कि वह भारत में मार्केट प्लेस मॉडल के तहत कारोबार कर रही है और उसका कारोबार पूरी तरह से एफडीआइ नियमों के अनुरूप है।

इन्सॉल्वेंसी सुधार की दिशा में पर्सनल इन्सॉल्वेंसी दूसरा बड़ा कदम है। इससे नए सबक की शुरुआत होने वाली है।

— एमएस साहू, चेयरमैन, आइबीबीआइ

छह और हवाई अड्डों के निजीकरण की सिफारिश

नई दिल्ली, प्रेट्र : एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) ने केंद्र से छह और हवाई अड्डों के निजीकरण की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक इन हवाई अड्डों में अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और तिरुचिरापल्ली के नाम शामिल हैं। इससे पहले सरकार छह हवाई अड्डों का निजीकरण कर चुकी है। निजीकरण का यह फैसला हवाई अड्डों की सुविधाओं में सुधार के लिए लिया गया है। निजीकरण किए जाने वाले हवाई अड्डों का विकास पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत किया जाएगा। एएआइ द्वारा भेजी गई इस सिफारिश को सरकार की स्वीकृति मिल जाने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास भेज दिया जाएगा। मंत्रालय की देखरेख में ही आगे की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। एएआइ इस समय देशभर में 100 से अधिक हवाई अड्डों की देखरेख की जिम्मेदारी संभाल रहा है। फरवरी में छह हवाई अड्डों का निजीकरण किया गया था। अडानी ग्रुप सबसे बड़ी बोली लगाकर सभी हवाई अड्डों को हासिल करने में सफल रहा था। इनमें लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुअनंतपुरम और गुवाहाटी शामिल हैं।

मारुति सुजुकी अप्रैल से पहले लांच कर देगी ब्रीजा का पेट्रोल वर्जन

साक्षात्कार

कार बाजार में अपनी शुरुआत के बाद मारुति सुजुकी ने हाल ही में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने कार बिक्री में दो करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ-साथ कंपनी भविष्य में भारतीय बाजार को लेकर भी बेहद आश्वस्त है। कंपनी के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स **शशांक श्रीवास्तव** ने **दैनिक जागरण** के आर्थिक ब्यूरो प्रमुख **नितिन प्रधान** से बातचीत में कहा कि फिलहाल बीएस-6 के दौर में कंपनी का फोकस पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों पर रहेगा। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश -

● कार बाजार की मौजूदा स्थिति को कैसे आंकते हैं?

- देखिए बीते एक साल में ऑटोमोबाइल उद्योग ने बहुत कुछ देखा है। अगस्त, 2018 से बिक्री में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था। अप्रैल, 2019 आते-आते कंपनियों के पास स्टॉक काफी इकट्ठा हो गया। यह पूरे उद्योग के लिए चिंता की बात थी। इसकी कई वजहें थी जिनमें सुरक्षा मानकों के लागू होने से कार की लागत का बढ़ना और महंगे बीमा व राज्यों में बढ़े हुए टैक्स की वजह से ग्राहक के लिए कार की लागत में वृद्धि प्रमुख थे। फिर एनबीएफसी में लिक्विडिटी की कमी की वजह से कर्ज मिलने में मुश्किलें आईं। उसके बाद अंत में बीएस-4 से बीएस-6 में तब्दील होने का वक्त नजदीक आने लगा। इन सब बातों ने बाजार पर असर डाला। अब कुछ सुधार की स्थिति बनी है और अक्टूबर का महीना पिछले 15 महीनों में सबसे अच्छा गया है। लेकिन अगर हमें यह कहना हो कि सेंटीमेंट बदल गया है, तो इसके लिए अभी तीन-चार महीने और इंतजार करना बेहतर होगा।

● बीएस-6 को लेकर आपकी तैयारी कैसी है?

- अप्रैल, 2020 से देश में बीएस-6 मानक लागू हो जाएंगे और उसके बाद केवल वही गाड़ियां बिकेंगी। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। मारुति ने इसकी तैयारी काफी पहले ही कर ली थी। अब तक हम आठ बीएस-6 मॉडल बाजार में उतार चुके हैं और दिलचस्प बात यह है कि ग्राहक उन्हें अपना भी रहे हैं। हम अब तक तीन लाख बीएस-6 वाहन बेच चुके हैं। यहां मैं आपके माध्यम से लोगों का एक भ्रम दूर करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि अप्रैल, 2020 के बाद बीएस-4 वाहन चलना बंद हो जाएंगे। इसलिए अभी अगर कोई ग्राहक बीएस-4 वाहन खरीदना चाहता है तो उसे देरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आखिरी वक्त में इनके लिए कोई भारी-भरकम सेल लगने वाली है। इसकी वजह यह है कि कंपनियों ने अपने स्टॉक को काफी सीमित कर लिया है। ग्राहकों में दूसरा भ्रम ईंधन को लेकर है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि बीएस-6 वाहनों को आप बीएस-4 ईंधन से भी चला सकते हैं और बीएस-4 वाहनों में बाद में बीएस-6 ईंधन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन ऐसा केवल पेट्रोल गाड़ियों में ही किया जा सकता है, डीजल में नहीं।

● भविष्य के लिए आपकी क्या रणनीति है?

- अभी हमारा पूरा फोकस पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर है। डीजल से चलने वाले बीएस-6 वाहनों की कीमत पेट्रोल के मुकाबले काफी अधिक होगी। इसलिए हम अभी उस सेगमेंट पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। अप्रैल, 2020 के बाद बढ़ी हुई कीमतों पर अगर ग्राहकों में डीजल गाड़ियों की मांग बनती है, तब विचार करेंगे। आप जानते हैं कि मौजूदा बाजार में एसयूवी सबसे लोकप्रिय सेगमेंट है। इसलिए हम ब्रीजा को पेट्रोल में लांच करने जा रहे हैं। यह वैरिएंट अप्रैल, 2020 से पहले बाजार में उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त सीएनजी गाड़ियों पर हम खास ध्यान दे रहे हैं। अभी हमारे पास आठ मॉडल हैं। सरकार देश में सीएनजी की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय कर रही है। मुझे लगता है जैसे-जैसे सीएनजी की उपलब्धता छोटे शहरों में पहुंचेगी, सीएनजी वाहनों की मांग और बढ़ेगी।

● आपने तीन लाख बीएस-6 वाहन बेचे हैं। मंदी के इस दौर में वाहनों की बढ़ी हुई कीमत के बीच इनकी बिक्री को आप किस नजर से देखते हैं?

- हमारे लिए भी यह काफी हैरानी भरा है। लेकिन इसे यूं देखा जाना चाहिए कि ग्राहकों के बीच जागरूकता काफी बढ़ रही है। कोई भी नई चीज लेने से पहले ग्राहक नवीनतम टेक्नोलॉजी पर जाना चाहता है। भले ही उसके लिए उसे कुछ अधिक कीमत चुकानी पड़े। इसलिए जहां कुछ लोग ऑफर्स के इंतजार में अभी गाड़ी खरीदने की अपनी योजना टाल रहे हैं, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो अभी से बीएस-6 वाहन खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। यहां मैं फिर से यही कहूंगा कि ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि बीएस-6 गाड़ियों को भी बीएस-4 ईंधन से चलाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि हमने सिर्फ बड़े शहरों में ही बीएस-6 वाहन नहीं बेचे हैं, बल्कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी लोग अभी से बीएस-6 को अपना रहे हैं।

● आपने ई-व्हीकल लाने का भी एलान किया है। उस पर क्या प्रगति है?

-जी हां, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमने कुछ वाहन बनाए भी हैं जिनका टेक्निकल टेस्ट चल रहा है। इनके नतीजे आने के बाद ही कुछ तय हो सकेगा। ई-व्हीकल की प्राइसिंग भी एक मुद्दा है। यह सब स्पष्ट होने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे।

जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये के पार

उम्मीद ▶ आर्थिक सुस्ती के बीच नवंबर के आंकड़ों पर दिखा त्योहारी सीजन की बिक्री का सकारात्मक असर

अब तक आठ बार एक लाख करोड़ रुपये का स्तर हुआ है पार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आर्थिक मोर्चे पर जूझ रही सरकार के लिए जीएसटी संग्रह का नया आंकड़ा थोड़ा राहत देने वाला है। नवंबर, 2019 में जीएसटी संग्रह ने एक लाख करोड़ रुपये का स्तर पार कर लिया है। इस दौरान जीएसटी संग्रह की राशि 1,03,492 करोड़ रुपये रही। दो महीने बाद इसकी वृद्धि दर सकारात्मक रही है। नवंबर में जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर छह फीसद है। बहरहाल इसे अर्थव्यवस्था के लिए पूरी राहत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर से मिले-जुले संकेत आ रहे हैं। अक्टूबर में ऑटोमोबाइल बाजार में तेजी के जो संकेत मिले थे, वे नवंबर में हवा हो गए हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की घरेलू बिक्री में 3.2 फीसद की गिरावट आई है।

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने यानी अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 95,380 करोड़ रुपये था। वहीं सालभर पहले यानी नवंबर, 2018 में जीएसटी संग्रह 97,637 करोड़ रुपये का रहा था। बीते महीने इसने 1,03,492 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया। जुलाई, 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से यह आठवीं बार है, जब एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का संग्रह हुआ है। नवंबर, 2019 में सीजीएसटी संग्रह 19,592 करोड़ रुपये और एसजीएसटी 27,144 करोड़ रुपये का रहा है। समीक्षाधीन अवधि में आइएसजीएसटी की राशि 49,028 करोड़ रुपये रही है और अधिभार संग्रह 7,727 करोड़ रुपये रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक घरेलू गतिविधियों से जीएसटी संग्रह में 12 फीसद की अच्छी वृद्धि दर काफी उत्साहित करने वाली है।

अर्थव्यवस्था के अन्य मोर्चों पर अब भी सुधरे नहीं हैं हालात। प्रतीकात्मक फोटो

तीसरा सबसे बड़ा संग्रह : सरकार इस बात से भी संतुष्ट हो सकती है कि जीएसटी लागू होने के बाद से नवंबर, 2019 का संग्रह तीसरा सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह है। चालू वित्त वर्ष में दूसरी बार संग्रह एक लाख करोड़ रुपये के पार गया है। सरकार ने आम बजट 2019-20 में हर महीने 1.14 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह का अनुमान लगाया था। हालांकि पिछले सात महीने में वास्तविक संग्रह इस लक्ष्य से काफी कम रहा है। नवंबर में जीएसटी संग्रह में हुई वृद्धि के लिए अक्टूबर के त्योहारों को श्रेय दिया जा रहा है। नवंबर के संग्रह की स्थिति दिसंबर के आंकड़ों में दिखाई देगी। नवंबर में जिस तरह से ऑटो सेक्टर में फिर तेज गिरावट दिखी है, उससे जीएसटी संग्रह में बनी यह तेजी बरकरार रहने को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं।

पिछले वित्त वर्ष (2018-19) और चालू वित्त वर्ष (2019-20) के शुरुआती आठ महीनों (अप्रैल से नवंबर) के जीएसटी संग्रह का तुलनात्मक अध्ययन :

माह	2018-19	2019-20
अप्रैल	103459	113865
मई	94016	100289
जून	95610	99939
जुलाई	96483	102083
अगस्त	93690	98202
सितंबर	94442	91916
अक्टूबर	100710	95380
नवंबर	97637	103492

(नोट : आंकड़े करोड़ रुपये में)

अभी तेजी के इंतजार में ऑटोमोबाइल सेक्टर

जीएसटी संग्रह के बेहतर आंकड़ों के बीच रविवार को नवंबर में वाहन बिक्री के आंकड़े भी सामने आए। बीते महीने मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 1,50,630 कारों की रही है, जो नवंबर, 2018 से 1.9 फीसद कम है। निर्यात को हटा दिया जाए तो घरेलू बिक्री में 3.2 फीसद की गिरावट हुई है। आम तौर पर नवंबर को त्योहारी सीजन माना जाता है। अमूमन हर साल नवंबर में ऑटो बिक्री में खासी वृद्धि होती है। इससे उलट इस साल नवंबर में कॉम्पैक्ट वर्ग की कारों को छोड़कर बाकी हर वर्ग की कारों की बिक्री फिर घट गई है। एसयूवी की बिक्री में 1.3 फीसद की गिरावट हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, होंडा कार्स की घरेलू बिक्री सालभर पहले के मुकाबले आधी हो गई। बीते महीने कंपनी ने 6,459 कारें बेचीं। हालांकि बीएस-6 की दिशा में कदम बढ़ा रही होंडा कार्स ने आंकड़ों को उम्मीद से बेहतर बताया है। देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई की घरेलू बिक्री में दो फीसद का इजाफा हुआ है। अगर निर्यात मिला दें कंपनी के वाहनों की कुल बिक्री में 7.2 फीसद का इजाफा हुआ है।

तुर्की से 11,000 टन प्याज आयात करेगी सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकारी ट्रेडिंग कंपनी एमएमटीसी अब तुर्की से प्याज आयात करने की तैयारी में है। इस आयात सौदे के तहत 11 हजार टन प्याज आयात किया जाना है। कंपनी पहले ही मिस्र से करीब छह हजार टन प्याज आयात कर रही है। घरेलू बाजार में प्याज की बेलगाम कीमत को नियंत्रित करने की योजना के तहत सरकार प्याज आयात कर रही है। पिछले महीने 1.2 लाख टन प्याज आयात के फैसले को कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी।

सूत्रों के मुताबिक एमएमटीसी ने तुर्की के साथ 11 हजार टन प्याज आयात करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह खेप जनवरी तक भारत पहुंच जाने की उम्मीद है। इससे पहले कंपनी ने मिस्र से 6,090 टन प्याज आयात का समझौता किया था। यह खेप अगले सप्ताह तक पहुंच जाएगी। केंद्र सरकार आयातित प्याज को 52-55 रुपये प्रति किलो की कीमत पर राज्य सरकारों को उपलब्ध करवा रही है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने पिछले महीने बताया था कि चालू खरीफ सीजन में प्याज के उत्पादन में करीब 26 परसेंट की गिरावट की आशंका है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि प्याज की कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।

प्रतीकात्मक फोटो

- **कुल 1.2 लाख टन प्याज आयात करने की है योजना**
- **मिस्र से आयातित प्याज की खेप जल्द पहुंचेगी भारत**

हर मोर्चे पर कदम उठा रही सरकार

गौरतलब है कि इस समय घरेलू बाजारों में प्याज की कीमत आसमान छू रही है। कई जगहों पर कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए कई स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके लिए प्याज के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही प्याज के भंडारण की सीमा भी निश्चित कर दी गई है। कीमत पर नजर रखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। इसके अलावा सचिवों की समिति और उपभोक्ता मामलों के सचिव के. श्रीवास्तव भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

जेपी इन्फ्रा की बोली आकर्षक बनाने की तैयारी में एनबीसीसी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी एनबीसीसी दिवालिया हो चुकी जेपी इन्फ्राटेक के लिए अधिक आकर्षक बोली जमा करने पर विचार कर रही है। एनबीसीसी गिरवी जमीन और बेनामी फ्लैट की जगह कर्जदाताओं को मालिकाना हक वाली अतिरिक्त जमीन देने पर विचार कर रही है। इसके अलावा एनबीसीसी घर खरीदारों को जल्दी घर तैयार करके देने पर भी विचार कर रही है।

कंपनी करीब 20 हजार फ्लैट को तयशुदा समय से पहले तैयार करने की शर्त को अपनी बोली में शामिल कर सकती है। इससे पहले एनबीसीसी की ओर से 17 नवंबर को जमा की गई बोली में चार वर्ष की अवधि में फ्लैट तैयार करने की बात कही गई थी। कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) की पिछली बैठक 28 नवंबर को हुई थी। इसमें एनबीसीसी और सुरक्षा रियल्टी को नए स्तर से बोली जमा करने का मौका दिया गया था। इस दौरान सीओसी ने कहा था कि दोनों कंपनियां तीन दिसंबर तक अपनी अंतिम बोली जमा कर दें।

▶ **कंपनी के कर्जदाता चाहते हैं पुरानी बोली में सुधार**

जेपी इन्फ्रा के कर्जदाताओं ने एनबीसीसी से कहा था कि वह अपनी बोली को और आकर्षक बनाए। उसे स्पष्ट मालिकाना हक वाली जमीन देने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि पहली बोली के दौरान एनबीसीसी ने जो जमीन देने की बात कही थी उसमें से 600 एकड़ जमीन विवादित थी। इसमें कुछ बेनामी फ्लैट भी शामिल किए गए थे। सीओसी ने इस ऑफर में सुधार करके दूसरी बोली जमा करने को कहा था। इसके अलावा कर्जदाताओं ने यमुना एक्सप्रेसवे को बिना किसी अतिरिक्त कर्ज के तैयार करके देने की बात भी कही थी।

गौरतलब है कि एनबीसीसी ने जेपी के कर्जदाताओं का 9,800 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने के लिए 1,426 एकड़ जमीन का ऑफर दिया था। इसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त कुछ फ्लैट देने की बात को भी बोली में शामिल किया गया था।

रिजर्व बैंक पर रहेगा रेपो रेट में फिर कटौती का दबाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट के कारण छह साल के निचले स्तर पर आई विकास दर को देखते हुए रिजर्व बैंक लगातार छठी बार नीतिगत दरों में कटौती कर सकता है। रिजर्व बैंक पांच दिसंबर को मौद्रिक नीति समीक्षा जारी करेगा। पिछले साल दिसंबर में शक्तिकांत दास के गवर्नर बनने के बाद से रिजर्व बैंक ने पिछली पांचों मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कटौती की है। अब तक रेपो रेट में कुल 1.35 फीसद की कटौती की जा चुकी है।

जुलाई-सितंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर 4.5 फीसद पर सिमट गई है। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की बदहाली का विकास दरों पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव दिखा है। सालभर पहले इसी अवधि में विकास दर सात फीसद पर थी। वहीं चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर पांच फीसद रही थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कह चुके हैं कि जब तक विकास दर पटरी पर नहीं लौट आती है, तब तक नीतिगत दरों में कटौती का कदम उठाया जाता रहेगा।

श्रमिक विवाद से औद्योगिक माहौल पर बुरा असर

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

आइएमटी मानेसर स्थित होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआइ) प्लांट में चल रहा श्रमिक विवाद गुरुग्राम के औद्योगिक माहौल पर नकारात्मक असर डाल रहा है। औद्योगिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में भविष्य में संभावित निवेश पर विराम लग सकता है। श्रमिक विवाद के समाधान को लेकर हरियाणा सरकार ने यदि ठोस कदम नहीं उठाया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। होंडा मामले में श्रम विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है। इस घटनाक्रम से निवेश आकर्षित करने की कोशिश में जुटे हरियाणा की छवि भी प्रभावित हो रही है।

मामले की गंभीरता को इससे भी समझा जा सकता है कि भारत में जापान के राजदूत केंजे हिरामात्सू ने होंडा के मानेसर प्लांट में खराब हो रहे माहौल के प्रति चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपनी चिंता से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भी अवगत कराया है। राजदूत ने पीएमओ से आग्रह किया है कि मामले के निपटारे के लिए हरियाणा सरकार से कहा जाए।

- **होंडा के मानेसर प्लांट में कई दिनों से श्रमिक-प्रबंधन के बीच तनाव**
- **भारत में जापान के राजदूत को उठाना पड़ा पीएमओ के समक्ष होंडा का मुद्दा**

होंडा प्लांट में चल रहे विवाद को सुलझाने का श्रम विभाग का प्रयास जारी है। हड़ताल में शामिल स्थायी कर्मचारियों ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। जल्द ही इस विवाद को पूरी तरह से सुलझा लिया जाएगा।

-अजयपाल डूडी, उप-श्रमायुक्त (सर्किल दो), गुरुग्राम

मानेसर प्लांट में अब भी एक ही शिफ्ट में काम शुरू हो पाया है। फाइल फोटो

उद्यमियों का कहना है कि जापान के राजदूत की ओर से यह मुद्दा उठाए जाने का सीधा अर्थ है कि मामला काफी गंभीर हो चुका है। जल्द ही सरकार ने कुछ ठोस नहीं उठाया तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है। प्रदेश में विदेशी निवेश प्रभावित होगा। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास और विस्तार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के महासचिव दीपक मैनी का कहना है कि औद्योगिक सुस्ती के दौर में इस तरह का विवाद औद्योगिक हितों के प्रतिकूल है। गुरुग्राम में जापानी कंपनियों की संख्या काफी है। मामला तुरंत नहीं संभाला गया तो अन्य कंपनियों पर भी असर दिख सकता है।

होंडा कंपनी में श्रमिक विवाद के कारण उत्पादन 11 नवंबर से 24 नवंबर तक पूरी तरह से ठप रहा था। 25 नवंबर से प्लांट में काम शुरू हुआ है। उत्पादन कार्य सिर्फ एक शिफ्ट में चल रहा है। फिलहाल धरने पर बैठे सभी स्थायी कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं। हालांकि माहौल पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। बता दें कि कंपनी ने 200 अस्थायी कर्मचारियों को कार्यकाल पूरा होने के बाद कार्यमुक्त कर दिया था। इसी के बाद से विवाद बढ़ा था। होंडा प्रबंधन ने छह स्थायी कर्मचारियों को माहौल खराब करने के आरोप में निलंबित कर दिया था।

शेयर समीक्षा

आर्थिक आंकड़ों व आरबीआइ रेट कट पर रहेगी नजर

बाजार में दिख सकती है कमजोर विकास दर के आंकड़ों की प्रतिक्रिया, मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के पीएमआइ डाटा पर भी रहेगी नजर

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस सप्ताह प्रमुख भारतीय शेयर बाजारों पर बड़े आर्थिक आंकड़ों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अलावा निवेशकों की नजर ऑटो सेल्स, आरबीआइ के रेपो रेट कट और हांगकांग के मुद्दे पर अमेरिका-चीन की ओर से आ रही खबरों पर रहेगी। इस सप्ताह मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का पीएमआइ डाटा भी आना है। शेयर बाजारों पर इसका असर भी देखने को मिलेगा।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर के मुताबिक नवंबर की ऑटोमोबाइल बिक्री के आंकड़े और आरबीआइ की ओर से रेट कट की उम्मीद का सीधा असर शेयर बाजारों पर देखने को मिलेगा। आरबीआइ की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक इसी हफ्ते होनी है। इसके अलावा सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तब बीती तिमाही में जीडीपी के कमजोर आंकड़ों पर भी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। बीते शुक्रवार को कारोबारी सत्र के बाद जीडीपी के आंकड़े जारी हुए थे। गौरतलब है कि जुलाई-सितंबर की तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट 4.5 परसेंट रही। यह चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही से 0.5 परसेंट कम है।

अगर शुक्रवार के सत्र को छोड़ दें, तो पिछले सप्ताह शेयर बाजारों ने ठीक-ठाक प्रदर्शन किया था। पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स कुल मिलाकर 434.40 अंक की बढ़त पाने में सफल रहा था। वहीं एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी ने भी 141.35 अंक की साप्ताहिक बढ़त दर्ज की थी।

प्रतीकात्मक फोटो

लगातार तीसरे महीने एफपीआइ बने शुद्ध निवेशक

सकारात्मक ग्लोबल संकेतों और उत्साहजनक घरेलू आर्थिक माहौल के चलते विदेशी निवेशकों ने पिछले महीने भारतीय स्टॉक मार्केट में रुचि दिखाई। इस दौरान पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने यहां कुल 22,872 करोड़ रुपये का निवेश किया। यह लगातार तीसरा महीना है, जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में शुद्ध खरीदार रहे हैं। डिपॉजिटरी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में एफपीआइ ने इक्विटी मार्केट में कुल 25,230 करोड़ रुपये का कारोबार किया। हालांकि उन्होंने डेट सेग्मेंट से 2,358.2 करोड़ रुपये निकाल लिए। इस तरह एफपीआइ का कुल निवेश 22,871.8 करोड़ रुपये रहा। जानकारों ने बताया कि ग्लोबल स्तर पर ट्रेड-वार्ता से संबंधित सकारात्मक खबरों और सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की घोषणा के चलते विदेशी निवेशकों में उत्साह देखा गया।

शीर्ष आठ कंपनियों के एम-कैप में जुड़े 52 हजार करोड़ रुपये

पिछले सप्ताह शेयर बाजार की शीर्ष 10 कंपनियों में से आठ के बाजार पूंजीकरण में 52,193.73 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। इस दौरान एसबीआइ और एचडीएफसी के एम-कैप में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई। शीर्ष 10 कंपनियों में सिर्फ टीसीएस और आइटीसी के बाजार पूंजीकरण में कमी देखी गई। आरआइएल, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, एचडीएफसी लिमिटेड, आइसीआइसीआइ बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआइ और इन्फोसिस के एम-कैप में वृद्धि दर्ज की गई। इसी दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने वाली देश की पहली कंपनी बन गई। पिछले सप्ताह एसबीआइ का एम-कैप 11,334.26 करोड़ रुपये के इजाफे के साथ 3,05,087.85 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एचडीएफसी लिमिटेड के एम-कैप में 10,492.7 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और यह 3,96,791.39 करोड़ रुपये रहा। आइसीआइसीआइ बैंक के एम-कैप में 9,871.88 करोड़ और कोटक महिंद्रा में 8,818.24 करोड़ रुपये का इजाफा देखा गया।

सरकारी कंपनियों के विनिवेश के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच

नई दिल्ली, आइएएनएस : आरएसएस से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने एयर इंडिया, बीएसएनएल और बीपीसीएल जैसी सरकारी कंपनियों के विनिवेश का विरोध किया है। मंच का कहना है कि रणनीतिक विनिवेश के इस कदम का इस्तेमाल भ्रष्ट अधिकारी कुछ विशेष कारोबारी घरानों को फायदा पहुंचाने में कर सकते हैं। एसजेएम की राष्ट्रीय समिति ने इन कंपनियों की रणनीतिक बिक्री के विरोध में रिजॉल्यूशन पास किया है।

एसजेएम ने कहा, 'भारत को अपनी राष्ट्रीय संपत्तियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों नहीं बेचनी चाहिए। विनिवेश की मौजूदा योजना कुछ कारोबारी घरानों से प्रभावित सलाहकारों, नौकरशाहों के षड्यंत्र का नतीजा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर नीति आयोग की रिपोर्ट को खारिज किया जाना चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों का मूल्यांकन अगले पांच साल में जीडीपी को दोगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।'

स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों को लेकर बनाई गई रिपोर्ट कुछ लोगों के निजी हितों का परिणाम है। एक नई रिपोर्ट तैयार कराई जानी चाहिए। यह जिम्मेदारी ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए, जो किसी पूर्व धारणा से बंधे नहीं हों और भारत की जरूरतों के हिसाब से मूल्यांकन कर सकें।

▶ **जीडीपी को बढ़ाने की दिशा में सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका पर पुनर्विचार की अपील**

एसजेएम ने इस बात से सहमति जताई कि कारोबार करना सरकार का काम नहीं है, लेकिन साथ ही विनिवेश के नाम पर अपनी राष्ट्रीय संपत्तियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों बेचने का विरोध जताया। मंच ने कहा कि जैसे ही सरकार ने बीपीसीएल की बिक्री की बात कही, सऊदी अरैमको इस पर निगाह गड़ाए है। राष्ट्रीय भावना और कठिन परिश्रम से तैयार संपत्ति को विदेशी कंपनियों के हाथ में नहीं जाने देना चाहिए।

12 दिनों तक पुलिस की घेराबंदी में रखा गया था हांगकांग पॉलीटेक्निक विश्वविद्यालय। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। घेराबंदी खत्म होने के बाद यहां नए सिर से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

न्यूज गैलरी

ईरान में संसदीय चुनाव के लिए नामांकन शुरू

तेहरान : ईरान में रविवार से 208 निवार्चन क्षेत्रों में होने वाले संसदीय चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो गया। ईरान की 290 सीटों वाली संसद के लिए 21 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लेने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी देश की संवैधानिक संस्था गार्जियन काउंसिल द्वारा की जा रही है। (एपी)

अफगानिस्तान में 31 आइएस आतंकियों ने डाले हथियार

नांगरहार : अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नांगरहार के अचिन जिले में शनिवार को इस्लामिक स्टेट (आइएस) के 31 आतंकियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। हथियार डालने वाले इन आतंकियों के साथ 62 महिलाएं और बच्चे भी थे। इसी जिले में गत 16 नवंबर को भी आइएस के 18 आतंकियों ने आत्मसमर्पण किया था। (एएनआइ)

रूस के साइबेरिया इलाके में नदी में गिरी बस, 19 की मौत

मॉस्को : रूस के साइबेरिया इलाके के जबैकास्क में रविवार को पुल से गुजरते वक्त एक बस बर्फ से जमी नदी में गिर गई। इस हादसे में 19 यात्रियों की मौत हो गई। 22 यात्री घायल हैं। बस श्रेतेंस्क शहर से चिटा जा रही थी। बताया जा रहा है कि पुल से गुजरते वक्त बस का अगला पहिया निकल गया। संतुलन बिगड़ने से बस सीधे नदी में जा गिरी। (रायटर)

अमेरिका में विमान दुर्घटना में नौ लोगों की मौत

वाशिंगटन : अमेरिका के साउथ डकोटा प्रांत में शनिवार को एक विमान दुर्घटना में दो बच्चों समेत नौ लोगों की मौत हो गई। तीन लोग घायल हैं। इलाके में तूफान की चेतावनी के बावजदू उड़ान भरने वाला पिलेटस पीसी–12 विमान चैंबरलेन एयरपोर्ट से एक मील दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इदाहो जा रहे विमान में 12 लोग सवार थे। हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने मौके पर पहुंच कर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पतालों में भर्ती कराया है। (एएफपी)

मेक्सिको में ड्रग्स तस्करों से मुठभेड़ में 14 की मौत

मेक्सिको सिटी : मेक्सिको के सीमावर्ती प्रांत कौहिला में शनिवार को ड्रग्स तस्करों और स्थानीय सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 14 लोग मारे गए। दिन के उजाले में यह मुठभेड़ विला यूनियन शहर में हुई। मेक्सिको में ड्रग्स माफिया के खिलाफ यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयान के बाद की गई। ट्रंप ने कहा था कि मेक्सिको के ड्रग्स तस्करों को अमेरिका आतंकी घोषित कर सकता है। (रायटर)

हांगकांग में फिर भड़का आंदोलन

लोकतंत्र की मांग ▸ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ सख्ती की मंशा जताई

चीन की आपत्तियों के बावजूद प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने वाले बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए रविवार को हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों ने विशाल रैली निकालकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया। रैली में अमेरिकी झंडे भी लहराए गए। एपी

आंदोलनकारियों ने अमेरिकी दूतावास पहुंच आभार जताया

हांगकांग, रायटर : हफ्ते भर से ज्यादा की शांति के बाद हांगकांग में लोकतंत्र की मांग कर रहे आंदोलनकारी रविवार को सड़कों पर वापस आ गए। निकाय चुनावों में मिली भारी सफलता और अमेरिका द्वारा समर्थन में बनाए गए कानून से आंदोलनकारी जोश से भरे हुए थे। एक हजार से ज्यादा आंदोलनकारियों ने जुलूस के रूप में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पहुंचकर आभार जताया। हजारों अन्य प्रदर्शनकारियों ने पूर्व की भांति महानगर के मुख्य व्यापारिक इलाके में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने इन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। बड़ी संख्या में बुजुर्गों और आम नागरिकों ने सड़कों पर आकर हांगकांग की चीन से आजादी की मांग की।

हजारों आंदोलनकारियों का प्रदर्शन सिम शा सुई व्यापार क्षेत्र में हुआ। यहां पर जैसे ही पुलिस की घेराबंदी हुई, वैसे ही हिंसा की आशंका से दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो गए। यहां पर भी कुछ बुजुर्ग लोग अपने पालतू कुत्ते लेकर प्रदर्शन स्थल पर आए, जैसे कि शनिवार को कोलून इलाके में आए थे। बाद में यहीं से एक हजार आंदोलनकारियों ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक जुलूस निकाला। वहां उन्होंने हांगकांग में मानवाधिकारों के सम्मान के लिए कानून बनाए जाने के लिए अमेरिकी संसद और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया। व्यापारिक इलाके में इसी के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले चलाए। पुलिस ने यहां से दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है।

एशिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में शुमार हांगकांग में हफ्ते भर से ज्यादा की शांति के बाद रविवार को यह प्रदर्शन हुआ। इससे पहले पॉलीटेक्निक विश्वविद्यालय में आंदोलनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद से शांति बनी हुई थी। लेकिन निकाय चुनावों में लोकतंत्र समर्थकों की जीत और पक्ष में अमेरिका के कानून बनाने से ठंडे पड़े आंदोलन को नई ऊर्जा मिली है। इसी के चलते चीन की सख्त कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद हजारों आंदोलनकारी और बुजुर्ग नागरिक भी सड़कों पर फिर उतरे हैं। आंदोलनकारियों ने आंदोलन को जारी रखने का संकल्प जताया है।

'संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार करे तालिबान'

▸ **अफगान राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा, तालिबान के लिए यह सबसे अच्छा मौका है**

▸ **ऐसा करने पर अफगानिस्तान सरकार के साथ उसकी बातचीत का मार्ग प्रशस्त होगा**

काबुल, एएनआइ : अफगान सरकार ने कहा है कि तालिबान को अमेरिका के संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो इससे अफगानिस्तान सरकार के साथ उसकी बातचीत का मार्ग प्रशस्त होगा। अफगान सरकार का यह बयान गत गुरुवार को अफगानिस्तान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में शांति बहाली की वकालत की थी।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता सादिक सिद्दीकी ने रविवार को कहा, 'हमें पूरी उम्मीद है कि तालिबान अमेरिका के संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। अगर वह वास्तव में संघर्ष विराम के प्रति प्रतिबद्ध है तो मेरी राय में यह उसके लिए सबसे अच्छा मौका है।' गुरुवार को अफगानिस्तान की अपनी पहली यात्रा में ट्रंप ने कहा था, अमेरिका और तालिबान के बीच होने वाले समझौते में तालिबान द्वारा संघर्ष विराम की शर्त शामिल है। मुझे लगता है कि तालिबान इसके लिए सहमत होगा। तालिबान समझौता करना चाहता है और हम उनसे मिलने वाले हैं। जब हम संघर्ष विराम चाहते थे, वे संघर्ष विराम नहीं चाहते थे। लेकिन अब वे संघर्ष विराम चाहते हैं।

सादिक सिद्दीकी। ट्विटर से साभार

पहले समझौता फिर होगी संघर्ष विराम की घोषणा : तालिबान के पूर्व सदस्य मावोलाना जलालुद्दीन शिनवारी ने कहा है कि तालिबान तब तक संघर्ष विराम समझौते पर सहमत नहीं होगा जब तक वह अमेरिका के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता। पहले समझौते पर हस्ताक्षर होंगे फिर संघर्ष विराम की घोषणा की जाएगी। समझौते पर दस्तखत के जरिये तालिबान अमेरिका से विश्वास बहाली की गारंटी चाहता है।

चीन में नया फोन नंबर लेने वालों को कराना होगा फेस स्कैन

▸ **आइटी अथॉरिटी ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को दिया आदेश**

▸ **सरकार के इस कदम पर सोशल मीडिया में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली**

बीजिंग, एएफपी : चीन में रविवार से नया फोन नंबर लेने वालों के लिए फेस (चेहरा) स्कैन अनिवार्य कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अथॉरिटी ने इस संबंध में सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को आदेश जारी कर दिया है। चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गत सितंबर में नागरिकों के ऑनलाइन हितों की रक्षा के लिए एक नोटिस जारी किया था। नए आदेश को उसी संदर्भ में देखा जा रहा है।

आदेश में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति नया फोन नंबर लेने आए तो टेलीकॉम ऑपरेटर उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) और अन्य तकनीक का उपयोग करें। सरकारी दूरसंचार कंपनी चाइना यूनीकॉम के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के अनुसार, नए नियमों के तहत नया फोन नंबर लेने वालों को विभिन्न मुद्राओं में फोटो स्कैन कराने पड़ेंगे। सितंबर में जारी नोटिस में कहा गया था कि अगले चरण में मंत्रालय फोन नंबर के लिए वास्तविक नाम पंजीकरण को सख्ती से लागू करेगा।

सरकार के इस कदम पर सोशल मीडिया में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ यूजर ने अपने बायोमीट्रिक डाटा के लीक होने और बेचे जाने को लेकर चिंता जताई है। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफार्म वीबो पर एक यूजर ने लिखा, यह नियंत्रण की पराकाष्ठा है। एक अन्य यूजर ने लिखा, नियंत्रण, अब और अधिक नियंत्रण। शोधकर्ताओं ने भी सरकार को फेस स्कैन के आंकड़ों को एकत्र करने से जुड़ी गोपनीयता के जोखिमों को लेकर चेतावनी दी है।

प्रतीकात्मक

आइएस ने ली लंदन हमले की जिम्मेदारी

लंदन, प्रेट्र : आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) ने लंदन में बीते शुक्रवार को हुई चाकूबाजी की घटना की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने हालांकि बाद में हमलावर को मार गिराया था।

आइएस ने अपने खिलाफ कई देशों की गोलबंदी का जिक्र करते हुए अमाक न्यूज एजेंसी पर कहा, 'लंदन में हमला करने वाला व्यक्ति आइएस का लड़ाका था और उसने गठबंधन देशों के नागरिकों को निशाना बनाने के लिए ऐसा किया।' आतंकी संगठन ने हालांकि अपने दावे की पुष्टि में किसी प्रकार का कोई सुबूत पेश नहीं किया है। शुक्रवार को मशहूर लंदन ब्रिज के पास इस हमले को अंजाम देने वाला उस्मान खान 2012 में भी आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता का दोषी करार दिया था और उसे सात साल की सजा सुनाई गई थी। वह दिसंबर, 2018 में पैरोल पर रिहा हुआ था और इलेक्ट्रॉनिक टैग के जरिये उसकी मॉनीटरिंग की जा रही थी।

बता दें कि ब्रिटेन के मशहूर लंदन ब्रिज के निकट बीते शुक्रवार को चाकूबाजी की घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया था और ब्रिज की घेराबंदी कर दी गई थी। साथ ही आपातकालीन सेवाओं को भी बहाल कर दिया गया है। इस आतंकी घटना की बाद सोशल मीडिया पर इससे संबंधित वीडियो वायरल हुए थे। लंदन ब्रिज उन इलाकों में से एक है, जहां जून 2017 में आइएस के आतंकी हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने भी लंदन ब्रिज के निकट हुए हमले की निंदा की है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जुड दीरे ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घटना की जानकारी दे दी गई है और हम लगातार घटना पर नजर लगाए हुए हैं। अमेरिका निर्दोष लोगों के खिलाफ हर तरह की हिंसक गतिविधियों की कड़ी निंदा करता है। इस समय हम अपने सहयोगी ब्रिटेन के साथ पूरी तरह खड़े हैं।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (दाएं से दूसरे) ने रविवार को लंदन ब्रिज क्षेत्र में घटनास्थल का दौरा किया, जहां चाकूबाजी में दो लोगों की मौत हो गई थी। उनके साथ गृह मंत्री प्रीति पटेल (बाएं से दूसरी) व लंदन की पुलिस प्रमुख क्रेसिडा डिक (बाएं) भी थीं। रायटर

अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में गोलीबारी 11 लोग घायल

वाशिंगटन, एजेंसियां : अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में रविवार तड़के गोलीबारी 11 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की घटना फ्रेंच क्वार्टर में हुई है। घायलों में दो की हालत गंभीर है। शहर के भीड़ भरे वाणिज्यिक इलाके में तड़के तीन बजे गोलीबारी हुई। उल्लेखनीय है कि इस ऐतिहासिक शहर में दुनियाभर से पर्यटक आते हैं।

पुलिस ने कहा कि घटना का पता चलते ही अधिकारी वहां पहुंच गए। लेकिन, दुर्भाग्यवश वहां इतनी भीड़ थी कि यह पता नहीं चल सका कि गोली किसने चलाई है? हमें यह भी पता नहीं कि यह किस तरह शुरू हुआ। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। हालांकि, अभी यह पता नहीं चल सका है कि गोलीबारी उसने की है या नहीं। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि अमेरिका में बीते कुछ सालों में गोलीबारी की घटनाएं काफी बढ़ गई है और इसमें सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं, जबकि कई लोगों की जान भी चली गई है। वहां लोगों को बंदूक का लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। गोलीबारी की बढ़ती घटनाओं के बाद अब इसके सख्त नियमन की मांग भी उठनी शुरू हो गई है।

असांजे की रिहाई की मांग...

विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के समर्थकों ने मेक्सिको सिटी में रविवार को प्रदर्शन किया और उनकी रिहाई की मांग की। अपनी वेबसाइट पर इराक युद्ध से जुड़े चार लाख गोपनीय दस्तावेज लीक करने के बाद वह अमेरिका के आंखों की किरकिरी बन गए थे। यौन अपराधों के मामले में उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था और वह जेल में हैं। असांजे के समर्थन में ब्राजील, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में भी प्रदर्शन हो चुके हैं। रायटर

इराकी संसद ने दी पीएम के इस्तीफे को मंजूरी

▸ **कामचलाऊ सरकार की भूमिका में आई पूरी कैबिनेट**

▸ **विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के संकेत दिए**

बगदाद, एएफपी : इराकी संसद ने प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल महदी के इस्तीफे को रविवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही संविधान के मुताबिक पूरी कैबिनेट कामचलाऊ सरकार की भूमिका में आ गई है। स्पीकर ने कहा है कि अब वह राष्ट्रपति बरहम सलेह से नए प्रधानमंत्री को नामित करने का अनुरोध करेंगे। हालांकि विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के संकेत दिए हैं।

दरअसल, देश में बढ़ती हिंसा की वारदातों के बीच शिया धार्मिक नेता अली सिसतानी के हस्तक्षेप के बाद प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा था कि वह संसद को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में संसद का सत्र रविवार दोपहर बाद शुरू हुआ और कुछ मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। दो महीने के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में अब तक 420 लोगों की जान जा चुकी है। संसद का सत्र शुरू होने के कुछ देर पहले भी एक प्रदर्शनकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

इराक ने दिखाई प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता : सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए समूचे इराक में जुलूस निकाले गए। सुन्नी बहुल इलाके में भी इस तरह के जुलूस देखे गए जबकि पहले इन इलाकों के लोग इस तरह के आयोजन में शामिल नहीं होते थे। प्रदर्शनकारी अक्टूबर से सरकार की बर्खास्तगी की मांग को लेकर राजधानी बगदाद और शिया बहुल इलाकों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार भ्रष्ट और अक्षम होने के साथ ही विदेशी शक्तियों के इशारे पर काम कर रही है। मुल्क में पिछले कुछ दिनों में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इनमें बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने के बाद इराक के सभी प्रांतों में प्रदर्शनकारियों के पक्ष में एकजुटता देखी जा रही है। मोसुल के एक विश्वविद्यालय में निकाले गए जुलूस में सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा, लोग अपने मूल अधिकारों के बारे में पूछ रहे हैं। सरकार को इसका जवाब देना होगा।

पुलिस अधिकारी को सुनाई मौत की सजा : प्रदर्शनकारियों की हत्या का दोषी ठहराते हुए इराकी अदालत ने एक पुलिस अधिकारी को मौत की सजा सुनाई। दो महीनों से चल रहे प्रदर्शन के दौरान किसी पुलिसवाले को दी गई यह पहली सजा है। दो नवंबर को दक्षिणी शहर में सात प्रदर्शनकारियों की मौत के मामले में पुलिस प्रमुख को सजा दी गई है।

आदिल अब्दुल महद। फाइल

इराक में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान एक घायल को अस्पताल ले जाते प्रदर्शनकारी। रायटर

हाफिज सईद के खिलाफ आतंकी फंडिंग के आरोपों की सुनवाई सात से

लाहौर, प्रेट्र : मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उद दावा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ आतंकी फंडिंग के आरोपों को लेकर आतंकवाद विरोधी अदालत में अगले महीने सुनवाई शुरू होगी। लाहौर में आतंकवाद विरोधी कोर्ट (एटीसी) ने शनिवार को सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकवाद की आर्थिक मदद करने के आरोपों की सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में हाफिज और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सात दिसंबर की तारीख तय कर दी। शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच जमात-उद दावा सरगना को कोट लखपत जेल से एटीसी लाया गया था।

सुनवाई के बाद कोर्ट के एक अधिकारी ने कहा, 'एटीसी न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सईद और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सात दिसंबर की तारीख तय कर दी।'

जेकेएलएफ से लेबर पार्टी के समर्थन लेने पर आपत्ति

▸ **भारतीय मूल के नेता डॉ. पाटिल ने तत्काल फैसला रद करने की मांग की**

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन में भारतीय मूल के लेबर पार्टी के नेता डॉ. नीरज पाटिल ने अपनी पार्टी द्वारा आतंकी संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) से चुनाव में समर्थन लेने पर कड़ी आपत्ति जताई है। कहा है कि आतंकी संगठन से समर्थन न लेने की अविलंब घोषणा कर पार्टी भविष्य में होने वाले छवि के नुकसान से बचे।

लेबर पार्टी के महासचिव जेनी फॉर्मबी को लिखे पत्र में डॉ. पाटिल ने कहा है कि जेकेएलएफ ने फरवरी 1984 में बर्मिंघम से भारतीय राजनयिक रवींद्र म्हात्रे का अपहरण किया था। संगठन ने म्हात्रे की रिहाई के बदले भारत से अपने संस्थापक सदस्य मकबूल बट की रिहाई की मांग की थी। बट उन दिनों भारतीय जेल में बंद था। भारत द्वारा इस मांग को माने जाने से इन्कार करने पर जेकेएलएफ ने म्हात्रे की निर्मम हत्या कर दी थी। डॉ. पाटिल ने लिखा है कि जेकेएलएफ ने भारत में तमाम आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। इसके चलते भारत सरकार ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। भारतीय मूल के लेबर नेता ने लिखा है कि पार्टी की ल्यूटन इकाई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जेकेएलएफ का सहयोग लेने का पत्र प्रकाशित कर रखा है। इस पत्र पर जेकेएलएफ के ब्रिटिश चैप्टर के प्रेसिडेंट सैयद तहसीन गिलानी के दस्तखत हैं। इसमें 12 दिसंबर के चुनाव में लेबर पार्टी का समर्थन करने की बात लिखी है।

डॉ. पाटिल ने कहा है कि वह भारत और पाक के बीच शांति और अच्छे संबंधों के प्रबल समर्थक हैं। दोनों देशों के लोगों को नजदीक लाने के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम बंधुओं के सहयोग से भारत-पाकिस्तान की साझी संस्कृति के पक्षधर लोगों की प्रतिमाएं लगवाने का कार्य भी किया है। डॉ. पाटिल ने लिखा है कि ल्यूटन की लेबर पार्टी के इस तरह से जेकेएलएफ से जुड़ने से उन्हें गहरा धक्का लगा है।

बांग्लादेश में भी ई-सिगरेट पर लगाया जाएगा प्रतिबंधित

ढाका, रायटर : अमेरिका और भारत के बाद बांग्लादेश ने भी ई-सिगरेट पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली है। युवाओं के बीच ई-सिगरेट की बढ़ती लत और सेहत पर इसके खतरनाक असर को देखते हुए बांग्लादेश की सरकार ई-सिगरेट के इस्तेमाल व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की तैयारी में जुट गई है।

बांग्लादेश के स्वास्थ्य विभाग के सचिव शेख यूसुफ हारुन ने बताया कि केंद्र सरकार तंबाकू नियंत्रण नीति 2019 के जरिये ई-सिगरेट समेत अन्य हानिकारक वेपोराइजर पर पाबंदी लगाने की दिशा में काम शुरू कर चुकी है। बिल को जल्द ही संसद से पारित करा लिया जाएगा।

ई-सिगरेट पर भारत सरकार बीते अक्टूबर में पाबंदी लगा चुकी है। हाल में अमेरिका में ई-सिगरेट की लत से 12 लोगों की मौत की खबर ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका के बाद अन्य देशों ने भी स्वास्थ्य से जुड़ी इस समस्या को गंभीरता से लिया है।

प्रकृति के खिलाफ युद्ध को रोका जाए

▸ **संयुक्त राष्ट्र महासचिव का दुनिया से आह्वान**

▸ **कहा– दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की है जरूरत**

▸ **जंगलों की आग से लेकर बाढ़ तक सभी कारण हैं मानवजनित**

▸ **पेरिस समझौते के प्रावधानों को अपनाना है जरूरी**

एंटोनियो गुतेरस। एएफपी

मैड्रिड, रायटर : प्रकृति के खिलाफ छिड़ा युद्ध बंद होना चाहिए और पर्यावरण में हो रहे बदलावों को रोकने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी। यह बात संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने रविवार को पर्यावरण पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से पूर्व कही है। सम्मेलन दो दिसंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा।

गुतेरस ने कहा, जंगलों की आग से लेकर भीषण बाढ़ की स्थिति तक सभी कारण मानवजनित हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए पेरिस समझौते में प्रावधान किया गया है। इससे धरती के बढ़ते तापमान को कम करने में मदद मिलती। इसलिए प्रकृति के खिलाफ युद्ध को निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए। जमीन की गहरी खुदाई और जमीन के भीतर की चट्टानों को तोड़ने के सिलसिले में कम कर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ को रोकने की शुरुआत कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को बरकरार रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल से हम प्रकृति को लाभ पहुंचा सकते हैं, जिसका अंततः फायदा समूची मानव जाति को होगा। कोयले के ईंधन के रूप में इस्तेमाल को रोककर ऑक्सीजन और अन्य लाभदायक गैसों के नुकसान को बचाया जा सकता है। ईंधन के रूप में लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल प्रकृति को दोहरा नुकसान पहुंचाने वाला है। पेरिस समझौते में ईंधन के रूप में लकड़ी और कोयले के इस्तेमाल को रोकने की वकालत की गई है।

गुतेरस ने कहा, कई देशों ने 2015 में हुए पेरिस समझौते के अनुसार कार्य करना शुरू नहीं किया है। राजनीतिक इच्छाशक्ति का कमजोर होना इसकी मुख्य वजह रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यह टिप्पणी कर अमेरिका को संदेश देने की कोशिश की, जहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में पेरिस समझौते के प्रावधानों को अमेरिका के लिए नुकसानदायक बताते हुए उससे हटने की घोषणा कर दी थी। गुतेरस की टिप्पणी को अमेजन के जंगल में इसी वर्ष लगी भयंकर आग को नियंत्रित करने में ब्राजील सरकार की लापरवाही के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है। ये जंगल दुनिया के सबसे बड़े कार्बन डाई ऑक्साइड के अवशोषक माने जाते हैं। गुतेरस ने सम्मेलन में चर्चा के अन्य आवश्यक बिंदुओं पर भी चर्चा की।

मैं व्यक्तिगत कारणों के चलते विश्व चैलेंज टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले रहा हूं, लेकिन प्रेसिडेंट कप में खेलूंगा।
— डस्टिन जॉनसन, गोल्फर, अमेरिका

वाटफोर्ड ने मैनेजर सांचेज फ्लोरेस को हटाया

लंदन : इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) क्लब वाटफोर्ड ने रविवार को अपने मैनेजर क्विकी सांचेज फ्लोरेस की छुट्टी कर दी। क्लब ने साउथैंपटन के हाथों मिली 1–2 की हार के बाद सांचेज को पदमुक्त करने का फैसला किया। क्रिस हॉटन को फ्लोरेस की जगह नया मैनेजर नियुक्त किया गया। सांचेज ने इस साल सितंबर में जावी गार्सिया का स्थान लिया था, लेकिन वह क्लब को 10 में से सिर्फ एक मैच में जीत दिला सके।

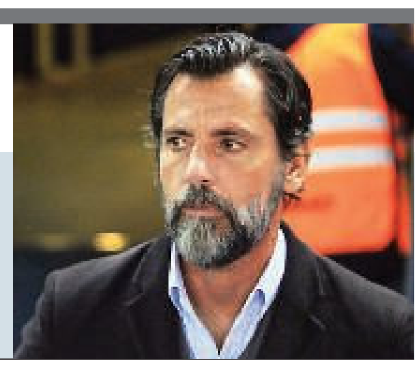

गांगुली का कार्यकाल 2024 तक बढ़ाने की तैयारी

बीसीसीआइ एजीएम ▶ पदाधिकारियों की समय सीमा बढ़ाने के लिए ली जाएगी सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, आइसीसी में जय शाह करेंगे प्रतिनिधित्व

मुंबई, प्रेट्र : सौरभ गांगुली की अगुआई वाले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने रविवार को यहां अपनी 88वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य प्रशासनिक सुधारों में ढिलाई देने का फैसला किया गया, ताकि पदाधिकारियों के कार्यकाल की सीमा को बढ़ाया जा सके। इसका उद्देश्य गांगुली के कार्यकाल की अवधि को बढ़ाने के लिए रास्ता साफ करना है। साथ ही सचिव जय शाह को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की बैठकों के लिए नियुक्त किया गया। शाह आइसीसी की मुख्य कार्यकारी समिति (सीईसी) की भविष्य की बैठकों में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे।

एजीएम के बाद प्रेसवार्ता के दौरान गांगुली ने कहा, 'आखिरकार अंत में कोर्ट फैसला करेगी।' मौजूदा संविधान के अनुसार अगर किसी पदाधिकारी ने बीसीसीआइ या राज्य संघ में मिलाकर तीन साल के दो कार्यकाल पूरे कर लिए हैं तो उसे तीन साल का अनिवार्य ब्रेक लेना होगा। गांगुली ने 23 अक्टूबर को बीसीसीआइ अध्यक्ष का पद संभाला था और उन्हें अगले साल पद छोड़ना होगा, लेकिन छूट दिए जाने के बाद वह 2024 तक पद पर बने रह सकते हैं।

बीसीसीआइ चाहता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड की मौजूदा व्यवस्था को हटाया जाए ताकि कोई भी पदाधिकारी बोर्ड या राज्य संघ में अलग-अलग दो कार्यकाल (छह साल) पूरे कर सके। यदि मंजूरी दी जाती है, तो यह कदम शाह के लिए एक विस्तार पाने का मार्ग प्रशस्त करेगा, क्योंकि उनके वर्तमान कार्यकाल में बचा हुआ समय भी एक वर्ष से कम है।

मुंबई में रविवार को एजीएम के दौरान (बायें से) बीसीसीआइ के सचिव जय शाह, अध्यक्ष सौरव गांगुली और कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमल। प्रेट्र

आइसीसी की मुख्य कार्यकारी की भविष्य की बैठकों में भाग लेने के लिए शाह को भारत का प्रतिनिधि बनाया गया है। जब बीसीसीआइ का प्रशासन सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा किया जा रहा था तब बीसीसीआइ के सीईओ राहुल जौहरी इन बैठकों के लिए बोर्ड के प्रतिनिधि थे। लेकिन, अब पूर्व बोर्ड का कार्यकाल होने के साथ ही यह भूमिका सचिव के पास वापस चली गई है।

बीसीसीआइ के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, 'जब भी बैठक होगी, जय इसमें बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे।' आइसीसी सीईसी की अगली बैठक की तारीख और स्थल अभी तय नहीं हुआ है। जब बोर्ड का प्रशासनिक काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) देख रही थी तब बीसीसीआइ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी बोर्ड के प्रतिनिधि थे। जय शाह गृहमंत्री अमित शाह के बेटे हैं।

गांगुली ने कहा, 'आइसीसी का नियम है कि आइसीसी सीईसी में सचिव द्वारा बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया जाता है।' हालांकि, बोर्ड ने अभी तक आइसीसी बोर्ड की बैठकों के लिए अपने प्रतिनिधि पर फैसला नहीं किया है। इसके अलावा बीसीसीआइ ने क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) की नियुक्ति को स्थगित करने का फैसला किया। गांगुली ने कहा कि विवादास्पद हितों के टकराव का नियम, जिसे सीओए को लागू करना मुश्किल लगता था, भी इसके रास्ते में आ रहा है। उन्होंने कहा, 'हम सीएसी बनाएंगे और हमने (लोकपाल) जस्टिस डीके जैन से मुलाकात की। मैं और वीवीएस (लक्ष्मण) स्पष्ट थे, लेकिन हमें पूरी तरह से स्पष्ट होने की जरूरत है कि हितों का टकराव क्या है और क्या नहीं है। यह नियम सभी को रोकता है, इसलिए हम सीएसी नहीं बना सकते हैं। हितों का नियम सिर्फ हमारे (पदाधिकारियों) के लिए होना चाहिए।'

नए संविधान के तहत हितों के टकराव के चलते सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और गांगुली के हटने के बाद कपिल देव, शांता रंगास्वामी और अंशुमन गायकवाड़ ने पुरुष टीम के मुख्य कोच की नियुक्ति की थी। जिसके बाद रवि शास्त्री को शीर्ष पद के लिए विस्तार मिला था। गांगुली ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि सचिन और लक्ष्मण वापस आना चाहेंगे।'

सीएसी को हितों के टकराव के आरोपों के कारण विवादों में रखा गया, जिसने तीन मूल सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए प्रेरित किया गया। रंगास्वामी और गायकवाड़ दोनों भारतीय क्रिकेटरों के संघ के प्रतिनिधि के रूप में शीर्ष परिषद का हिस्सा हैं। चयनसमिति की नियुक्ति करना सीएसी का विशेषाधिकार है। बोर्ड यह भी चाहता है कि कोर्ट संवैधानिक संशोधनों पर भविष्य के फैसलों से बाहर रहे और प्रस्ताव दिया गया है कि एजीएम में तीन-चौथाई बहुमत अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए पर्याप्त होगा। अधिकारियों का यह भी मानना है कि हर संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लेना व्यावहारिक नहीं है, जो मौजूदा संविधान के अनुसार होना चाहिए।

धौनी के टी–20 विश्व कप में खेलने के सवाल पर बोले गांगुली, उन्हीं से पूछें

मुंबई, प्रेट्र : सौरव गांगुली से पूछा गया कि क्या विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धौनी अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी–20 विश्व कप में हिस्सा लेंगे? इसके जवाब में बीसीसीआइ अध्यक्ष ने कहा, 'कृपया धौनी से पूछें।' धौनी जुलाई में इंग्लैंड में वनडे विश्व कप में भारत के सेमीफाइनल में बाहर होने के बाद से ही क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वह वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं गए और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी नहीं खेले।

गांगुली से जब एक पत्रकार ने धौनी की टी–20 विश्व कप में खेलने की संभावना के बारे में पूछा तो उनका सीधा जवाब था, 'कृपया धौनी से पूछें।' गांगुली बोर्ड की 88वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हाल ही में महेंद्र सिंह धौनी जब एक कार्यक्रम के लिए मुंबई में आए थे तब भी उनकी वापसी को लेकर पत्रकारों ने सवाल किए थे। हालांकि धौनी ने अपनी वापसी से जुड़े सवाल को बीच में ही काटते हुए कहा था कि उनसे इस बारे में जनवरी तक कुछ नहीं पूछा जाए।

एमएसके प्रसाद की अगुआई वाली चयन समिति का कार्यकाल खत्म : गांगुली

मुंबई, प्रेट्र : एमएसके प्रसाद का चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में घटनाप्रधान कार्यकाल रविवार को समाप्त हो गया क्योंकि बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने स्पष्ट किया है कि, 'आप अपने कार्यकाल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकते।' प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने का मतलब है कि गांगुली की अगुआई वाला बीसीसीआइ पुराने संविधान के अनुसार चल रहा है जिसमें चयनसमिति के लिए अधिकतम कार्यकाल चार साल का था। संशोधित संविधान में अधिकतम पांच साल के कार्यकाल का प्रावधान है।

प्रसाद और गगन खोड़ा को 2015 में नियुक्त किया गया था और उनकी जगह अब नए सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। गांगुली ने बीसीसीआइ की 88वीं वार्षिक आम बैठक के बाद कहा, 'कार्यकाल समाप्त हो गया है। आप कार्यकाल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकते। उन्होंने अच्छा काम किया।' जतिन परांजपे, शरणदीप सिंह और देवांग गांधी 2016 में चयन समिति से जुड़े थे और उनके कार्यकाल का अभी एक साल बचा हुआ है। उन्होंने कहा, 'हम चयनकर्ताओं का कार्यकाल तय करेंगे। हर साल चयनकर्ताओं की नियुक्ति करना सही नहीं है।' भारतीय टीम ने पांच सदस्यीय पैनल के कार्यकाल के दौरान अच्छी सफलताएं हासिल कीं लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम अनुभव के कारण उन्हें लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था।

प्रियम बने अंडर–19 विश्व कप के लिए भारत के कप्तान

अमित तिवारी, मेरठ

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मेरठ का नाम अब तक गेंदबाजी के लिए सुना जाता रहा है। प्रवीण कुमार, कर्ण शर्मा और वर्तमान में भारतीय टीम के स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार गेंद के साथ गिल्लियां उड़ाते रहे हैं। मेरठ की बल्लेबाजी भी पहली बार दुनिया भर में मेरठ का नाम रोशन करने जा रही है। अंडर-19 भारतीय टीम के कप्तान के तौर पर मेरठ के प्रियम गर्ग भारत से इंग्लैंड तक अपनी धुआंधार बल्लेबाजी की छाप पहले ही छोड़ चुके हैं। उन्हें रविवार को मुंबई में हुई चयनसमिति की बैठक में अंडर-19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान बना भी बना दिया गया। इस बैठक में पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को भी खास तौर से आमंत्रित किया गया था। शनिवार को प्रियम का जन्मदिन था और उसी दिन उन्हें उत्तर प्रदेश रणजी टीम का कप्तान बनाया गया था। उसके अगले दिन ही उन्हें अंडर-19 विश्व कप के लिए भी कप्तान चुन लिया गया। उत्तर प्रदेश के ही ध्रुव चंद जुरेल को उप कप्तान चुना गया है। हालांकि, बीसीसीआइ ने टीम की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

यहां से खुलता है भारतीय टीम का रास्ता : मुहम्मद कैफ, विराट कोहली, युवराज सिंह, जहीर खान सरीखे क्रिकेटर्स ने भी अपनी छाप अंडर-19 विश्व कप टीम से ही छोड़ी थी। उसी रास्ते पर आगे बढ़े प्रियम के लिए भी यह उपलब्धि भारतीय टीम का रास्ता खुलने जैसी ही है। अंडर-19 भारतीय टीम के कप्तान के तौर पर प्रियम इंग्लैंड में ही इंग्लैंड की टीम को हराकर लौटे। त्रिकोणीय सीरीज सीरीज में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ भी इंडिया अंडर-19 टीम की अगुआई की। बीसीसीआइ की चैलेंजर ट्रॉफी में भी प्रियम ने बेहतरीन कप्तानी के साथ ही बल्ले से शानदार प्रदर्शन दिखाया। दायें हाथ के बल्लेबाज प्रियम मध्य क्रम में खेलते हैं और इंडिया अंडर-23 के कप्तान भी रह चुके हैं।

मेरठ से ही शुरू होगी रणजी कप्तानी : छह साल बाद मेरठ में रणजी ट्रॉफी का मैच होगा। भामाशाह पार्क में यह मैच नौ से 12 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश और रेलवे के बीच होगा। इसी मैच से प्रियम उप्र रणजी टीम की कप्तानी संभालेंगे। रणजी टीम के कप्तान के तौर पर प्रियम अपना पहला मैच घरेलू मैदान पर ही खेलेंगे। आठ साल की उम्र से इसी मैदान पर क्रिकेट की ट्रेनिंग लेते हुए प्रियम ने यूपी की अंडर-14, अंडर-16 और अंडर-19 तक का सफर तय किया है। इसके साथ ही भारत की जूनियर टीमों का भी हिस्सा रहे।

मुंबई में बीसीसीआइ मुख्यालय में अंडर–19 विश्व कप के लिए टीम चयन की बैठक में हिस्सा लेने जाते पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़। प्रेट्र

पिता की तपस्या, बेटे का हुनर : प्रियम के पिता नरेश कुमार गर्ग टैक्सी चलाने के साथ हर दिन सुबह किला परीक्षितगढ़ (मेरठ) क्षेत्र से प्रियम को भामाशाह पार्क पहुंचाते और शाम को अपने साथ ही लेकर जाते थे। मेरठ कॉलेज क्रिकेट अकादमी में कोच संजय रस्तोगी के मार्गदर्शन में प्रियम ने क्रिकेट का ककहरा सीखा ही नहीं, बल्कि बहुत जल्द उसे जीने भी लगे।

साल 2011 में प्रियम क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने लगे थे। उसी दौरान उनके पिता नरेश व माता कुसुम देवी माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे और प्रियम के लिए बेहतरीन क्रिकेट करियर की प्रार्थना की। नरेश कुमार के अनुसार माता ने प्रार्थना सुनी, लेकिन उसी दौरान प्रियम के मां की तबीयत बिगड़ने लगी। पीलिया की शिकायत से जांच शुरू हुई जो लीवर के इंफेक्शन तक पहुंच गई। उसके बाद स्थिति खराब होती गई और 11 मार्च 2012 को उनके निधन के साथ ही प्रियम ने भी बल्ला छोड़ दिया।

यासिर के शतक के बावजूद पाकिस्तान पर हार का खतरा

डे–नाइट टेस्ट

एडिलेड, एएफपी : ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर अपनी किरकरी करा रहे पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आइना स्पिन गेंदबाज यासिर शाह ने दिखाया जब उन्होंने रविवार को डे-नाइट टेस्ट में आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कंगारुओं के खिलाफ शतक जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में पाकिस्तानी बल्लेबाज मेजबान टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने संघर्ष करते आ रहे हैं और यही हाल उनका सीरीज के इस दूसरे टेस्ट मैच में देखने को मिला। वहीं, शाह ने इन गेंदबाजों का पिच पर डट कर सामना किया। शाह के पहले टेस्ट शतक के बावजूद फॉलोऑन खेलने वाले पाकिस्तान पर दूसरी पारी में शीर्ष क्रम लड़खड़ाने के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी की हार का खतरा मंडरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल स्टार्क (6/66) ने पहली पारी में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए।

अभी भी पाक को 248 रन की जरूरत : पाकिस्तान ने रविवार को तीसरे दिन बारिश के कारण जल्दी खेल समाप्त किए जाने तक दूसरी पारी में तीन विकेट पर 39 रन बनाए थे और उसे पारी की हार से बचने के लिए अब भी 248 रन की जरूरत है। पाकिस्तान को दोपहर को अपनी पहली पारी छह विकेट पर 96 रन से आगे बढ़ाई। यासिर (113) के शतक और बाबर आजम के 97 रन की मदद से उसने अपनी पहली पारी में 302 रन बनाए। इस दौरान टीम के उपयोगी बल्लेबाज आजम शतक लगाने से चूक गए। इसके बावजूद वह ऑस्ट्रेलिया से 287 रन पीछे रह गया जिसने डेविड वार्नर की नाबाद 335 रन की मदद से अपनी पहली पारी तीन विकेट पर 589 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी।

दूसरी पारी में भी पाक बेहाल : ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने पाकिस्तान को फॉलोऑन के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही। जोश हेजलवुड ने सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक को एलबीडब्ल्यू आउट करके उन्हें खाता भी नहीं खेलने दिया। स्टार्क ने कप्तान अजहर अली (09) को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच कराकर स्कोर दो विकेट पर 11 रन कर दिया। दिन में बारिश का खतरा बना रहा और इससे बीच में व्यवधान भी पड़ा। बारिश थमने के बाद जब खेल शुरू हुआ तो हेजलवुड को बाबर आजम (08) का कीमती विकेट लिया, लेकिन बारिश आने से ऑस्ट्रेलिया आगे कहर बरपाना जारी नहीं रख सका।

यासिर ने जगाई उम्मीद : इससे पहले यासिर और आजम ने पाकिस्तान की धुंधली उम्मीद कायम रखी थी। अपनी स्पिन गेंदबाजी के लिए मशहूर और इससे पहले 36 टेस्ट मैचों में कभी 42 रन से आगे नहीं बढ़ पाने वाले यासिर ने दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने शतक जड़ा। गेंदबाजों को तब खास मदद नहीं मिल रही थी और आजम व यासिर ने इसका फायदा उठाकर 105 रन की साझेदारी की। आजम जब शतक के करीब थे तब स्टार्क की गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर पेन के दस्तानों में चली गई। स्टार्क ने अगली गेंद पर शाहीन अफरीदी को आउट किया, लेकिन मुहम्मद अब्बास (29) ने उन्हें हैट्रिक नहीं बनाने दी। यासिर ने 192 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया। उन्हें आखिर में पैट कमिंस ने नाथन लियोन के हाथों कैच कराकर पाकिस्तानी पारी का अंत किया। ब्रिसबेन टेस्ट में पाकिस्तान को पारी से हार का सामना करना पड़ा था।

08
वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए यासिर शाह (113) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट शतक लगाने वाले सातवें बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले इंग्लैंड के डब्ल्यूडब्ल्यू रीड (117), वेस्टइंडीज के सीसी डेपियाजा (122), वेस्टइंडीज के ही एफसीएम एलेक्सजेंडर (108), न्यूजीलैंड के एडम परोरे (110), इंग्लैंड के मैट प्रायर (118), भारत के रिद्धिमान साहा (117) इस क्रम पर खेलते हुए कंगारुओं के खिलाफ शतक लगा चुके हैं

2006
के बाद आठवें क्रम पर खेलते हुए शाह पाकिस्तान के लिए टेस्ट शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। 2006 में कामरान अकमल ने भारत के खिलाफ कराची में 113 रन बनाए थे

13
टेस्ट मैच लगातार पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में गंवाए हैं

एडिलेड में रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ने के बाद कुछ इस अंदाज में जश्न मनाते पाकिस्तान के यासिर शाह। एएफपी

▶ आजम शतक से चूके, स्टार्क ने झटके छह विकेट

▶ फॉलोऑन खेलते हुए पाक ने सस्ते में गंवाए तीन विकेट

संक्षिप्त स्कोर बोर्ड

ऑस्ट्रेलिया (पहली पारी) : 589/3 पारी घोषित (127 ओवर), डेविड वार्नर 335*, शाहीन शाह अफरीदी 3/88

पाकिस्तान (पहली पारी) : 302, यासिर शाह 113, बाबर आजम 97, मिशेल स्टार्क 6/66

पाकिस्तान (दूसरी पारी) : 39/3 (16.5), शान मसूद 14*, जोस हेजलवुड 2/15

रमीज राजा की टीम को सलाह, भविष्य में ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना

लाहौर, आइएएनएस : ऑस्ट्रेलिया के हाथों पहले टेस्ट में शर्मनाक हार का सामना करने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरे टेस्ट में भी पारी की हार के कगार पर खड़ी है। टीम के प्रदर्शन से निराश पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज राजा ने अपने देश की टीम को भविष्य में ऑस्ट्रेलिया का दौरा ही नहीं करने की सलाह दी है। राजा ने कहा, 'मेरा दिल टूट गया। मैं इस टीम का समर्थन करते हुए थक गया हूं। अगर आपके पास ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं, जो टेस्ट मैच जिता सकें तो फिर ऑस्ट्रेलिया मत जाएं। इयान चैपल (पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर) ने ठीक ही कहा था कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया में कहीं नहीं टिकता और मुकाबला पूरी तरह से एकतरफा रहता है। अब तो हालत यह है कि खुद ऑस्ट्रेलिया के ही दर्शक डेविड वार्नर के तिहरे शतक से खुश नहीं दिखे और उन्होंने पाकिस्तानी टीम को किसी तरह का मुकाबला नहीं करने के लिए लताड़ा। बाबर आजम और गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी ने ही थोड़ी लाज रखी, अन्यथा तो पूरी टीम निकम्मी साबित हुई। टीम के खराब प्रदर्शन से अब पाकिस्तानी प्रशंसक भी टीम से ऊब चुके हैं।'

रोहित तोड़ सकते हैं लारा का 400 रन का रिकॉर्ड : वार्नर

एडिलेड, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर का मानना है कि भारत के रोहित शर्मा में टेस्ट मैचों में नाबाद 400 रन के वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को तोड़ने की क्षमता है। लारा के नाबाद 400 रन टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है जो उन्होंने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। 33 वर्षीय वार्नर ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह व्यक्तिगत खिलाड़ी पर निर्भर करता है। हमारे यहां बाउंड्री काफी लंबी है, कभी–कभी चीजें काफी मुश्किल हो जाती हैं। जब थकान हावी होती है तो कड़े प्रयास करना और बड़े शॉट खेलना मुश्किल हो जाता है। अंत में मैंने तेजी लाने के लिए दो रन लेने का प्रयास किया क्योंकि मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा सकता हूं।' ऑस्ट्रेलिया के इस धुरंधर ओपनर ने कहा, 'मुझे लगता है कि अगर किसी खिलाड़ी का नाम लेना है तो एक दिन रोहित ऐसा कर सकते हैं।'

टेस्ट खेलने के लिए सहवाग ने प्रेरित किया : वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली नाबाद 335 रनों की अपनी पारी के पीछे वीरेंद्र सहवाग को प्रेरणा बताया है। वार्नर ने कहा, 'आइपीएल के दौरान दिल्ली के लिए खेलते हुए जब मैं सहवाग से मिला था। तब हम एक दिन बैठकर आराम से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुझे कहा कि मैं टी–20 खिलाड़ी की तुलना में बेहतर टेस्ट खिलाड़ी बनूंगा। मैंने उन्हें (सहवाग को) कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने काफी प्रथम श्रेणी मैच भी नहीं खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में टीमें स्लिप और गली में फील्डर खड़ा करती हैं। कवर में जगह खाली होती है, मिडविकेट होता है। मिड ऑफ और मिड ऑन होते हैं। ऐसे में आप तेज शुरुआत कर सकते हो और पूरा दिन खेल सकते हो।' वार्नर ने कहा, 'सहवाग की इस सलाह के बाद यह बात हमेशा मेरे दिमाग में रही। जब हम बातें कर रहे थे तो ये चीजें काफी आसान लग रही थीं।'

दूसरा टेस्ट

इंग्लिश कप्तान जो 114 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद, रोरी ने बनाए 101 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने पहली पारी में बनाए पांच विकेट पर 269 रन

रूट और बर्न्स के शतक से इंग्लैंड की वापसी

हैमिल्टन, एएफपी : कप्तान जो रूट और रोरी बर्न्स के शतकों से इंग्लैंड ने वापसी की, लेकिन न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन रविवार को अंतिम क्षणों में दो विकेट चटकाकर अपना पलड़ा भारी रखा।

रूट ने फॉर्म में वापसी की और वह 114 रन बनाकर खेल रहे हैं। बर्न्स ने क्षेत्ररक्षकों की गलतियों का फायदा उठाते हुए 101 रन की पारी खेली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी भी की। बारिश के कारण दिन का खेल जब 16 ओवर पहले समाप्त घोषित किया गया तब इंग्लैंड ने पांच विकेट पर 269 रन बनाए थे। विकेटकीपर बल्लेबाज ओली पोप चार रन बनाकर कप्तान का साथ निभा रहे हैं। इंग्लैंड की टीम अब भी न्यूजीलैंड से 106 रन से पीछे है जबकि उसके पांच विकेट शेष हैं। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 375 रन बनाए थे।

इंग्लैंड ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 39 रन से की जिसके बाद रूट और बर्न्स ने स्कोर 201 रन तक पहुंचाया। बर्न्स ने जीवनदान का पूरा फायदा उठाया। न्यूजीलैंड के क्षेत्ररक्षकों ने 10 और 19 रन के स्कोर पर उनके कैच टपकाए जबकि 87 रन के स्कोर पर उन्हें रन आउट करने का मौका गंवा दिया। बर्न्स ने नील वैगनर की गेंद को फाइन लेग पर एक रन के लिए खेलकर शतक पूरा किया। वह हालांकि दो गेंद बाद रन आउट हो गए। जीत रावल के थ्रो पर बीजे वाटलिंग ने उन्हें रन आउट कर दिया। बेन स्टोक्स भी 26 रन बनाने के बाद टिम साउथी (2/63) की गेंद पर रोस टेलर को कैच दे बैठे।

रूट ने वैगनर के ओवर में तीन चौकों के साथ 259 गेंद में 17वां टेस्ट शतक पूरा किया। इंग्लैंड के कप्तान की यह पारी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे जिससे यह सवाल उठने लगा था कि क्या कप्तानी के अतिरिक्त दबाव से उनकी फॉर्म प्रभावित हो रही है। फरवरी में वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जड़ने के बाद से पिछली 15 टेस्ट पारियों में यह रूट का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है।

पदार्पण कर रहे जैक क्राउले भी सिर्फ एक रन बनाने के बाद वैगनर की गेंद पर वाटलिंग को कैच दे बैठे। इसके कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई और दिन का खेल निर्धारित समय से पहले समाप्त करना पड़ा।

हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (बायें) और रोरी बर्न्स। एएफपी

अबू धाबी में हैमिल्टन ने किया सत्र का शानदार समापन

अबू धाबी, एएफपी

मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने रविवार को साल की आखिरी फॉर्मूला वन रेस अबू धाबी ग्रांप्रि जीतकर मौजूदा सत्र का शानदार समापन किया। पहले ही विश्व चैंपियनशिप पर कब्जा जमा चुके हैमिल्टन ने शुरुआत से ही रेस पर अपनी पकड़ बनाए रखी और सत्र की कुल 21 में से 11वीं जीत हासिल की।

दूधिया रोशनी के बीच आयोजित फाइनल रेस में 34 वर्षीय हैमिल्टन रिकॉर्ड 88वीं बार पोल पोजीशन के साथ उतरे और रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टापेन को 16 सेकेंड के बड़े अंतर से पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। फरारी के युवा ड्राइवर चार्ल्स लेकलर्क तीसरे स्थान पर रहे जिन्हें इस रेस के दौरान इंधन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं मर्सिडीज के ड्राइवर वाल्टेरी बोटास चौथे और फरारी के दिग्गज ड्राइवर सबेस्टियन वीटल पांचवें स्थान पर रहे। मौजूदा सत्र में दो रेस पहले ही हैमिल्टन का विश्व चैंपियन बनना तय हो गया था। अबू धाबी में उन्होंने पहले स्थान से रेस शुरू किया और पूरी रेस में वह आगे रहते हुए अबू धाबी में पांचवीं बार जीत हासिल की। इस दौरान उन्होंने सबसे तेज लैप भी निकाली। फॉर्मूला वन सर्किट पर सर्वाधिक 91 रेस जीतने का रिकॉर्ड माइकल शूमाकर के नाम है जिनसे अब हैमिल्टन महज सात जीत दूर हैं।

फॉर्मूला वन

▶ साल के आखिरी ग्रांपि रेस में लुइस ने हासिल की जीत

▶ दो रेस पहले ही विश्व चैंपियनशिप जीत चुके थे हैमिल्टन

413 अंकों के साथ लुइस हैमिल्टन 2019 विश्व चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहे। दो रेस पहले ही उन्होंने अपना छठा विश्व खिताब हासिल कर लिया था

सुमित ने सेना को समर्पित की जीत

नई दिल्ली : डेविस कप में पाकिस्तान को हराकर भारत को 2020 के क्वालीफायर में पहुंचाने वाले टीम इंडिया के सदस्य सुमित नागल ने इस जीत को भारतीय सेना को समर्पित किया है। भारत की इस जीत के बाद सुमित ने इंस्टाग्राम पर लिखा, यह जीत भारतीय सेना और उनके परिवारों को समर्पित, जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा करते हैं। रोमांचक सप्ताह रहा। इससे बेहतर सप्ताह नहीं हो सकता। टीम में सभी का प्रदर्शन शानदार था।

मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहेगी।
– मायमोल रॉकी, कोच, भारतीय महिला फुटबॉल टीम

न्यूज गैलरी

शमीम ने जीता खिताब

अहमदाबाद : दिल्ली के गोल्फर शमीम खान ने अंतिम दौर में दो अंडर 70 का कार्ड खेलकर यहां रविवार को केंसविले ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में तीन शॉट की बढ़त से आसान जीत हासिल की। अनुभवी गोल्फर ने शनिवार तक दो शॉट की बढ़त बना रखी थी। उनका कुल स्कोर 13 अंडर 275 का रहा। शमीम ने इस तरह टाटा स्टील पीजीटीआइ में 15वीं ट्रॉफी अपने नाम की। यह उनके करियर की कुल 17वीं पेशेवर जीत है। पुणे के उद्यान माने अंतिम दौर में 71 का कार्ड खेला और कुल 10 अंडर 278 के स्कोर के साथ उपविजेता रहे। (प्रेट्र)

फाइनल में भिड़ेंगे भारत–पाक

काठमांडु : दक्षिण एशियाई खेलों में पुरुषों की वॉलीबॉल स्पर्धा के फाइनल में गत चैंपियन भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। सेमीफाइनल में रविवार को भारत ने श्रीलंका को 27–25, 25–19, 21–25, 25–21 से हराया जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 25–15, 25–21, 26–24 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला मंगलवार को खेला जाएगा। उधर, भारतीय महिला टीम भी फाइनल में पहुंच चुकी है और उसे भी मंगलवार को फाइनल में मेजबान नेपाल से भिड़ना है। (प्रेट्र)

डीवाइ स्टेडियम का निरीक्षण

मुंबई : विश्व की शीर्ष फुटबॉल संचालन संस्था फीफा के अधिकारियों ने यहां नवी मुंबई के डीवाइ पाटिल स्टेडियम का निरीक्षण किया और तैयारियों की प्रगति पर संतोष जताया। यह स्टेडियम अगले साल महिलाओं के अंडर–17 फुटबॉल कप की मेजबानी के प्रस्तावित स्थलों में से एक है। फीफा अधिकारी ओलिवर वोग्ट ने कहा कि मौजूदा ढांचा अच्छा है। हमारे लिए यह भी काफी अहम है कि यहां पर ऐसी मजबूत टीम है जो पहले भी फीफा विश्व कप की मेजबानी कर चुकी है और उसे इसका काफी अच्छा अनुभव है। फीफा दल के साथ आयोजन समिति (एलओसी) के सदस्य भी मौजूद थे। (प्रेट्र)

जोशुआ का नया विश्व रिकॉर्ड

वेलेंसिया : यूगांडा के जोशुआ चेप्तेगेइ ने रविवार को वेलेंसिया में 10 किलोमीटर स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाते बनाया। जोशुआ ने केनयान लियोनार्ड कोमोन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर सत्र का शानदार समापन किया। 10000 मीटर के मौजूदा विश्व चैंपियन जोशुआ ने 26 मिनट और 38 सेकेंड का समय लेकर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया और केनयान के रिकॉर्ड को छह सेकेंड से पीछे छोड़ा। (रायटर)

फुटबॉल डायरी ▸ सीरी–ए में जुवेंटस ने सासुओलो से 2–2 से खेला ड्रॉ, क्रिस्टियानो ने पिछले चार मैचों से चले आ रहे गोल के सूखे को किया खत्म

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जुवेंटस को हार से बचाया

तुरिन, रायटर : स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अक्टूबर के बाद जुवेंटस के लिए पहला गोल करते हुए सीरी-ए में अपनी टीम को सासुओलो के खिलाफ हार से बचा लिया। इटालियन फुटबॉल लीग में रविवार को जुवेंटस को सासुओलो से 2-2 से ड्रॉ खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस सत्र में यह केवल तीसरी बार है जब इटालियन चैंपियन जुवेंटस को अंक गंवाना पड़ा।

तुरिन में लियोनार्डो बोनुसी (20वें मिनट) ने गोल करके जुवेंटस को शुरुआती बढ़त दिलाई लेकिन उनके गोल के तीन मिनट बाद ही जेरेमी बोगा ने गोल करके सासुओलो को बराबरी दिलाई। इसके बाद फ्रांसिस्को कैपुतो (47वें मिनट) ने दूसरे हाफ की शुरुआत में जुवेंटस की डिफेंस और गोलकीपर बुफोन की गलती का फायदा उठाकर सासुओलो को बढ़त पर ला खड़ा किया। हालांकि पहले हाफ के बाद रोनाल्डो को गोल करने का शानदार मौका मिला। जुवेंटस को पेनाल्टी मिली और पेनाल्टी पर किक लेने रोनाल्डो आए और उन्होंने 68वें मिनट में गोल करके जुवेंटस को बराबरी दिलाई। इसके बाद दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाई और यह मैच बराबरी पर खत्म हुआ।

इसके साथ ही रोनाल्डो का पिछले चार मैचों में खराब प्रदर्शन रहा था और वह उन चार मुकाबलों में कोई गोल नहीं कर पाए थे जिसके कारण टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस मुकाबले के दौरान रोनाल्डो की फ्री किक पर सासुओलो के 18 वर्षीय गोलकीपर स्टेफानो तुराती ने शानदार बचाव किया। अगर तुराती इसका बचाव नहीं कर पाते तो टीम को एक और खाना पड़ जाता। इसके साथ ही सासुओलो का जुवेंटस के खिलाफ पिछले सात मैचों से चला आ रहा हार का क्रम टूट गया। इससे पहले रोनाल्डो स्पेनिश क्लब रीयल मैड्रिड के लिए खेलते थे और उस क्लब में उनका गोल करने का जलवा रहता था।

तुरिन में इटली के सीरी–ए फुटबॉल लीग के दौरान रविवार को सासुओलो के खिलाफ गोल करने के बाद जुवेंटस के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रायटर

लेवरकुसेन ने बायर्न म्यूनिख को 2–1 से हराया

बर्लिन, एएफपी : जर्मन फुटबॉल लीग बुंडिशलीगा में लियोन बेली के दो गोल की मदद से 10 खिलाड़ियों से खेल रही बायर लेवरकुसेन की टीम ने बायर्न म्यूनिख को 2–1 से हरा दिया। बायर्न के अंतरिम मैनेजर के तौर पर हेंसी फ्लिक को पिछले पांच मुकाबलों में पहली बार शिकस्त झेलनी पड़ी। इस मुकाबले में लेवरकुसेन के जमैकन स्ट्राइकर बेली (10वें और 35वें मिनट) ने पहले हाफ में दो गोल करते हुए बायर्न पर अपना शिकंजा कसा। यही वजह थी कि थॉमस मूलर (34वें मिनट) का गोल भी बायर्न को हार से नहीं बचा पाया। इस मुकाबले में लेवरकुसेन के जोनाथन टाह को 81वें मिनट में रेड कार्ड दिखाया गया। वहीं बायर्न के गोल मशीन रोबर्ट लेवांदोवोस्की कोई गोल नहीं कर पाए। उधर एक अन्य मुकाबले में शनिवार को आरबी लेप्जिग ने पैडेरबॉर्न को 3–2 से हराया।

ग्रुप ऑफ डेथ में जगह मिलने पर भी उत्साहित हैं जोकिम

लीड्स, एएनआइ : यूरो 2020 के लिए शनिवार को घोषित किए गए ड्रॉ में जर्मनी को ग्रुप–एफ में मौजूदा विश्व चैंपियन फ्रांस और पुर्तगाल के साथ जगह मिली है जिसे ग्रुप ऑफ डेथ माना जा रहा है।

हालांकि जर्मनी के कोच जोकिम लो ग्रुप ऑफ डेथ में अपनी टीम को जगह मिलने पर भी उत्साहित हैं। उन्होंने फ्रांस और पुर्तगाल के खिलाफ होने वाली अपनी टीम की भिड़ंत को इस टूर्नामेंट का आकर्षण बताया है। लो ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है क्योंकि हमें फ्रांस और पुर्तगाल के खिलाफ आकर्षक मुकाबले खेलने को मिलेंगे। हमें विश्व चैंपियन और यूरोपियन चैंपियन के खिलाफ खेलना है। यूरो 2020 का आयोजन अगले साल 12 जून से 12 जुलाई तक किया जाएगा।

बैलन डि ओर के लिए मेसी और रेपिनो प्रबल दावेदार

पेरिस, एएफपी : प्रतिष्ठित बैलन डि ओर 2019 पुरस्कार के लिए पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के दिग्गज स्ट्राइकर लियोन मेसी और महिला वर्ग में अमेरिका की विश्व कप विजेता टीम की सुपरस्टार मेगान रेपिनो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। पेरिस में सोमवार को होने वाले इस समारोह में फुटबॉल जगत की नामी हस्तियां शिरकत करेंगी। पांच बार के विजेता मेसी बैलन डि ओर पुरस्कार को पाने की दौड़ में सबसे आगे हैं, जिन्हें लिवरपूल के विर्गिल वान डिज्क और जुवेंटस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर तरजीह मिलने की पूरी संभावना है। फ्रांस फुटबॉल मैग्जीन द्वारा दिए जाने वाले बैलन डि ओर पुरस्कारों के लिए पिछले महीने 30 खिलाड़ियों को नामित किया गया था जिनमें से दुनिया के 180 पत्रकारों के वोट के आधार पर सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाएगा। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के स्टार खिलाड़ी मेसी ने पिछले ला लीगा सत्र में 36 गोल किए थे और अपनी टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। मेसी छठी बार इस पुरस्कार को हासिल करने की दौड़ में सबसे आगे हैं। हाल ही में स्पेनिश मीडिया में खबर आई थी कि मेसी का बैलन डि ओर जीतना तय हो गया है और इसके बारे में उन्हें सूचित भी कर दिया गया है।

खिताब जीतने से चूके सौरभ वर्मा

खेल संवाददाता, लखनऊ

सैयद मोदी बैडमिंटन

- चैंपियनशिप के फाइनल में चीनी ताइपे के वांग जू वेई से हारे वर्मा
- ओलंपिक चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारिन ने महिला सिंगल्स की ट्रॉफी जीती

सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मुख्य दौर से फाइनल तक का शानदार सफर तय करने वाले भारतीय शटलर सौरभ वर्मा पुरुष सिंगल्स में खिताब जीतने से चूक गए। सौरभ को फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे के वांग जू वेई ने सीधे गेमों में 21-15, 21-17 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस तरह से भारतीय खिलाड़ी का यहां पहली बार खिताबी जीत का सपना पूरा नहीं हो सका।

दूसरी ओर, महिला सिंगल्स में ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन भी यहां पहली बार विजेता बनीं। स्पेनिश स्टार ने थाइलैंड की फिटायापोर्न चाईवान को 40 मिनट तक चले मुकाबले में आसानी से 21-12, 21-16 से हराया। मिक्स्ड डबल्स का खिताब रूस की रोडियान व एलिना की जोड़ी ने और महिला डबल्स में कोरिया की चांग हे ना व किम हेई की जोड़ी चैंपियन बनी।

विश्व रैंकिंग में 36वें नंबर पर काबिज भारतीय खिलाड़ी सौरभ फाइनल में आठवें वरीय चीनी ताइपे के वांग जू वेई को बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सके। 48 मिनट तक चले मुकाबले के दौरान भारतीय खिलाड़ी सिर्फ एक बार लड़ते दिखे। पहले गेम में तो सौरभ वांग के आक्रामकता के सामने खुद को संभालते नजर आए। भारतीय शटलर ने जिस अंदाज में क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में जीत दर्ज की थी, खिताबी मुकाबले में वैसा प्रदर्शन उनकी तरफ से नजर नहीं आया।

दूसरी ओर, ताइपे के स्टार शटलर और 22वीं रैंकिंग के वांग जू ने बेहद आक्रामक अंदाज में शुरुआत की और पहले गेम के बाद दूसरे गेम को भी जीतने में उन्हें कोई खास परेशान नहीं हुई। सौरभ का जू वेई के खिलाफ इससे पहले 1-1 (जीत-हार) का करियर रिकॉर्ड था। वहीं, ओलंपिक चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारिन खिताबी मैच में अलग अंदाज में खेलती नजर आईं। उन्होंने पहले गेम में धैर्य का परिचय देते हुए धीमी शुरुआत की, लेकिन एक बार लय पकड़ने के बाद मारिन ने फिटायापोर्न चाइवान को टिकने का मौका नहीं दिया। पहले गेम में एक समय चार अंकों से पिछड़ने वाली स्पेनिश स्टार ने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए 21-12 से जीत दर्ज कर थाइलैंड की खिलाड़ी को चौंका दिया।

दूसरे गेम में शुरुआत में मारिन फिटायापोर्न चाइवान से पांच अंकों से पीछे चल रहीं थी। ऐसे में लग रहा था कि यह मैच तीन गेमों तक जाएगा। हालांकि इसके बाद ओलंपिक चैंपियन ने अपने जोरदार स्मैश से लगातार छह अंक जुटाए और फिटायापोर्न पर एक बढ़त हासिल करने के बाद दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरे गेम में कैरोलिना ने शानदार 21-16 से जीत दर्ज की। इससे पहले ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू और साइना नेहवाल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था।

विष्णु और मुजामिल ने जीते खिताब

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : चेन्नई के विष्णु प्रसाद और बेंगलुरु के सैयद मुजामिल अली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को यहां जेके टायर फेस्टिवल ऑफ स्पीड में अपने-अपने वर्ग के खिताब जीते।

बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में जुटे 35 हजार से अधिक दर्शकों की मौजूदगी में एमस्पोर्ट के विष्णु और उनके साथी रघुल रंगास्वामी ने जेके टायर एफएमएससीआइ राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप में फॉर्मूला एलजीबी-4 वर्ग में पहले दो स्थान अपने नाम किए विष्णु और रघुल अंतिम दिन 73 अंकों के साथ ट्रैक पर उतरे। विष्णु ने नाटकीय अंदाज में जीत हासिल की जबकि रघुल ने तीसरे स्थान के साथ चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। सुजुकी जिक्सर कप में सैयद मुजामिल अली पहले और तनय गायकवाड दूसरे स्थान पर रहे।

इस बीच, एक्स1 लीग बेंगलोर रेसिंग स्टार्स की टीम ने पहले दौर में जीत हासिल की। इस टीम में अर्जुन मेनेनी, ओलीवर वेब, विष्णु प्रसाद और मिशेल गैटिंग शामिल थे। इस टीम ने पहले दिन दोनों रेस जीती थी।

पंजाब के पहलवान गुरप्रीत और हरप्रीत ने जीते स्वर्ण

जागरण संवाददाता, जालंधर

राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप

पंजाब के पहलवान गुरप्रीत सिंह और हरप्रीत ने रविवार को यहां पीएपी के इंडोर स्टेडियम में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के अंतिम दिन ग्रीको रोमन मुकाबलों में स्वर्ण पदक हासिल किए।

अंतरराष्ट्रीय पहलवान गुरप्रीत सिंह ने 77 किग्रा में रेलवे के साजन को 3-1 से मात दी। इस भार वर्ग में हरियाणा के अमित व झारखंड के मनजीत ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता। 82 किग्रा में हरप्रीत ने कड़े मुकाबले में रेलवे के राजबीर ने 4-1 से पटखनी दी। इसी वर्ग में बिहार के अविनाश व एसएससीबी के प्रमोद ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही पांच स्वर्ण पदक के साथ ग्रीको रोमन मुकाबले में रेलवे पहले, तीन स्वर्ण के साथ एसएससीबी (सर्विसेस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड) दूसरे और दो स्वर्ण के साथ पंजाब तीसरे स्थान पर रहा। ग्रीको रोमन के 55 किग्रा में एसएससीबी के अर्जुन और अजय ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीता जबकि महाराष्ट्र के अभिजीत व झारखंड के मनजीत ने संयुक्त रूप से कांस्य हासिल किया। 60 किग्रा में रेलवे के मनीष ने स्वर्ण, एसएससीबी के ज्ञानदोष ने रजत, झारखंड के विजय व दिल्ली के परवेश ने संयुक्त रूप से कांस्य जीता। 63 किग्रा में रेलवे के विक्रम ने स्वर्ण, रेलवे के ही दीपक ने रजत, चंडीगढ़ के सचिन शर्मा व एसएससीबी के एम. तिआगबंगनशा ने संयुक्त रूप से कांस्य पर कब्जा जमाया। 67 किग्रा में एसएससीबी के रविंदर ने स्वर्ण, एसएससीबी के सचिन ने रजत, झारखंड के सौरभ व एसएससीबी के सूरजमल ने कांस्य जीता। 72 किग्रा में रेलवे के अमित ने स्वर्ण, हरियाणा के सुनील ने रजत, एमपी के आकाश व रेलवे के कुलदीप मलिक ने संयुक्त रूप से कांस्य जीतने में सफल रहे।

विविध

ऑटो व टेक्नो सेक्टर की कंपनियों को जागरण हाईटेक अवार्ड

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- जागरण न्यू मीडिया के सीईओ भरत गुप्ता ने प्रदान किए अवार्ड

टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कंपनियों को शुक्रवार को जागरण न्यू मीडिया की ओर से जागरण हाईटेक अवार्ड- 2019 दिया गया।

यहां होटल ओबेरॉय में आयोजित कार्यक्रम में जागरण न्यू मीडिया के सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) भरत गुप्ता ने विजेता कंपनियों के अधिकारियों को अवार्ड दिए। सभी कैटेगरी के विजेताओं को यूजर्स और जूरी मेंबर्स ने वोटिंग के जरिये चयनित किया है। इस मौके पर भरत गुप्ता ने कहा कि अपने यूजर्स की बेहतर लाइफस्टाइल के लिए जागरण टीवी स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत तमाम जानकारीपरक वीडियो उपलब्ध कराता है। ऑडी ए-6 को लग्जरी कार, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड को गैजेट, होंडा सीबी 300आर को बाइक, वनप्लस 7टी प्रो को स्मार्टफोन और हुंडई वेन्यू को कार, रीयलमी के सीईओ माधव सेठ को टेक पर्सनैलिटी ऑफ दी ईयर अवार्ड दिया गया।

वहीं, रीयलमी एक्सटी को कैमरा फोन और मोस्ट प्रॉमिसिंग स्मार्टफोन ब्रांड, वनप्लस-7 सीरीज को परफॉर्मेंस फोन और स्मार्टफोन गेम चेंजर अवॉर्ड मिला। नोकिया 7.2 को वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन, ओप्पो रेनो-2 को डिजाइन फोन, वीवो वी-15 प्रो को मिड बजट स्मार्टफोन, आसुस आरओजी फोन-2 को गेमिंग स्मार्टफोन ऑफ दी ईयर अवार्ड मिला। एमजी हेक्टर को कनेक्टेड कार, बीएमडब्ल्यू थ्री-सीरीज को सेडान, जीप कंपास ट्रेलहॉक को एसयूवी, हीरो एक्सपल्स को बाइक, मारुति सुजुकी अर्टिगा को एमपीवी व एसप्रेसो को हैचबैक, होंडा एक्टिवा बीएस-6 को स्कूटर, फोक्सवैगन इंडिया को ऑटो मैन्युफैक्चरर, ओप्पो को टेक मैन्युफैक्चरर और हुंडई के पुनीत आनंद को ऑटो पर्सनैलिटी ऑफ दी ईयर अवार्ड दिया गया। अवार्ड के प्रायोजक दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और मीडियाग्राफिक्स रहे।

नई दिल्ली के ओबेराय होटल में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में जागरण हाईटेक अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। इस मौके पर जागरण न्यू मीडिया के सीईओ भरत गुप्ता (मैरून रंग के कोट में) और ऑटोमोबाइल व टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियों के अधिकारी। जागरण

एडिटर्स च्वॉइस अवॉर्ड

ऑनर इंडिया के प्रेसिडेंट चार्ल्स पेंग को एमर्जिंग टेक पर्सनैलिटी, मैप माई इंडिया को कनेक्टेड मोबिलिटी सोल्यूशन, टाइमेक्स आईकनेक्ट को लाइफस्टाइल स्मार्टवॉच, किया सेल्टॉस को कार, दुकाती दियावेल–1260 को बाइक ऑफ दी ईयर अवार्ड दिया गया। अधिक जानकारी के लिए के लिए https://event.jagran.com/events/hitech-awards/mobile.html पर लॉगिन करें।

कमांडो– 3 के जरिये अखाड़ों की छवि खराब करने का प्रयास : बजरंग

अनिल भारद्वाज, गुरुग्राम : दो दिन पहले रिलीज हुई फिल्म कमांडो- 3 में अखाड़े व पहलवानों को गलत तरीके से दिखाए जाने पर अंतरराष्ट्रीय पहलवान बजरंग पूनिया ने अपना विरोध दर्ज कराया है। पहलवान ने अपने फेसबुक व ट्विटर अकाउंट पर विरोध जताया है। बजरंग ने कहा कि अखाड़े को तैयार करते समय उस मिट्टी में सरसों का तेल, हल्दी, मेहंदी अन्य सामग्री डालकर श्रद्धा से तैयार किया जाता है और अखाड़ा एक पहलवान के लिए मंदिर होता है, जिसकी वह हर रोज पूजा करता है।

बजरंग पूनिया फाइल

अखाड़े का हर पहलवान हनुमान भक्त होता है। कभी किसी एक व्यक्ति के गलत कार्य करने से सभी अखाड़े और पहलवान खराब नहीं कहे जा सकते हैं। अखाड़ों को बदमाशी का केंद्र बताकर फिल्म निर्देशक आदित्य दत्त अखाड़ों, पहलवानों और उनके गुरुओं को बदनाम कर रहे हैं। पहलवान बजरंग ने कहा कि इस प्रकार की फिल्म पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए और साथ ही इस प्रकार की कहानी लिखने वाले लेखक और फिल्म निर्माता -निर्देशक पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिल्म बनाने वालों से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या सोचकर पवित्र अखाड़े को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। यदि इस प्रकार की फिल्म चलती रही, तो भविष्य में नए युवा अखाड़ों से दूरी बना लेंगे।

'बेटी बचाओ' के संकल्प के साथ परिणय सूत्र में बंधे बबीता–विवेक

चरखी दादरी के गांव बलाली में विवेक सुहाग और बबीता फोगाट फेरे लेने से पहले एक साथ। जागरण

सोनू जांगड़ा, चरखी दादरी

अंतरराष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट रविवार को अपने पैतृक गांव बलाली में पहलवान विवेक सुहाग के साथ परिणय सूत्र में बंध गईं। नवदंपती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ आठवां फेरा लिया। उन्होंने एक-एक पौधा लगाकर पर्यावरण को बचाने का आह्वान किया।

बबीता और विवेक की शादी बहुत ही सादे तरीके से हुई। विवेक बगैर गाजे-बाजे के 21 बरातियों के साथ शादी करने पहुंचे थे। बलाली स्थित घर में वर-वधू ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। बड़ी बहन ओलंपियन पहलवान गीता की तरह बबीता ने भी शादी में सात के बजाए आठ फेरे लिये। शादी समारोह में पहलवान बजरंग पूनिया, विदेशी कोच जर्जिया के साको बैनजीनियस सहित कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हुए।

देसी खाने का था मेन्यू : शादी में पहलवानों के लिए फोगाट परिवार ने देसी खाने का मेन्यू तैयार करवाया गया। मेन्यू में सिंपल रोटी, केसर की खीर तैयार की गई थी। इसके अलावा मिस्सी रोटी, मक्खन, लस्सी, गाजर का हलवा,, जूस, रायता, सलाद और गुड़ शामिल था।

फिजूलखर्ची से बचने की दी सीख : बबीता के पिता द्रोणाचार्य अवार्डी महाबीर फोगाट ने बताया कि शादी का आयोजन सादगी और फिजूलखर्ची न हो इसका ध्यान रखते हुए किया गया है। विवेक सुहाग ने भी इसका समर्थन किया। बताया कि शादी में उनके निजी रिश्तेदार व परिवार के 21 बराती आए हैं। दहेज का तो सवाल ही नहीं उठता।

महिलाओं को अश्लील फोटो व वीडियो भेजने वाला फर्जी आइपीएस गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : खुद को आइपीएस अफसर बताकर महिलाओं को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर दोस्ती करने वाले आरोपित को दक्षिणी जिले के कोटला मुबारकपुर थाना पुलिस ने रविवार को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से दो मोबाइल, चार सिम कार्ड और फर्जी आइडी पुलिस ने बरामद की है। डीसीपी दक्षिणी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि आरोपित गौरी शंकर, नाड़वा बिसनपुर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, गत 25 नवंबर को कोटला मुबारकपुर थाने में एक महिला ने शिकायत में बताया कि एक युवक खुद को आइपीएस बताकर उनके मोबाइल पर बीते एक माह से अश्लील मैसेज, फोटो और वीडियो भेज रहा है।

सड़क हादसे में स्कूटी सवार दो नाबालिग सहित तीन की मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

रिसेप्शन पार्टी से लौट रहे युवक की स्कूटी खूनी दरवाजे के पास बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में स्कूटी चला रहा युवक व पीछे बैठे दो नाबालिगों की मौत हो गई। दोनों नाबालिग चचेरे भाई हैं। आइपी स्टेट थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

तुर्कमान गेट डीडीए फ्लैट निवासी मोहम्मद ओसामा (20) शनिवार को अपने रिश्तेदार मोहम्मद हमजा (15) और मोहम्मद साद (16) के साथ इलाके में ही एक रिसेप्शन पार्टी में गए थे। रात करीब सवा ग्यारह बजे तीनों स्कूटी से घूमने निकल गए। पुलिस के मुताबिक स्कूटी मोहम्मद हमजा चला रहा था। तीनों जब बहादुरशाह जफर मार्ग पर मौलाना आजाद मेडिकल कालेज से दिल्ली गेट की ओर जा रहे थे। उसी समय स्कूटी की गति अधिक होने की वजह से चालक नियंत्रण नहीं रख सका और स्कूटी खूनी गेट के पास बिजली के खंभे से टकरा गई। हेलमेट नहीं लगाए होने की वजह से तीनों के सिर पर गंभीर चोटें आईं। घटना के वक्त सड़क से गुजर रहे एक राहगीर ने रात करीब 11.34 बजे हादसे की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) को दी। चार मिनट बाद मौके पर पीसीआर टीम मौके पर पहुंची। इसी बीच घायलों को स्थानीय लोग लोक नायक अस्पताल ले जा चुके थे। दुर्घटना में स्कूटी का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। स्कूटी चला रहे मो. हमजा के सिर में गंभीर जबकि अन्य के सिर में भीतरी चोटें आई है। स्कूटी मो. हमजा के मामा मोहम्मद आदिल की है।

परिजन बोले, पुलिस के पीछा करने से हुआ हादसा, सुबह तक किया प्रदर्शन : घटना की जानकारी जब स्कूटी सवार युवकों के परिजनों को मिली तो वे अवाक रह गए। तुर्कमान गेट में उत्साह का माहौल मातम में बदल गया। रात में ही परिजन के साथ करीब 800 स्थानीय लोग दिल्ली गेट पर पहुंच गए। यहां रात करीब 1.30 बजे उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। उनका कहना था कि पुलिस ने जिप्सी से स्कूटी का पीछा किया, इसकी वजह से हादसा हुआ। इस दौरान लोगों ने जमकर बवाल काटा। हंगामा बढ़ता देख जिले की पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल को तैनात कर दिया गया। इधर प्रदर्शनकारियों आरोप है कि पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए उन्हें घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज पुलिस नहीं दिखा रही है। बाद में मध्य जिला के डीसीपी मंदीप सिंह रंधावा व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कमान संभाली। उनके द्वारा लोगों को समझाने बुझाने पर रविवार की सुबह करीब 8 बजे प्रदर्शनकारी दिल्ली गेट से हटे। इधर पुलिस का कहना है कि किसी के गलत अफवाह फैलाने की वजह से परिजन में गुस्सा था। पुलिस ने स्कूटी का पीछा किए जाने से साफ इन्कार किया है।

फोरेंसिक टीम ने नमूने किए एकत्र : घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस का दावा है कि सीसीवीटी फुटेज में कोई भी वाहन स्कूटी का पीछा करता हुआ नहीं दिख रहा है। बावजूद इसके आइपी स्टेट थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। स्थानीय के अलावा रोहिणी की फोरेंसिक टीम ने नमुने एकत्र किए हैं। पुलिस को घटना स्थल से बीयर की बोतल के टुकड़े भी मिले हैं। उधर तीसरे पहर पोस्मार्टम करा तीनों के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मध्य जिला के डीसीपी मंदीप सिंह रंधावा ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है।

मौसम विशेष

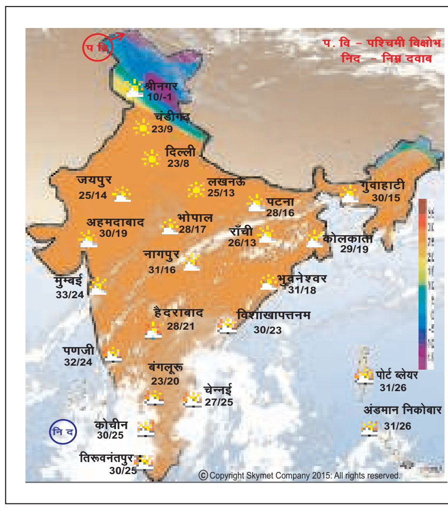

राजस्थान, हरियाणा व पंजाब में शीतल सुबह में कुछ स्थानों पर कोहरा व कुहासा छाया रहेगा। दिल्ली में शुष्क मौसम के साथ प्रदूषण स्तर सामान्य बना रहेगा। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क व ठंडा बना रहेगा। कश्मीर घाटी में सुबह में कंपकंपाती ठंड रहेगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/24/सा	अहमदाबाद	30/20/आंबा
कोलकाता	29/19/सा	बड़ौदा	31/22/सा
चेन्नई	29/24/आंबा	नागपुर	31/16/आंबा
हैदराबाद	28/22/आंबा	इन्दौर	27/14/आंबा
बंगलूरू	24/19/आंबा	रांची	26/14/आंबा
त्रिवेन्द्रम	30/25/आंबा	पटना	29/17/आंबा
गुवाहाटी	25/15/सा	जमशेदपुर	28/15/आंबा
गंगटोक	10/-3/आंबा	पुणे	27/18/सा

दैनिक जागरण

राष्ट्रीय संस्करण

सोमवार 2 दिसंबर 2019

आजकल

16

www.jagran.com

पहली बार हुआ था स्थायी कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण

1982 में आज ही के दिन पहली बार 61 साल के रिटायर्ड दंत चिकित्सक बार्ने क्लॉर्क्स को स्थायी रूप से कृत्रिम हृदय लगाया गया। कॉर्डियोथोरेसिस सर्जन डॉ. विलियम डेव्रिज ने खराब हो चुके हृदय को हटाया। फिर स्थायी कृत्रिम हृदय जर्विक-7 का प्रत्यारोपण किया। बार्ने क्लॉर्क्स 112 दिनों तक जीवित रहे।

भारतीय बीमा में मिली निजी क्षेत्र को मंजूरी

1999 में आज ही बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को मंजूरी मिली थी। 1993 में भारत सरकार ने इसके निजीकरण के लिए आरएन मल्होत्रा समिति बनाई गई थी। समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद कैबिनेट ने निजी और एफडीआइ 49 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

डॉ. अचला नागर ने लिखी बागबान की पटकथा

फिल्मों में कहानी, पटकथा व संवाद लेखिका डॉ. अचला नागर का जन्म 1939 में आज ही लखनऊ में हुआ था। वह साहित्यकार अमृतलाल नागर की पुत्री हैं। बागबान की पटकथा नागर ने ही लिखी थी। नगीना, निकाह, निगाहें भी उनकी चर्चित फिल्में हैं। फिल्म निकाह के लिए 1983 में सर्वश्रेष्ठ संवाद का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उन्हें साहित्य भूषण, हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी सम्मान, यशपाल अनुशंसा सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान आदि से नवाजा जा चुका है।

सड़क हादसों को रोकने के लिए मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला ऑस्ट्रेलिया बना पहला देश

आधुनिक समाज में मोबाइल फोन रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा है। मोबाइल न हो तो बेचैनी होने लगती है, लेकिन मोबाइल के प्रति यह अनुराग कभी कभी जानलेवा भी साबित हो रहा है। बहुत से लोग वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में यदि आप मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे। रविवार को यहां पर मोबाइल फोन का पता लगाने वाला कैमरा लगाया गया है। ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है। दावा किया जा रहा है कि इससे सड़क हादसों में एक तिहाई की कमी लायी जा सकेगी।

हर मौसम में करेगा काम

यह हर मौसम में दिन रात काम करने में सक्षम है। न्यू साउथ वेल्स के सहायक पुलिस आयुक्त मिशेल कोर्बोय का कहना है कि यह वह प्रणाली है जो संस्कृति को बदल देगी। इसी साल जनवरी और जून में कैमरों का परीक्षण किया गया था।

तीन महीने बाद लगेगा भारी जुर्माना

यह प्रणाली शुरू करने के बाद मोबाइल का प्रयोग करने वाले लोगों को पहले तीन महीने तक चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद 180 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब आठ हजार सात सौ रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि स्कूल क्षेत्र में ऐसा मामला सामने आया तो 240 डॉलर का जुर्माना देना होगा।

क्यों उठाना पड़ा यह कदम

न्यू साउथ वेल्स में इस साल अब तक 329 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल भर में 354 लोगों की मौत हुई थी। प्रशासन की कोशिश इन आंकड़ों को कम करना है। उन्होंने 2021 में सड़क हादसों में होने वाली मौतों को 30 फीसद कम करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का अनुमान है कि 2012 से 2018 तक न्यू साउथ वेल्स में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के चलते 158 लोगों की मौत हुई है।

ऐसे काम करेगा कैमरा

न्यू साउथ वेल्स ट्रांसपोर्ट के मुताबिक यह दुनिया का पहला कैमरा है, जो पता लगा सकता है कि वाहन चलाते वक्त चालक मोबाइल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। यह मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर आधारित है। यह तस्वीरों का परीक्षण करता है और मोबाइल के गलत इस्तेमाल का पता लगाता है। स्थानीय कानून के मुताबिक वाहन चलाते हुए मोबाइल फोन कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए हैंड्स फ्री उपकरण इस्तेमाल करना होगा। वीडियो कॉलिंग, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और फोटो खींचना गैर कानूनी है।

सड़क हादसों में हताहत मामले में भारत शीर्ष पर

भारत में हर साल होने वाले सड़क हादसों में लाखों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। इस मामले में हमारा देश दुनिया में सबसे आगे है। कुछ समय पूर्व कड़े नियम कानूनों को लागू किए जाने के बाद इसमें कमी की उम्मीद की जा रही है।

4.34 लाख करोड़ रुपये सालाना सड़क हादसों से आर्थिक चपत

29 बच्चों की रोजाना भारत में सड़क हादसों में मौत हो जाती है

50 फीसद सड़क हादसों में होने वाली मौतें कम की जा सकती हैं तेजी से मदद पहुंचाकर

17 लोग हर घंटे भारत में सड़कों पर जान गंवा देते हैं

13 लाख लोगों की पिछले एक दशक के दौरान सड़क हादसों में हुई है मौत

50 लाख लोग पिछले एक दशक में सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल हुए

इधर-उधर की

महिला के पेट से निकला उसके ही बालों का गुच्छा

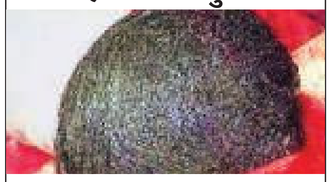

न्यूयॉर्क, एजेंसी : अमेरिका के एक अस्पताल में डॉक्टर उस समय दंग रह गए जब एक महिला के पेट से बालों का बड़ा सा गुच्छा निकला। इस गुच्छे का व्यास करीब 15 सेमी था। दरअसल 38 वर्षीय महिला पेटदर्द और सूजन के कारण परेशान थी, जिसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उसके पेट में मौजूद बाल का गुच्छा निकाला। दरअसल यह महिला दुर्लभ रापुनजेल सिंड्रोम से पीड़ित थी। यह इतना दुर्लभ मामला है कि मेडिकल साहित्य में अब तक सिर्फ 88 बार इसका उल्लेख मिलता है। बीएमजे जनरल के अनुसार, ट्राइकोटिलोमैनिया नामक अनियमितता के चलते यह सिंड्रोम विकसित होता है जिसमें पीड़ित अपने बाल नोंचने पर विवश हो जाता है। और अक्सर वह बालों को खा लेता है। यह महिला भी पिछले आठ माह से अपने बाल खा रही थी। जिससे उनका वजन लगातार कम होने लगा था। आंतों में बालों का बड़ा गुच्छा बनने से पाचन क्रिया गड़बड़ा चुकी थी। बहरहाल ऑपरेशन से महिला के पेट से बालों का गुच्छा निकाला जा चुका है। उन्हें मनोवैज्ञानिक थेरेपी की सलाह दी गई है।

जहरीले प्रदूषकों का पता लगा सकता है नया सेंसर

तकनीक ▶ चिकित्सा और फोरेंसिक विश्लेषण के क्षेत्र में लाएगा बदलाव

रूस की फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया यंत्र

▶ विस्फोटकों में इस्तेमाल होने वाले नाइट्रोएरोमेटिक के यौगिकों की आसानी से होगी पहचान

▶ ब्लैक सिलिकॉन की मदद से बनाया गया है उपकरण

यह अध्ययन एसीएस सेंसर्स नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। फाइल

मास्को, प्रेट्र : रूसी शोधकर्ताओं ने ब्लैक सिलिकॉन पर आधारित एक अति संवेदनशील डिटेक्टर विकसित किया है, जिससे चिकित्सा और फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए बेहद जहरीले प्रदूषकों का पता लगाया जा सकता है। एसीएस सेंसर्स नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में दावा किया गया है कि नया सेंसर ज्यादातर विस्फोटकों में इस्तेमाल होने वाले नाइट्रोएरोमेटिक यौगिकों की पहचान करने में सक्षम है।

इस अध्ययन के शोधकर्ताओं में रूस की फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी (एफईएफयू) के शोधार्थी भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि इस सेंसर को ब्लैक सिलिकॉन से बनाया गया है जो अति सूक्ष्म, विशिष्ट प्रकाशीय गुणों को दर्शाने वाली नैनो स्केल नुकीली सतह से लैस है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह सतह एक स्तर वाले जटिल प्रकाशीय कणों से ढकी होती है जिसे कार्बाजोल कहते हैं। कार्बाजोल का यही स्तर डिटेक्टर को बड़ी मात्रा में फैले नाइट्रोएरोमेटिक पदार्थों जैसे कि ट्राइनाइट्रोटॉल्युएंस (टीएनटी) विस्फोटक के प्रति संवेदनशील बनाता है।

हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि यह सेंसर बेंजेन, मिथेनॉल, इथेनॉल जैसे अन्य कणों की मौजूदगी में कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है।

एफईएफयू के शोधकर्ता और इस अध्ययन के सह लेखक एलेक्जेंडर कुचमिजाक ने कहा, 'नाइट्रोएरोमेटिक के यौगिक पेंट संयंत्रों और सैन्य साजो-सामान के अपशिष्ट जल में मिल सकते हैं और ये हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। अधिकांशतः इनका इस्तेमाल विस्फोटकों में किया जाता है। इन्हें पहचानना एक जटिल प्रक्रिया वाला काम है।'

अध्ययन में बताया गया है कि सेंसर कार्बाजोल की परत के प्रकाश में प्रतिक्रिया करने के तरीके में बदलाव को दर्ज करके नाइट्रोएरोमैटिक यौगिकों की उपस्थिति की पहचान करता है।

एफईएफयू के शोधकर्ता और इस अध्ययन के सह-लेखक अलेक्जेंडर मिरानेंको ने बताया, 'ब्लैक सिलिकॉन के रूपात्मक और ऑप्टिकल गुणों के संयोजन को कार्बाजोल अणुओं के साथ सिलिकॉन की सतह को क्रियाशील बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सतह के रसायनों के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। इससे अभूतपूर्व संवेदनशीलता प्राप्त होती है।'

उन्होंने कहा कि यह सेंसर प्रति ट्रिलियन सांद्रणता में नाइट्रोएरोमेटिक यौगिकों को पहचान सकता है। यानी एक खरब प्रदूषक किसी स्थान पर होंगे तो इस सेंसर की मदद से नाइट्रोएरोमेटिक यौगिकों की आसानी से पहचान हो सकती है। मिरानेंको ने कहा, नाइट्रोएरोमेटिक यौगिकों की पहचान ब्लैक सिलिकॉन के अद्वितीय आकार के कारण संभव होती है।

बिना दुष्प्रभाव के कीमोथेरेपी करने का तरीका ईजाद

यरुशलम, एएनआइ : कीमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए प्रभावी उपचार है, लेकिन इससे मरीज के शरीर पर पड़ने दुष्प्रभावों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती है। इलाज की यह प्रक्रिया इतनी दर्दनाक होती है कि कई मरीज इलाज बीच में छोड़ देते हैं। अब यरुशलम की हिब्रू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा तरीका विकसित किया है, जिसमें कीमोथेरेपी सीधे कैंसर प्रभावित कोशिकाओं पर प्रहार करेगी। इस खोज का मुख्य उद्देश्य रोगियों को दी जाने वाली कीमो की खुराक को कम करना है, जिससे उपचार के दौरान होने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सके।

यूनिवर्सिटी में प्लेन प्लास्टिसिटी रिसर्च ग्रुप के हेड अलेक्जेंडर बिंसटोक ने बताया कि कैंसर के इलाज के ज्यादातर तरीकों के दौरान कैंसर प्रभावित कोशिकाओं के साथ ही स्वस्थ कोशिकाओं पर भी असर पड़ता है। कीमोथेरेपी में भी इसी तरह के दुष्प्रभाव होते हैं। कीमो को केवल कैंसर कोशिकाओं पर केंद्रित करने और कीमो की मात्रा कम करने से ऐसे कई दुष्प्रभावों से बचना संभव हो सकता है।

कीमोथेरेपी एक प्रकार का उपचार है, जिसमें कैंसर का इलाज करने के लिए एक या एक से अधिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। कीमो का उद्देश्य कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा करना या रोकना होता है। कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के साथ-साथ कीमोथेरेपी मुंह के अंदर की कोशिकाओं को भी नष्ट कर सकती है। इससे मुंह लाल पड़ सकता है और संक्रमण होने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। शोधकर्ताओं ने कहा इस समस्या से बचने के लिए नया तरीका मददगार सिद्ध हो सकता है।

इस्लामाबाद म्यूजियम में रखी गई बुद्ध की दुर्लभ कलाकृति

▶ स्वात घाटी से खोजी गई थी तीसरी से चौथी सदी के दौरान निर्मित यह मूर्ति

इस्लामाबाद के म्यूजियम में प्रदर्शित भगवान बुद्ध के सिर की दुर्लभ कलाकृति। इसे इटली के पुरातत्वविद गिसेप तुसी ने खोजा था। रायटर

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के म्यूजियम में भगवान बुद्ध के सिर की एक दुर्लभ कलाकृति प्रदर्शन के लिए रखी गई है। स्वात घाटी क्षेत्र से खोदाई में मिली इस कलाकृति को मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना कहा जा रहा है। तीसरी से चौथी सदी के दौरान निर्मित इस कलाकृति को बीती सदी के छठे दशक में इटली के पुरातत्वविद गिसेप तुसी ने खोजा था।

इस्लामाबाद म्यूजियम के निदेशक अब्दुल गफूर लोन ने कहा, 'स्वात के चूना पत्थर से बनी भगवान बुद्ध की यह मूर्ति दुर्लभ है। इसमें बुद्ध के सौम्य चेहरे और जूड़े में बंधे बालों को दर्शाया गया है। प्राचीन काल में हमलावरों से बचाने के लिए ऐसी मूर्तियों को बौद्ध मठों के अंदर जमीन में गाड़ दिया जाता था।' उन्होंने कहा कि आमतौर पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां तक्षशिला और अफगानिस्तान में पाई जाती हैं।

स्वात से मिली इस कलाकृति में उनके बालों को सिर पीछे की ओर लपेटा गया है। झुकी हुई आंखें और सौम्य चेहरा इसे उनकी

स्पेक्ट्रम

अन्य मूर्तियों से विशिष्ट बनाता है। लोन ने कहा, 'आमतौर पर बुद्ध की प्रतिमाओं में उनके कानों में कुंडल देखे जाते हैं पर इस कलाकृति उनके कान सामान्य हैं। कुषाण काल से संबंधित यह असाधारण कलाकृति बौद्ध स्तूप से भी पुरानी है।'

प्रदर्शनी में इसके अलावा टेराकोटा से बनी बुद्ध की तीन अन्य कलाकृतियां भी प्रदर्शित की जा रही हैं। तीनों दुर्लभ कलाकृतियां दूसरी से तीसरी सदी हैं। उनकी खुदाई ब्रिटिश पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल ने की थी। इनमें शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में बुद्ध के सिर को तराशने पर विशेष ध्यान दिया गया है और महीन सामग्री का भी उपयोग किया गया है। लोन ने कहा, 'जब हूणों ने बौद्ध मठों और स्तूपों को जला शुरू कर दिया था तो लोगों ने इन्हें जमीन के नीचे दफनाकर संरक्षित करने का प्रयास किया था।

शोध अनुसंधान

खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है कॉफी का सेवन

हालिया शोध में सामने आया है कि कॉफी का सेवन पुरुष और महिलाओं दोनों में साइकिलिंग की गति बढ़ाने में सहायक हो सकता है। कॉफी का सेवन व्यायाम करने की क्षमता भी बढ़ा देता है। अध्ययन के दौरान पांच किलोमीटर की साइकिलिंग ट्रायल के दौरान कॉफी का असर जांचा गया था। अध्ययन में 38 प्रतिभागियों को शामिल किया गया था, जिनमें बराबर संख्या में पुरुष व महिलाएं थीं। इस दौरान कॉफी का सेवन करने वाले पुरुषों ने पांच किलोमीटर का ट्रायल नौ सेकेंड पहले और महिलाओं ने छह सेकेंड पहले पूरा कर लिया। वहीं प्लेसबो या अन्य कंट्रोल ग्रुप के मामले में ऐसी कोई तेजी नहीं दिखी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन नतीजों की मदद से शारीरिक क्षमता पर कॉफी के असर को समझने में मदद मिलेगी। अब तक ऐसे शोध मुख्यतः पुरुषों पर ही केंद्रित रहे हैं। - एएनआइ

यलो ड्रैगन डिजीज से फलदार पेड़ों को बचाने की कवायद

फलों को एचएलबी के संक्रमण से बचने के लिए फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी परिसर में ही साइट्रस के पेड़ों को लगाकर अध्ययन करना शुरू किया है। फलदार वृक्षों में होने वाली इस बीमारी को यलो ड्रैगन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले चीन में यह बीमारी सामने आई थी। इससे संक्रमित पेड़ों की पत्तियां और फल समय से पहले ही पीले पड़ कर गिर जाते हैं। फ्लोरिडा में यह बीमारी सबसे पहले वर्ष 2005 में देखने को मिली थी, जिसके बाद से ही शोधकर्ताओं ने फलदार पेड़ों को इसके संक्रमण से बचाने की कवायद शुरू कर दी थी। एएफपी

घोड़ों की मौत के विरोध में निकाला मार्च

हॉर्स रेस के दौरान घोड़ों की मौत होने से क्षुब्ध पशु प्रेमियों के एक समूह ने कैलिफोर्निया के पासाडोना में स्थित सांता एनीता रेस पार्क में मार्च निकाला और हॉर्स रेस बंद करने की मांग की। इस वर्ष यहां रेस में 37 घोड़ों की मौत हो चुकी है। यह अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध हॉर्स रेस पार्क में से एक है। इसके अलावा देश के अन्य रेस पार्कों में भी मार्च निकाला गया। देश में हॉर्स रेस के औचित्य को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। एएफपी

स्क्रीन शॉट

वेब पर सेंसरशिप का ध्यान खुद रखना चाहिए : रिचा चड्ढा

सात सवाल

लगातार फिल्मों के साथ वेब सीरीज का हिस्सा बनीं रिचा चड्ढा अब 'इनसाइड एज 2' में एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया के दांवपेचों से रूबरू होती दिखेंगी। यह शो 6 दिसंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रसारित होगा। अपने शो, फिल्मों और निजी जिंदगी पर उन्होंने हमसे बात की...

● पहले सीजन के मुकाबले दूसरे सीजन में आपका किरदार कितना बदलेगा?

पहला सीजन देख चुके दर्शकों को मेरे किरदार जरीना में बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। अब जरीना आगे बढ़ना चाहती है। वह नहीं चाहती कि उसे किसी भी बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। इस बार क्रिकेट के लिए ज्यादा जगह रखी गई है। इतने सारे पुरुष किरदारों के बीच सारा नियंत्रण मेरे किरदार के हाथों में है।

● आपके मुताबिक डिजिटल पर सेंसरशिप कितनी जरूरी है?

मुझे लगता है कि एक हद में रहकर कंटेंट बनाना चाहिए। ऐसा कंटेंट नहीं बनना चाहिए, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपशब्द कहे गए हों, बेमतलब की मारधाड़ हो या बोल्ड दृश्य हो। हर माध्यम पर सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। शो बनाने वाले लोगों को खुद ही सेंसरशिप का ध्यान रखना चाहिए।

● अपने किरदार के लुक्स को लेकर आप बहुत ध्यान रखती हैं...।

किरदार के लिए वजन बढ़ाने-घटाने, बाल बड़े-छोटे करने से मुझे दिक्कत नहीं है। खासकर बायोपिक में तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 'शकीला' फिल्म के लिए मैंने अपना वजन बढ़ाया था। इस वक्त मैं जिस फिल्म पर काम कर रही हूं उसके लिए मैं लुक्स पर भी काम कर रही हूं।

● 'शकीला' फिल्म कब तक रिलीज होने की संभावना है?

फिल्म की शूटिंग और डबिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म को किस-किस भाषा में रिलीज किया जाना है, इसको लेकर बात चल रही है। 'शकीला' पूरी तरह से हिंदी फिल्म है। लेकिन यह फिल्म साउथ में भी चलेगी।

● 'इनसाइड एज 2' के बाद 'मिर्जापुर 2' का प्रसारण शुरू होगा। अली फजल की वजह से यह शो भी आपके लिए खास होगा?

मैं उत्सुक हूं इस बार यह देखने के लिए कि अली 'मिर्जापुर 2' में क्या नया करेंगे। मैं उनके साथ लंदन में छुट्टियां बिताकर आई हूं। जिस दिन लंदन से लौटी, उसी दिन शाम की अगली फ्लाइट लेकर दूसरे शहर फिल्म की शूटिंग करने पहुंच गई।

● आपने हॉलीवुड में काम करने के बारे में नहीं सोचा?

हॉलीवुड में काम मुश्किल से मिलता है। मुझे हॉलीवुड में काम करने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। वहां जाकर धक्के खाने पड़ेंगे, तब जाकर कुछ हो पाएगा।

● अली की फिल्म 'डेथ ऑन द नाइल' का सेट आपने देखा होगा?

हां, मैं उनके सेट पर गई थी। एक प्रमोशनल शूट चल रहा था। वहां काम का कल्चर बहुत अलग है। बहुत कम वक्त में अली के कई दोस्त बन गए हैं। उनसे मिलकर अच्छा लगा। वहां उन्हें बहुत अच्छा अभिनेता माना जाता है।

प्रियंका सिंह

अध्ययन

हड्डियां तंदुरुस्त रखनी है तो जमकर सेंकिए धूप

सर्दियों में लोगों के शरीर में विटामिन-डी की हो जाती है कमी, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया के खतरे से बचा सकती है थोड़ी सी सतर्कता

नई दिल्ली, आइएएनएस : स्वस्थ जीवन के लिए हड्डियों को मजबूत बनाए रखना बेहद जरूरी है। दिल्ली जैसे महानगरों में सर्दी के मौसम में प्रदूषण के कारण लोगों तक सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पातीं। ऐसे में लोगों को प्राकृतिक विटामिन-डी भी बहुत कम मिल पाता है और उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इस संबंध में फोर्टिस राजन ढल हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के ऑर्थोस्कॉपी एंड स्पॉर्ट्स इंजरी के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. विश्वदीप शर्मा ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि सर्दियों में यदि हम सही समय पर धूप सेंकते हैं तो इससे कई बीमारियों से बच सकते हैं।

दिन में धूप सेंकने के उचित समय और विटामिन-डी के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने को लेकर कई शोध हो चुके हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि शरीर का 20 प्रतिशत हिस्सा यानी बिना ढके हुए हाथ-पैर आदि से प्रतिदिन 15 मिनट धूप का सेवन करने से विटामिन-डी अच्छी मात्रा में लिया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि दिन का कौन-सा प्रहर सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने का सबसे उपयुक्त होता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह और शाम की धूप सेंकना शरीर के लिए सबसे उपयुक्त होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सुबह 10 से दोपहर तीन बजे के बीच के दौरान धूप का सेवन मानव शरीर की त्वचा को विटामिन-डी प्रदान करता है। बशर्ते धूप सेंकने के दौरान त्वचा पर क्रीम या लोशन नहीं लगा हो। राजधानी दिल्ली जैसे शहर, जहां प्रदूषण के कारण धूप नहीं आ पाती, वहां लोग दूध के उत्पादों के जरिये विटामिन डी की कमी पूरा कर सकते हैं।

इन्हें होती है ज्यादा परेशानी : प्री-मेनोपॉजल और पोस्ट-मेनोपॉजल की श्रेणी की महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया होने की संभावना होती है। वहीं खुद को पूरी तरह से ढकने वाली महिलाओं और सनक्रीम लगाने वाली महिलाओं में विटामिन-डी की मात्रा काफी कम होती है, क्योंकि उनकी त्वचा में धूप प्रवेश नहीं कर पाती। वहीं बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की समस्या होने लगती है। इसलिए बच्चों को शुरुआती दिनों से ही पर्याप्त आहार के साथ-साथ धूप भी सेंकनी चाहिए। बच्चों में भी खास कर उन बच्चों को जिन्होंने मां का दूध पीना छोड़ दिया है, उन्हें विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कराना आवश्यक है।

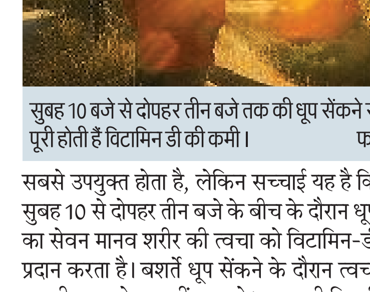

सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक की धूप सेंकने से पूरी होती हैं विटामिन डी की कमी। फाइल

व्यायाम भी है फायदेमंद

सर्दियों में हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम से भी फायदा मिलता है। इससे हड्डियों का घनत्व बना रहता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। इसके अलावा यदि हड्डियों को मजबूत बना रखना है तो सर्दियों में जितना संभव हो सके उतना धूप के संपर्क में रहें। क्रीम और लोशन के प्रयोग न करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि हम विटामिन-डी की कमी पर ध्यान नहीं देते तो हो सकता है कि हमें दिव्यांगता से जूझना पड़े।

अगले साल रिलीज होगी परिणीति चोपड़ा की थ्रिलर फिल्म

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपने किरदारों को लेकर काफी संजीदा रहती हैं। आने वाले साल में उनकी दो फिल्में रिलीज होंगी। इनमें से पहली फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' की हिंदी रीमेक है। फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला की है, जो एक हत्या की गवाह बन जाती है और वह उस घटना के रहस्यों को सुलझाने में लग जाती है। हॉलीवुड में बनी इस थ्रिलर फिल्म को काफी सफलता मिली थी। अब दर्शक बॉलीवुड में इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा करते हुए परिणीति ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, 'मेरी जिंदगी की सबसे थ्रिलिंग राइड। अब इसकी रिलीज डेट।' बता दें कि फिल्म अगले साल आठ मई को रिलीज होगी। परिणीति की 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' को सिनेमाघरों में सुशांत सिंह की फिल्म 'दिल बेचारा' से टक्कर मिलेगी। इसके अलावा परिणीति अगले साल साइना नेहवाल की बायोपिक में भी नजर आएंगी।

बहन खुशी के साथ अमेरिका में छुट्टियां मना रहीं जाह्नवी

जाह्नवी कपूर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी जिंदगी से जुड़े तमाम यादगार पलों को अपने फैंस से साझा करती हैं। जाह्नवी इस समय अमेरिका में हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन खुशी कपूर के साथ कुछ फोटो शेयर किए हैं। इन तस्वीरों में दोनों बहनें एक साथ मस्ती करती दिख रही हैं।

बहन खुशी की एक तस्वीर शेयर करते हुए जाह्नवी ने लिखा 'टू मच खुशी!' (बहुत ज्यादा खुशी), वहीं दूसरी तस्वीर में जाह्नवी कुछ खाते दिख रही हैं। उल्लेखनीय है कि अगले साल जाह्नवी की चार फिल्में रिलीज होने वाली हैं। गुंजन सक्सेना की बायोपिक इनमें से सबसे पहले रिलीज होगी। इसके बाद हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'रूहीआफजा' में वे राजकुमार राव के अपोजिट नजर आएंगी। यह फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होगी। इसके अलावा करण जौहर की पीरियड ड्रॉमा फिल्म 'तख्त' में जाह्नवी अहम किरदार निभाएंगी। इसके बाद वे अपने पिता बोनी कपूर की एक महिला केंद्रित फिल्म में नजर आएंगी।